Motion of Thanks on the President`s Address

श्री अखिलेश यादव (कन्नौज) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपनी पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है । अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों लगातार अपनी बात रख रहे हैं । अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपको और आपके साथ-साथ सभी चुने हुए सांसदों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ । साथ ही साथ, मैं सबसे पहले देश के उन सभी समझदार और ईमानदार मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने लोकतंत्र को एकतंत्र बनने से रोका ।

अध्यक्ष जी, चुनाव के समय ऐसा कहा गया कि हम 400 पार करेंगे, लेकिन मैं समझदार जनता को फिर एक बार धन्यवाद दूंगा । मैं कुछ कहना चाहता हूं-

आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरुर,

दरबार तो लगा है पर, बड़ा गमगीन बेनूर है ।

अध्यक्ष महोदय, दरबार तो लगा है पर, बड़ा गमगीन बेनूर है और पहली बार ऐसा लग रहा है कि हारी हुई सरकार विराजमान है, लेकिन जनता कह रही है कि चलने वाली नहीं है सरकार । जनता कह रही है कि चलने वाली नहीं सरकार, यह गिरने वाली सरकार है, क्योंकि-

ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं

अधर में जो है अटकी हुई, वह तो कोई सरकार नहीं

अध्यक्ष जी, दरअसल पूरा इंडिया समझ गया है कि इंडिया ही प्रो-इंडिया है । इस चुनाव में इंडिया एलायंस की नैतिक जीत हुई है । यह पीडीए इंडिया की सकारात्मक राजनीति और जो पोजिटिव पोलिटिक्स है, उस पोजिटिव पोलिटिक्स की जीत हुई है । यह इंडिया, पीडीए और सोशल जस्टिस मुहिम की विक्ट्री है । वर्ष 2024 का परिणाम हम इंडिया वालों के लिए जिम्मेदारी से भरा पैगाम भी है ।

अध्यक्ष महोदय, अगर मैं यूं कहूं कि 15 अगस्त, 1947 औपनिवेशिक राजनीति से आजादी का दिन था तो 4 जून, 2024 देश के लिए सांप्रदायिक राजनीति से आजादी का दिन रहा । इस सांप्रदायिक राजनीति के अंत और सामुदायिक राजनीतिक की शुरुआत है । जहां सांप्रदायिक राजनीति का अंत हुआ है, वहीं सामुदायिक राजनीति की शुरुआत हुई है । सबसे अच्छी बात यह हुई है कि इस चुनाव में सांप्रदायिक राजनीति की हमेशा के लिए हार हो गई ।

अध्यक्ष महोदय, कहने को यह सरकार कहती है कि यह फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और जीडीपी के मामले में वर्ल्ड की फिफ्थ इकोनॉमी बन गई है । लेकिन, यह सरकार क्यों छिपाती है कि अगर हमारी यह सबसे

लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हम पाँचवें नंबर पर हैं तो हमारे देश की पर-कैपिटा इनकम (प्रति व्यक्ति आय) किस स्थान पर पहुंची है ।

अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने देखा है कि अगर दिल्ली की सरकार ने कहा होगा कि पाँच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगी तो जहां से प्रधानमंत्री जी चुनकर आते हैं, उस प्रदेश की सरकार भी कह रही है कि हम वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना लेंगे । देश की इकोनॉमी कहां पहुंच गई, पर-कैपिटा इनकम क्या है? अगर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना है तो कम से कम 35 परसेंट की ग्रोथ चाहिए । मुझे नहीं लगता है कि 35 प्रतिशत की ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश में आ पाएगा । हम हंगर इंडेक्स में कहां खड़े हैं, नीचे से कहां हैं? जो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वह इनइक्विलिटी के पैरामीटर पर कहां खड़े हैं, वह हैपीनेस इंडेक्स में कहां खड़े हैं?

अध्यक्ष महोदय, जो लोग चुनाव को अपने तरीके से मोड़ते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस चुनाव के परिणाम ने तोड़ने वाली राजनीति को तोड़ दिया है और जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है । इस चुनाव में धन, छल और बल की नकारात्मक राजनीति की शिकस्त हुई है । इस देश का जो चुनाव हुआ, उसमें सकारात्मक राजनीति का नया दौर शुरू हुआ है । इस बार प्रो-कंस्टीट्यूशन वालों की जीत हुई है । हम मानते हैं कि संविधान ही संजीवनी है और उसी की जीत हुई है ।

इस संविधान मंथन में संविधान रक्षकों की जीत हुई है । अब ऊपर से नीचे की राजनीति का अंत हो गया है । अब नीचे से जो समाज की आवाज उठेगी, वही राजनीति का आधार बनेगी । मैं कहना चाहता हूं कि देश किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं, जनआकांक्षा से चलेगा । मतलब, अब मनमर्जी नहीं जनमर्जी चलेगी । इस चुनाव का बड़ा पैगाम यही है ।

अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें हुईं । अगर उत्तर प्रदेश की बात न हो, क्योंकि यह सबसे बड़ा प्रदेश है, उसने हर बार दूसरे दल को समर्थन देकर सरकार बनाई है । मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूं कि लोग क्योटो से फोटो लेकर बनारस की गलियों से लेकर गंगा जी तक ढूंढ रहे हैं । उनको लगता है कि जिस दिन मां गंगा साफ हो जाएगी, शायद उस दिन कहीं क्योटो उसकी गोद में मिल जाएगा । बनारसी लोग चाहते हैं कि कोई गंगा जी के तल में उतरकर उसका दर्द भी जाने । उत्तर प्रदेश की जनता का बस यही आग्रह है कि जिस गंगा जल को हाथ में लेकर सच कहने की कसम खाई जाती है, कम से कम उस गंगा जल से तो झूठ न बोला जाए । जहां विकास के नाम पर खरबों रुपये की लूट का राज खोलते भ्रष्टाचार के गड्ढे प्रदेश का नाम खराब कर रहे हैं, वहीं पहली बारिश में ही टपकती हुई छत और गिर चुकी स्टेशन की दीवार बेईमानी की निशानी बन गई है ।

अध्यक्ष महोदय, विकास का ढिंढोरा पीटने वाले इस विनाश की जिम्मेदारी कब लेंगे? और रही सच्चे विकास की बात, तो हमने जो सड़क बनाई, उस पर हवाई जहाज उतरे थे और उत्तर प्रदेश की मुख्य नगरी में सड़कों पर नावें उतरी हैं । अभी बारिश और हो जाएगी, तो नाव से भी चलना पड़ेगा । यही स्मार्ट सिटी के जुमले का भी हाल है । न तो जाम से छुटकारा मिला, न कोई बुनियादी सुविधाएं मिल पाई हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि देश के प्रधान सांसद जी ने अनाथ पशुओं के बारे में बहुत कुछ कहा था । अनाथ पशुओं की समस्या से छुटकारा दिलवाने का वादा किया गया था । कई चुनाव बीत गए हैं, अभी तक गन्ने के भुगतान का दो हफ्ते का जो वचन दिया था, कहां दिया था, अब तो वचन देने वाले को भी याद नहीं है । हर बात को जुमला बना देने वाले लोगों के ऊपर से जनता का भरोसा उठ गया है । इसीलिए, यह बहुमत की सरकार नहीं है, यह सहयोग से चलने वाली सरकार है । डबल इंजन के नाम पर उत्तर प्रदेश को टकराहट के सिवाय कुछ

हासिल नहीं हुआ । उत्तर प्रदेश में प्रभुत्व की लड़ाई दो लोगों को आपस में लड़ा रही है, लेकिन उसकी मार जनता को सता रही है । पिछले दस सालों की उपलब्धि बस इतनी रही कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ ।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश ने वो हालात देखे हैं कि नौजवान जब भी तैयारी करके जाता था और परीक्षा देकर लौटता था तो उसे पता लगता था कि पेपर लीक हो गया । उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर ही लीक नहीं हुआ, बल्कि जितनी भी परीक्षाएं हुईं, सभी के पेपर्स लीक हुए । केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं माननीय सांसद की बात सुन रहा था, कई ऐसे प्रदेश हैं, जहां पर परीक्षाएं देने तो बच्चे गए, लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया । अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया, उसके बाद जो बात उठी है, देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा, उसका भी पेपर लीक हो गया । आखिरकार यह पेपर लीक हो क्यों रहा है? सच्चाई तो यह है कि यह सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती । वह नौजवनों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती है । पिछले दस सालों की उपलब्धि इतनी रही है कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है, जिसने तथाकथित अमृतकाल में युवाओं के भविष्य की आशाओं को ही जहर दे दिया है । जो सरकार उम्मीद को मार दे, वह न तो वर्तमान को सुधार सकती है न भविष्य को संवार सकती है । सरकार आशा का प्रतीक होनी चाहिए, निराशा का नहीं । जनता चाहती है कि हर समस्या के लिए बीते कल को जिम्मेदार ठहराने के बहाने छोड़े और आने वाले कल की बात करें । अगले हजार साल के झूठे सपने दिखाने वाले अगले महीने होने वाली परीक्षाओं के लीक न होने की गारंटी सरकार कब लेगी? जनता अब न तो किसी बहकावे में आएगी न किसी के बहलावे-फुसलावे में आएगी, जो लोग कहते हैं कि अमृत काल की बात करने वाले जनता का जागरण काल आ गया है, इस सदन में नये जागरण के अनेक नये प्रतिनिधि बैठे हुए हैं । अब बात होगी तो सच्ची बात होगी, जनता के सामने पूरी सच्चाई और जिम्मेदारी के साथ हम लोग बात रखेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, एक जीत और हुई है । मैं जानता हूं सत्ता पक्ष वाले लोग समझ गए होंगे । अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है । हम यही सुनते आए हैं:

?होई वही जो राम रचि राखा, यह है उसका फैसला ।

होई वही जो राम रचि राखा, यह है उसका फैसला

जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज

जो करते थे किसी को लाने का दावा

वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार?

मैं फिर कह देना चाहता हूं,

होई वही जो राम रचि राखा,

यह है उसका फैसला, जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज

जो करते थे किसी को लाने का दावा

वे हैं खुद किसी के सहारे के लाचार ।

हम अयोध्या से लाये उनके प्रेम का पैगाम,

जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण ।

सदियों में जन-जन गाता है जिनकी गान,

अभयदान देती जिनकी मंद-मंद मुस्कान,

मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान ।

अध्यक्ष महोदय,

जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम,

ऊफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध,

वह हैं अवध के राजा पुरुषोतम प्रभु राम,

हम अयोध्या से लाये हैं उनके प्रेम का पैगाम ।

कुछ बातें समय और काल से परे होती हैं,

इसलिए आज यहां उत्तर प्रदेश के सदन में पढ़ा गया एक शेर याद आ गया । जो तब सही था, अब और सही साबित हो रहा है । इजाज़त हो तो अर्ज करूं,

हुजुर-ए- आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में

महफिल लूट ले गया कोई, जबकि सजायी हमने ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब चुनाव हुए तो मॉडल ऑफ कंडक्ट लागू हुआ । उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर सरकार मेहरबान रही और कमीशन भी मेहरबान रहा । मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन कहीं न कहीं उस संस्था पर प्रश्न चिह्न लगा है । अगर उस संस्था पर प्रश्न चिह्न लगा है तो इसे लगाने वाली सरकार की वजह से ही लगा है । अगर वह संस्था, निष्पक्ष होगी तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा, बल्कि दुनिया में हमारा लोकतंत्र और मजबूत दिखाई देगा ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे ईवीएम पर कल भी भरोसा नहीं था और आज भी नहीं है । अगर मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी भरोसा नहीं होगा । मैंने चुनाव में कहा था कि ईवीएम से जीतकर ईवीएम हटाने का काम करेंगे, न ईवीएम का मुद्दा मरा है और न ही खत्म होगा, जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, हम समाजवादी लोग उस बात पर अडग रहेंगे ।

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश वह प्रदेश है जिसने बीजेपी की सरकार बनवाई, एक बार नहीं, दो बार बनवाई और उसी उत्तर प्रदेश के साथ कितना बड़ा भेदभाव हुआ । मुझे याद है वह दिन जब माननीय प्रधान मंत्री जी एयर फोर्स के सबसे भारी वाहन से, हवाई जहाज से सड़क पर उतरे थे, वह अलग बात है कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं बैठ पाए थे । वहां एक्सप्रेस वे बना था और आज भी उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, सब उत्तर प्रदेश के बजट से ही बन रहे हैं, दिल्ली की तरफ से कोई एक्सप्रेस वे नहीं दिया गया है ।

मैं कहना चाहता हूं कि न केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर में भेदभाव हुआ है, बल्कि हमें याद है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने बड़े पैमाने पर गांव गोद लिए थे । आप सोचिए, अगर देश के प्रधान सांसद किसी गांव को गोद ले लें और उस गांव की तस्वीर न बदले तो मैं नहीं समझता कि किसी गांव की तस्वीर दस साल में बदली होगी । माननीय प्रधान मंत्री जी की ?आदर्श गांव? योजना थी, उसके तहत उन्होंने गांव गोद लिया था ।

पांच साल पहले खूब शोर हुआ था कि बनारस शहर की तरह डोमरी में चमचमाने लगेगा एक गांव, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं हुआ । उसकी दुर्दशा वैसी की वैसी ही है । यह गांव जैसा था, वैसा ही है । टूटी सड़कें, कच्ची पगडंडियां, उखड़े और टूटे हुए ईंट के खड़ंजे, बदहाल हैंडपंप, पावरलूम और पंखे की जाली के कारखाने को आखिर कब रफ्तार मिलेगी? उस गांव में ये सब काम होते थे और लोग इसे करते थे । खाली पड़े रसोई गैस के सिलेंडर, अंधाधुंध बिजली कटौती के बीच इस गांव के लोगों के लिए हर सुबह मजदूरी की कभी न खत्म होने वाली तलाश आखिर कब पूरी होगी? आप सोचिए, यह एक गांव की तस्वीर है । वह गांव जो कभी गोद लिया गया था, उस गांव की तस्वीर भी नहीं सुधर पाई है ।

माननीय अध्यक्ष जी, भाजपा के स्मार्ट सिटी के झूठे सपने में गांव के लिए कोई जगह नहीं है । उन्होंने गांव गोद लेने की जो बात कही थी, क्या वह भी जुमला था? पता नहीं, जिस गांव को गोद लिया था, उस गांव का नाम भी किसी को याद है? मैं नाम पूछकर किसी को शर्मिंदा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर नाम याद है तो यह और भी बुरी बात होगी कि उन्होंने नाम याद रखने के बावजूद भी कुछ नहीं किया । जिसे गोद लिया जाता है, उसे अनाथ बनाकर छोड़ देना अच्छी बात नहीं है । अगर उन तमाम गोद लिए गांवों की तस्वीर दस साल में बदली हो तो मैं सत्ता पक्ष के लोगों से कहूंगा कि सदन में जरूर इसकी बात रखें । आप जरूर बताएं । जो बात कास्ट सेंसस की उठी थी, हम उसके पक्ष में हैं । बिना कास्ट सेंसस के सामाजिक न्याय संभव नहीं है । सबको हक दिला पाना मुश्किल है । राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अग्निवीर को लेकर जो चिंता विपक्ष की थी और देश के नौजवानों की थी, वह चिंता वैसी की वैसी बनी है । मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हुआ हूं । मेरे साथ के बहुत से लोग बड़े पैमाने पर फौज में हैं । मेरे साथ पढ़े हुए जो सीनियर थे, मैंने समय-समय पर उनसे भी जानकारी हासिल की है । बड़े-बड़े अधिकारियों से मैंने पूछा है । वे शायद आपको न बता पाएं, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है ।

महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता यदि कोई है, तो वह देश की सीमाओं की सुरक्षा है । अग्निवीर जैसी व्यवस्था से यह कभी संभव नहीं है । हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं । आज नहीं तो कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, तो अग्निवीर व्यवस्था हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी । जिन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दो गुनी कर देंगे । आज पूरे देश का किसान देख रहा है कि उसकी आय कहां दो गुनी हो गई । सरकार बताए कि महंगाई बढ़ने पर उसकी आय कितनी होनी चाहिए । इन्फ्रास्ट्रक्चर की जो बड़ी-बड़ी बातें की गई थीं कि एमएसपी लागू करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, लेकिन जहां तक मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, अगर इस सरकार में एक भी नई मंडी बनी हो, तो मुझे सरकार बता दे ।

महोदय, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर सेक्टर में बनाने की बात कही गई थी, अगर सरकार की तरफ से एक भी मंडी 10 साल में बनी हो, तो सरकार जरूर बताए । जो सरकार मंडी नहीं बना सकती है, उस पर एमएसपी का भरोसा कैसे कर सकते हैं? आपके माध्यम से मैं यही कहूंगा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो लीगल गारंटी एमएसपी को मिलनी चाहिए थी, वह क्रॉप्स को नहीं मिली है । न केवल फसलों को मिले, बल्कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी एमएसपी देने का फैसला हो, जिससे हमारा किसान खुशहाल हो सके । साथ ही साथ ओपीएस की

बात अभिभाषण में नहीं आई है । ओपीएस लागू हो, जिससे हमारे तमाम सरकारी कर्मचारियों का भविष्य बन सके ।

देश की एक बड़ी आबादी, जहां से मैं चुनकर आता हूं, वहां और देश के कोने-कोने में बुनकर समाज के लोग बड़े पैमाने पर रह रहे हैं, लेकिन बुनकरों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे भी इस सरकार में नहीं मिल पा रही हैं । पिछली प्रदेश सरकारों ने बुनकरों के लिए जो योजनाएं चलाई थीं, वे भी बंद कर दी गई हैं । मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने नौजवानों को नौकरी नहीं दी है, बल्कि नौकरी और रोजगार उनसे छीने हैं ।

अत: मैं कहना चाहता हूं कि आपके राज में न नौकरी की उम्मीद है, न रोजगार । आपने छोटे कारोबारी को इतना छोटा बना दिया है कि न तो वह अपना पेट भर सकता है, न किसी को नौकरी पर रख सकता है । जो पद निकलते भी हैं, तो उन पर लेटरल एंट्री के नाम से पिछले दरवाजे से कुछ खास संगी-साथियों को रख लिया जाता है । आरक्षण का हक ?नॉट फाउंड सुटेबल? के नाम पर हड़पा जा रहा है । महोदय, आरक्षण के साथ इतना खिलवाड़ किसी सरकार ने नहीं किया होगा, जितना इस सरकार ने किया है । सरकारी नौकरियां इसलिए नहीं दी जा रही हैं, क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा । जिस प्रदेश से मैं आता हूं, वहां सबसे बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार है । पिछले 10 सालों में उन्होंने जो क्वैश्चन पेपर लीक कराये हैं, वे इसीलिए कराये हैं, ताकि नौकरी न देनी पड़े । अगर नौकरी देनी पड़ेगी तो उन्हें आरक्षण भी देना पड़ेगा । यह जान-बूझकर सरकार नौकरी और आरक्षण के साथ खिलावाड़ कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि आशा है यह सरकार तब तक चलेगी, जब तक उसके केंद्र में इस देश का हरेक गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी महिला, युवा, छोटा कारोबारी, ईमानदार नौकरी पेशा आम आदमी, कर्मचारी-अधिकारी, मजदूर और किसान होगा, न कि धनवान होगा । शासन के आधार पर संविधान होगा व जुमलों की जगह सच में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, साम्प्रदायिक हिंसा, दलित व महिला उत्पीड़न और समाजिक अन्याय जैसे मूलभूत मुद्दों का समाधान होगा । भोजन, बिजली, पानी, दवाई और पढ़ाई जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए कागजी योजनाओं की जगह सच में इंतजाम होगा । ? (व्यवधान)

मैं एक बार फिर उत्तर प्रदेश की समझदार जनता द्वारा सबसे बड़ी पार्टी चुने जाने के साथ-साथ इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें जिताने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं । मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हो, वह सरकारी भाषण न हो । सच्चाई के साथ सरकार अपनी बातें रखे ।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

श्री संतोष पांडेय (राजनंदगाँव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं कि आज आपने मुझे कीमती समय देकर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं सबसे पहले अपने छत्तीसगढ़ और उन राजनंदगाँव क्षेत्र की समस्त जनता और मतदाता का भी आभार प्रकट करता हूं । मैं आप सभी वरिष्ठजनों के प्रति कृतज्ञ हूं और मैं आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं ।

महोदय, कल जब से चर्चा शुरू हुई, वह रात के 12 बजे तक चली । जिस प्रकार से अभी अखिलेश जी बोल रहे थे और कल जब शुरूआत हुई तो नेता प्रतीपक्ष राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार की बातें की, आज जब अखिलेश जी ने शेरो-शायरी और गजल की पंक्तियों से शुरूआत की तो मैं भी यह बता दूं कि अखिलेश जी-

?ज़रा सा क़ुदरत ने क्या नवाज़ा आके बैठे हो फलसफे में

तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई-नई है ।?

यहां जितने भी लोग बैठे हैं, ये सब उसी प्रकार की बातें कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बार-बार भगवान शंकर का फोटो दिखा रहे थे । वे भगवान भोलेनाथ हैं । वे भगवान शंकर हैं । यह आपकी फितरत में है । आपने छत्तीसगढ़ में, मैं नाम नहीं लूंगा, आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ को निपटा दिया और वे लोक सभा चुनाव में भी आकर निपट गए । वे महादेव जी के नाम से सत्ता चला रहे थे, जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने निपटा दिया । आपको ध्यान होगा कि 6000 करोड़ रुपये से ऊपर का सट्टा, जिसका संचालन आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने किया था । भगवान शंकर को ऐसे आसानी से न लें और बात-बात में चित्र दिखाने की कोशिश न करें ।

राहुल गांधी जी, आपने जो शुरूआत की है, आपने जिस प्रकार से हिन्दुत्व को लेकर, हिन्दू को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हिंसक कहा है, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी के सामने इस सदन में रखना चाहता हूं कि क्या हिन्दू हिंसक हो रहा है? क्या भाजपा हिंसा की बात करती है? इस हिन्दुस्तान के अंदर हिंसा कौन फैला रहा है? हिन्दू समाज कितना हिंसक हुआ है? कितना हिंसक ये तथाकथित शांतिप्रिय समाज है? यह पूरा भारत जनता है, क्या कर्नाटक में प्रवीण नेत्तारू की हत्या हिन्दू समाज की भीड़ ने की थी?

राजस्थान में कन्हैया लाल (टेलर) की गला रेतकर हत्या क्या हिन्दू समाज ने की थी? क्या हिन्दू समाज है, जो अलग-अलग जगहों पर हंगामा खड़ा कर रहा है? पूरे हिन्दुस्तान में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, राहुल गांधी जी ने आपने एक सवाल किया है कि जम्मू-कश्मीर में बम विस्फोट करने वाला किस समाज का है? जम्मू-कश्मीर पर हमला करने वाले किस समाज से आते हैं? ? ज़िदाबाद का नारा लगाने वाले किस समाज के हैं? आपने संसद के अंदर इसकी शुरुआत की है । संसद के अंदर आपने चिल्ला-चिल्लाकर जिस प्रकार की बातें की हैं, यहां की परंपराओं को तोड़ने की कोशिश की गई है । मर्यादा को तार-तार करने की कोशिश की गई है । किंतु हमारी यह उच्च परंपरा रही है, आप इसमें सफल नहीं हो पाएंगे ।

राहुल गांधी जी, आप संसदीय पाठ न पढ़ाएं । आज आपने जिस प्रकार से हिन्दुत्व का अपमान किया है, आपने कल जो शुरू किया था, आपकी ही पार्टी के उत्तर प्रदेश के एक सांसद ने कहा है, उन्होंने छत्तीसगढ़ की बात की थी । इमरान मसूद जी ने छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग की बात की है । मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि वे छत्तीसगढ़ में कौन-सा काम करने के लिए गए थे । क्या आपको मालूम है? कैसे रात के अंधेरे में वह नदी में कूद गए । आप ये फालतू की बात न करें । छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार की मॉब लिंचिंग पूर्व मुख्यमंत्री के समय हुई थी, आप उनकी बात बताइए ।

मैं आज सदन को यह बताना चाहता हूं कि जब हिन्दुत्व की बात होती है, तब मुझे अटल जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं -

?हिन्दू तन-मन, हिन्दू जीवन, रग-रग हिन्दू मेरा परिचय,

मैं आदि पुरुष, निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर,

पय पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर,

मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतःस्थल वर विशाल,

जग के ठुकराए लोगों को, लो मेरे घर का खुला द्वार,

अपना सब कुछ लुटा चुका, फिर भी अक्षय है धनागार,

मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकीयों का वह राजमुकुट,

यदि इन चरणों पर झुक जाए, कल वह किरीट तो क्या विस्मय,

हिन्दू तन-मन, हिन्दू जीवन, रग-रग हिन्दू मेरा परिचय ।

होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, कल लूं जंग को गुलाम?

मैंने तो सदा सिखाया, करना अपने मन को गुलाम,

गोपाल-राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए?

कब दुनिया को हिन्दू करने घर-घर में नरसंहार किए?

भू-भाग नहीं, शत-शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय,

हिन्दू तन-मन, हिन्दू जीवन, रग-रग हिन्दू मेरा परिचय ।?

ये हिन्दुत्व है । आपने हिन्दू, हिन्दू समाज और हिन्दुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, यदि मैं यह कहूं कि मोदी जी हैं, तभी वह मुमकिन है । उस काम की शुरुआत नहीं, बल्कि डिलीवरी हुई है, जिन्हें पूरा करना ही असंभव लगता था । मोदी जी हैं, तभी वह गुंजाइश अभी भी बनी हुई है । कश्मीर में मोदी जी असंभव को संभव कर दिया । ये वे काम हैं, जिसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है । जिसे दुनिया का 8 वां अजूबा कहा जा रहा है, पड़ोसी देश भी कहीं उस मुकाबले में नहीं हैं । जम्मू-कश्मीर में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है ।

अध्यक्ष महोदय, कश्मीर का चिनाब रेल ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है । वह रेल ब्रिज न सिर्फ बनकर तैयार है, बल्कि ट्रेन्स दौड़ाकर देखी जा चुकी हैं, उसका ट्रायल हो चुका है । पहले सिर्फ नारे लगते थे, हम कहते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, किंतु उसे सार्थक करने का काम माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया है । दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज बनाया है । यूएसबीआरएल यानी उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लाइन

प्रोजेक्ट के निर्माण पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई थी, उसको माननीय मोदी जी ने पूरा किया है । भारत ने कर दिखाया है, पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है ।

अध्यक्ष महोदय, नदी की सतह से इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर है । यह पुल एफिल टॉवर से भी 35 मीटर ऊंचा है । जहां लोग फोटो खिंचाने जाते हैं और उसका नाम लेते हैं, यह पुल उससे भी 35 मीटर ऊंचा है । हमारे देश में बने कुतुब मीनार से यह पांच गुना ऊंचा है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी ने हर मुश्किल को संभव किया है । ठीक वैसे ही जैसे कोरोना काल की महामारी में अंतर्राष्ट्रीय बीमारी के कारण पूरी दुनिया में त्राहि-त्राहि मची हुई थी । विदेश के लोग कहते थे कि भारत में इतनी बड़ी आबादी है, उसका क्या होगा? किंतु इस कोरोना के तूफान से भी राष्ट्र की कश्ती को सुरक्षित बाहर निकालने का काम यदि किसी ने किया है, तो वह इस देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है । कोविशील्ड और कोवैक्सीन का निर्माण ही नहीं कराया, बल्कि संसाधन मुहैया कराएं । लैब के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करते रहे । देश के लोगों को 300 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज़ लोगों को मुहैया करायी है । इतना ही नहीं, उन्होंने दुनिया के अन्य देशों को भी सब प्रकार की सुविधाएं दीं । उस समय भी उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को नहीं छोड़ा ।

अध्यक्ष महोदय, उस तरफ बैठने वाले यह नहीं चाहते थे कि वैक्सीन भारत में निर्मित हो । ये तो फाइज़र की वकालत कर रहे थे, विदेशी कंपनियों की वकालत कर रहे थे । ये सेन्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का भी निर्माण नहीं चाहते थे, ये जीएसटी का कलेक्शन नहीं चाहते थे । डर्टी पॉलिटिक्स इनके रक्त में है । माननीय प्रधानमंत्री जी हार नहीं मानने वालों में से हैं, उन्होंने गतिरोधों को दूर किया । नए ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए, मुफ्त टीकाकरण, ऑक्सीजन रेल ने ताकत दी, नए वेंटिलेटर्स का निर्माण किया, नए अस्पतालों का निर्माण किया । उस समय देश में एक ही कोविड सेंटर हुआ करता था, उन्होंने हजारों कोविड सेंटर्स स्थापित किए । पहले पीपीई किट नहीं बनती थी, आज हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं । ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई, कॉरिडोर बनाया गया । एयरपोर्ट पर टैंकर दिए, क्रॉयोजेनिक्स से लाने की बात की गयी । इसमें पीएम केयर्स फंड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम किया गया है । मैं यह कहूंगा कि ये केवल सिर्फ गरीबों के बारे में केवल चर्चा करते रहे हैं, किंतु यदि गरीबों की, मजदूरों की और अंत्योदय के लिए कोई सरकार है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है । आज पूरा देश उस पर गर्व कर रहा है । चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे पेयजल का क्षेत्र हो, यदि किसी ने राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए काम किया है, तो माननीय मोदी जी ने किया है । मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूं । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं ।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Speaker Sir, thank you for giving me the opportunity to deliver the speech on the President?s Address.

The hon. President of India read her speech which was drafted by the Union Government led by Shri Narendra Modi ji, the hon. Prime Minister. In the

President?s Address, the role of the Election Commission of India has been praised. What she could have done except praising! We have great respect for the Election Commission of India and all the Constitutional bodies. The standard of conducting an election in a fair manner was really and seriously set up by Shri T. N. Seshan when he was the Election Commissioner. If we look at it from outside one may come to the conclusion that this time also, the election was conducted. But repeatedly, during the election, all of us, including our leader, the hon. Chief Minister Mamata Banerjee, raised so many questions about the role of the Election Commission of India.

Now, the question is this. Has the Election Commission of India conducted the elections in 2024 impartially?

In our State, the ... had acted on the basis of the desire of the Bhartiya Janata Party leaders. A good number of police officers right from DG to OC were transferred because of the desire of the BJP leaders and not only that, before effecting such transfers, the Leader of the Opposition of the State Assembly in a public speech said that these officers will be transferred, these officers will be transferred, these officers will be transferred! ? (*Interruptions*) He was saying this in his public speech and the ... acted on the dictation of the Bhartiya Janata Party leaders. At every stage, every time, the ... intervened and interfered in the election process. But when we lodged the complaint against the BJP candidates and their leaders, no step was taken. They have won 10,000 votes, 7000 votes, or 8000 votes only because of the blessings of the .... Otherwise, you would not have seen these 12 MPs from the Bhartiya Janata Party from West Bengal.

What did the CISF do? The CISF personnel were threatening the voters to cast vote in favour of the Bhartiya Janata party. Do you know that in the fifth phase of election, that was the date of my constituency election and Sajda Ahmed?s constituency elections, on the previous night, the CISF personnel entered the House, molested two women. ? (*Interruptions*) Yes, they did. ? (*Interruptions*)

One woman is from Uluberia and the other woman is from Jangipara. It is a shame on ..., that his CISF entered the House. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं ।

? (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी **:** क्यों नहीं बोलेंगे? बोलना होगा । ? (*Interruptions*) Why was the seventh phase of the election conducted? ? (*Interruptions*) The election was conducted for three months. Who did they want to accommodate? ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं । हमें चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर निष्पक्षता का सवाल न उठाए तो ठीक रहेगा ।

? (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE: Sorry, I could not have done that.

माननीय अध्यक्ष **:** बी. महताब जी, आप क्या बोलना चाहते हैं?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Kalyan Banerjee is a very senior Member and he is a very learned person. He is a very eminent jurist also. My only request to you, Sir, is that when we make allegations on an individual or an institution, there is a provision in the rules that he or she should be given an opportunity to reply. I do not find that there is anyone in this House, who can stand up on behalf of Election Commission to reply...(*interruptions)*

माननीय अध्यक्ष **:** आप रूल 353 देख लें ।

?(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, keeping that in mind, I would request Kalyan Banerjee Sir to consider that. ? (*Interruptions*). Please consider that. ? (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE: I would not have raised the issue unless in the Speech it has not been written. It reads, ?I also express my gratitude to the Election Commission of India on behalf of crores of Indians today. This was the largest election in the world.? I am opposing that.? (*Interruptions*). Why have you brought the Election Commission into the Speech? ? (*Interruptions*). If you brought it in the President?s Address, you have to hear, Mr. Mahtab. ? (*Interruptions*). You must have tolerance to hear now. ? (*Interruptions*) You have gone to that side. Now, you increase your patience. ? (*Interruptions*) You increase your tolerance. ? (*Interruptions*) This is written here. ? (*Interruptions*) I go by the law. ? (*Interruptions*) अभी इतना गुस्सा आ गया**,** आप बाद में देखना कि क्या होगा??(व्यवधान) अभी-अभी इतना गुस्सा । ?(व्यवधान) Why was the election held in seven phases? Why? And why for two months and 15 days? Why? ? (*Interruptions*) Why has the entire development of the country been

stopped? Why? ? (*Interruptions*) It was done to accommodate ... to go all over the States. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** यह गलत है । चुनाव आयोग निष्पक्ष है, निर्विवाद है, वह अपनी तारीख खुद तय करता है ।

?(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी **:** नहीं, we are saying this. ? (*Interruptions*) This is the charge against the Election Commission of India. ? (*Interruptions*).

Sir, speeches have been delivered. Hatred speeches have been delivered. Hatred speeches against the minority community and Muslims have been delivered. ? (*Interruptions*) What steps have been taken by the Election Commission of India against them? ? (*Interruptions*) Only steps were taken against the Opposition. ? (*Interruptions*) All the steps against the Opposition leaders were taken. ? (*Interruptions*)

Now, I come to another chapter. I will go into it one by one. माननीय प्रधान मंत्री**,** हम आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं । आप देश के माननीय प्रधान मंत्री हैं । आप एज में सीनियर हैं । आपने ही कल कहा है कि जो सीनियर हैं**,** उनकी इज्जत करनी चाहिए । हम लोग इज्जत करते हैं, but I am in the Opposition. I have to criticize also. This is my role, and that is why, people of Sreerampur Parliamentary constituency have chosen me by a margin of 1,75,000 votes. मोदी जी के वोट से बहुत ज्यादा । Modi Ji, why are you showing so much hatred, vindictive attitude towards the Opposition? Why? In a democracy, Opposition parties will always criticize the Ruling Party. That is the fundamental job of the Opposition parties. Why do you hate all the Opposition leaders all the time or spread hatred towards the Opposition or towards the minorities?

Since 10 long years, I have never heard any sweet words or any soft words from Modi Ji as far as the Opposition is concerned. ? (*Interruptions*) I have never heard any words of praise from the hon. Prime Minister for the Opposition. ? (*Interruptions*) I have never heard any praise for the Chief Ministers who are there in the non-BJP ruled States. Nowhere have I heard that. ? (*Interruptions*) With great pain, I am saying so.

In our State, you hate our Chief Minister, Mamata Banerjee; in Tamil Nadu, you hate Mr. Stalin; in Delhi, you hate Arvind Kejriwal; in Jharkhand, you hate Hemant Soren; in Maharashtra, you hate Uddhav Thackeray; in Uttar Pradesh, you hate Akhilesh Yadav. ? (*Interruptions*)

12.00 hrs

In Karnataka, you hate Siddaramaiah. Anyway, that is the reason ? (*Interruptions*) If you are arrogant, I do not mind. But today, time has come to oversee this arrogancy yourself. ? (*Interruptions*) This arrogancy, this hatred, this vindictiveness has downgraded the popularity of Mr. Narendra Modi in India itself. You must appreciate that this is the point which you have taken.

What is called stable Government with clear majority? Since BJP has lost 63 seats and is not having majority, you wish to redefine the term ?stable Government? on the basis of the strength of other political parties. You are rewriting the term ? stable Government?. It is a fantastic procedure. आपने बोला था न, अब की बार 400 पार । आपने बोला था ।? (व्यवधान) सर, खेल शुरू हो गया था । खेल तो बहुत से हैं ।? (व्यवधान) Chu-kit-kit भी खेल है । Chu-kit-kit में चू धरा 400 में, kit-kit-kit-kit में कितना हुआ 240. उस गेम में भी हार गए ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप इधर एड्रेस कीजिए ।

श्री कल्याण बनर्जी **:** सर, मैं तो आपको ही देख रहा हूं । मैं किसी और को नहीं देख रहा हूं । एक बार साइड से देखने से? (व्यवधान) सर, सुनिये । आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं हैं, कोई जेंटलमैन नहीं हैं, जो उनको देखेंगे । गुड एक्ट्रेस भी आईं, लेकिन उनको नहीं देखता हूं, मैं आपको ही देखता हूं । सिर्फ आपको ही देखता हूं । आप ही मेरे अंदर में हैं । ? (व्यवधान)

Remember your attitude towards the Opposition. You could not fulfil your promise whatever promise you made in every field either in ?Mann Ki Baat? or in ?Dil Ki Baat?. मोदी जी की गारंटी है, लेकिन मोदी जी की गारंटी में वारंटी नहीं है । Public knows that there is no warranty. ? (*Interruptions*) गारंटी है लेकिन वारंटी नहीं है ।? (व्यवधान) Sir, please keep in mind that I am addressing you. Please keep in mind that this NDA Government secured around 48.86 per cent votes including 8.3 per cent in NDA. The total percentage is 48.86 per cent. What did INDIA bloc get? INDIA bloc secured 51.14 per cent votes. ? (*Interruptions*) There is a change. Of course, suddenly, there is a change in the country itself. What has the hon. President of India said? She said what has been done. Change is this. There is an unstable Government and on the other side, there is a strong Opposition in the country. ? (*Interruptions*) आपको हर पल, हर दिन याद रखना होगा । हम लोग अनस्टेबल हुए और इंडिया ब्लॉक ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा सख्त है ।? (व्यवधान) हम इधर जो बोलेंगे, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ाई चलेगी । पॉलिटिकल लड़ाई चलेगी । ये ज्यादा दिन नहीं रहेंगे । सिर्फ महाराष्ट्र के इलैक्शन होने दीजिए, उत्तर प्रदेश के इलैक्शन होने दीजिए, उसके बाद यह गवर्नमेंट डेढ़ वर्ष में साफ हो जाएगी । इधर कोई नहीं रह सकता है । ? (व्यवधान) In our country, excepting the Emergency days, never has any Prime Minister misused his or her power for targeting the Opposition leaders by using ED and CBI like what has happened in this Government. ? (*Interruptions*) You are claiming a stable

Government. While we are habituated to see Narendra Modi ji, Prime Minister coming here, entering into the Parliament, standing on his feet, delivering the speech with all confidence, but now what do we see? Now we see that the Prime Minister is entering into the Parliament with two crutches.

One crutch is Nitish ji?s Party and another crutch is Naidu Babu?s Party. वे दो क्रचेज लेकर चलते हैं । He will be moving around all over India with two crutches. Not only in India, he will be moving around internationally with two crutches. Earlier, we have seen that our hon. Prime Minister was having so much confidence in him. But today, he is not having that confidence in him.

You have always blamed us that the corrupted leaders assembled and created Opposition-bloc of INDIA alliance. That is the allegation against us. Modi ji has said this all the time. Today also, he will say this thing. But I have a simple question to ask. Modi ji, what about Shri Chandrababu Naidu? What about Shri Ajit Pawar? What about Praful Patel? Did CBI and ED arrest Shri Chandrababu Naidu? Why are these cases still pending?

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, जो सदस्य यहाँ के मेम्बर नहीं हैं, उनका नाम न लें ।

श्री कल्याण बनर्जी **:** ठीक है । Then, what about the TDP leaders? मैं चेंज कर देता हूँ । What about the NCP leaders? Are they not corrupted? Why was the top leader of TDP not arrested by the ED/CBI? Why is it so? He has become now honest. देखिए, बीजेपी के साथ रहने के बाद वाशिंग मशीन में कैसे क्लीन हो गये । वे ऐसे क्लीन हो गये? (व्यवधान) Now, what political compulsion is there? फेट देखिए । क्या पॉलिटिकल कमपल्शन है कि आपको भी डिसऑनेस्ट, करप्ट लीडर्स को लेकर सरकार बनाना पड़ता है । यही फेट है ।? (व्यवधान)

In May, 2024, during the course of the conduct of the General Elections to the Lok Sabha, Shri Narendra Modi and Shri Amit Shah ji gave television interviews as part of their political campaign and asked people to buy shares before 4th June, 2024. Amit Shah ji said, ?You can buy before 4th June. This market will shoot up?. The stock market crashed spectacularly after the declaration of results on 4th June, leading to heavy losses of around Rs. 31 lakh crore of the investors. The modus operandi of this was that all the *Godi* media predicted more than 356-BJP led seats in India in exit polls. All the *Godi* media predicted inflated results for BJP almost in all States. And in our State, it was claimed that the BJP would get 29 to 31 seats; whereas the results showed only 12 seats. It is because of the prediction of the *Godi* media in the exit polls that the stock market saw an unprecedented rally on 3rd June. It is also

important to note that the agency ?Axis My India? was also hired by the BJP to conduct election survey for the BJP Party.

Hon. Speaker, Sir, since you have asked me not to take any name, I will not take the name. … Now, who will conduct the investigation? No investigation has been conducted. It is because they are on that side.

Hon. Speaker, Sir, in the Presidential Speech, it has been written at serial number 3 that this has happened after six decades. ? (*Interruptions*) Sir, I have twenty-five minutes. Please allow me to speak.

Hon. Speaker, Sir, this Government has interfered with the federal structure of the State. The Government wants to run this country disobeying the non-BJP ruled State Governments. The Government has even gone to the extent of discussing water sharing issues relating to Ganga and Teesta rivers with the hon. Prime Minister of Bangladesh without having the views and participation of the hon. Chief Minister of the State of West Bengal.

Such unilateral deliberations and discussions without consultations and opinion of the State Government is neither acceptable and desirable. Our hon. Chief Minister Mamata Banerjee by a letter dated 24th June, 2024 pointed out such unacceptable and undesirable attitude of the hon. Prime Minister. You have ignored paramount interest of the people of the West Bengal.

What are Governors doing? Why have they been appointed in the non-BJP States? Is the Central Government running a parallel Government through the … When will such discussions take place? We are going on with these things for the last three years. We are asking for a discussion on this issue of Governors in the non-BJP States. What are they doing? Two MLAs are holding *dharna*. Do you know the reason? The reason is that they have to go to the Governors House to request him. If you ask the Members of Parliament to go to the Rastrapati Bhawan and take oath, what will you feel? Tell me. This kind of thing is being done. This is ridiculous.

Three *Sanhitas* were brought. At that time, you have suspended 140 MPs. We were outside. No discussion has happened from our side. You make a big claim that colonial law is being replaced. Very good. I have no objection. But, why? In these laws, 90 per cent provisions in toto have been made from the old laws. Some cosmetic changes are in the new laws. Cosmetic changes are there. Title has been changed. You have got enough time to give a complete new code. A man like Bhupender Yadav is there with you. He was the Chairman of the Standing

Committee on Law for five years. I worked with him. He is a very nice man. So many lawyers are there. Why could you not take help from them? इस नए लॉ के लिए आपके दिमाग में क्यों नहीं आया? ? (व्यवधान) अभी तो आप ब्रिटिश लॉ को लेकर चल रहे हैं । ? (व्यवधान) It has ninety per cent provisions of the British laws and title is only in Hindi or in Sanskrit. You are claiming that you have brought a new law in this country. सर, मुझे तो बहुत-कुछ बोलना था, आप मेरे से क्यों इतना रूठ गए हैं? ? (व्यवधान) आज आप क्यों मुझसे बहुत रूठ गए हैं? ? (व्यवधान) मैं क्या करूंगा, सर? ? (व्यवधान) मैं आपसे ?न? नहीं बोल सकता, यही मेरी दिक्कत है । ? (व्यवधान) I will give data on 3-4 points. I can say no to my wife but I cannot say no to you. That is the whole problem of mine.

Sir, in 2014, the Global Competitive Index Ranking was 60 out of 141 countries. In 2019, it was 68 and in 2023, it has gone down to 65.

GDP growth was 7.41 per cent in 2014, in 2019, it was 3.74 per cent and in 2023, it was 7.6 per cent. India?s foreign loan in 2017 was 446.2 billion US dollar. In 2019, it was 543.1 billion US dollar and in 2023, it was 663.8 billion US dollar. आप लोग महिलाओं के लिए बहुत बोलते हैं न? ? (व्यवधान) आप कब मणिपुर गए? ? (व्यवधान) अरे, बसीरहाट में तो बहुत कुछ हुआ है । ? (व्यवधान) तीन लाख से ज्यादा वोटों से जीते । ? (व्यवधान) संदेशखाली के लिए तो बहुत बोला है । ? (व्यवधान) रेखा जी को फोन करके बोला कि उधर खड़ी हो जाइए । ? (व्यवधान) एक बार वहां नहीं गए । ? (व्यवधान) श्री प्रहलाद जोशी जी, बताइए? ? (व्यवधान) एक बार प्राइम मिनिस्टर या कोई वुमेन मिनिस्टर किसी इफेक्टिड वुमेन को फोन करके नहीं बोल सकती थी कि बेटी, तू देश की बिटिया है, तू मेरी बिटिया है, हम तुझको देखेंगे । ? (व्यवधान) यह बात नहीं बोल सके? ? (व्यवधान)

The crime against women reported per lakh population in country is like this. In 2014, it was 56.3. In 2019, it was 66.4 and in 2023, it was 75.8.

The total number of cases of crime against women in 2014 was 3,37,922. In 2019, it was 3,70,503. In 2023, it was 4,00,045.

महोदय, थोड़ा शेड्यूल कास्ट के बारे में सुन लीजिए । ये शेड्यूल कास्ट के लिए बहुत रोते हैं । The number of cases of crime against SC people in 2014 was 40,401. In 2019, it was 45,961. In 2023, it was 57,522. The number of cases of crime against ST people was 6,827 in 2014. In 2019, it was 7,570. In 2020, it was 10,064. सर, आपने हमें बहुत अपॉर्चुनिटी दी है । I am very grateful to you.

माननीय अध्यक्ष **:** जितना आपकी पार्टी का समय है, मैंने उतना ही समय दिया है, ज्यादा नहीं दिया है ।

श्री कल्याण बनर्जी **:** महोदय, हमारा 5 मिनट का समय और है तो वह हमें दे दीजिए ।

माननीय अध्यक्ष **:** आपकी पार्टी का समय शेष है, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से एक और वक्ता बोलने वाले हैं ।

श्री कल्याण बनर्जी **:** सर, समय है तो हमें बोलने दीजिए ।

माननीय अध्यक्ष **:** नो-नो ।

श्री कल्याण बनर्जी **:** सर, आप जो बोलेंगे, वह हम करेंगे । हम बैठ जाते हैं ।

Thank you, Sir. I am concluding now. सर, हम कुछ नहीं माँगते हैं । माँगने की कोई बात नहीं है, जो है, वह हम लड़ाई करके, लड़कर ले लेंगे, लेकिन थोड़ा प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलिए कि अपोजिशन की तरफ थोड़ा पोलाइट हो जाइए ।? (व्यवधान) पोलाइट हो जाइए ।? (व्यवधान) वे कैसे नींद में जाते हैं?? (व्यवधान) इतना वेन्जन्स लेकर, इतना खिलाफ होकर, अपोजिशन के खिलाफ इतनी नफरत रखकर कैसे वे नींद में चले जाते हैं?? (व्यवधान) धन्यवाद ।? (व्यवधान)

पर्यावरण**,** वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री **(**श्री भूपेन्द्र यादव**):** महोदय, हमारे साथी महताब जी ने एक विषय उठाया था । कल्याण बनर्जी जी एक सीनियर काउंसिल तो रहे हैं, ये अनपार्लियामेन्टरी वर्ड को भी जानते हैं ।

माननीय अध्यक्ष **:** हाँ, उनको हटा देंगे ।

श्री भूपेन्द्र यादव **:** अनपार्लियामेन्टरी वर्ड में इलेक्शन कमीशन के लिए जो कहा गया है ।

माननीय अध्यक्ष **:** इलेक्शन कमीशन और राज्यपाल वाला विषय हटा दिया है ।

श्री भूपेन्द्र यादव **:** सर, टीडीपी और जेडीयू से हमारा प्री-पोल अलायंस था, उनका तो कांग्रेस के साथ अलायंस भी नहीं था । हमारे अलायंस को लेकर जो इन्होंने अनपार्लियामेन्टरी कहा है, प्रधानमंत्री जी को लेकर, उसको भी हटाया जाए ।

श्री सौमित्र खान (बिष्णुपुर) **:** सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ ।? (व्यवधान)

महोदय, सबसे पहले तो मैं बिष्णुपुर लोक सभा की जनता को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने आज हमें तीसरी बार संसद में चुनकर भेजा है ।? (व्यवधान) इसके लिए मैं अपने बिष्णुपुर की पूरी जनता को प्रणाम और नमस्कार करता हूँ ।? (व्यवधान) मैंने सोचा था कि आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ जो माहौल बन चुका है तो कुछ न कुछ तो मुझे बोलना चाहिए ।? (व्यवधान)

आप लोग हमें बोलने दीजिए ।? (व्यवधान) सर, ऐसे कैसे चलेगा? सर, कल्याण दा ने इलेक्शन कमीशन को बोला है ।? (व्यवधान) मेरा राष्ट्रपति महोदया को प्रणाम है ।? (व्यवधान) अभी कल्याण दा इलेक्शन कमीशन के बारे में बोल रहे थे ।? (व्यवधान) मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि बंगाल में लोक सभा और विधान सभा के इलेक्शन के अलावा कोई इलेक्शन नहीं होता है ।? (व्यवधान) बंगाल का एक ट्रेडिशन बन गया है कि ये राज्पाल को नहीं मानेंगे ।? (व्यवधान) बंगाल का एक ट्रेडिशन हो गया है कि ये राष्ट्रपति को नहीं मानेंगे ।? (व्यवधान) बंगाल का एक ट्रेडिशन हो गया है कि ये कोर्ट को भी नहीं मानेंगे ।? (व्यवधान) कल्याण दा ने जो बात कही है, ये वरिष्ठ लीडर हैं, ये मेरे वरिष्ठ नेता थे । कल्याण दा, जब इलेक्शन कमीशन ने इतना घटिया काम किया है, लेकिन सुनिए अगर पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन और सेन्ट्रल फोर्सेज नहीं रहेगी तो वहाँ इलेक्शन कभी नहीं होगा । वहाँ

कोई भी पंचायत इलेक्शन नहीं होता है । वहाँ कोई भी म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन नहीं होता है । वहाँ पर विरोधी पक्ष के 200 आदमी से ज्यादा हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार दिया है ।? (व्यवधान)

विरोधी पक्ष को कोई फ्रीडम नहीं है । विरोधी पक्ष से किसी को भी बोलने का हक नहीं है ।? (व्यवधान) यहां मीटिंग्स होती हैं, लेकिन बंगाल में कोई मीटिंग नहीं होती है । पश्चिम बंगाल में विरोधी पक्ष के सांसद, एमएलए को कभी नहीं बुलाते हैं । यहां तो स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग्स होती हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं होता है । इलेक्शन के बाद भी बीजेपी के युवा कार्यकर्ता को मार दिया गया है ।

12.22 hrs

(Shri Jagdambika Pal *in the Chair*)

कूच बिहार में तृणमूल वालों ने एक महिला को रास्ते पर नंगा घूमाया ।? (व्यवधान) तृणमूल कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि यह मुस्लिम राष्ट्र है और मुस्लिम राष्ट्र में ऐसा ही होता है । बंगाल में महिला की रास्ते पर पिटाई होती है और ये लोग महिला की बात कर रहे हैं । कल पश्चिम बंगाल के चोपड़ा में यह घटना हुई है लेकिन कोई भी शिकायत दर्ज नहीं होती है ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** कल्याण बनर्जी जी, आप कृपया बैठ जाएं । कृपया आप सभी लोग बैठ जाएं । माननीय सतीश गौतम जी, आप भी बैठ जाएं ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आप सभी कृपया बैठ जाएं । मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जब अध्यक्ष जी या सभापति पीठ से खड़े होते हैं, तो उस समय सभी को शांत हो जाना चाहिए । यह 18 वीं लोक सभा का पहला सत्र है । 381 नए सदस्य चुन कर आए हैं । हम जो प्रिसिडेंट कायम कर रहे हैं, इसे पूरा देश देख रहा है । जब भी अध्यक्ष जी या सभापति चेयर से खड़े हो जाते हैं, तो सभी को बैठ जाना चाहिए, चाहे पक्ष के सदस्य हों या प्रतिपक्ष के सदस्य हों । स्पीकर साहब ने सभी को बोलने का पर्याप्त समय दिया है, इसलिए शांत रह कर अन्य माननीय सदस्यों की बात को भी सुनना चाहिए । मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जिस माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दिया गया है, उसे बोलने दें । महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा में जब प्रतिपक्ष के लोग सरकार की आलोचना अपने शब्दों में कर रहे हैं, तो उसका जवाब सरकार देगी इसलिए व्यवधान न उत्पन्न करें ।

श्री सौमित्र खान **:** महोदय, बंगाल में हम 18 विरोधी पक्ष के सांसद हैं, लेकिन किसी भी दिशा की मीटिंग में हमें नहीं बुलाया जाता है । पांच साल में एक भी दिशा की मीटिंग नहीं हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? बंगाल में जो डिस्ट्रिक्ट मीटिंग होती है, उसमें विरोधी पक्ष के एमपी या एमएलए को नहीं बुलाया जाता है और यहां प्रधान मंत्री जी को कहा जाता है कि विरोधी पक्ष को बुलाओ ।

सर, ?जेसीबी? नामक तृणमूल कांग्रेस का एक लीडर कल एक महिला को पीट रहा था और बोल रहा था कि यह मुस्लिम राष्ट्र है और मुस्लिम राष्ट्र में ऐसे ही होता है, महिला को रास्ते में पीटेंगे ।? (व्यवधान) यह कैसे हो गया? क्या यह देश मुस्लिम राष्ट्र हो गया है? ? (व्यवधान)

पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में बीजेपी का काम करने के कारण एक महिला को रास्ते में नंगा घुमाया ।? (व्यवधान) क्या यह तृणमूल कांग्रेस का कल्चर है?? (व्यवधान) ये लोग आपको क्या बोलेंगे?? (व्यवधान)

कांग्रेस के लीडर्स जो-जो खड़े हैं, जो यहां पर एम.पी. चुनकर आए हैं, अधीर चौधरी को तृणमूल कांग्रेस ने क्या बोला? उन्हें इलेक्शन जीतने नहीं दिया । यहां पर गठबंधन की बात कर रहे हैं और वहां पर एन्टी काम कर रहे हैं । यह कैसा गठबंधन है? यह कैसा ?इंडिया? गठजोड़ है? ? (व्यवधान) वहां पर अधीर चौधरी को गाली दे रहे हैं और यहां पर बोल रहे हैं कि ?इंडिया? गठबंधन है । ? (व्यवधान) वहां पर कांग्रेस कर्मी की हत्या की है और यहां पर कह रहे हैं कि गठबंधन है । यह कैसा गठबंधन है? ? (व्यवधान) यह कैसे चलेगा? ? (व्यवधान)

सर, मैं यही चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में काम होना चाहिए, जैसे हमारे एरिया में बहुत सारे काम हुए । वहां विष्णुपुर-तारकेश्वर रेल लाइन का काम हुआ, लेकिन वहां दो किलोमीटर जमीन नहीं दे रहे हैं । आज बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्य भी होने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कुछ करेंगे नहीं, और करने भी नहीं देंगे ।? (व्यवधान) अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमें बोलते हैं कि हमने जीता है, हम सब कुछ करेंगे ।? (व्यवधान)

सर, आप ही बताइए, क्या तृणमूल कांग्रेस की 29 सीट्स ज्यादा हैं या 240 सीट्स ज्यादा हैं? ये लोग बोलते हैं कि हम पूरे देश के प्रधान मंत्री बन जाएंगे ।? (व्यवधान) ममता बनर्जी की इच्छा है, पश्चिम बंगाल के सी.एम. की इच्छा है कि हम देश के प्रधान मंत्री बने, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्हें संख्या नहीं मिलती है ।? (व्यवधान) इनके जितने सारे लोग हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूं, पूरे देश के लोग सुन लीजिए, अगर पश्चिम बंगाल को आप लोग ठीक तरह से नहीं देखेंगे तो एक दिन यह पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से जुड़ जाएगा, क्योंकि ?जय बांग्ला? बोल कर पूरे विरोधी पक्ष को कुचल रहे हैं ।? (व्यवधान) वहां पर इतना तुष्टीकरण हो रहा है कि यहां जो ये लोग खड़े हैं, दस सालों के बाद वे भी वहां खड़े नहीं हो पाएंगे, वहां पर मुस्लिम राष्ट्र का शासन चालू हो गया है, सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है ।? (व्यवधान)

सर, हम लोग जब पूजा करते हैं, तो आप ?जय श्रीराम? नहीं बोल पाएंगे, आप काली पूजा नहीं कर पाएंगे ।? (व्यवधान) आप सरस्वती पूजा कर नहीं पाएंगे ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** माननीय सदस्यगण, आप लोग बैठ जाइए । आपको बोलने का अवसर मिलेगा ।

? (व्यवधान)

श्री सौमित्र खान **:** सर, सबसे बड़ी बात यह है कि वहां लोग उल्टा-सीधा बोलते हैं ।? (व्यवधान) अगर पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होता है तो वहां जितने सारे डिस्ट्रिक्ट कलक्टर्स हैं, बी.डी.ओज़. हैं, सब इनसे जुड़े हुए हैं ।? (व्यवधान) संसदीय चुनाव की काउंटिंग में सभी काउंटिंग एजेंट्स को बाहर कर दिया गया और ये लोग बोलते हैं कि वहां अच्छी तरह इलेक्शंस होते हैं ।? (व्यवधान) अगर अभी वहां इलेक्शन करना है तो वहां के सारे ऑफिसर्स को बाहर करना होगा, नहीं तो ये लोग तुष्टीकरण करके सारे ऑफिसर्स को लेकर भारत से बाहर हो जाएंगे ।? (व्यवधान)

सर, मैं यही बोलूंगा कि जैसे पूरे देश में अच्छी तरह से इलेक्शंस होते हैं, यहां पर सुदीप दा हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि वहां पर आज भी घोटाला है ।? (व्यवधान) वहां पर आज भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनको बाहर करके आप लोग उनकी जमीनें ले रहे हैं ।? (व्यवधान) आप लोग वह क्यों हड़प रहे हैं, इसका उत्तर दीजिए ।? (व्यवधान)

सर, मैं यही बोलूंगा कि पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों के बाद पूरा हिन्दू धर्म खत्म हो जाएगा, वहां पर मुस्लिम राष्ट्र का गठन होगा ।? (व्यवधान) मैं बोल रहा हूं कि दस सालों के बाद पूरे बंगाल में हमारी बात को याद किया जाएगा ।? (व्यवधान)

SHRI SUNIL DATTATREY TATKARE (RAIGAD): Hon'ble Chairman Sir, 18th Lok Sabha has come into existence and Hon'ble President has delivered her Address. Today, I rise to support the President's Address on behalf of my party NCP, Maharashtra has a legacy of 700-800 years old tradition of undertaking 'Waari' to worship Pandurang and I want to wish these lacs of waarkaris.

Today I heard the speech of Shri Kalyan Banerji. Yesterday, I also heard the speech of Shri Amol Kolhe and I felt really bad. We have faced the emergency in the year 1975, imposed by Congress Party. Shri Jaiprakash Narayan Ji fought against it. Dr Babasaheb Ambedkar ji had introduced this parliamentary democracy in this country Pt. Jawaharlal Nehru became Prime Minister of this country in the year 1952, 1962 and I hold a great respect for him. But, in those days, there was no social and electronic media and print media also had many restrictions. Smt. Indira Gandhi also became Prime Minister of India thrice. But she had to face defeat due to emergency. Shri Narendra Modi ji has also become Prime Minister for third time and that is why they are unhappy. Who had toppled the Morarji Desai Government in 1977 and Chandrashekher Government in 1990? The Government should sustain for complete five years, but who had toppeled these Governments even before completing 5 years term?

Kalyanji, I want to ask you why Mamta Didi formed a new party? You formed TMC to counter the autocracy of Congress Party. So, congress party was responsible and today you are unncessarily blaming BJP. I am a founding Member of NCP. Sharad Pawar ji also had to form NCP in the year 1999 just to fight against the Congress Party. This is harsh reality and you cannot deny that.

Today, Shri A. Raja, and Smt. Kanimozhi ji talked about it I used to sit next to them during last Lok Sabha. Who was responsible to frame the charges against him in 2G scam? It was UPA Government and you were a Minister in that Government. Both of you had to suffer a lot and I was concerned about you. But today you are supporting them only. Your minds are filled with hatred against Modi Ji.

Prime Minister Narendra Modi ji has enhanced the reputation of our country during last 10 years? time. I hail from Raigad where Chhatrapati Shivaji Maharaj

established his 'Hindvi Swarajya' and Dr. Babasaheb Ambedkar started his struggle for equality.

Our Hon'ble Prime Minister has started many welfare schemes like PMAY, Jal Jeevan, Ayushman Bharat, Shetkari Sanman Yojana, Ujjwala Gas Yojana, and these schemes are not for a particular community or religion. Today you are blaming him in the name of religion but he never discriminated in the name of religion. You all are blind with hatred against him and that is why you cannot see his qualities and virtues. Our leader Sharad Pawar ji had dreamt of a lake city, so started the construction of Lavasa city, but Congress condemned him like anything. Congress leaders and Environment Minister scrapped that project. These opposition parties have ill will against Modi Ji.

We developed corona vaccine and successfully landed on moon under his Prime Ministership. In the year 1971, when we liberated Bangladesh, Atal Bihari Vajpayi ji had called the then Prime Minister of India Smt. Indira Gandhi, 'Durga'. But when we develop corona vcaccine and successfully completed the lunar operation, the opposition parties were not ready to give the credit to Shri Narendra Modi ji but to the scientists.

Today I want to make it clear that our NDA alliance is fully strong and the credit goes to our constitution. Lastly, I want to congratulate our Hon'ble President and support the Motion of thanks on the President's Address.

Within next five years, we will grow stronger and surely become the third largest economy in the world. Our Mahayuti Government in Maharashtra will strongly support this Modi Government for the overall development of India. I want to express our support to Modi ji for the national cause in public interest once again and we will build a strong nation under his leadership.

Jai hind. Jai Maharashtra.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to participate in the debate on the Motion of Thanks on the President?s Address.

While reading the President?s Address, there is one word which strikes me, and it was discussed yesterday also. The President?s Address has clearly stated ??. that the people of India have elected a stable government with a clear majority ?.?. I

thought about it as to why the President is insisting that the Government is having a clear majority. We are quite sure that the insecurity of the Government is being reflected through the President?s words of ?a secure Government.?

The Government itself is not believing the security of this Government. Technically, they are in power. We are also agreeing that technically they are in power. But what was the real pre-election situation in this country? Yesterday, our hon. LoP narrated all these things. I do not want to repeat it. The BJP got 240 seats. First of all, you said that you will get 400-plus seats but your strength has come down from 303 to 240 seats. You have got these 240 seats with the clear support of the Enforcement Directorate, CBI, and the Income Tax Department. Not only that, there was the so-called corporate-sponsored media which was showing 24x7 hate, hate, and hate. Of course, there was misuse of election machinery. If that would not have helped you, you would have only got a maximum of 140 seats. That was the real picture of this country.

माननीय सभापति **:** प्रो. सौगत राय जी, कृपया इधर पीठ करके मत खड़े होइए ।

? (व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL : Sir, the Enforcement Directorate has become a tool of the BJP. Already, the BJP is being quoted as a washing machine to clean up the corrupt people. They have talked in a very big manner about other scams. Where are those people who have done these scams? They talked about the biggest irrigation scam. Where is the person who has done this irrigation scam? The washing machine has cleaned out all these people. It is okay. It is well and good. Despite all these facts, without the ED, without the Income Tax Department, without any media help, the I.N.D.I.A alliance got 237 seats. That is the moral victory. Morally, we have won. Morally, you have lost the election. This is my first point.

Our hon. Prime Minister said something while Rahul ji decided to contest from the Raebareli seat. Modiji said in a public meeting in Kerala that Rahul Gandhi is going to lose in Wayanad. That is why he is going to Raebareli now. Rahul Gandhi won both Wayanad and Raebareli seats with about four lakh votes, which is more than double the Prime Minister?s win margin. He also said that after Amethi, he will lose Wayanad. I do not want to say what happened to Amethi. You people know who left Amethi now. Everybody said that. Kishori Lal is here. For 40 years, he was in Congress as a common *karyakarta*. You said that Congress fielded Gandhi family?s *sipahi* in Amethi. This is the BJP?s narrative but people of Amethi chose Kishori Lal

with more than 1,67,000 votes, which is more than Narendra Modiji?s win margin from Varanasi seat. This is the situation.

Sir, I am quoting an Article from our Constitution. Article 123(3A) says:

?The promotion of, or attempt to promote, feelings of enmity or hatred between different classes of the citizens of India on grounds of religion, race, caste, community, or language, by a candidate or his agent or any other person with the consent of a candidate or his election agent for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate.?

This provision is there for corrupt practices in the Model Code of Conduct. Now, I am coming to what the Prime Minister said in April. The Prime Minister, while addressing a public meeting in Banswara, Rajasthan on 21st April said: ?They want to snatch the gold of the women and distribute it among the people. They will not spare even your *mangalsutra*. They will take your money and give it to those who have more children, to the illegal immigrants. They will distribute them to the Muslims who, they said, have the first right to the resources.?

?? They will go to the extent where they will not spare even your Mangalsutra ??.

This is the speech delivered by our hon. Prime Minister in Banswara. ? (*Interruptions*) The fact is that he spoke in Banswara. Who is the Member from Banswara now? An INDIA alliance Member has won with a margin of 2,67,000 votes in Banswara. The Prime Minister spoke to the people of Banswara, and the people of Banswara totally rejected his claim.

The Prime Minister again was asking people on having children. I do not know whether the Prime Minister checked how many children his Ministers have. ? (*Interruptions*) The Prime Minister should at least check how many children his Ministers and MPs have. ? (*Interruptions*) It is because he only told this to the country. ? (*Interruptions*)

Thereafter, in Gujarat on 1 May, the Prime Minister told the voters of Banaskantha that if you have two buffaloes, the Congress will take away one if it wins the Lok Sabha elections and you will be able to leave only one buffalo for your child. Surprisingly and fortunately, in Gujarat, his own State, the Banaskantha people also rejected BJP. We won that seat.

Yesterday, we already narrated about the Ayodhya results. ? (*Interruptions*) This is what I am telling. ? (*Interruptions*) This is actually anti-Constitutional. ? (*Interruptions*) I quoted the Constitutional provision. ? (*Interruptions*) This is actually against the Constitution. ? (*Interruptions*) The Prime Minister as a candidate and political leader violated the entire Constitutional norms. ? (*Interruptions*)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Mr. Venugopal, kindly allow me to say something. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please wait.

? (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL : No, Sir, I am not yielding. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please allow him. The Parliamentary Affairs Minister wants to say something. I am allowing him to speak.

? (*Interruptions*)

SHRI KIREN RIJIJU: Venu ji, this is just a courtesy. We give time to each other. I am saying that we are patiently listening to your speech and we must listen. You are a senior Member and we are patiently listening to your words.

My only observation is this. मैं हिन्दी में बोलना चाहूंगा । मुझे ऐसा लगता है अगर किसी को नहीं पता कि इस चुनाव में किसको कितना सीट मिला है । वेणुगोपाल जी का भाषण सुनेंगे तो ऐसे लगेगा कि यह उस पार्टी से हैं जिसको 240 मिला है और हम 98 सीट पर बैठे हैं । गुजरात में हम 25 सीट जीते हैं, वह एक सीट के बारे में बोल रहे हैं । जहां-जहां जीते हैं उसी के बारे में बोल रहे हैं ।

SHRI K. C. VENUGOPAL : Sir, I brought to the notice of this august House a serious matter. Our Prime Minister has clearly violated the entire Constitutional norms while speaking. How can a Prime Minister talk like this?

We have given hundreds of petitions to the Election Commission. ? (*Interruptions*) They have become silent spectator. The ... is also acting like a frontal organization. ? (*Interruptions*)

Yesterday, Rahul ji mentioned about Hinduism. Thereafter, every BJP leader was very much busy having Press Conference of Chief Ministers, Press Conference of leaders and so on. You are very much talking about Hinduism. Are you a real believer or we, the people, are the real believer? I am going to challenge you

people. You are not a Hindu believer at all. You are using Hinduism for polarizing the people to win the election. ? (*Interruptions*) I am coming to the point. As regards Lord Jagannatha, yesterday only the hon. LoP told about the non-biological birth of our Prime Minister. Of course, he is not biologically born like us. ? (*Interruptions*) Mr. Sambit Patra on 20-5-2024 said that Lord Jagannath is Modi bhakht. ? (*Interruptions*) On 22-6-2024, J. P. Nadda ji said that : ?Now, even God is not supporting Congress. Narendra Modi is now Surendra Modi. He is the lord of Gods?.

He is the lord of Gods. Thirdly, ?Shri Narendra Modi is an ?*ansh*? of Lord Rama and Lord Vishnu who take care of us?, said Kangana Ranaut ji. ?Bajrang Bali is a Dalit, forest dweller, hill dweller and deprived?, said Yogi Adityanath ji. ? (*Interruptions*) Ravan was an intellectual. ? (*Interruptions*) In your Cabinet, there is a Minister who said, ?Ravan was an intellectual. Rama is an imaginary character. I do not consider Ramayana to be a true story. I accept the fact that Lord Rama was a great historical person?. Shri Jitan Ram Manjhi, who is the Cabinet Minister, said this. ? (*Interruptions*)

You are a Hindu and we are anti-Hindu. What is a real Hindu? The fundamental question before us is not that who is a Hindu or who is not, but who is a real Hindu who understands the message of debate, tolerance and human values.

Both Mahatma Gandhi and Godse believed in Bhagavad Gita. Both of them read Bhagavad Gita but Gandhi learned non-violence, tolerance and respect for human life and the message of Lord Krishna. Godse learned violence, murder, and intolerance from the same text. We, the Congress Party, and INDIA Alliance believe in Gandhi?s Hinduism, not Godse?s Hinduism. We follow Gandhi?s Hinduism. We do not follow Godse?s Hinduism. Ram Manohar Lohia also said about Hinduism. Pandit ji said about Hinduism.

I am a Hindu, brother. I used to go to Guruvayur Temple every month. I visit Sabarimala every year. I visited Ajmer Mosque also. I went to Golden Temple along with my leader, Shri Rahul Gandhi. We did *Seva*. We saw the situation there. ? (*Interruptions*) Sister, please listen. Brother, you really think that Modi is bigger than God. You projected it as if the Prime Minister is bigger than God. That is the biggest anti-Hindu statement. That is the biggest non-believer statement. Nobody is bigger than God as per Hindu tradition. You projected Modi as bigger than God. That is why, God punished you in this election.

Yesterday, the hon. Home Minister showed this Rule Book to us. We also respect the Rule Book and the Directions by the Speaker. But the Rule Book has to be applicable to all the hon. Members of this House. The hon. Speaker expunged the speech of the hon. Leader of the Opposition but he did not touch the speech of Shri Anurag Thakur. How many allegations did Anurag ji make yesterday? ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: If you feel he uttered some unparliamentary words, there is a rule that says that you can give in writing and the hon. Speaker will look into it.

SHRI K.C. VENUGOPAL : There are two businessmen. If their names are taken by anybody in this House, the entire Opposition will jump. They are the names of two big businessmen.

That has been expunged yesterday. I am only talking about two people. ? (*Interruptions*) Sir, Anurag Thakur ji ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Parliamentary Affairs Minister.

? (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, I am coming to my point. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I am taking the name of the Parliamentary Affairs Minister.

SHRI KIREN RIJIJU: Venu Ji, you have raised a question about deletion of a portion of speech from the proceedings. There is a rule and we all know. ? (*Interruptions*) विपक्ष की ओर से अगर हमारे किसी सदस्य ने बोलते समय किसी रूल का उल्लंघन किया है, तो आप नोटिस दे सकते हैं । आप यहां अपनी बात बोलेंगे और रूल से संबंधित जो कदम उठाना चाहिए, वह आप नहीं उठाएंगे, तो गलत संदेश जाएगा और ऐसा लगेगा कि चेयर से स्पीकर साहब और चेयरमैन मनमर्जी कर रहे हैं, जबकि हमारे यहां से रूल 115 के अंतर्गत नोटिस दिया गया । उसके बाद स्पीकर साहब को जो कार्रवाई करनी थी, वह उन्होंने की । मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं । मैं एक बौद्ध हूं । अलग-अलग धर्मों के लोग यहां पर रहते हैं । हमें एक-दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए । ? (व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष और सारी कांग्रेस पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि बार-बार हिंदुओं का मजाक उड़ाकर आपको क्या फायदा मिलेगा? ? (व्यवधान) हर भाषण में आप हिंदुओं का मजाक क्यों उड़ाते हैं? ? (व्यवधान) यह ठीक बात नहीं है । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** के सी वेणुगोपाल जी और गौरव जी, पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर ने अभी कुछ कहा, but I will advise to Shri Venugopal Ji, if you cast any aspersions on the Chair, it will be expunged.

Shri Venugopal Ji.

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, Shri Anurag Thakur yesterday told about corruption.

HON. CHAIRPERSON: If you want to criticize the Government, you can do that.

? (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL: I am talking about certain incidents like Delhi airport roof collapse, Jabalpur airport roof collapse, canopy collapse in Rajkot airport, bad conditions of Ayodhya roads, leakage in Ram Mandir temple, cracks in Mumbai Trans Harbour link bridge, three new bridges falling down in Bihar in 2023 and 2024 and submerging of Pragati Maidan tunnel. All these constructions that happened during the NDA period have collapsed. Under their rule, every building is under threat of collapse. ? (*Interruptions*)

I have already told about the electoral bonds system. Do you dare to enquire about the electoral bond system? I am challenging the hon. Prime Minister. ? (*Interruptions*) I am talking about corruption. ? (*Interruptions*) How much money have you made? ? (*Interruptions*) What is the practice, Sir? ? (*Interruptions*) Whoever people who are not donating funds to the BJP, the IT will come suddenly, IT will raid. ? (*Interruptions*) ED will come and ED will investigate. Then, automatically, electoral bonds will come to the BJP Party. ? (*Interruptions*) Then nothing is there. One of the biggest scams the country has ever seen was the electoral bond scam. ? (*Interruptions*) If you are not scared of anything, why do you not set up an inquiry? You set up an inquiry led by a Parliamentary Committee. You are not ready. Actually, that is one of the biggest scams happened during their period.

Sir, the hon. President talked about the bullet train for comfortable journey, but we need safety bullet trains also. How many train accidents happened this year? As per the Crime Records Bureau statistics - I am only quoting those statistics - about 2.6 lakh people have lost their lives in train accidents in the last 10 years.

13.00 hrs

The same Railway Minister was in charge for the last five years ? (*Interruptions*) The figure is 2.6 lakhs.

HON. CHAIRPERSON: No.

? (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL: This is as per the National Crime Records Bureau ? (*Interruptions*)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) **:** सर, ये झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं । ? (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL: You can verify. I am quoting this. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I think, Shri K.C. Venugopal ji, you must correct yourself. The figure of 2.6 lakhs is definitely not true.

? (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, I will authenticate it. ? (*Interruptions*)

माननीय सभापति **:** उन्होंने कहा है कि मैं इसको ऑथेंटिकेट करूंगा ।

? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर **:** सर, मेरा नाम पहले लिया गया, इसलिए जवाब देने का मेरा हक बनता है । ? (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, I am not yielding. ? (*Interruptions*)

माननीय सभापति **:** उन्होंने खड़े होकर कहा कि आपने उनका नाम लिया था, इसलिए वे कुछ कहना चाहते हैं ।

? (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, how many train accidents happened in the last 10 years? ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You have mentioned his name. That is why he is asking.

? (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, what action has been taken by this Government to control train accidents?

HON. CHAIRPERSON: The Government will reply. Certainly, you can raise it.

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, that is what I am asking. I am not asking you; I am asking the Government only. ? (*Interruptions*) How many train accidents happened?

There is no train safety at all. Passenger safety is a low priority for this Government. ? (*Interruptions*)

माननीय सभापति**:** अनुराग जी, इनकी स्पीच के बाद मैं आपको बोलने का मौका दे दूंगा । आप बैठ जाइए । You will get an opportunity after his speech. Let him finish.

? (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, the President?s Address mentioned about the feasibility studies on bullet trains in the country. First of all, we need bullet-proof safety for these trains. At least, you should ensure that before going for any bigger plan.

The unemployment situation in this country was debated here. First of all, in 2014 Modi ji promised two crore jobs per year. Already, 10 years are over. How many jobs have you provided? Due to demonetisation and bad GST, a number of people lost their existing jobs. That was the result. That is why the entire youth was against you in this election. Therefore, unemployment situation in the country is very much alarming. It was 8.1 per cent in April 2024 whereas it was 7.4 per cent in March 2024.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude. You have taken more than 20 minutes.

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, I will just conclude. I am coming to another alarming issue. ? (*Interruptions*) Our fishermen are in a great distress. Like our *adivasis* in forests, fishermen are there in the entire sea coast. Due to CRZ norms, our poor fishermen are not in a position to construct dwelling houses and they are not in a position to do their fishing activities. Several Members of Parliament raised this issue so many times but so far nothing has happened. The poor fishermen at least need some justice from this Government. There is a need to have a substantial change in the CRZ norms enabling fishermen to construct their homes.

Finally, the Government is not interested to talk about Manipur. They think that Manipur is not a part of our country. It is one of the best States of our country, one of the beautiful States of our country with cultural heritage. Very interesting and intelligent people are living in that State. But everybody knows what has happed in Manipur. That entire episode of Manipur is a result of this Government?s activities.

I am concluding my speech by quoting Father of the Nation, Mahatma Gandhi. And I must also say that the world listened to him even before the Gandhi film. This is the biggest surprise for me. When I was a child, studying in first standard, I heard

about Mahatma Gandhi. Every Indian, and even people living in abroad also, heard about Mahatma Gandhi. Our Prime Minister is telling that they know about Mahatma Gandhi only after Gandhi film.

I am quoting Mahatma Gandhi:

?No perfect democracy is possible without a perfect non-violence at the back of it.?

We believe in Gandhi?s philosophy of non-violence. Yesterday also, you ransacked the Ahmedabad Party Office -- PCC Office. It was attacked by BJP. Yesterday, Rahul ji told the same thing that please believe in Gandhi ji?s philosophy of non-violence. Thank you very much, Sir.

I am concluding.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर **:** सभापति जी, महात्मा गांधी जी के नाम पर कोई इतना झूठ बोलकर चला जाए, इनकी ऐसी हालत हो गई है ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आप केवल अपने आपको कन्फाइंड रखिए । उन्होंने आपका नाम लिया था और आपसे कहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं । आप उस पर अपना जवाब दीजिए । आपकी स्पीच नहीं होनी है । आप उसका जवाब दे दें, क्योंकि आपका नाम लिया गया था और आपसे कहा गया था कि आप झूठ बोल रहे हैं ।

? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Tagore, he has mentioned his name. That is why, I have allowed him to speak. Mr. Hooda, I have given permission to him to speak.

? (*Interruptions*)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर **:** माननीय सभापति जी, मेरे खड़े होने से इनको इतना दर्द क्यों होता है? क्या मेरा एक सदस्य होने के नाते इतना हक भी नहीं है कि ये मेरा नाम लें और मुझ पर आरोप लगाएं?

माननीय सभापति जी, मेरा इतना ही कहना है कि कल अगर मेरी पार्टी और मेरे प्रधानमंत्री जी ने अपना और अपनी पार्टी का पक्ष रखने का अवसर मुझे दिया था, तो अगर उसमें एक भी बात असत्य हो, जैसा कि मैंने कहा कि आपने इमरजेंसी लगाई थी, लोकतंत्र का चीरहरण आपने किया था । ?(व्यवधान) अगर आपको लगता है कि झूठ है, तो आप इस पर बोलिए । मैंने कहा था ।?(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Okay. Thank you.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Dilip Saikia ji.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Mr. K. C. Venugopal, especially, he has mentioned that in his speech, Shri Anurag Singh Thakur told a lie. That is why, I gave an opportunity to him to explain.

? (*Interruptions*)

श्री दिलीप शइकीया **(**दारंग-उदालगुड़ी**) :** सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रही है, मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । इसके साथ ही मेरा संसदीय क्षेत्र दारंग-उदालगुड़ी है, वहां के जितने भी वोटर्स हैं, मैं आज इस सदन के माध्यम से उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं ।

सभापति महोदय, कल सुबह से मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के धन्यवाद प्रस्ताव पर सभी आदरणीय सांसदों का वक्तव्य सुन रहा हूं । विशेषकर एलओपी राहुल गांधी जी का वक्तव्य सुना, आज सुबह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का वक्तव्य सुना और अभी मैं वेणुगोपाल जी को सुन रहा था । ये लोग आरोप लगाते हैं कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार संविधान को खतरे में डाल रही है । देश की कानून-व्यवस्था को खत्म कर रही है । मैं उनको यह याद दिलाना चाहता हूं और सबसे पहले तो राहुल गांधी जी से विनम्रतापूर्वक एक निवेदन करना चाहता हूं कि 140 करोड़ भारतवासियों से तीन कारणों के लिए उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए ।

पहला कारण है, कल उन्होंने अपने उद्बोधन में जो विषय उठाया है, उन्होंने प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति को अपमानित किया है । हिन्दुत्व, हिन्दू और सनातन की एक प्रकार से उन्होंने आलोचना की है । यह हिन्दू है तो भारतवर्ष धर्मनिरपेक्ष है । हिन्दू की मेजोरिटी है तो भारतवर्ष आज इस गणतंत्र के मूल विचार को आगे बढ़ाकर ले जा रहा है । राहुल गांधी जी न हिन्दू हैं, न किसी अन्य धर्म के हैं । देश की जनता उनसे सवाल करती है कि उनका मूल क्या है? वे भूल जाते हैं कि यह सनातन संस्कृति, जो कि भारत की विरासत है, यही विश्व में हमारी पहचान है ।

दूसरा कारण है, जिसके लिए राहुल गांधी जी से मैं माफी मांगने की डिमांड करता हूं । 25 जून, 1975 को राहुल गांधी जी की दादी और तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी ने देश भर में संविधान को कुचलने का काम किया था । गणतंत्र को खत्म करने का काम किया था । लेकिन, ये लोग हिस्ट्री का अध्ययन नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो भी उसको छुपाने की कोशिश करते हैं । लेकिन, देश की जनता उसको भूली नहीं है । 25 जून, 1975 का दिन जनता नहीं भूली है । इसी के कारण से राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए कि वर्ष 1975 में उन्होंने जो किया था, वह गलत किया था । संविधान को खत्म करने का काम किया था । आज हमें हंसी आती है । हमारे देश के लोग आज शिक्षित हैं, जागरुक हैं । हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग दांत होते हैं । ये लोग संविधान को दिखाते हैं । मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपको 25 जून, 1975 का 392 नंबर ऑर्डिनेंस लेकर के घूमें, देश को दिखाएं, जनता को दिखाएं कि हमने 25 जून, 1975 को गणतंत्र और संविधान के साथ क्या किया था?

तीसरा, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही गणतंत्र नहीं है । जब सरदार पटेल जी को कांग्रेस स्टेट कमेटी ने प्रधान मंत्री बनाने पर मुहर लगायी थी, तब सरदार पटेल जी को मेजोरिटी और समर्थन होने के बाद भी सरदार पटेल को छोड़कर नेहरू जी को प्रधान मंत्री बनाया गया था । उसके लिए भी राहुल गांधी को सदन और देश से माफी मांगनी चाहिए ।

सभापति महोदय, ये सनातन विरोधी, हिन्दू विरोधी, आरएसएस विरोधी, बीजेपी विरोधी और हिन्दुस्तान का विरोध करने की इनकी एक आदत बन गया है । ये नहीं चाहते हैं कि हिन्दुस्तान तरक्की करे । ये नहीं चाहते हैं कि हिन्दुस्तान विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बने । ये नहीं चाहते हैं कि हिन्दुस्तान विकसित राष्ट्र बने । ये नहीं चाहते हैं । इनको हजम नहीं होता है । पाकिस्तान में लोग जैसी भाषा बोलते हैं, वैसी ही इनकी भाषा होती है ।

सभापति महोदय, आज मैं बहुत दुख के साथ यहां पर खड़ा हूँ । चुनाव में हार-जीत होती रहती है । हम 400 पार नहीं हुए, उसके लिए हम लोग जितने दुखी है, उससे ज्यादा हमें लगता है कि ये लोग दुखी हैं । हम 400 पार नहीं हुए तो ये लोग ज्यादा दुखी हो गए । पिछले तीन चुनावों में वर्ष 2009, वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में कांग्रेस को कुल जितनी सीटें मिली थीं, उसकी तुलना में भाजपा को अकेले आज 240 सीटें मिली हैं । अगर तीनों चुनावों का योग किया जाए तो उसमें भी कांग्रेस कम होती दिखाई देती है ।

कांग्रेस वाले और कांग्रेस के सपोर्ट में इंडिया अलायंस के जो लोग बैठे हुए हैं, वे नरेन्द्र मोदी जी को एक अंगुली दिखाते हैं, प्रधान मंत्री जी को अंगुली दिखाते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि बाकी की चार अंगुलियां उनको दिखाती हैं । अगर भ्रष्टाचार की कोई जननी है तो वह कांग्रेस पार्टी है । भ्रष्टाचार को इस देश में कांग्रेस पार्टी ने पनपने दिया है । सन् 1959 में इस देश में सरकारी भ्रष्टाचार की शुरुआत पंडित नेहरू जी के कार्यकाल में जीप क्राइसलर स्केम के साथ हुई । उस समय इस देश में सरकारी भ्रष्टाचार का सिलसिला शुरू हुआ । इस पर कांग्रेस जवाब दीजिए । उसके बाद सदन के सभी मेरे साथी जानते हैं कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक सिक्के के दो पहलू हैं । कांग्रेस का हाथ हमेशा दलालों के साथ रहता है । हमेशा कमीशनखोरों के साथ रहता है ।

माननीय सभापति **:** कृपया समाप्त कीजिए ।

श्री दिलीप शइकीया **:** सभापति महोदय, मैं दूसरी बार चुनकर आया हूँ । मुझे थोड़ा और समय दीजिए ।? (व्यवधान) इस चुनाव में आपका 240 का आँकड़ा नहीं पहुंचा है तो आप इतनी तेज आवाज में मत बोलिए ।

माननीय सभापति **:** दिलीप शइकीया जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए । आप उनकी तरफ मत बोलिए ।

? (व्यवधान)

श्री दिलीप शइकीया **:** सर, मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ । आज ये मणिपुर का विषय उठाते हैं । यह बहुत अच्छी बात है । ये मणिपुर के साथ इतनी सॉलिडेरिटी दिखाते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट को इनके जमाने में सब कुछ मिल गया था । नॉर्थ ईस्ट को उस समय कुछ नहीं मिला था । अगर नॉर्थ ईस्ट को 55 सालों में किसी पार्टी ने स्टेप मदर्ली एटिट्यूड दिखाया है तो वह कांग्रेस पार्टी है ।

माननीय सभापति **:** माननीय सदस्य, अब आप कृपया अपने भाषण को समाप्त कीजिए ।

? (व्यवधान)

श्री दिलीप शइकीया **:** सभापति महोदय, मुझे दो मिनट और दीजिए । ?My heart goes out to the people of Assam.? किसने बोला था? राहुल गांधी जी के दादाजी ने बोला था । इस सदन में नहीं

आकाशवाणी पर बोला था ।? (व्यवधान) आज मणिपुर की हिंसा के लिए, मणिपुर की परिस्थिति को संभालने के लिए हम लोग हैं । हम लोग संभाल रहे हैं, लेकिन सन् 1979 से 1985 तक जब इमिग्रेशन एक्सपल्शन के लिए विदेशियों के बहिष्कार का आंदोलन असम में हुआ था तो 855 असम के जवानों को मारने का काम किसने किया था? यही कांग्रेस पार्टी, यही गौरव गोगोई जी यहां बैठे हुए हैं । ?(व्यवधान)

माननीय सभापति **:** अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

? (व्यवधान)

श्री दिलीप शइकीया **:** सभापति महोदय, आप मुझे बोलने के लिए दो मिनट समय दे दीजिए । ?(व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आप अपनी बात समाप्त कीजिए । आपके बोलने का समय पूरा हो गया है ।

?(व्यवधान)

श्री दिलीप शइकीया **:** सभापति महोदय, हम नॉर्थ -ईस्ट से हैं ।?(व्यवधान) आज नॉर्थ-ईस्ट को कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने किया है । रेल नेटवर्क, एयर नेटवर्क, रोड नेटवर्क और इंटरनेट से अगर किसी ने नॉर्थ-ईस्ट को जोड़ा है, तो नरेन्द्र मोदी जी ने जोड़ा है ।?(व्यवधान) नरेन्द्र मोदी जी ने काफी पुण्य का भी काम किया है । नरेन्द्र मोदी जी देश के गरीब लोगों को अन्न दान किया है, देश के गरीब लोगों को जल दान किया है, देश के गरीब लोगों को घर दान किया है । नरेन्द्र मोदी जी ने एक और अच्छा काम किया है । ?(व्यवधान) नॉर्थ-ईस्ट में काँग्रेस का सफाया किया है । यह भी अच्छा काम किया है ।

मैं फिर से सभापति महोदय, राहुल गांधी जी का वह स्टेटमेंट, अखिलेश यादव, अभी फैजाबाद के माननीय एमपी साहब बैठे हुए हैं ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आप अपनी बात कहिए ।

?(व्यवधान)

श्री दिलीप शइकीया **:** मैं अपनी बात कह रहा हूं । अखिलेश यादव जी, आपके पिता जी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने निहत्थे कारसेवकों के ऊपर गोली चलवायी थी ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आप इस तरह से नाम न लें ।

? (व्यवधान)

श्री दिलीप शइकीया **:** वह भी हिन्दू समाज कभी नहीं भूलेगा ।?(व्यवधान) मैं कोठारी भक्तों का स्मरण करता हूं ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आप कृपया अपनी बात समाप्त करें ।

श्रीमती हरसिमरत कौर ।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिण्डा) **:** सर, शुक्रिया । इस हाउस में खड़े होकर मेरे जैसे जो ना पक्ष के साथ हैं और ना विपक्ष के साथ हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये ?चार सौ पार? का नारा देकर, ईडी और सीबीआई यूज करने के बाद भी 330 से 240 पर आ गए हैं, तब भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं । ये 50 से 99 पर चले गए हैं, ये अपना पीठ थपथपा रहे हैं । इन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है? हां, हम जहां खड़े थे, वहीं खड़े हैं ।?(व्यवधान)

सर, इस बार जो राजनीति हुई है, शायद देश ने ऐसी राजनीति कभी नहीं देखी है । यहां से वहां जितनी माइग्रेशन हुई है, दल बदल दो, हलका बदल दो, पार्टी बदल दो, कुछ पता नहीं लग रहा है । जो कल यहां पर बैठे थे, आज वहां पर बैठै हैं । हमारे राज्य में रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों इकट्ठी हो गईं, तो अब अपोजिशन कहां? कल राहुल जी कह रहे थे कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, तो यहां पर कंफर्म कर दीजिए कि आप आम आदमी के भी अपोजिशन के लीडर हैं, क्योंकि पंजाब में कुछ बोलते हैं और बाकी देश में कुछ और बोलते हैं ।

सर, जहां तक इनकी बात है, तो मैं इनके बारे में क्या कहूं । मैं इन पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगी । क्योंकि समय कम होता है और बोलने के लिए बहुत कुछ है । मैं अपने राज्य के मुद्दों पर आना चाहूंगी । आज मैं आपके माध्यम से राष्ट्रपति जी से आग्रह करती हूं कि सरकार को बोलिए कि पंजाब एक किसानी सूबा है ।

Farmers of Punjab have faced a lot of difficulties. Take the farmers, the youth and the minorities. All of them have rejected this Government. That is why, their tally of MPs in the Lok Sabha has come down drastically. Sir, 700 protesting farmers became martyrs due to ill treatment of this Government. Before the U.P. elections, the Government had assured that legal guarantee of MSP for foodgrains will be given. However, the demands of the protesting farmers were not accepted. In 2024, when the farmers of Punjab wanted to come to Delhi to protest, the Haryana Government and the police unleashed persecution and brutal force on these farmers at the Punjab-Haryana border. Tear gas shells were lobbed at them and bullets were fired at them. Lots of farmers were injured and their tractors were destroyed. A young man, Shubhmeet from my constituency, became a martyr because of police brutality.

I urge upon the Government to sort out the issues pertaining to the farmers. The Government calls them separatists and terrorists but unleashes terror by the police on them. This must stop. The promises made by the Government to the farmers must be fulfilled.

I also request the Government to open the Attari-Wagah border and Hussainiwala border so that trade with Pakistan through these borders could resume. It will help our farmers, unemployed youth and also our industries. If trade with Pakistan can be allowed through Gujarat?s sea-routes, then why can it not be allowed through the land border routes of Punjab? I demand that these industrial and trade routes

with our neighbour should be opened so that bilateral trade can take place through these routes.

While the farmers are at the receiving end in Punjab, our youth is facing another kind of danger, the danger posed by the epidemic of drugs. Drugs have become rampant in Punjab. The Congress Party had sworn upon a religious book that they will uproot the drug menace in four weeks. The AAP, on the other hand, promised to eradicate this menace in 10 days. However, they proved to be empty promises. Daily, young men and women of Punjab are dying due to the drug menace. Even policemen have fallen prey to the scourge of drugs. Conditions have gone from bad to worse.

The Chief Minister of Punjab has handed over half of Punjab to BSF. However, hundreds of drones are crossing the international border into Punjab in the night time with consignments of drugs and arms and ammunitions. This is ruining Punjab. I ask the Government as to what steps they are taking to stop this menace. For every one drone that is intercepted, five drones go undetected and dump their cargo in Punjab. Gangsters and drug-peddlers are ruling the roost in Punjab. There is no one to check this menace. People are suffering. So, our youths are migrating to foreign countries in search of a better life.

I urge upon the Central Government to grant an industrial package to Punjab. During the Vajpayee era, Badal ji had got the Bathinda refinery for Punjab. Especially, in border areas, industries are in shambles. Our neighbouring States like Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir are getting incentives on industries. As a result, the industries of Punjab are migrating to these neighbouring States in search of greener pastures. If a border State like Punjab develops and remains peaceful, only then can the country develop and remain peaceful.

I also urge upon the Central Government to respect the religions of minorities. The Government must not interfere in the religious affairs of minorities and Sikhs. Rahul Gandhi ji claims that he went to the Golden Temple to pay obeisance. The ruling party claims that they have celebrated 550 years of a religious event of Sikhs. When you want to pat your backs, then you talk about Sikhs. But, what is happening to the Sikhs? The Congress Party used tanks and soldiers to desecrate and destroy our holiest shrine and indulged in genocide of Sikhs in the country. But, what is the present Central Government doing? They are trying to occupy our religious bodies and shrines. The Haryana SGPC was disbanded and it was taken over by the Central Government. The same thing happened in Delhi SGPC. Even in

Nanded Sahib, the Government officials captured our religious Board. And then you talk about celebrating 550 years of a religious event.

In 2019, while celebrating 550 years of Guru Nanak Dev ji?s birth, you had promised that our imprisoned Sikh youths languishing in jails will be released. Over four years have passed. But you did not release them. First, the Government issued a notification. Then the Government said in the court that they are a threat to society. Now, as per new rules, they are supposed to apologize. Why are all these rules framed only for Sikhs? When our ?Amritdhari? Sikhs go to Rajasthan to appear in an exam, your stooges do not allow them to appear in exams because they are ? Amritdharis?. You ask us to remove all symbols of Sikhism. This is a direct attack on our religion.

A Member of Parliament of Punjab whom people have made victorious from Khadoor Sahib is not being allowed to take oath. This is injustice against Sikhs. The mandate of people must be respected by each Government. Conditions have come to such a pass in Punjab that the radical forces are gaining ground and the moderate forces are becoming weakened. This should come as a matter of great concern for the Central Government.

Sir, the Congress, BJP and AAP, all three of them, want to snatch away the river-water of Punjab. The river-water of Punjab belongs to only Punjab. At first, one side gave away our river-water to other neighbouring States. Now, the current dispensation at the Centre is doing the same thing.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Shiromani Akali Dal has always fought against this injustice whether it is perpetrated by the Congress or the BJP or the AAP. We will not allow you all to plunder even one drop of Punjab?s water and give it to the neighbouring States on a platter.

In the end, let me say that Chandigarh is the rightful capital of Punjab. The Congress Governments never gave it to Punjab. Now, the present Central Government is also diluting Punjab?s claim on Chandigarh. Let me say with full force that Chandigarh is the capital of Punjab. We will not give up our claim on it.

Please give back our capital city to us. Stop plundering our river-water. Our farmers must be meted out justice. You must apply balm to the bruised hearts of Punjab. Then, the Punjabis will be at the vanguard in protecting the freedom and integrity

of the country. If you isolate us and persecute the minorities, it will not be in the interest of the country.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Let me remind all that when the Congress Party had imposed Emergency. The first protest march was led by late Sardar Parkash Singh Badalji. He courted arrest along with others. Everyday a group of Sikhs started from Akal Takht Sahib and courted arrest as a protest against Emergency. 40,000 Sikhs and Akalis had courted arrest in this movement. I hoped that the hon. President would mention the contribution of two per cent Sikh population against Emergency. However, it was not done.

Now, a backdoor Emergency is being imposed by using UAPA and NSA. The new laws have given sweeping powers to the police. This too is a sort of Emergency.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Akali Dal will continue to fight against all kinds of injustices.

माननीय सभापति **:** सभी माननीय सदस्यों के लिए एक सूचना है कि जो माननीय सदस्य अपना लिखित भाषण देना चाहते हैं, वे सदन के पटल पर अपना लिखित भाषण रख सकते हैं । धन्यवाद ।

श्री अजय भट्ट जी ।

श्री अजय भट्ट **(**नैनीताल**-**ऊधमसिंह नगर**) :** माननीय सभापति जी, श्री अनुराग ठाकुर जी ने जो माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उस पर आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ ।

मैं अध्यक्ष महोदय को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उनका दूसरा कार्यकाल बेहतर होगा । यह पिछले कार्यकाल से भी बेहतर होने वाला है । उनकी छत्रछाया में पक्ष-विपक्ष और देश-दुनिया की, प्रगति की बातों को अच्छी तरह से पहले भी ले गये हैं और हम आगे भी ले जाने वाले हैं ।

मैं भारत की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार देश को दी है ।

मैं उत्तराखण्ड की जनता एवं नैनीताल-ऊधमसिंह नगर की जनता का भी विशेष आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे दूसरी बार इस सदन में सेवा करने के लिए भेजा है ।

मान्यवर, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होता है । विपक्ष का काम आई-ओपनर का होता है । जो सत्ता में होता है, अगर कहीं कोई ऐसी बात होती है, तो हम लोग उसमें संशोधन करते हैं । कभी कोई यहाँ बैठता है, कभी कोई

वहाँ बैठता है । लेकिन अगर एक टायर भी पंचर हो जाता है, तो लोकतंत्र की गाड़ी डगमगाती है । पहले क्या जमाने होते थे हँसी-ठिठोली के । हमने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने को भी देखा है, सुषमा स्वराज जी को भी सुना है । वर्ष 1971 में अटल जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ो, देश रहेगा तब हम लोग रहेंगे । चुनाव तो 10-15 दिनों में हो जाएगा, लेकिन मर्यादा में रहते हुए, लोकतंत्र की परिधि में हम एक-दूसरे के ऊपर जो भी छींटाकशी करेंगे, वह कर लेंगे । लेकिन आज यहाँ तो हद हो गई है । पत्नी भी विपक्ष में हो सकती है और पति दूसरे दल में हो सकता है । भाई-भाई दूसरे दलों में हो सकते हैं । बेटा और पिता भी अलग-अलग दलों में होते हैं । लेकिन मर्यादाएं कभी नहीं टूटती हैं । मर्यादा अपनी जगह पर रहती है । यहाँ मैं देख रहा हूँ कि नेता प्रतिपक्ष, आज नहीं, मुझे भी देखते हुए पाँच वर्ष हुए हैं कि मर्यादा तहस-नहस हो रही है ।

अरे, हम उस के हैं, जहां राम हैं, शिव हैं । अपनी मर्यादाओं के लिए राम जी वनवास चले गए, पिता की आज्ञा मानी । यहां तो बात ही नहीं होती । हम किस तरह से बोलते हैं? मैं एक वीडियो देख रहा था ? यह नरेन्द्र मोदी, अब देखेगा, नहीं जीतेगा । क्या है भाई? पिता के तुल्य होंगे, भाई के तुल्य होंगे, बड़े भाई के तुल्य होंगे । क्या यह कोई बोलने का तरीका है?

आप सरकार के खिलाफ खूब बोलिए । इसकी हर एक को छूट है, लेकिन आपकी मर्यादा, लैंग्वेज ठीक हो । आप कल ही देखिए, कितना अच्छा चल रहा था । ये कह रहे थे कि ?हम संविधान बचाते हैं, हम संविधान बचाते हैं?, ठीक है संविधान बचाया, तो वर्ष 1975 का जून भी तो याद होगा? नाखून उखाड़ दिए, विपक्षी दलों को गिरफ्तार कर लिया, भूखों मार दिया, लोगों की आंतें सूज गईं, कई लोग सालों-साल तक बीमार रहे और अंततोगत्वा संसार छोड़कर चले गए । यह संविधान बचाया आपने? आज आप कौन सा संविधान बचा रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आप हिंदुओं को गाली देकर किसको खुश करना चाहते हैं? यह तो साफ होना चाहिए । आखिर क्या बात है? आखिर हिंदुओं से क्या नफरत है?

मान्यवर, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि क्या हिंदू हिंसक हैं? कहीं किसी पर झपटे हैं? ?वसुधैव कुटुम्बकम? किसने दिया है? ?वसुधैव कुटुम्बकम? के बारे में कौन कहता है? यह हमारा है । यह हमारी सनातनी का अपना स्लोगन है । ?One Earth, One Family, One Future? के बारे में हमने कहा है, हमारे लोगों ने कहा है । अब तो इसको जी20 में पूरे विश्व ने स्वीकार कर लिया है, सबने अपना लिया है । आखिर हम कहां जा रहे हैं?

हमको विदेशों में सभी जगह ?Mother of Democracy? कहा जाता है । क्या यही ?Mother of Democracy? है? हम अपने माता-पिता, बड़े भाई-बहनों से ठीक से नहीं बोलते हैं । नेता सदन एक पवित्र ओहदा है, नेता प्रतिपक्ष भी पवित्र ओहदा है । दोनों मिलकर लोकतंत्र की गाड़ी को आगे ले जाते हैं । नेता सदन जब कोई बात कहते हैं, तो किस तरह से उन पर आरोप लगाए जाते हैं? तू-तड़ाक बोला जाता है, गाली दी जाती है, खूनी से लेकर क्या-क्या आरोप नहीं लगाए गए । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि कभी भी उन्होंने अपना वाणी संयम नहीं खोया । वे सब चीज देखते हैं ।

मान्यवर, आप देखिए कि क्या हिंदू हृदय सम्राट पूज्य शिवाजी महाराज हिंसक थे? क्या हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप जी हिंसक थे? क्या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी हिंसक थीं? क्या सुभाष चन्द्र बोस जी, चन्द्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरू जी हिंसक थे? ये सब सनातनी भी थे । कहां

हिंसक थे? किस तरह की बात कल नेता प्रतिपक्ष ने कल कही? मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप किसको खुश करना चाहते हैं? ? (व्यवधान)

क्या भगवान राम हिंसक थे? ? (व्यवधान) क्या भगवान शिव हिंसक थे? ? (व्यवधान) क्या भगवान विष्णु हिंसक थे? ? (व्यवधान) क्या नौदुर्गा माता हिंसक थीं? ? (व्यवधान) क्या भगवान कृष्ण हिंसक थे? ? (व्यवधान) देश को हर समयकाल, हर परिस्थिति में, हर जगह देश को बचाने के लिए, समाज को बनाने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में, जो सबको बराबर सम्मान देते हैं, उन ग्रंथों में कहा गया है ?

?यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥?

इसी तरह से यह भी कहा गया है ?

?विप्र, धेनु, सुर, संत हित लीन्ह मनुज अवतार ।?

यह बात भी आई है । अत्याचारियों को, आततताइयों को, जब जरूरत पड़ी है, उनको सबक सिखाने के लिए देवताओं ने, किसी ने गांडीव उठाया, किसी ने अपनी तलवार उठाई, किसी ने त्रिशूल उठाया, तब उनको सबक सिखाया । किसके लिए उठाया? संत जनों के लिए, विप्र जनों के लिए, अच्छे लोगों के लिए, समाज के अच्छे लोगों की रक्षा के लिए हमारे देवता, हमारे पूज्यनीय लोग आगे आए हैं ।

हिंदुओं ने तो कभी कुछ किया ही नहीं । कहां हिंसा की? कहां हम विस्तारवादी हैं? कहां गाली-गलौच करते हैं? अभी आपको अटल जी की कविता सुना दी, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं । एक व्यक्ति भी बता दे कि हिंदू एक मक्खी मारने के लिए भी कहीं गया हो? हां, आन-बान-शान के लिए शिवाजी ने क्या किया? महाराणा प्रताप जी ने क्या किया? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी ने क्या किया? यह पूरी दुनिया जानती है । जब आततताइयों ने अति कर दी थी, तो चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव ने क्या किया?

?अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई?

मान्यवर, आज हमारे देश में लोग फिर से किस तरह की बात कर रहे हैं? आपने यह देखा है । सारा विश्व हमें देख रहा है । विपक्ष के नेता किस तरह से हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं और आपस में सबको लड़ाते हैं ।

मान्यवर, इन्होंने उन लोगों का साथ दिया, जिन्होंने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी जारी । इन्होंने, हमारे विपक्ष के साथियों ने वहाँ जाकर उनकी पीठ थपथपाई है । हमारे नेता प्रतिपक्ष उस समय वहाँ जाकर खुद खड़े हुए थे । क्या यह कोई तरीका है? आखिर कैसे हम लोग एक बनेंगे, कैसे हम आगे जाएंगे? गाली-गलौच करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को विदेश में जाकर गाली दी । एक बन्धु, कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के अंदर गए । यह हमारी बहुत बड़ी डिग्निटी, बहुत बड़ा पवित्र पद होता है, चाहे किसी पार्टी, किसी दल का हो । हम विदेश में जाकर कभी भी ऐसा नहीं कह सकते हैं । पूजनीय हैं, हमारे देश की साख खराब होती है । आज जब हम विदेश में जाते हैं, हम किसी पार्टी की हैसियत से नहीं जाते हैं, हम विदेश में भारत के नागरिक की हैसियत से जाते हैं । वे हमसे पूछते हैं कि Where do you come from? हम उन्हें बताते हैं कि I am from India. वे कहते हैं कि मोदी जी कंट्री का है, वेलकम-वेलकम-वेलकम । चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो, वहाँ सबका वेलकम होता है । आखिर हम कहाँ जा रहे हैं?

मान्यवर, गलवान में पड़ोसी को ऐसा सबक सिखाया, जिससे दुनिया हिल गई । आपने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके अंदर तक घुस गए, दुनिया हिल गई, लेकिन हमारे विपक्ष के लोगों ने वही सवाल उठाए, वही प्रश्न पूछे, जो पाकिस्तान ने पूछे थे । आखिर हम क्या कहना चाहते हैं? आपने देखा कि अभिनन्दन को तुरन्त भारत वापस भेजा दिया । ऐसा पहली बार हुआ कि 24 घंटे के अंदर अभिनन्दन को वापस भारत भेजना पड़ा । यह एक देखने की बात है कि कहाँ हम जा रहे हैं, क्या हमारे वहाँ हो रहा है? हमारा विपक्ष, मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ, मान्यवर, अगर अमर्यादित भाषा हो तो निकाल दीजिए, बचकाना है, नासमझदार है, बेवफा है । यह मैं विपक्ष पर खुलेआम आरोप लगाना चाहता हूँ । इन्हें बात करने का तरीका नहीं है । आप मणिपुर की बात करते हैं, यह किसकी देन है, मैं उस पर कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत कुछ पहले बोल दिया गया है । हिट एंड रन-हिट एंड रन, यह कांग्रेस का, विपक्ष का अपना एक तकिया कलाम है, मारो और भागो । पिछली बार जब मणिपुर की बात इसी सदन में हुई थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने उत्तर दिया था, मैं इससे पहले वाली लोक सभा में भी था, ये सब भाग गए थे । आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर देंगे, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सुनकर जाएं, भागकर न जाएं, तब पोल खुलेगी, तब सब लोगों को अच्छा पता लग जाएगा ।

माननीय सभापति **:** अजय भट्ट जी, कृपया अब समाप्त कीजिए ।

श्री अजय भट्ट **:** मान्यवर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ । हम लोगों ने कितने बड़े-बड़े काम किए हैं । अभी इन्होंने कहा है कि हम जाति, धर्म, साम्प्रदायिकता फैलाते हैं । हम फैलाते हैं या आप फैलाते हैं । कोरोना के दौर में जो तीन-तीन वैक्सीन मुफ्त में लगाई गईं, क्या किसी देशवासी से जाति, धर्म, वर्ग पूछा गया? 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, 5 साल तक और देंगे, क्या इसमें जाति, धर्म, वर्ग पूछा जा रहा है? आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपये का जो इलाज किया जा रहा है, क्या इसमें जाति, धर्म, वर्ग पूछा गया? जो मुफ्त आवास दिए गए हैं, क्या उनमें जाति, धर्म, वर्ग पूछा गया?

मान्यवर, यह सब एक कहने की बात है, हम लोगों ने कहीं पर भी कभी यह देखा ही नहीं, सबको बराबरी का समान दर्जा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है । हमारा चन्द्रयान पहुँच गया है । आज हमारा आदित्य एल-वन चित्र ले रहा है ।

माननीय सभापति **:** आपकी बात आ गई है । अब समाप्त कीजिए ।

श्री अजय भट्ट **:** आपको पता है कि राम जी को कैकेयी माता के वरदान पर मात्र 14 साल का वनवास दिया था । हमारे विपक्ष और कांग्रेस ने तो 500 साल तक भगवान राम को वनवास दिया और जब मोदी जी आए तब वनवास खत्म हुआ और आज वे गद्दी पर बैठे हैं ।

माननीय सभापति **:** आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अजय भट्ट **:** मान्यवर, आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊँगा ।

माननीय सभापति **:** एक मिनट में और बोल लीजिए ।

श्री अजय भट्ट **:** मान्यवर, मैं एक मिनट और बोल लेता हूँ, वैसे तो हमारी अभी शुरूआत ही हो रही है ।

माननीय सभापति **:** आपके दल से अभी और बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं ।

श्री अजय भट्ट **:** अर्थव्यवस्था में हम आगे हैं । जल, थल और नभ में हम आगे हैं । विदेशी मुद्रा का भंडार भरा है, स्वदेशी मुद्रा का भंडार भरा है, हमारी पर-कैपिटा इनकम बढ़ रही है, देश में 10 सालों में कायाकल्प हो गया है । यह विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है । दुनिया के जाने-माने अर्थशास्त्री मॉगर्न स्टेनली ने वर्ष 2004 से वर्ष 2010 की रिपोर्ट में कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था गिरती हुई है ।

मान्यवर, आप सब जानते हैं । उन्होंने साफ-साफ यह बोला है, लेकिन वर्ष 2014 से वर्ष 2023 की उनकी रिपोर्ट में यह आया है कि आज देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है । भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ गई है । आज हम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं । हमारे पास अपना फाइटर प्लेन हो गया है । हमने अपने विक्रांत बना लिया है । दुनिया हिल गई है ।

मान्यवर, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे समय दिया और मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ । धन्यवाद ।

श्री विनोद लखमशी चावड़ा (कच्छ) **:** मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं और 18 वी लोकसभा में जिस प्रकार भारत की राष्ट्रपति सुश्री द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने अभिभाषण में सरकार की नीतियों ओर भावी योजनाओं पर विचार प्रस्तुत किये उसका मैं सम्मान करता हूँ, इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति जी ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के ऐतिहासिक क पैमाने पर प्रकाश डाला और लोकसभा में हुए 64 करोड रिकार्ड मतदान का उल्लेख किया । आज हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है, यह सब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से ही सम्भव हो रहा है । हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चार साल सात मास पूरे किये है । ये गरीबो, विकास वंचितों के लिये काम करती सरकार हैं, किसानों, दलित और वनवासी बंधुओं के लिये काम करती सरकार है, लोकतंत्र में लोगो से फिर से मिला जना देश नए भारत के निर्माण के लिये दिया गया है । एक ऐसा नया भारत जिसमें हमारी पुरातन संस्कृति का गौरव हो ओर जो 21 वी सदी में विश्व को अपने ज्ञान की शक्ति से समृद्ध करें, एक ऐसा नया भारत जो चोथी ओध्योगिक क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाये ओर विश्व मंच में हम नई ऊंचाइयों पर पहुंचे और इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि 2024 का चुनाव नीति, इच्छा, समर्पण और निर्णयों में विश्वास का चुनाव है । एक मजबूत और निर्णायक सरकार पर विश्वास; सुशासन, स्थिरता और निरंतरता पर विश्वास; ईमानदारी और कड़ी मेहनत पर विश्वास; सुरक्षा और समृद्धि पर विश्वास; सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास; भारत के विकसित भारत बनने के संकल्प पर विश्वास ।

भारत की स्थिर सरकार के वैश्विक महत्व को रेखांकित किया, जिसे लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए स्पष्ट बहुमत से चुना गया है । उन्होंने बताया कि यह 6 दशकों के बाद हुआ है । राष्ट्रपति ने सरकार के सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के संकल्प पर जोर दिया और भारत की आर्थिक उपलब्धियों का उल्लेख किया, जिसमे इसे विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थवयवस्था में बदलने का श्रेय दिया । उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में, भारत 11 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से बढ़कर 5 वीं सबसे बड़ी अर्थवयवस्था बन गया है । वर्ष 2021 से 2024 तक, भारत ने औसतन 8% वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति की है । उन्होंने यह भी बताया कि भारत अकेले वैश्विक आर्थिक वृद्धि में 15% का योगदान दे रहा है और सरकार भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थवयवस्था बनाने के लिए कृतसंकल्प है ।

किसानों को उनकी छोटी-मोटी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत ₹3,20,000 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई है । अपने नए कार्यकाल के प्रारंभिक दिनों में ही, सरकार ने किसानों को ₹20,000 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की है । सरकार ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में रिकॉर्ड वृद्धि भी की है । इसके साथ ही, सरकार एक बड़े पैमाने पर कि सान उत्पादक संगठनों (FPOs) और PACS जैसी सहकारी संगठनों का नेटवर्क बना रही हैं । और उपलब्धियां जो आज दिख रही हैं, वे बीते 10 वर्षों की साधना का विस्तार हैं : हम सभी बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे थे । अब हम जीवन में पहली बार बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होते देख रहे हैं । नीति आयोग के अनुसार, मेरी सरकार के एक दशक के कार्य काल में, करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं । यह प्रत्येक गरीब में विश्वास जगाने वाली बात है । जब 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हो सकती है तो उसकी भी गरीबी दूर हो सकती है ।

माननीय राष्ट्रपति ने भारत सरकार के स्त्री-नेतृत्व में विकास और सशक्तकरण के प्रति स्थिर प्रति बौद्धता को उजागर किया, जो राष्ट्र की प्रगति में एक नये युग की निशानी है । लंबे समय से बढ़ती मांग को पहचानते हुए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रावधान से लोक सभा और विधान सभा में महिलाओं की अधिक संसदीय प्रतिष्ठान सुनिश्चित करके महिलाओं को सशक्त किया गया है । एक व्यापक अभियान शुरु की गई है जिसका उद्देश्य है 3 करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाना, स्व- सहायता समूहों को अधिक वित्तीय सहायता के साथ समर्थन देकर । इस पहल का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक कौशल और अवसरों में सुधार करने के लिए नहीं है बल्कि समाज में महिलाओं के स्थान और सम्मान को भी बढ़ाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है ।

हमारी सरकार मोटे अनाज 'श्री अन्न' को सुपर फूड के रूप में दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने का अभियान भी चला रही हैं, भारत की पहल पर, वर्ष 2023 को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया गया । 19 लाख से अधिक लोगों ने केदार धाम की यात्रा की है, अयोध्या धाम में ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 दिनों में ही 13 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, भारत के हर हिस्से में तीर्थ स्थलों पर सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है, भारत को मीटंग और प्रदर्शनी से जुड़े सेक्टर में भी अग्रणी बनाना चाहती है, इसके लिए भारत मंडपम और यशोभूमि जैसा इन्फ्राटेकचर बनाया जा रहा है, आने वाले समय में टूरिस्म, रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा ।

नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने एकात्म मानवता के दर्शन माध्यम से अंत्योंदय की कल्पना को साकार करते हुए 'सबका साथ सबका विकास' के मजबूत संकल्प को मूर्तिमंत किया है ।

इस तरह हमारी सरकार सर्वागीण विकास के लिये हरेक पहेलु पर विकास कर रही हैं, 'मेक इन इंडिया', स्कील इंडिया आदि के एकीकृत पहल के माध्यम से रोजगार सर्जन प्रशस्त हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता एवम अनुसंधानो को प्रोत्साहन, स्वास्थय, स्वछता, तथा कुपोषण को झड़ से खत्म करने हमारी सरकार कृत सकलिप्त है, आइये हम सब मिलकर स्वामी विवेकानंद ओर महात्मा गांधीजी के सपनों के एक समृद्ध भारत के निर्माण दिशा में आगे बढ़े, और हमारी सरकार ने ऐसे अनेक अभूतपूर्व कार्य किए हैं, जिसके लिए मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का पूर्ण समर्थन करता हूँ । धन्यवाद ! जय हिन्द ! जय भारत !

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : मैं स्वतंत्र भारत के 87 वीं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखना चाहता हूं । संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति जी का संबोधन व्यापक और

प्रगति के साथ-साथ सुशासन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है । देश द्वारा की जा रही प्रगति और भविष्य में आगे की संभावनाओं को भी शामिल किया गया है । चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया है । सामान्य नागरिकों के जीवन में खुशहाली कैसे लाया जाए इसका भी उल्लेख किया गया है ।

हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र प्रगति की राह पर है । चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, सडक व परिवहन का क्षेत्र हो नल- जल की व्यवस्था हो, लड़कियों के लिए विशेष शिक्षा का क्षेत्र हो जल-जीवन हरियाली का क्षेत्र हो, ,दूसरे राज्यों की तरह प्रगति कर रहा है ।

वरिष्ठ अर्थशास्त्री अभिजीत मुखोपाध्याय का कहना है कि सोशल, इकोनोमिक डेवलपमेंट के पैमाने पर बिहार बंगाल या उड़ीसा जैसे राज्यों का स्पेशल का मामला आज़ादी के बाद के दूसरे दशक से शुरू हुआ । जब केंद्र सरकार ने महसूस किया कि विकास की दौड़ में पिछड़ रहे कुछ राज्यों को सहारा देना होगा । नीति आयोग के उपाध्यक्ष डी. आर. गार्डगिल के फार्मूले पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की व्यवस्था की गई । आर्थिक और बुनियादी ढाँचों के लिहाज से पिछड़े राज्यों और ऐसे राज्यों पर विचार किया गया जो अपने लिए पर्याप्त राजस्व की व्यवस्था न कर पाते हों । इसमें 11 राज्यों की लिस्ट बनी । चौदहवें फाइनेंस कमीशन में स्पेशल कैटेगरी की लिस्ट में राज्यों को न जोड़ने की सलाह दी थी जो कि बिहार जैसे राज्य के लिए उचित नहीं है ।

बिहार बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से लेकर अनेक प्रकार की अलग-अलग समस्याओं से सामना करता है । बिहार में 76% जनता बाढ़ से प्रभावित है । 29 जिलों के 35.06 लाख हेक्टेयर जमीन हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है । नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 51.91 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है । बिहार का औद्योगिक एवं आर्थिक विकास कई राज्यों की तुलना में पिछड़ा है । झारखंड अलग होने के बाद प्राकृतिक संसाधन की मात्रा न्यून हो गई है । सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बिहार एक Land Locked State है जिसके कारण यहाँ बड़े और भारी उद्योग की स्थापना मुश्किल है । ऐसी परिस्थिति में central टैक्स में छूट से उद्योग में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है । निवेश में कमी के कारण रोज़गार में कमी जिससे प्रतिव्यक्ति आय अन्य विशेष दर्जा वाले राज्यों से कम है । अतः मैं धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए क्योंकि विशेष राज्य के लिए जो मापदंड निर्धारित है उसे बिहार पूरा करता है ।

बिहार राज्य का अपना विशिष्ट स्थान है यह उत्तर-पूर्वी भारत और नेपाल की सीमा से लगे बड़े-बड़े बाज़ारों से जुड़ा है । अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की उपस्थिति इसे शेष भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से अच्छी तरह से जोड़ती है । बिहार में निवेश और नए व्यवसायों तथा उद्योगों की स्थापना के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है । मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि बिहार राज्य में अधिक से अधिक निवेश और उद्योग स्थापित किए जाएं ।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन-जिसे हम अमृत योजना के नाम से भी जानते है । अमृत योजना देश भर के चुनिंदा 500 शहर और टाऊन को विकसित करने के उद्देश्य से लाया गया है। इसमें शहरों एवं नगरों को basic Infrastructure जैसाकि जल आपूर्ती सीवरेज, वेस्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, जल संरक्षण हरित स्थानों और पार्कों इत्यादि बुनियादी ढाँचों को विकसित करना है । अमृत योजना पाँच बरस के लिए अर्थात् 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शुरू किया गया है । अभी तक राज्यों ने 82,222 करोड रुपए की 5,873 परियोजनाएं शुरू की हैं । विकास की बढ़ती धारा में मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज को भी शामिल किया जाए ताकि वहाँ बुनियादी infrastructure विकसित हो सके ।

मैं सरकार का ध्यान थावे जंक्शन की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा ताकि इस बार अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत निकास के कामों को गति दिया जा सके । क्योंकि यहाँ ग्रामीण पर्यटन विकसित होगा साथ-साथ One station One Product भी बड़े बाजारों तक पहुचेगा ।

मैं धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए यह सुझाव देना चाहूंगा कि बंजर भूमि तथा सड़कों एवं रेलवे ट्रैक की साइड में खाली पड़ी सरकारी भूमि पर फलदार का पौधारोपण किया जाए ताकि बेकार पड़ी सरकारी भूमि का पूर्ण सदुपयोग किया जा सके ।

Skill India Mission के माध्यम से मन्त्रालय ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू किए हैं जिससे कि देश के युवाओं को Skill Development की ट्रेनिंग दी जाएगी । इस ट्रेनिंग के दो components है वह Short Term Training और Recognition of Prior Learning है । ट्रेनिंग पूरा होने के बाद नौकरियाँ भी दी जाती है । अभी तक बिहार में 81,285 युवाओं एवं मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में 2,217 युवाओं को नौकरियां मिल चुकी हैं । बिहार को प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से 128.65 करोड का आवंटन हुआ है जिसमें से मात्र 36.82 करोड़ ही रिलीज हुआ है । अगर बकाया पैसा बिहार राज्य को जल्दी मिल जाती है तो निश्चित ही विकास की गति को तेजी मिलेगी ।

केन्द्र प्रायोजित स्कीम विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार को सहायता योजना के तहत विभिन्न किसान अनुकूल विस्तार गतिविधियों जैसे किसान प्रशिक्षण Demonstrations, एक्सपोजर, किसान मेला, फार्म स्कूलों का आयोजन आदि के माध्यम से किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकी में बढ़ाना और अच्छी कृषि पद्धतियों को उपलब्ध करना है । वर्तमान में यह योजना 28 राज्यों और 5 Union Territories के 691 जिलों में लागू है । बिहार राज्य को 7200 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई जिसमें से 1800 लाख राशि जारी की जा चुकी है । इससे 93,875 किसान लाभान्वित हुए हैं । अतः आत्मा स्कीम में आबंटित राशि को शीघ्र दिया जाए ताकि New Technology का विस्तार किसानों तक किया जा सके ।

Outsourcing और contractual जॉब नौकरियों में वंचित वर्ग की भागीदारी काफी न्यूनतम है । इसमें पारदर्शिता का भी अभाव है । सैकडों युवा जो कि शिक्षित है और SC/ST/OBC समाज से आते हैं Outsourcing और contractual नौकरियों में जगह नहीं मिल पाती है ।

मेरा सरकार को यह सुझाव है कि भारत Guideline जो कि वर्ष 2018 में issue हुआ है उसको सभी विभागों पर लागू किया जाए ताकि वचित वर्ग को भी outsourcing और Contractual नौकरियों में जगह मिल सके वे गरीबी से बाहर निकल सकें ।

बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल (बाड़मेर) **:** मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के अभिभाषण पर अपने विचार रखना चाहता हूँ । उम्मीद करता हूँ कि पहली बार निर्वाचित सदस्यों को अपनी बात सदन में रखने का पूरा मौका मिलेगा । इसी योग्यता एवं आत्मीयता के कारण आपको दुबारा लोकसभा अध्यक्ष बनने का मौका मिला । आपको लोकसभा अध्यक्ष बनने की बधाई । विश्व के सबसे बडे लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सर्वोच्च सदन 18 वीं लोकसभा में निर्वाचित सभी सदस्यों को बधाई । हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर बधाई ।

मैं आभारी हूँ बाडमेर-जैसलमेर-बालोतरा संसदीय क्षेत्र की देवतुल्य जनता का जिन्होंने मुझ पर और मेरी पार्टी के सिद्धान्तों पर भरोसा कर इस सदन में अपना प्रतिनिधी चुनकर भेजा । मैं मेरे निर्वाचित क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा हर क्षण और अन्तिम सांस भी उनकी सेवा एवं क्षेत्र की उन्नति के लिए था और सदैव रहेगा ।

27.6.2024 को महामहिम राष्ट्रपति के भाषण में सरकार के कार्यों का महिमा मण्डल किया गया हैं । वो कहां तक सत्य हैं मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा । मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि भौगोलिक विषम परिस्थितियों एवं सीमावर्ती होने के कारण अभावग्रस्त, इन्सानियत एवं अपनेपन को छोड कर अन्य सभी क्षेत्रों में पिछडे मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता का क्या दोष है जो देश आजादी के इतने वर्षों के बाद भी मूलभुत एवं आधारभूत सुविधाओं एवं तकनीकी से वंछित हैं । मैं यह नहीं कह रहा कि विभिन्न सरकारों ने कोई काम नहीं किया । या मेरे पूर्व प्रतिनिधियों ने जनता की पैरवी नहीं की । मैं तो बस यह कहना चाहता हूँ कि कही न कही ईच्छा शक्ति की कमी रहीं हैं ।

बाडमेर-जैसलमेर-बालोतरा क्षेत्र में आज भी शिक्षा, चिकित्सा, सडक, बिजली, पानी एवं रोजगार की भयंकर कमी हैं । देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में हम आज भी बहुत पिछडे हैं । यहां बस्तीयां छतराई ढाणियों में बसी हैं । इस कारण यहां निर्धारित मानदण्डों के अनुसार विद्यालय कम खोले गये है यदि खोले भी गये हैं तो उनमें अध्यापक नहीं हैं थर्ड ग्रेड के 60 प्रतिशत, सेकण्ड और फस्ट ग्रेड के 30-40 प्रतिशत पद आज भी खाली हैं । हमारे बच्चों ने क्या गुनाह किया है । यहां अतिरिक्त केन्द्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूलों के साथ ही उमावि एवं प्राथमिक स्तर के स्कूलों की नितान्त आवश्यकता हैं । साथ ही विद्यालयों में अत्याधुनिक तकनीकी से शिक्षा देने हेतु प्रत्येक विद्यालय फायबर लेबल कनेक्शन, विद्युतिकरण, स्मार्ट क्लासेज हेतु संसाधन एवं मानव संसाधन उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता हैं । शिक्षा सब समस्याओं का समाधान हैं । ज्ञान होगा तो विज्ञान भी आ जायेगा ।

आज भी 80 प्रतिशत जनता गांव ढाणियों में बस्ती हैं । यहां खेती एवं पशुपालन जीवन का मुख्य आधार हैं । बरसात की कमी से खेती नहीं होती और पशुपालन भी दुर्लभ हो गया है किसानों की हालत खराब हैं । किसानों ने बैंकों से ऋण लिया तो वे भरने की स्थिति में नहीं है उनकी जमीने कुर्क हो रही हैं । बैचारा किसान 24 घण्टे चिन्ता ग्रस्त रहा है । एक तरफ तो उनसे राम रूठा हुआ और दुसरी तरफ राज भी रूठ गया है । किसान जाये तो कहां जाये इज्जत की जीन्दगी नहीं मिलने से उनके पास अपनी देह लीला खत्म करने के अलावा क्या रास्ता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि किसानों के ऋणों को माफ किया जाए । राज्य सरकार को निर्देश दे की भूमि विकास बैंकों, स्थानीय कॉ आपरेटिव बैंकों के ऋण माफ कर किसानों को राहत प्रदान करावें । शिक्षा के अभाव, सरकारी तन्त्र की उदासीनता के कारण यहां के किसानों फसल बीमा योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा हैं । सम्मान निधि के नाम पर तो अन्न दाताओं के साथ भिखारियों जैसा बरताव कर उनका मजाक उडाया जा रहा हैं । उनको सहायता के रूप सम्मान निधि नहीं नवीन तकनीकी, बैंकों से ऋण, उन्नत किस्म के बीज, उपकरण और प्रशिक्षण की आवश्यता हैं न की सम्मान निधी से सम्मान की । पिछले 10-15 सालों में तो किसानों की स्थिति बहुत की खराब हुई है विशेषकर हमारे क्षेत्र के किसान की ।

यहां ना तो सड़क हैं पीएमजीएसवाई के तहत बनाई गई हैं तो उनकी रिपेयरींग के अभाव में अब वे चलने लाईक नहीं रही हैं । यहां छीतराई बस्तीयों के कारण आबादी घनत्व कम होने के कारण वर्तमान की 150 जनसंख्या वाले गावों को सडकों से जोडा जावें । और टुटी सड़कों का नवीनीकरण करावें । डीएनपी में स्थानीय लोगों की मांगों को ध्यान में रख कर उनको छुट दी जावें । रिफायनरी में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने, यहां पैट्रोकेमिकल हब का निर्माण करने एवं उनमें भी स्थानीय छोटे स्तर के व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के स्थानीय लोगों के रोजगार उपलब्ध करवाये जाने हेतु कॉ प्रोडेक्टस को स्थानीय व्यापारियों को ही उपलब्ध करवाया जावे न की बड़े उद्योगपतियों कॉरपरेटरों को । सोर उर्जा एवं पवन उर्जा के उत्पादन हेतु यहां सभी प्रकार की

परिस्थितिया अनुकुल हैं । इस क्षेत्र में यहा उद्योग लगाये जायें । यहां सस्ती जमीन, भुगर्भ में मिनिरलस, मानव संसासन एवं अन्य सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं । ऐसी स्थिति में जीरों इन्डस्ट्रीज के इस क्षेत्र में सिमेन्ट एवं अन्य प्रकार के कारखाने खोले जायें ।

इस क्षेत्र की जनता उद्योगपतियों एवं सरकारी नियमों की अनदेखी से इतनी त्रस्त हैं की एक मात्र नदी मरूगंगा में पाली जोधपुर की औद्योगिक ईकाईयों द्वारा रसायनयुक्त पानी से डोली से लगाकर गांधव तक सभी गावों में गन्दा पानी फैलने से बीमारियो फैल रहीं हैं, पीने का पानी, स्थानीय हवा दुषित होने एवं फसले और खेतो के खराब होने के कारण किसान त्रस्त हैं । इस हेतु दुषित पानी को कैनाल या पाईप लाईन के माध्यम से कच्छ के रण में छोडा जाये तो उचित होगा ।

मेरे क्षेत्र की निम्न मुख्य मागें हैं इनको आगामी बजट में सम्मिलित किया जावें । बाडमेर में सिवील एयरपोर्ट । जैसलमेर-बाडमेर-भाभर रेल्वे लाईन जो पूर्व में स्वीकृत हैं । जानबुझ कर ठण्डे बस्ते में डाल रखी हैं । पेयजल के स्थाई समाधान हेतु माही परियोजना, नर्मदा परियोजना एवं इंदिरा गांधी परियोजना को सम्मिलित कर ERCP की तर्ज पर WRCP परियोजना बनाकर इस क्षेत्र में पीने एवं सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाया जावें । सैनिक एवं केन्द्रीय विद्यालय खोलने । 150 की वर्तमान जनसंख्या वाले राजस्व ग्रामों को सड़कों से जोड़ने । गांव-गावं ढाणी-ढाणी तक पानी पहुंचाने की योजना जनता जल मिशन में खाली पाईप लाईन बिछाई गई हैं पानी कहां हैं । पाईप लाईन बिछाने में भाई भतिजावाद हुआ हैं । शासन, प्रशासन एवं ठेकेदारों की मिली भगत से बहुत बड़ा घोटाला हुआ हैं उसकी जाँच कर आपजन को पानी कैसे पर ध्यान नहीं दिया तथा मिले इस पर चिन्ता की जावें । सरकार ने इन पर ध्यान नहीं दिया तभी प्रधानमंत्री जी के जनसभा होने के बावजूद बायतु विधानसभा व बाड़मेर लोकसभा चुनाव में मेरे सामने बीजेपी को जनता ने नकारकर तीसरे स्थान पर धकेला जमानत बड़ी मुश्किल से बचा पाएं थार की जनता ने उम्मीदों के साथ मुझे आर्शीवाद दिया ।

श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर (बनासकांठा) **:** मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण मे संशोधन हेतु अपने कुछ बिंदुओं को प्रस्तुत करती हूं । जिस प्रकार सरकार महिलाओं के उत्थान की बात करती है उस प्रकार इस अभिभाषण मे गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि कई घरों में गैस सिलेंडर तो है परंतु इसकी कीमत ज्यादा होने के कारण लोग गैस सिलेंडर भराने में अक्षम है । जिसके कारण रसोई घरों में महिलाओं को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है लेकिन इस बात का कोई उल्लेख नहीं है ।

अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो अभी हाल ही में गुजरात के राजकोट में गैर कानूनी गेमिंग जोन में 25.05.2024 को भीषण आग लगने से 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई । लेकिन अभिभाषण में निष्पक्ष जांच, न्याय और उचित मुआवाजों के लिए एक शब्द भी नहीं है ।

हमे खेद है कि राष्ट्रपति अभिभाषण में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कोई ठोस कदम की या आखिरी दस साल में किसानों की किस पैदावार में कितनी वृद्धि हुई उसकी कोई बात नहीं है ।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में रेलवे में बुजुर्गों, पत्रकारों और खास वर्ग के लोगों के लिए जो स्पेशल सब्सिडी यात्रा में मिलती थी उसको कोरोना काल से सरकार ने बंद की है जिसे शुरू करने का कोई जिक्र नहीं है ।

जिस प्रकार सरकार दो करोड़ नौकरियां देने के बात करती थी लेकिन सरकारी नौकरियों मे कितनी जगह खाली है और उसे भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहें हैं इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह **(चन्दौली) :** मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में निम्न बातों को जोड़ना चाहता हूं क्योंकि उन बिंदुओं का जिक्र माननीय राष्ट्रपति महोदया के भाषण में नहीं हुआ था ।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है । कृषि पूर्णतया सिंचाई के साधनों पर निर्भर होती है । हमारे संसदीय क्षेत्र चंदौली में स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने कृषि सिंचाई हेतु नहरो की व्यवस्था की थी उनके बाद 1 मीटर भी नहर नहीं बनवाई गई । उन नहरो की मरम्मत तक नहीं की गई नहर के पानी का मुख्य स्रोत चंद्रप्रभा बांध है जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है । करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद इसका लीकेज बंद नहीं हुआ है जबकि भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दुहाई देती रहती है । इसमें भ्रष्टाचार हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए ।

देश में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की हालत बहुत ही चिंताजनक है । विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आकस्मिक चिकित्सा केंद्र (गंभीर प्रकृति के रोग से संबंधित) के इलाज हेतु कोई व्यवस्था नहीं है । ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा की स्थिति देश में और भी बदतर है, जहां शिक्षकों द्वारा शिक्षा देने के अलावा लगभग सारे काम कराए जाते हैं, जैसे रैलियों में भीड़ इकट्ठा करना, प्रधानमंत्री जी के स्वागत में फूल बरसाना त्योहारों पर दिए जलवाना आदि काम उनसे लिया जाता है । सरकार समान शिक्षा नीति की बात तो करती है परंतु गरीब समाज के बच्चों को समान अवसर नहीं प्रदान करती है । इसे माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जोड़ने का कष्ट करें ।

माननीय राष्ट्रपति महोदया ने देश के विकास में सड़कों के योगदान की बात तो कही, परंतु ग्रामीण सड़कों के पक्ष में कोई जिक्र तक नहीं किया । हमारे लोकसभा क्षेत्र चंदौली में गांव के संपर्क मार्ग की हालत बहुत ही खस्ता हाल है वहां किसान, मजदूर व गरीबों के बच्चे चलते हैं । प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का पोर्टल विगत कई वर्षों से चंदौली जनपद का नहीं खुल रहा है, जिससे वहां के सड़कों का प्रस्ताव सरकार तक नहीं पहुंच पा रहा है । माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के अंत में इसे जोड़ने का कष्ट करें ।

बड़े दुख के साथ कहना है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में रोजगार के संदर्भ में एक शब्द भी नहीं कहा । सरकार देश में होने वाली नीट परीक्षा एवं यूजीसी नेट परीक्षा के साथ कई दर्जन परीक्षाएं तो कराई, पर सरकार का रोजगार देने का नियत सही नहीं था | अतः सभी परीक्षाओं को लिक कराया गया | इसमें एनटीए के चेयरमैन की संलिप्तता सीधे प्रतीत होती है ।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 घंटे बिजली का राग अलापते रहती है । परंतु धरातल पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है । उदाहरण के तौर पर मेरे संसदीय क्षेत्र चंदौली के सभी 33/11 सब-स्टेशन ओवरलोडेड है । अतः लगातार बिजली कटौती की समस्या बनी रहती है । कृपया इस वक्तव्य को भी माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जोड़ा जाए ।

बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में नमामि गंगे की सफलता का कोई जिक्र तक नहीं किया । उन्होंने नहीं बताया कि विगत 10 वर्षों में हजारों करोड़ खर्च करने के बाद भी गंगा कितने प्रतिशत साफ हुई क्या सरकार इसे जांच का विषय बनाएगी? गंगा नदी में हो रहे लगातार कटान से किनारे स्थित गांव खतरे में आ गए हैं । कटान से गांव वासी बहुत परेशान है । उसे रोकने के लिए व्यापक स्तर पर समाधान की आवश्यकता है । माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस बिंदु को जोड़ते हुए कृपया सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का कष्ट करें ।

श्री नरेश गणपत म्हस्के (ठाणे) **:** मैं महाराष्ट्र से शिवसेना पक्ष की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं ।

मैं देश के सदन में पहली बार चुन के आया हूं । मुझे यहां शिवसेना की ओर से अपने विचार रखने का मौका मिला इसलिए मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री तथा हमारे शिवसेना के गुट नेता डॉ श्रीकांत शिंदे जी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी का आभार व्यक्त करता हूं । हमारी मराठी में सुप्रसिद्ध लेखक व पु काले जी की कुछ पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध है वह कहते हैं -

कबुतराला गरुडाचे पंख लावता येतीलही पण गगनभरारी घेण्याचं वेड रक्तातच असावं लागतं कारण आकाशाची ओढ दत्तक घेता येत नाही

इसलिये जिन्हें देश के विकास की मन से आस है ऐसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सदन में प्रथमतः मन से अभिनंदन करता हूं ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण के दौरान ने पांच' न' की बात की । मैं उसका जिक्र शुरुआत में ही करना चाहता हूं । उन्होंने कहा, यह सरकार नीति, नोयत निष्ठा, निर्धार और निर्णय के साथ काम करने वाली सरकार है । ऐसी सरकार का हिस्सा होने का मुझे सोभाग्य मिला इसलिए में खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं । सरकार के हर एक निर्णय का विरोध करने वाले विपक्ष को राष्ट्रपति जी के इन पांच' न' द्वारा एक तरीके से पाठ देकर सरकार की कटिबद्धता को सराहा है ।

कोई शायर कहता है-

पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे को,

उसके मुक्कहर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नही होते...

विकास और सुशासन की राह पर चलने वाली और तीसरी बार संपूर्ण बहुमत से चुनकर सत्ता में आई हुई इस मोदी सरकार विपक्ष को क्या दिक्कत है यह मुझे अभी तक समझ में नहीं आया । बहुमत की सरकार और आपातकाल का उल्लेख होते ही विपक्ष के लोगों की हालत, जैसे मराठी में कहते हैं, " नाकाला मिर्च्या झोंबल्या" जैसी हो जाती है । परंतु मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बहुत ही सही, सच्ची बातें सीधे तरीके से कह दी । राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सही कहा, विपक्ष को संसदीय परंपराओं का ध्यान रखते हुए अपनी बात करनी चाहिए ।

मेरे जैसे कई सदस्य पहली बार इस सदन में चुनकर आए हैं ना कि में व्यक्तिगत तौर पर बल्कि हमारे पक्ष के साथ-साथ पहली बार चुन कर आए हुए इस सदन के सभी सदस्यों की तरफ से में माननीय राष्ट्रपति जी तथा माननीय अध्यक्ष जी को आश्वस्त करना चाहता हूं की पहली बार चुनकर आए हुए किसी भी सदस्य के द्वारा इस सदन की गरिमा को अबाधित रखेंगे ।

आईटी, हेल्थ सेक्टर, किसान की आय में वृद्धि, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पूर्वोत्तर राज्यों का विकास, आयुष्मान योजना तथा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित की हुई लखपति दीदी योजना जैसी योजनाओ को देश के आम आदमी तक पहुंचाने के सत्कार्य में विपक्ष भी हमारे साथ जुड़े क्योंकि, चुनाव तक यह घोषणाएं शायद किसी पक्ष की हो सकती है लेकिन सरकार अभी पूरे देश की है और आम आदमी के हित की किसी भी योजना के लिए विपक्ष ने भी अपना पूरा सहयोग देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं ।

मैं फिर एक बार शिवसेना पक्ष और महाराष्ट्र के करोड़ों लोगों की ओर से महामहिम राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू जी के अभिभाषण के उपलक्ष्य पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपके मार्गदर्शन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के आभार प्रस्ताव का में पूरे जोर से समर्थन करता हूं ।

विश्वास की लकीरें

खींची है हमने उनके हथेली पर

इसी बात का नतीजा है ये जीत का तीसरा अंक !! जनता ने पूरी विश्वास के साथ हम पर सौंपी हुई जिम्मेदारी हम बखूबी निभाएंगे इसी विश्वास के साथ जय श्रीराम, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय !

I thank all the voters of my Thane Lok Sabha Constituency, who elected and sent me to this House as their Member of Parliament to raise their questions.

While starting this speech, I want to quote great Marathi poet, Jnanpith Award winner Shree. Kusumagraj Shree. He writes,

?Let me put brave Marathi Tikka on my head

Who belongs to hardness of rough and tough environment.?

Sant Dnyaneshwar says, ?Marathi is finest language.?

I want to thank and bow down to the people of Maharashtra. I want to reiterate my demand for classical status to the Marathi language.

I wish to express my views on the Motion of Thanks to the President?s Address made by the hon. President of India, Droupadi Murmuji.

Actually, I was supposed to speak on the Motion of thanks to the President?s Address but the Leader of the Opposition, Mr. Rahul Gandhi yesterday made a nonsensical speech in the House. When will he act like a matured person? People call you yuva leader (youth leader) but he is in his fifties. His IQ and age do not match. He has learned a tactic to raise the voice while delivering a speech. This does not mean he is true.

You said every Indian will get Rs.9,000 in their bank accounts on 1st July. I did not get the money yet. You cannot win the battle on the basis of fake narratives. Rahulji, you can only win by doing the work honestly towards the society. You won 99 seats out of 542, but still if you feel you are ruling the Government, then my salute to your immaturity.

Hindus are famous in the world for their tolerant nature. They do not start a fight with anyone. Both Muslims and Christians are brothers of Hindus. You said, ?Modiji or RSS is not a Hindu society?. Then, is Rahul Gandhi a Hindu society? Or, what is it? Rahulji always stands for one particular segment. He spreads fake narratives during the elections and also gives wrong signals to the Muslims who are living

peacefully. While presenting yourself as secular, you humiliated all the religions. Now, Hindu, Muslim, Christan, Sikh and Jains are done with your pseudo-secularism. That is why, people did not give you the mandate.

Balasaheb Thakre used to say with pride, *?Garv se kaho hum Hindu hain.?* (Say with pride that you?re Hindu) Yes, we are proud to be Hindus. I want to quote a poem written by late Prime Minster Shri Atal Bihari Vajpayeeji. I will be quoting four lines:

?I am a perfect Sindhu, this is my Hindu society.

My relation to this is immortal, I am the individual and this is the society.

Through this I gained body and mind, through this I gained life.

My only duty is to dedicate everything to it.

I am a member of the society.

I am a servant of the society.

I can sacrifice an individual for the sake of the whole Abhay.

Hindu is my body and mind.

Hindu is life; Hindu is all skin; and Hindu is my introduction.?

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल) **:** मुझे 18 वीं लोक सभा के गठन पर महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में अपने विचार व्यक्त करने का मौका देने के लिए आभार । मुझे इस नये संसद भवन में राष्ट्रहित के लिये जनतादल (यू) लोक सभा में नेता के रूप में अपने विचार व्यक्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है ।

भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को शुभकामनाएँ एवं साधुवाद भी देता हूँ कि आप पुनः तीसरी बार एन०डी०ए० सरकार में प्रधानमंत्री का शपथ लिए है । मैं अध्यक्ष जी को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ कि उन्होने पुनः लोक सभा के अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है ।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण सुनकर हम सभी अभिभूत हैं । उन्होंने भारत के उज्जवल भविष्य की जो संकल्पना की है उससे यह प्रतीत होता है कि निश्चय ही 2047 तक हमारे भारत को विकसित, आत्मनिर्भर एवं विश्वगुरू बनने से कोई नहीं रोक सकता । महामहिम जी के अभिभाषण में ऐसे राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना की गई है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो, जिसमें आधुनिकतावाद का हर स्वर्णिम अध्याय हो, जो आत्मनिर्भर हो और जो अपने मानवीय दायित्वों को पूरा करनें में समर्थ हो, जिसमें गरीबी न हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो । ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो जिसकी एकता और अधिक अटल हो ।

भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी एवं प्रगतिशील आर्थिक नीतियां एवं योजनायें जो समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ सभी वर्गो को सामानांतर एवं सार्थक लाभान्वित करती है इसके लिये मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय के गहराईयों से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के चौथे खंड में उल्लेख किया है कि "राज्य के विकास से देश का विकास, दुनियाभर से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्यों में स्वस्थ स्पर्धा हो? । मैं बिहार जैसे अति पिछड़े राज्य से आता हूँ । बिहार अन्य राज्यों की अपेक्षा प्रगति के क्षेत्र में काफी पिछड़ गया है । हमारे नेता एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पिछले दो दशकों से अपने सीमित संसाधन के द्वारा राज्य के विकास के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं । उनकी कई दूरगामी योजनाएं राज्य मे तो सफल हो ही रही है पूरे देश में भी उन योजनाओं का अनुकरण किया जा रहा है । किन्तु राज्य को अधिक आर्थिक सहायता एवं विशेष राज्य का दर्जा अगर केन्द्र सरकार द्वारा मिल जाता है तो बिहार राज्य भी अन्य विकसित राज्यों की श्रेणी में जल्द ही सम्मिलित हो जाएगा एवं देश की उन्नति में बिहार राज्य का अहम योगदान साबित होगा ।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है । भारत की 70 प्रतिशत आबादी कृषि एवं उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर है । एन०डी०ए० सरकार किसानों की खुशहाली के लिए हर संभव सराहनीय प्रयास कर रही है । हमारे देश के अन्नदाताओं को कृषि उपज का उचित मुल्य मिले, यह हमारे सरकार की प्राथमिकता है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को दिल की गहराईयों से धन्यवाद देता हूँ कि उनके द्वारा पी०एम० किसान सम्मान निधि के तहत किसानहित तथा देशहित में प्रोत्साहन के रूप में 6 हजार रूपये प्रतिवर्ष देश के करीब 9 करोड़ किसानों को सम्मानित किया जा रहा है । इस योजना के तहत अब तक देश में करीब 3 लाख 20 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा की राशि किसानों के बैंक खाते में दी गई है ।

मेरा संसदीय क्षेत्र सुपौल बिहार के सीमावर्ती बाढ़ग्रस्त अतिपिछड़ा क्षेत्र है । हमारे संसदीय क्षेत्र के प्रतापगंज रेलवे स्टेशन, नरपतगंज और राघोपुर के बीच है तथा पूर्व में उक्त स्टेशन पर सभी गाड़ियां रूकती थी । अब ट्रेन न 0.13211/13212 (जोगबनी से दानापुर) तथा 13213/13214 (जोगबनी से सहरसा) चलती है का ठहराव नहीं है तथा मात्र एक पैसेंजर गाड़ी है । अतः उक्त दोनों ट्रेनों का एक मिनट का ठहराव प्रतापगंज में जनहित के लिए किया जाय । साथ ही सरायगढ़ से नई दिल्ली भाया सुपौल-सहरसा तथा सरायगढ़ भाया सुपौल पटना के लिए नई ट्रेन दी जाय अथवा वैशाली एक्सप्रेश ट्रेन न 0.12553/12554 तथा राज्यरानी एक्सप्रेश ट्रेन न 0.12567/12568 को सहरसा से सरायगढ़ तक विस्तार की जाय ।

मैं अपनी बातों को समाप्त करते हुए सरकार द्वारा पच्चीस करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफलता हासिल किया है, उसके लिए बधाई देता हूँ और विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के गरीब, युवा, नारीशक्ति और किसान कैसे सशक्त होंगे, सरकार इसके प्रति वचनबद्ध हो, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

श्रीमती मंजू शर्मा **(जयपुर) :** मैं महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा दिये गये अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ । किसी भी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की अध्य भूमिका होती है । जितना हमारा बुनियादी ढांचा विकसित होगा या यह कहिये कि बुनियादी ढांचा किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है । इसी को ध्यान में रखते हुये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास पर पूरा जोर दिया है । आज देश में उच्च कोटि की सड़कों का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है । पहाड़ी क्षेत्रों और दूरगामी स्थानों में सड़क निर्माण को प्राथमिकता दी गई है । साथ ही साथ हमने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर उच्च कोटी की सड़कों का जाल बिछा दिया है । हमारी फौज को अपना साजो सामान लाने ले जाने में सुविधा हो गई है । हमारी सरकार ने

दुर्गम स्थानों पर भी सुरंगों का निर्माण किया है, इससे न केवल यातायात में सुविधा हुई है बल्कि सेना को समान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाने में भी सुविधा हुई है । उदाहरण के तौर पर चार धाम योजना भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है । इसके पूरा होने से न केवल पर्यटन के बढ़ावा मिलेगा बल्कि सेनाओं को भी बहुत लाभ मिलेगा । इसके लिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद और बधाई देती हूँ कि जिला बुनियादी ढांचे को विकसित करने में 60 वर्षों में जो कार्य कार्य हुआ उससे कहीं ज्यादा काम पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार ने करके दिखाया । देश का संविधान हमें सिखाता है कि गाँव, गरीब और किसान की सेवा में सरकार कोई कमी न छोडे । सही मायने में संविधान निर्माताओं का सपना 10 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत दिखाई दे रहा है । एक समय जब देश में कोई महामारी आती और देखते थे । दवा तो हम दूसरे देशों की लिए मोहताज होते थे । लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन और सोच ने देश को नई दिशा देने का काम किया है । कोरोना काल खण्ड की ही बात करें तो देश का आम नागरिक भारत सरकार के कार्यों की प्रशंसा कर रहा है । विकसित देश भी हैरान है कि कैसे भारत ने सबसे पहले कोरोना का टीका तैयार कर लिया है । भारत सरकार पिछले 4 वर्षों से 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त राशन प्रदान कर रही है और सरकार ने अगले 5 वर्षों तक उस योजना को बढ़ाने का निर्णय लिया है । कई देशों की इतनी आबादी भी नहीं है जितना सरकार मुफ्त राशन प्रदान कर रही है, इसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत हो रही है । इससे भारत सरकार की छवि अच्छी हुई है । भारत सरकार किसानों को भी 6000 रुपये की राशि हर वर्ष प्रदान कर रही है, जिससे कि वह अच्छे बीज खरीद सके । महिलाओं के लिए भी हमारी सरकार अनेकों कार्यक्रम चला रही है जिससे कि महिलाएं सशक्त हो सके और किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर न रहे । आज हमारे देशवासी गर्व से कहते हैं कि भारत का भविष्य एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में सुरक्षित है जो कि बहुत दूर की सोचते हैं और उनका सारा फोकस इसी पर है कि देश की उन्नति कैसे हो, देश आगे कैसे बढ़ चाहे वह रक्षा क्षेत्र दो चाहे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र हो और चाहे कोई भी अंदरुनी क्षेत्र हो । माननीय अध्यक्ष जी आज हमारी अन्तर्राष्ट्रीय जगत में पहचान बनी है । आज कोई भी विकसित देश भारत को हल्के में लेने का दुस्साहस नहीं कर सकता । देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, निरन्तर बढ़ रहा है । आज हम विश्व की 5 वीं अर्थव्यवस्था है और निकट भविष्य में हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं । यह सब माननीय प्रधानमंत्री जी की मेहनत और दूरदृष्टिता का परिणाम है ।

मैं अपनी सरकार को हर क्षेत्र में विकास के लिए बधाई देते हुये और महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा दिये गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करती हूं ।

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): I am grateful to my party for giving me this opportunity to express my gratitude to Madam President for her speech: On behalf of my party, I respectfully disagree with some of her observations and highlight the serious issues that have been gravely ignored by the BJP Government in the past and also recently.

In the midnight of 1947, India started its journey as a modern nation-state which Prime Minister Nehru described as a 'tryst with destiny'. Almost all the countries that got their independence during our time were not able to maintain their initial democratic values, but India's story is different. It is different because certain values were cultivated under the leadership of Mahatma Gandhi during our freedom movement. Additionally, the collective strength of India proved the

success of democracy under the leadership of Prime Minister Nehru. It puts me in immense pain to say that, unfortunately, in the last 10 years, we have seen a reverse cycle, a complete erosion and systematic dismantlement of public institutions. This Government has exploited these public institutions against the representatives of the people. In the period of the Modi Government, nearly 95% of political cases filed by the ED were against the opposition leaders, while the conviction rate was a mere 2- 3%. If this is not finishing dissent, then what is?

I respectfully disagree with the sentiment expressed by the Hon'ble President about 'Reform, Perform and Transform', that it has delivered significant positive outcomes. This slogan, while appealing, appears to have primarily benefited the party in power rather than the citizens and the country. Upon closer scrutiny, it becomes evident that these reforms and transformations have not materialized into substantial improvements in the lives of our citizens. The promises made have fallen short of delivering real, meaningful change that addresses the pressing needs of our communities and this is evidently visible in the election results of this time.

While this Government glorifies our rural life in their speeches, the allocation for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), which serves as a lifeline for rural India, has been dwindling over the years. The current allocation of Rs 60,000 crore marks a substantial 33% decrease from the previous year and is only 0.198% of the total GDP. Such a drastic reduction in funding is not just a number; it translates into fewer job opportunities and diminished financial support for the rural population that depends on this program for their livelihood. This revolutionary Act was introduced by Dr. Manmohan Singh-led Government for the welfare of the real India, it is disheartening for us to see it being pushed to the peripheries.

This Government also claims to be a champion of tribal welfare. However, I would like to highlight that the BJP has only selectively engaged with tribal culture and history, neglecting crucial aspects of tribal identity- their language, religion, and habitat. In 2020, the Government introduced a new environmental impact assessment draft notification, replacing the 1994 notification and its 2006 amendments. This new draft reduced public participation in the environmental clearance process by shortening the notice period for public hearings and eliminating them for many projects. These recurring initiatives are nothing but

efforts to displace tribes from the land, forests, and other resources on which they depend.

Further, the Forest Rights Act (FRA), which recognized the rights of tribal people over forest resources, has also been undermined under this Government. This legislation required the consent of forest dwellers before acquiring their land for projects. However, in 2017, the Government decided that forest land leases could be issued without the necessary clearances. In 2019, the Government issued a circular permitting Stage I or "in-principle" approval for other projects without needing consent from forest dwellers. Despite protests, this change remained in effect. By taking away the required consent from forest dwellers, the Government has prioritized its "close" industrial friends over the rights of tribal communities.

We all know that health is an utmost priority despite numerous reports and recommendations from various committees, our health budget as a percentage of GDP remains at a mere 1.3%. This situation is in stark contrast to the recommendations outlined in the National Health Policy of 2017, by the Modi Government itself. It clearly said that the budget allocation for healthcare must steadily increase to reach a target of 2.5% of GDP in a time-bound manner. This goal was set with the vision of ensuring better healthcare for all and improving the overall health infrastructure of our country.

There is an old saying that a family is just one episode of serious illness away from poverty. Sadly, this is not just a cliche, but a harsh reality for millions of our citizens. A recent report by Niti Aayog confirms this cliche. According to the report, 7% of India's population, about 10 crore people are pushed into poverty every year due to the exorbitant costs they incur on healthcare.

This statistic is alarming and highlights the urgent need for us to address the inadequacies in our healthcare system. When families are forced to choose between health and financial stability, it is clear that we are failing to provide the necessary support and protection that every citizen deserves. As we discuss the critical issue of healthcare in our country, l must bring to the attention of the Government a serious limitation in the healthcare scheme- AYUSHMAN BHARAT. While the scheme provides essential issuance support to people, it is largely restricted to in-patient departments (IPD) and does not extend assistance to outpatient departments (OPD). This is a significant oversight, considering that OPD services account for 40-80% of all healthcare services.

This restriction leaves a vast majority of our population without the necessary support for their day-to-day medical needs. OPD services, which include consultations, diagnostic tests, and minor procedures, are crucial for maintaining the overall health of our citizens. By not covering these services, we are neglecting a fundamental aspect of healthcare.

I would like to draw the attention of the Government to the so-called prime schemes and programs initiated by this Government, which were launched with much fanfare and promises. Take, for example, the 'Make in India' initiative, unveiled with great enthusiasm. The Government set itself three ambitious goals: a) increasing manufacturing growth by 12-14% per annum b) increasing the share of manufacturing in the GDP to 25% by 2022 c) creating 100 million jobs in the manufacturing sector by 2022. However, I see no celebrations of success from the Government. Let me show the real picture. Post 2013-14, the manufacturing growth rate has averaged a mere 5.9%. The share of manufacturing in our GDP has stagnated and was just 16.4% in 2022-23.

Further, instead of the promised job creation, the Manufacturing Sector saw its workforce halved between 2016 and 2021. These figures paint a stark contrast to the initial promises and show us how this Government just knows how to promise things but fails at keeping its word. I would request the Government to instead of showing creativity in the titles and slogans of their schemes and programs, they must focus on putting efforts into strengthening the public delivery systems.

I would also like to thank the Hon?ble President for touching upon the recent paper leak controversy during her address. I must also speak about the students who devoted years of hard work into preparing for these exams, and cracking these exams; some of them even taking 1 year, 2 years gap for preparation. Such instances of Paper leaks shake the entire morale of these Students. The random practice of granting grace marks is an additional anxiety provoking act that has also severely affected the youth of our country who were only pursuing their aspirations. This Shows how a Central Government Agency, which is entrusted with the future of our youth, or children- can recklessly just destroy it within seconds. I would like to question the Government. How do they plan to give justice to each and every student who suffered due to it? Do they have the capacity to even map who all and how many have suffered?

And let me also inform that this is not the initial instance where NTA, formed as an independent entity in 2018, has come under criticism for exam-related errors. In

the CUET 2022, there were accusations of question-and-answer key leaks, alongside incorrect translations from English to regional languages. Similarly, earlier this year, numerous Students raised concerns about Possible irregularities in the JEE (Main) exams. While there is a celebration of the victory during the elections, I must remind the Government that whatever has happened in the past decade is not worth a celebration. It is high time for the Government to acknowledge that while history May remember them for their long- Standing Power, true success will only be achieved if they are also recognized as a Government committed to the values of our constitution and public well-being. Thank you, Jai Samvidhan, Jai Hind

DR. DHARAMVIRA GANDHI (PATIALA): First of all, I thank for allowing me to express my views on the Presidential Address. I find a lot of inconsistencies in the speech of the hon. President. While it boasts of phony achievements of BJP Government, it does not make mention of miseries faced by farmers, workers, youth, students, Scheduled Castes, tribals, and minorities.

The facts mentioned on GDP, trade deficit, foreign laws, and employment are misleading.

Hon. President?s Address boasts of fast developing economy but does not mention of the status of our country on the Human Development Index, Gender Development Index, Hunger Index, Human Rights, Press Freedom Index, and Freedom of Expression Index where we stand trailing at the lowest level of the tally.

I wonder at the stoic silence of our hon. Prime Minister on the historic farmers agitation in which more than 650 farmers laid down their lives, horrible treatment meted out to our women wrestler?s association, atrocities against Manipur women, Bilkis Bano Case, and NEET scam which spoilt the carrier of lakhs and lakhs of students across the country.

Based on above facts, I disagree with the claims made by the Government structured Presidential Address.

स्मिता उदय वाघ (जलगांव) **:** सर्वप्रथम मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद । हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा पेश किए गए इस धन्यवाद प्रस्ताव का में तहेदिल से समर्थन करती हूं । हमारी एन डी ए सरकार के विगत 10 सालों के समर्पित प्रयासों का ही

परिणाम है भारत 11 वीं विश्व की सबसे कड़ी अर्थव्यवस्था से बढ़कर आज 5 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वन गया है । आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत अब विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थवयवस्था बनने की ओर अग्रसर है । सरकार के सतत प्रयासों का ही परिणाम है कि हमारे देश के हर क्षेत्र में तरक्की की है । चाहे वह जनता के बेहतर स्वास्थ्य की बात हो अथवा देश के आर्थिक विकास की । चाहे विदेश नीति का क्षेत्र हो अथवा देश की रक्षा का प्रश्न हो ।

हमारी सरकार सभी वर्गों विशेषकर किसानों, महिलाओं, गरीबों व युवाओं के उत्थान के लिए कृत संकल्प है । विगत दस सालों में हमारी सरकार ने सभी कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में जितनी वृद्धि की है, उतनी अब तक आजादी के इतिहास में कभी नहीं हुआ । प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि निश्चय ही किसानों को उनकी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाने में काफी सहायक सिद्ध हुई है ।

जहां भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनकर उभरा है, वहीं सरकार ने विगत एक दशक में 380000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कर देश के विकास की गति काफी तेज कर दी है । 3 करोड़ महिला दीदी को लखपति बनाना, नमो ड्रोन दीदी योजना, कृषि सखी योजना सहित हमारी सरकार महिलाओं के चहुमुंखी उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है । हमारी सरकार के इन्हीं समर्पित प्रयासों का परिणाम है कि विगत दस सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आ गए हैं ।

आयुष्मान भारत योजना के तहत अभी तक 55 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है । अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को कवर करने का सरकार का निर्णय निश्चय ही प्रशंसनीय व उत्साहवर्द्धक है ।

रक्षा क्षेत्र में जहां हमारी सरकार के प्रयासों से रक्षा उत्पादों के आयात में काफी कमी लायी गई और कीमती विदेशी मुद्रा की बचत की गई, वहीं दूसरी ओर हमारी 40 से अधिक आर्डिनेंस फैक्ट्रियों में बने रक्षा उपकरणों के निर्यात से देश को काफी विदेशी मुद्रा का अर्जन हो रहा है ।

जैसा कि हमारी राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में बताया, 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था तथा यह हमारे सांविधानिक व लोकतांत्रिक इतिहास पर एक काला धब्बा साबित हुआ है । वहीं हमारी सस्कार ने विगत 10 सालों में एक बार भी संविधान के खिलाफ काम नहीं किया है । विगत 10 सालों की अवधि में एक भी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाना, सरकार की संविधान एवं सहकारी फेडरेशन के प्रति पूर्ण समर्पण का ज्वलंत उदाहरण है ।

हमारी सरकार ने कभी साहसिक फैसलों को लेने में कोई कोताही नहीं बरती । चाहे वह नोट बंदी का निर्णय हो अथवा कश्मीर से धारा 370 को हटाया जाना । हर क्षेत्र में हमारी सरकार नई नई उपलब्धियां हासिल कर रही है तथा बधाई की पात्र है ।

इस अवसर पर मैं अपने जलगांव संसदीय क्षेत्र की निम्नलिखित समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हुए अनुरोध करती हूं कि वह इन समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर इनके समाधान हेतु यथोचित एवं शीघ्र कार्यवाही करने हेतु कदम उठाए जाएं ।

मेरा जलगांव क्षेत्र कई दशकों से भयंकर पानी के संकट का सामना कर रहा है । इस समय भी हमारे जलगांव के छह तालुकों के 75 गांवों में टैंकरों से पेयजल आपूर्ति की जा रही है । जलगांव किसी भी तरह के उद्योग नहीं होने के कारण विकास के मामले में काफी पिछड़ गया है तथा यहां औद्योगीकरण को गति देने हेतु एक या दो बड़े उद्योग लगाये जाने की तत्काल आवश्यकता है । आम जनता की अपेक्षाओं के मद्देनजर जलगांव जिले में 100 बिस्तरों वाला एक नेचुरोपैथी अस्पताल स्थापित किया जाना चाहिए । जलगांव की पानी की समस्या के स्थायी

समाधान के लिए लगभग 25 साल पहले लोअर ताप्ती सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया था । परन्तु पैसे की कमी के कारण यह योजना विगत 25 सालों से अधूरी पड़ी हैं । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस योजना को प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई परियोजना के तहत स्वीकार कर उसके लिए आवश्यक धनराशि जारी की जाए तथा उस पर समयबद्ध ढंग से निर्माण कार्य पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि जलगांव की प्यासी जनता को पेयजल व सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो सके । जलगांव में बड़ी संख्या में प्लास्टिक इकाई हैं जो विभिन्न प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण करती हैं । यहां प्लास्टिक उद्योग के विकास हेतु एक प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाए । जलगांव में बड़ी संख्या में विद्यमान कताई मिलों के विकास तथा उससे जुड़े अन्य उद्योगों के विकास हेतु यहां एक टेक्सटाइल पार्क अथवा कलस्टर स्थापित किया जाए ताकि यहां आर्थिक विकास के साथ ही साथ नौजवानों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो । हमारे जलगांव जिले में केला, आम और संतरा प्रजाति के फलों का काफी बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है । अतः फल उत्पादक किसानों को उनके बेहतर कीमत सुनिश्चित करने तथा इनके प्रसंस्करण हेतु यहां प्रसंस्करण उद्योगों के साथ ही साथ एक आय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाए ताकि प्रसंस्करण हेतु लघु उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी आय के स्रोतों में वृद्धि के साथ ही साथ रोजगार के अवसरों में श्री वृद्धि हो ।

इन शब्दों के साथ मैं हमारे सहयोगी श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा पेश किए गए धन्यवाद् प्रस्ताव का तहेदिल से समर्थन करती हुं । धन्यवाद ।

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): Party Leadership *aur Kishanganj ke logon ka shukriya!*

This was my 8th election. It was not only the longest, *dukh ki baat hai ki bahut hi nichley star ka tha. Natija ? Jo 400 paar aur 370 paar kahte the, unko logon ney 240 paar tika diya.*

This election focused mainly on Muslim bashing.

DATE	NAME	TOWN	STATE	CATEGORY
7 Jun	Guddu Khan	Raipur	Chhattisgarh	Killed
7 Jun	Chand Miya Khan	Raipur	Chhattisgarh	Killed
7 Jun	Saddam Qureshi	Raipur	Chhattisgarh	Killed
14 Jun	Residents protested flat allocation to Muslim (Govt. Employee)	Vadodra	Gujarat	Hatred

16 Jun	Madrasa, Muslim properties attacked	Medak	Telangana	Riots
18 Jun	Aurangzeb	Aligarh	Uttar Pradesh	Killed
19 Jun	Javed	Nahan town	Himachal Pradesh	Looted
19 Jun	1800 structures razed, Basti	Akbarnagar	Uttar Pradesh	Bulldozed
22 Jun	Salman Vohra	Chikhodra	Gujarat	Killed
23 Jun	16 Muslim traders exodus	Nahan town	Himachal Pradesh	Exodus
27 Jun	12 Muslim houses bulldozed	Morena	Madhya Pradesh	Bulldozed
27 Jun	2 Mosques bulldozed	Mangolpuri	New Delhi	Bulldozed
29 Jun	Salman Vora	Chikhodra	Gujarat	Killed

There has been a total of eight lynching incidents after the results of the General Elections were announced on 4 June.

Twenty-three-year-old Salman Vohra, who had gone to watch a cricket tournament match in Chikhodra, Gujarat on 22 June, was mercilessly beaten to death by a group of men.

Three Muslim men, residents of Uttar Pradesh, were brutally attacked by a Hindutva mob in Chattisgarh's Raipur on 7 June. Saddam Qureshi and his cousin Chand Miya Khan (23), both from Saharanpur district, and Guddu Khan (35) from

Shamli district, were transporting cattle when they were allegedly chased by a mob in Raipur; two died on the spot, while one died after 10 days.

A 35-year-old Muslim man Aurangzeb alias Farid was beaten to death by a group of Hindu men in Aligarh late on Tuesday (June 18), leading to communal tension in the communally sensitive city of Aligarh in Western Uttar Pradesh. 10 days after lynching, he and eight others were booked on June 29 by the Aligarh police in Uttar Pradesh for dacoity.

On 24 June, a Christian woman was murdered in Toylanka village in Chhattisgarh's Dantewada after she and some of her family members had converted to Christianity. The brutal murder was operated and planned by the local Hindu men including family members, her relatives alleged.

2 Lynching over 'phone theft' suspicion in Kolkata- Two alleged incidents of lynching in Kolkata came into light in a span of 24 hours, one in the heart of the city and the other in the Salt Lake area. In the first incident, Irshad Alam, 37, was tied up and beaten to death at Bow Bazaar area, Central Kolkata, on June 28. The police arrested 14 persons in connection with this incident. Just 24 hours later, Prasen Mandal, 22, was lynched in the Salt Lake area.

Communal tensions gripped Telangana's Medak district where a clash erupted between two communities on 15 June over transportation of cows. The Hindu mob also carried out an attack on Minhaj ul Uloom madrasa and a local hospital in the district. Several locals who were inside the madrasa were injured in the attack and had to be taken to hospital.

In Balasore, a curfew was imposed for over a week after a communal scuffle that broke out on 17 June. It was relaxed only earlier this week. There was a confrontation between two groups over allegations of cow slaughter near a mausoleum near Patrapada area. After some locals noticed that water in the drain near the mausoleum turned red, they protested, claiming it was due to cow slaughter. Meanwhile, in Khordha, a Hindutva mob was seen entering Muslim houses, taking away freezers on suspicion of storing beef. They also allegedly vandalised the homes in the presence of the police.

Communal tension broke out in Jalori Gate area of Jodhpur, which led to stone pelting, leaving at least 16 people, including four policemen injured on June 22. The two sides clashed with each other over installing a religious flag in connection with Eid, police said. According to NDTV, a three-day Parshuram Jayanti festival is also

underway in Jodhpur and religious flags were put up by both communities, which led to an argument that spiraled into clashes.

On June 21st, communal violence reportedly took place in Jodhpur's Soor Sagar area. This has resulted in two police men being injured and 51 people arrested in the wake of the violence. A shop was also set on fire and two vehicles were damaged. The issue took place with relation to the construction of a gate near an Eidgah at Rajaram Circle of the city.

On 19 June, a mob looted and vandalized a textile shop belonging to Muslim man named Javed in Himachal Pradesh's Nahan. This was after he had reportedly shared a picture of animal sacrifice on his WhatsApp status. Following this, there were reports that due to the tense atmosphere and pressure from Hindutva groups, around 16 Muslim shopkeepers also left the town. A week Shamli police have arrested the shop owner Javed following an FIR against him in which he is accused of promoting enmity. Although police investigation later confirmed that Javed had not slaughtered a cow but it was a buffalo, which is legally permitted for slaughtering and consumption.

Several homes belonging to Muslims were demolished by authorities in Mandla, Madhya Pradesh allegedly on the pretext of possession of cow meat. However, the police claimed that the reason for the demolition was that the people's houses were built on Government land.

Authorities in Madhya Pradesh demolished the homes of four Muslim men just after detaining them on charges of throwing bovine remains at a temple in Jawra, Ratlam district, even as the Madhya Pradesh High Court was hearing a petition against the impending demolition drive, The administration issued demolition backdated notices dating June 14 on June 16 around 12:30 PM, and demolitions began shortly after. The court granted a stay order around 2:30 PM, but the houses had already been demolished between 12:30 PM and 1:30 PM.

Another large-scale demolition was carried out in Akbarnagar in Uttar Pradesh's Lucknow.

Three weeks after the election results, 13 cases of atrocities against Muslims happened in UP, MP, Gujarat, Himachal, Chhattisgarh and Telangana. Six Muslims were killed/lynched. Basti, Mosques and houses were bulldozed. This has been happening since last ten years of BJP Government. Multiple cases of killing/lynching have been there.

Masjid/Mazar/Madrasa/Kabristan/houses/shops/bastis have been bulldozed and destroyed. Waqf and Muslim properties have been taken away. Muslim journalists/activists have been sent to jail. This has to be stopped. There are 25 crore Muslims out of 140 crore population but only 24 Muslim MPs. There is not a single Muslim MP or Minister from NDA. It is not only sad but very shameful. I suggest, we need amendment to reserve at least 80 seats for Muslims as is the provision for SC/ST category.

AMU Centre was a gift to the people of Bihar Seemanchal to provide quality education to the most deprived people by the UPA Government in 2013. There are no funds. Also, no teaching/non-teaching staff has been provided yet after my multiple requests in the Parliament and despite meeting the Minister. Please do not deprive the people of Bihar their due. Is it because AMU *mein ?Muslim? likha hai?*

Every monsoon, hundreds of villages suffer. Thousands of acres of land is lost. Also, houses/roads/Mosques/graveyards are lost every year. We need a proper study and solution. One lakh crore is required for the development of Seemanchal in the next five years. Special status to Bihar and financial package is required. My demands are: Government Medical College in Kishanganj; AIIMS in Kishanganj; Dental College in Baisi; Engineering College in Thakurganj; Polytechnic College in Bahadurganj; Physiotherapy College in Amour; Law College in Terhagachh; Pharmacy College in Dighalbank; Agriculture College in Rauta; Job-related projects in my Constituency; Bridges on major rivers; Mahananda basin: Dredging of River, Concrete walls or boulder walls on both sides of the river; and Rejuvenation and beautification of Ramzan River after removal of encroachment as per 1902-03 survey.

श्री मितेश पटेल (बकाभाई) (आणंद) **:** मैं सबसे पहले 18 वीं लोक सभा अध्यक्ष को पदभार संभालने के लिए हार्दिक शुभकामनायें देना चाहता हूं ।

18 वीं लोक सभा के पहले संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुये भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने मोदी जी की नेतृत्व वाली भारत सरकार की 10 साल के उपलब्धियों और आने वाले समय में मोदी सरकार, भारत को विकसित बनाने के लिए किस दिशा में आगे बढ़ेगी देश की जनता के अपेक्षाओं को पूर्ण करने में किस तेजी से सक्रिय रहेगी उसके पक्ष में मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका देने के लिए कोटी कोटी धन्यवाद करता हूँ ।

महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण से स्पष्ट है कि पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी सरकार जी के नेतृत्व में भारत सरकार की नीतियों से अर्थव्यवस्था, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संसाधन, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास और सामाजिक कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में शानदार उपलब्धियों को प्राप्त किया है ।

स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष होने पर देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तो उसी समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने "अमृत काल" की संकल्पना रखी । उन्होंने बताया कि 2022 से 2047 तक जो कालखंड होगा वह भारत के लिए अमृतकाल होगा और भारत के अमृतकाल के संकल्प के तौर पर आदरणीय मोदी साहेब ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा । महामहिम के भाषण में जो उपलब्धियां गिनायी गयी हैं और आगे का जो रोडमैप दर्शाया गया है उससे भारत के 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का विश्वास दृढ़ होता है ।

युवा, किसान, गरीब, महिला इनके सशक्तिकरण के लिए मोदी जी की सरकार शुरू से ही प्रतिबद्ध रही है जिसके सुखद परिणाम निकल रहे हैं । देश के युवाओं की अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर देने के लिए सरकार एक डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में काम कर रही है । मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में उनके परिश्रम और प्रयासों से भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम बन चुका है । सरकार अर्थव्यवस्था के तीन स्तंभों विनिर्माण, सेवायें और कृषि को समान महत्व दे रही है । पी0 एल 0 आई योजनाओं और कारोबार में सुगमता उपायों ने बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसरों में वृद्धि में योगदान दिया है ।

सरकार के शुरुआत के दिन से ही किसानों को उनकी छोटी मोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीन लाख 20 हजार करोड़ रुपये की धनराशि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रदान की जा चुकी है । आज का भारत अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा है । सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नीतियां बना रही हैं । खरीफ फसलों के एमएसपी में रिकर्ड वृद्धि की है । किसान उत्पादक संगठनों एवं पैक्स जैसे सहकारी संगठनों का नेटवर्क बना रही है । भारत सरकार दलहन और तिलहन में दूसरे देशों की निर्भरता खत्म करने के लिए बड़ी कोशिश कर रही है । हरित रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु बड़े प्रयास किए जा रहे हैं । गांव में कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है । छोटे किसानों की बड़ी समस्या भंडारण से जुड़ी होती है । मोदी सरकार दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना पर काम शुरू कर चुकी है । पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं । इसमें एससी-एसटी हर क्षेत्र के लोग शामिल हैं । विशेषकर आदिवासी समाज में ये बदलाव और भी समझ में आ रहा है । 20 हजार करोड़ रुपये की योजना अति पिछड़े जानजातीय समूह के माध्यम बन रही है । नारी वंदन अधिनियम भारत सरकार के स्त्री नेत्रित्वित विकास और सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है । सरकार की योजनाओं में देश के गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसानों को अहम महत्व दिया जा रहा है । देश तभी विकास कर सकता है । इसीलिए सरकार की योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता इन्ही चार स्तंभों को दी जा रही है । 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का व्यापक अभियान चल रहा है । नमो ड्रोन दीदी योजना इस उद्देश्य में एक महत्वपूर्ण पहल है । पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ पीएम आवास घरों में बहुमती महिलाओं को आवंटित किए गए हैं । स्वयम सहायता समूहों से 30 हजार महिलाओं को कृषि सखी प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं । माननीय मोदी जी की कोशिश इनको हर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की है ।

आज मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता से उतरते हैं, भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकॉनमी है, भारत इतना बड़ा चुनाव निष्पक्षता, बिना बड़ी हिंसा और अराजकता से पूरा कराता है तो हमें गर्व होना स्वाभाविक है । 7 दशक तक वंशवाद के जकड़न में खुद को असहाय महशूस करने वाला भारत अब तेजी से विकास के पथ पर उन्मुक्त दौड़ रहा है ।

देश के हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम बन रहे हैं । भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुनिया में बेहतरीन हो इस मानदंड पर भारत काम कर रहा है । इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इस दिशा में बदलते भारत की योजना को दिखा रही है । गांव में 3 लाख 80 हजार किलोमीटर से ज्यादा सड़क बनाई है । आज भारत में नेशनल हाइवे का जाल बिछ रहा है । नेशनल हाईवे बनाने की गति में दोगुना वृद्धि हुई है । सरकार बुलेट ट्रेन के लिए पूर्वी, उत्तर भारत में फिजिबलिटी स्टडी शुरू कर चुकी है । आज हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी घरेलू विमानन बाजार बनकर उभरे हैं । आज भारत 2014 से पहले 209 से बढ़कर 2024 में 605 रूट्स तक पहुँच गया हैं ।

सरकार सार्वजनिक सेक्टर को भी मजबूत करने में जुटी है । आज भारत आईटी से लेकर हेल्थ सेक्टर में बड़ी शक्ति बन रहा है । इन सेक्टरों में रोजगार और स्व रोजगार के अवसर मिल रहे हैं । असम में 27 हजार करोड़ के निवेश से सेमी कंडक्टर प्लांट स्थापित किया जा रहा है इससे उत्तर पूर्व सेमी कंडक्टर का हब बनेगा । यह मेड इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देने की दृष्टि से मेल खाता है । वैश्विक महामारी के बाद भी और दुनिया के अलग-अलग देशों में चल रही मुश्किलों के बाद भारत ने ये विकास हासिल किया है । आज भारत अकेले ही दुनिया की अर्थव्यवस्था में 15 फीसदी का योगदान कर रही है । आज भारत को दुनिया को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने में मोदी जी की सरकार जी जान से जुटी है । लगातार तीसरी बार जनादेश देश को विकसित बनाने के लिए मिला है । राज्यों का विकास देश का विकास है और मोदी सरकार इसी भावना के साथ आगे बढ़ रही है । भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है । 10 साल में भारत 11 वें नंबर की अर्थव्यवस्था से उठकर 5 वें नंबर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचा है ।

25 जून 1975 को लागू हुआ आपात काल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था । तब पूरे देश में हाहाकार मच गया था । लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया । क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही हैं । राष्ट्रपति महोदया के भाषण में आपातकाल का जिक्र ये दर्शाता कि वर्तमान सरकार का नेतृत्व संविधान के प्रति श्रेष्ठ और गहरी श्रद्धा और सम्मान रखता है ।

1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद दंड की जगह न्याय को प्राथमिकता मिलेगी और न्याय प्रक्रिया में तेजी भी आएगी । ये कानून देश के न्यायिक प्रक्रिया में गेमचेंजर बनेंगे और जनता का भरोसा सरकार पर और दृढ़ होगा ।

जब किसी भी हवाई जहाज को उड़ान भरनी होती है तो रनवे पर हवाई जहाज धीमी गति से शुरू होकर गति पकड़ता है । जमीन छोडकर आसमान में उड़ने से पहले यानि टेक आफ के ठीक पहले हवाई जहाज की गति सबसे तेज होती है । यानी टेक आफ के ठीक पहले हवाई जहाज सबसे अधिक ताकत लगानी होती है तब जाकर वह आसमान में उड़ पाता है । एक देश के तौर पर भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में पिछले 10 सालों में रनवे पर गति पकड़ चुका है और तीसरा कार्यकाल अब देश के टेक आफ का है । नए भारत का यह टेक आफ विकसित भारत की तरफ होना है और ऐसे समय में देश को सबसे अधिक संगठित होकर अपने नेता के साथ खड़े होने की जरूरत है ।

अंत में कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने विकसित भारत कि जो गारंटी दी है महामहिम राष्ट्रपति महोदया के भाषण से उसके पूर्णता कि दिशा में भारत अग्रसर है इसका विश्वास दृढ़ होता है ।

श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर (दाहोद) **:** मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने एक बार फिर इतना उत्तम अभिभाषण दिया । नए सदन में, ये महामहिम राष्ट्रपति जी के कार्यकाल का ये तीसरा अभिभाषण है जो फिर एक बार पुरे देश में सकारात्मक संदेश लेकर के आया है, आशा की किरण लेकर आया

है, उमंग का आगाज लेकर के आया है और हम सबने जो विकसित भारत के सपने देखे है हम उसके आखिरी पायदान पर खड़े है ।

महामहिम राष्ट्रपति जी का ये अभिभाषण फिर से भारत के संविधान और दूर-सुदूर के किसानों, आदिवासियों, युवाओं एवं महिलाओं के साथ-साथ पूरे देश का सम्मान का भी अवसर है ।

महामहिम राष्ट्रपति जी को उदृबोधन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा सभी देश के नागरिको के किये विकास कार्यों की एक झलक दिखी है । मैं समझता हूँ कि पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी ऋणी है कि इतने कम समय में इतना विकास, जो पिछले कई दशकों में नहीं हो पाया । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के विजन और देश में बीते 10 साल की अवधि में हुए कामकाज का विस्तार से जिक्र किया ।

18 वीं लोक सभा शुरुआत में ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का पहला कार्य देश के किसानो के प्रति समर्पित है । पीएम किसान निधि की 17 वीं किस्त जारी कर दी है । इससे 9.3 करोड़ किसानों को फायदा हो रहा है । इस किस्त के तहत करीब 20,000 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में जारी किए गए । ये पहला क्रन्तिकारी कदम दर्शाता है कि मोदी 3.0 सरकार पूरी तरह किसान कल्याण के लिए समर्पित है । पदभार संभालने के बाद पहला फैसला किसानों के कल्याण के लिए किया गया है और आने वाले समय समय में किसानों और कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए और कदम उठाएंगे ।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देश के सभी किसानों को आर्थिक रूप से मदद करना है । भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित हैं । कई बार किसानों को खेती में नुकसान भी सहना पड़ता है और कृषि संबंधित कई सारी समस्याएं भी उनके सामने चुनौती बनकर आती है । इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है की देश के सभी छोटे एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान किया जायेगा, जिसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है । PM-Kisan योजना के माध्यम से किसानों को बेहतर आजीविका प्राप्त होगी साथ ही किसान इस योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन पाएंगे ।

पिछली बार मोदी 2.0 में सरकार द्वारा ध्यान रखा गया था कि खेती में लागत कम हो और लाभ अधिक है । 10 करोड़ से अधिक किसानों को देश की कृषि योजना में प्रमुखता दी है । पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मोदी 2.0 में ही 2 लाख 80 हजार करोड़ रुपये किसानों को मिल चुके थे । दो सालों में किसानों के लिए बैंक से आसान लोन में तीन गुना वृद्धि की गई है । पिछले 10 वर्षों में लगभग 18 लाख करोड़ रुपये एमएसपी के रूप में धान और गेहूं की खेती करने वाले किसानों को मिले हैं । किसानों को सस्ती खाद मिले इसके लिए 10 सालों में 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक रुपये खर्च किए गए ।

किसान हमारे 'अन्नदाता' हैं' । प्रत्येक वर्ष, पीएम-किसान सम्मान योजना के तहत सीधे 11.8 करोड़ किसानों को फाइनेंशियल सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें मार्जिनल और छोटे किसान शामिल हैं । पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल इंश्योरेंस दिया जाता है । इनके अलावा, कई अन्य कार्यक्रमों के अलावा, देश और विश्व के लिए भोजन बनाने में 'अन्नदाता' की सहायता कर रहे हैं ।

इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ने 1361 मंडी को एकीकृत किया है, और 3 लाख करोड़ की ट्रेडिंग मात्रा के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं प्रदान कर रहा है । यह क्षेत्र समावेशी, संतुलित, उच्च विकास और उत्पादकता के लिए तैयार है । ये किसान-केंद्रित पॉलिसी, आय सहायता, कीमत के माध्यम से जोखिमों के

कवरेज और 6 इंश्योरेंस सहायता, स्टार्ट-अप के माध्यम से प्रौद्योगिकियों और इनोवेशन को बढ़ावा देने में सुविधाजनक हैं ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए, जनता का विश्वास और मजबूत करने के लिए सभी दायित्व को निभाया जा रहा है । 25 करोड़ नागरिकों का गरीबी से बाहर निकलना एक नया विश्वास पैदा करता है कि हम भारतवासी बहुत जल्द ही गरीबी से मुक्त पाने में सफलता प्राप्त लेंगे और ये मानवजाति की बहुत बड़ी सेवा होगी । देश के लोग 140 करोड़ नागरिक परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखते हैं । मोदी 3.0 में हम उनके लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर जुटाएं । इसी एक कल्पना से हमारा ये सदन 18 वीं लोकसभा संकल्पों से भरी हुई हो, ताकि ये सपना जल्द पुरा हो सके ।

आज हमारे विशेषकर आदिवासी समाज में बहुत से बदलाव और भी स्पष्ट नज़र आ रहा है । आदिवासियों जीवन मोदी 1.0 बेहतर तो मोदी 2.0 में बेहतरीन और मेरी आशा और पूरी उम्मीद है मोदी 3.0 में बेहतरीन से भी बहुत बेहतर होगा ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अंतरिम बजट 2024-25 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को 13,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष में आवंटन से 70 प्रतिशत अधिक है । जनजातीय मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7,605 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे ।

सरकार ने 2024-25 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) के निर्माण के लिए 6,399 करोड़ रुपये रखे हैं, जो 2023-24 में इस उद्देश्य के लिए आवंटित 2,471.81 करोड़ रुपये से 150 प्रतिशत अधिक है ।

ईएमआरएस का उद्देश्य जनजातीय छात्रों को दूरदराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है, जिससे उन्हें सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों और नौकरियों में आरक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके, साथ ही गैर-एसटी आबादी के बराबर शिक्षा में सर्वोत्तम अवसरों तक पहुंच प्राप्त हो सके । प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के लिए आवंटन 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है ।

इस योजना के तहत, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, रोजगार-सह-आय सृजन जैसे क्षेत्रों में अंतर को पाटने के लिए जनजातीय लोगों के विकास और कल्याण के लिए अधिसूचित एसटी आबादी वाले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को धन प्रदान किया जाता है । आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 111 करोड़ रुपये कर दी गई है । हालांकि, 'एसटी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप और छात्रवृत्ति' के लिए बजट आवंटन 2023-24 में 230 करोड़ रुपये से घटाकर 2024-25 में 165 करोड़ रुपये कर दिया गया है ।

महामहिम ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया कि 25 जून, 1975 को लागू हुआ आपातकाल, संविधान पर सीधा हमला था और तब पूरे देश में हाहाकार मच गया था । लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही हैं । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार भारत के संविधान को जन-चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए मोदी जी प्रयास कर रहे हैं और हम भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पर निष्ठा रखते हैं, इसलिए उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस रूप में देखते है है । 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं । भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि जब भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था । संविधान के लरि- लीरा (अस्पष्ट) उड़ा दिए गए थे, देश को जेलखाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया

गया था । इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम भारतवासी गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि लोकतंत्र जीवंत रहे, हम संकल्प करेंगे, भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा करना ही हमारा लक्ष्य होगा ।

महामहिम ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया कि विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब देश के गरीब, युवा, नारीशक्ति और किसान सशक्त होंगे । युवा, गरीब, महिला व किसान को सुदृढ़ करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने इन चारों को विकसित भारत का स्तंभ माना है । और विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए हर कदम उठाने का प्रयास किया है । 1. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना । 2. सुकन्या समृद्धि योजना । 3. महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने से आर्थिक रूप से मजबूत होना । 4. महिला सम्मान बचत पत्र योजना के जरिए 2 लाख रुपये तक निवेश पर 7.5 फीसदी ब्याज मिलना । 5. ग्रामीण महिलाओं के लिए महिला शक्ति केंद्र स्कीम लाना । 6. मैटरनिटी लीव 12 की जगह 26 हफ्ते करना । 7. प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को बच्चे के जन्म पर 5000 रुपये देना । 8. मुस्लिम महिलाओं के लिए तीन तलाक पर कानूनी पाबंदी लाना । 9. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कलनेक्शन और सिलिंडर देना । 10. महिला ई-हाट स्कीम शुरू करना । 11. महिलाओं के लिए कई स्टार्टअप स्कीम । 12. महिला पोषण अभियान । 13. महिला हेल्पलाइन स्कीम योजना । 14. सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना । 15. फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत हर राज्य में सालाना 50 हजार से अधिक सिलाई मशीन फ्री में देना । 16. आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपये तक फ्री में इलाज । 17. वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम चालू करना । 18. वन स्टॉप सेंटर स्कीम, जिसके तहत हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सभी तरह की मदद एक ही छत के नीचे मिलना । 19. मातृत्व वंदन योजना के तहत गर्भ में बच्चों को पौष्टिक आहार योजना । 20. शिशु का जन्म अस्पताल में कराने का बड़ा अभियान चला । 21. बेटियां स्कूल न छोड़े, इसके लिए करोड़ों शौचालय बनाने का अभियान । 22. बेटियों के पानी देने के लिए हर घर पाइप से पानी देने का अभियान । 23. सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना । 24. पीएम आवास योजना के तहत बेटियों को संयुक्त भागीदारी का हक देना । 25. महिलाओं को बैंक से बिना गारंटी वाली मुद्रा योजना की शुरुआत । 26. इस साल लालकिले से 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने की योजना की शुरुआत । 27. सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को लोन देने की योजना की शुरुआत । 28. सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देना । इन जैसे महत्वपूर्ण कार्य और योजनाए महिलाओं की भलाई के लिए माननीय मोदी सरकार द्वारा पुरजोर तरीके किये जा रहे है ।

"भारत की युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है । हमारे युवा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रीय प्रगति में योगदान दे रहे हैं" । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी युवाओ भलाई के लिए

1. "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके अंतर्गत, सूक्ष्म व लघु उद्योग को बढ़ावा देने और ढेरों रोजगार पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की शुरूआत की । 7 अप्रैल 2015 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे गैर-बैंकिंग वित्त संस्थान के रूप में रजिस्टर्ड किया गया और इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया । इस योजना के तहत उद्योग शुरू करने के लिए सरकार 50 हजार से 10 लाख रुपये तक का लोन मुहैया कराती है ।

2. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस योजना के अंतर्गत युवाओं को कौशल विकास के जरिए फ्री ट्रेनिंग देकर उनको रोजगार के योग्य बनाना और आजीविका में वृद्धि करने का लक्ष्य है । इस योजना को प्रधानमंत्री यूथ

ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी शुरुआत जुलाई 2015 में हुई थी । इसके पहले चरण में तो करीब 19.86 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी गई ।

3. पीएम स्वनिधि योजना, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की भी शुरुआत की । स्ट्रीट वेंडर्स को स्वावलंबी बनाने, उनके रोजगार को बढ़ाने और उनकी आय में बढ़ोत्तरी के लिए मोदी सरकार ने साल 2020 में पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी, जिसमें बिना गारंटी और कम ब्याज दरों पर 10 हजार से 50 हजार रुपये तक का आसान लोन केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है ।

ऐसी ही लाभ प्रदान करने वाली अनेक योजनाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही ।

महामहिम ने अपने अभिभाषण में देश की रक्षा, विदेश और आर्थिक नीतियों का जिक्र किया । उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र करते हुए कहा, सरकार विधायिका में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र किया

उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा, 22 जनवरी को लंबी प्रतीक्षा के बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए । हमारी विरासत ऐसी हो, जिससे आने वाली पीढ़ियां हमें याद करें । राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी जो अब पूरी हुई है । बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह गत 22 जनवरी को हुआ । पीएम मोदी ने राम लला की उत्सव मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की । इस मौके पर देश-विदेश के लगभग आठ हजार मेहमान विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है । राष्ट्रपति जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार का जो मूल मंत्र है 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका प्रयास' को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार के द्वारा विभिन्न बुनियादी योजनाओं, सुविधाओं को गरीबो, किसानो और मजदूर तक की पहुंच में लाने के लिए एक ही मोटो, एक ही लक्ष्य और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी जो एक ही विचार है 'India First Citizen First' सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी पर अपने अभिभाषण के दौरान महामहिम राष्ट्रपति जी ने बताया की ऐसे क्षेत्र को भी पहली बार विकास से जोड़ा है जो दशकों दशकों तक उपेक्षित रहे हैं । हमारी सीमाओं से सटे गांव को अंतिम गांव कहा जाता था । मेरी सरकार ने उन्हें देश का पहला गांव बनाया है । इन गांव के विकास के लिए काफी काम किया है ।

अपने भाषण के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप का भी जिक्र किया । उन्होंने कहा कि ये द्वीप विकास से वंचित थे । हमारी सरकार ने इन द्वीपों में भी आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया है । वहां सड़क, हवाई यातायात और तेज इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई है ।

उन्होंने कहा कि दुनिया भर में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है और लगातार पिछली दो तिमाही में देश की विकास दर साढ़े सात प्रतिशत रही ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया और पहली बार आरक्षण की सुविधा दी गई है । मोदी जी की सरकार ने बाबा साहेब आंबडेकर से जुड़े 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि हमारे यहां विश्वकर्मा परिवारों के बिना दैनिक जीवन की कल्पना मुश्किल है । सरकार ने ऐसी विश्वकर्मा परिवारों की भी सुध ली है । पीएम विश्वकर्मा योजना से 84 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं ।

आदिवासियों के लिए मोदी सरकार की योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि मेरी सरकार ने उनकी भी सुध ली है जो अब तक विकास की धारा से दूर रहे हैं । ऐसे आदिवासी गांव हैं जहां पिछले 10 सालों में बिजली पहुंची हैं । उनको पाइप से पानी मिलना शुरू हुआ है । हजारों आदिवासी बहुल गांव में 4 जी नेट सुविधा पहुंचा रही है । जनजातियों में सबसे पिछड़े जनजातियों की सुध ली है । उनके लिए 26 हजार करोड़ रुपये की पीएम जनमन योजना बनाई है ।

अपने भाषण में किसानों का भी जिक्र किया । उन्होंने कहा कि उनकी देश में 15 नवंबर से विकसित भारत संपर्क यात्रा चल रही है अभी तक इस यात्रा से करीब 19 करोड़ देशवासी जुड़ चुके हैं । पिछले दो वर्षों में विश्व ने दो युद्ध देखे और कोरोना जैसी महामारी देखी । इसके बावजूद मेरी सरकार ने देश में महंगाई को काबू में रखा और सामान्य भारतीयों का बोझ नहीं बढ़ने दिया । 2014 से पहले के 10 वर्षों में औसत महंगाई दर 8 फीसदी से अधिक थी । पिछले दशकों में औसत महंगाई 5 प्रतिशत रही । मेरी सरकार का प्रयास रहा है कि सामान्य देशवासी की जेब में अधिक से अधिक बचत कैसे हो । पहले देशवासियों को 2 लाख रुपये की आय पर टैक्स लग जाता था । आज भारत में 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगता ।

साहिबजादों के बलिदान की स्मृति में 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' की घोषणा एवं 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' इसी सोच का परिचायक है । सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि स्वरूप, उनके जन्म-दिवस 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि आज देश के चार बेहद अहम स्तंभ हैं । उन्होंने कहा कि युवाशक्ति, नारीशक्ति, किसान और गरीब से ये देश खड़ा है । देश के हर समाज में इनकी स्थिति ऐसी ही है । इसलिए इन चार स्तंभों को ठीक करने के लिए हर स्तर पर काम कर रही है । 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्का घर मिला है ।

नल से जल योजना के तहत अभी तक 11 करोड़ ग्रामीणों को पाइप से पानी पहुंचा है । कोरोना काल से ही 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है । अब इसे आनेवाले 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है । इसपर 11 लाख करोड़ रुपये और खर्च होने का अनुमान है ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने डिजिटल इंडिया का जिक्र किया, भारत में बिजनेस करना आसान हो इसके लिए मेरी सरकार काम कर रही है । इज ऑफ डूइंग आसान हो रहा है । मेरी सरकार का एक और बड़ा रिफॉर्म डिजिटल इंडिया का निर्माण है । डिजिटल इंडिया ने भारत में बिजनेस को आसान बना दिया गया है ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि बैंकिंग सिस्टम जो पहले पूरी तरह से चरमरा गई थी वो आज दुनिया में सबसे मजबूत बना है । एनपीए जो पहले डबल डिजिट में होता था वो अब 4 फीसदी ही रह गया । कुछ साल पहले भारत खिलौना आयात करता था आज मेड इन इंडिया खिलौना निर्यात कर रहा है । भारत का डिफेंस प्रोजेक्ट एक लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है । लड़ाकू विमान तेजस अब हमारी वायुसेना की ताकत बन रहा है ।

औपनिवेशिक आपराधिक कानूनों के स्थान पर नए कानून बनाए जाने, नारी वंदन अधिनियम और सरकार के कई अन्य कदमों का उल्लेख किया । उन्होंने तीन दशक बाद नारी शक्ति वंदन विधेयक पास करने के लिए सबकी

सराहना की और कहा, "मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करने के लिए सदस्यों का अभिवादन करती हूं । यह मेरी सरकार के महिला नीत विकास के संकल्प को मजबूत करता है । इससे लोक सभा और विधानसभा में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित हुई है । इस संसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था । 26 जनवरी को भी हमने देखा किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति के सामर्थ्य-शौर्य को अनुभव किया ।

आईपीसी अब इतिहास हो गया है । अब दंड को नहीं बल्कि न्याय को प्राथमिकता है । देश को न्याय संहिता मिली है । अब दंड को नहीं न्याय की प्राथमिकता, न्याय संहिता देश को मिली है ।

बीते 12 महीनों में मेरी सरकार अनेक महत्वपूर्ण विधेयक लेकर भी आई । ये विधेयक, आप सभी संसद सदस्यों के सहयोग से आज कानून बन चुके हैं । ये ऐसे कानून है जो विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का मजबूत आधार हैं । 3 दशक बाद, नारी शक्ति बंदन अधिनियम पारित करने के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं । इससे लोक सभा और विधानसभा में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित हुई है । यह वीमेन लेड डेवलपमेंट के मेरी सरकार के संकल्प को मजबूत करता है । रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने कमिटमेंट को मेरी सरकार ने लगातार जारी रखा है । गुलामी के कालखंड से प्रेरित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब इतिहास हो गया है । अब दंड को नहीं, अपितु न्याय को प्राथमिकता है । 'न्याय सर्वोपरि' के सिद्धांत पर नई न्याय संहिता देश को मिली है । डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम से डिजिटल स्पेस और सुरक्षित होने वाला है । अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम से देश में रिसर्च और इनोवेशन को बल मिलेगा । जम्मू और कश्मीर आरक्षण कानून से, वहां भी जनजातीय समुदायों को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलेगा । इस दौरान सेंट्रल यूनिवर्सिटी कानून में भी संशोधन किया गया । इससे तेलंगाना में समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का रास्ता सुगम हुआ । पिछले वर्ष 76 अन्य पुराने कानूनों को भी हटाया गया है । मेरी सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंता से अवगत है । इसलिए ऐसे गलत तरीकों पर सख्ती के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया गया है ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने बताया कि बीता वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है । इस दौरान देशवासियों के गौरव बढ़ाने वाले अनेक पल आए । दुनिया में भारत सबसे अधिक तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था बना है । ऐतिहासिक जी-20 सम्मेलन की सफलता ने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ा था । मिशन आदित्य को लॉन्च किया । भारत को सबसे बड़ा अपना समुद्री पुल अटल सेतु मिला ।

केंद्र की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति बोलीं कि 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' को सरकार ने लगातार जारी रखा है । उन्होंने इस दौरान महिला आरक्षण कानून पारित होने का उल्लेख भी किया और कहा, "मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करने के लिए सदस्यों का अभिवादन करती हूं । यह मेरी सरकार के महिला नीत विकास के संकल्प को मजबूत करता है ।"

ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा साल 2023, नया संसद भवन भारत की ध्येय यात्रा को ऊर्जा देता रहेगा; यहां नई और स्वस्थ परंपराओं की शुरुआत का भरोसा । नई संसद भवन से एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर झंडा फहराने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत, मिशन मोड में सरकारी नौकरियां देना बड़ी उपलब्धि । भारत में जी-20 देशों के सम्मेलन का सफल आयोजन । देश के करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी रेखा से ऊपर निकले । भारत दुनिया की 5 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही हम तीसरी पायदान पर आने वाले है देश में स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर एक लाख के आंकड़े से भी आगे निकली देश में मोबाइल मैनुफैक्चरिंग में पांच गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई । डिजिटल इंडिया से बड़ा बदलाव, यूपीआई से 18 लाख

करोड़ रुपये का रिकॉर्ड लेन-देन । खेती को किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाने पर जोर । पहली बार कृषि निर्यात की नीति बनाई गई, देशभर में 1300 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है । स्थानीय सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखेगी । सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना लागू की गई । सरकार रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के लिए कटिबद्ध ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय नीतियां जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के द्वारा लाई गई है, गरीबों के लिए सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई है उन पर भी प्रकाश डाला है । यह हमारे संविधान के लागू होने का भी 75 वां वर्ष है । इसी कालखंड में आज़ादी के 75 वर्ष का उत्सव, अमृत महोत्सव भी संपन्न हुआ है ।इस दौरान देश भर में अनेक कार्यक्रम हुए ।देश ने अपने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया । 75 साल बाद युवा पीढ़ी ने फिर स्वतन्त्रता संग्राम के उस कालखंड को जिया । प्रधानमंत्री जी का ये कार्यकाल देश भर में एक उत्सव की तरह मनाया गया । हाल में हुए अमृत महोत्सव के दौरान ही कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई । राजधानी दिल्ली में देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित म्यूजियम खोला गया । शांति निकेतन और होयसला मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुए । साहिबज़ादों की याद में वीर बाल दिवस घोषित हुआ । भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया । विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया गया । मेरी माटी, मेरा देश अभियान के तहत, देश भर के हर गाँव की मिट्टी के साथ अमृत कलश दिल्ली लाए गए । 2 लाख से ज्यादा शिला-फलकम स्थापित किए गए । 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पंच प्राण की शपथ ली । 70 हजार से ज्यादा अमृत सरोवर बने । 2 लाख से ज्यादा अमृत वाटिकाओं का निर्माण हुआ । 2 करोड़ से ज्यादा पेड़-पौधे लगाए गए । 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड की ।

राष्ट्रपति जी ने कहा कि भारत ने बीते एक दशक के दौरान वैश्विक विवादों और संघर्षों के इस दौर में भी, अपने हितों को मजबूती से दुनिया के सामने रखा है । उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 में आजादी की 100 वीं वर्षगांठ को देखने के लिए अनेक साथी इस सदन में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन हमारी विरासत ऐसी होनी चाहिए कि तब की पीढ़ी हमें याद करे ।

अमृतकाल के आगामी 25 वर्ष का कालखंड, स्वतन्त्रता की स्वर्णिम शताब्दी का, और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड के रूप में प्रकाश डाला है जिसमे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्यों की पराकाष्ठा करके दिखाने और एक नव युग निर्माण के अवसर को देखा जाएगा जिससे 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण होना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा होगा और आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय होगा । प्रधानमंत्री जी द्वारा एक ऐसा भारत बनाने की कौशिश की जा रही है, जो आत्मनिर्भर हो और जो अपने मानवीय दायित्वों को पूरा करने के लिए भी समर्थ होगा, ऐसा भारत - जिसमें गरीबी न हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त होगा, ऐसा भारत - जिसकी युवाशक्ति और नारीशक्ति, समाज और राष्ट्र को नई दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़ी हो, जिसके युवा समय से दो कदम आगे चलेंगे, ऐसा भारत - जिसकी विविधता और अधिक उज्ज्वल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल होगी ।

अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की आकांक्षा को जगाया है । जो विकास के लाभ से सबसे अधिक वंचित था । अब जब मूल सुविधाएं इस वर्ग तक पहुंच रही हैं, अब ये लोग नए सपने देखने में सक्षम हो पा रहे हैं । अनुसूचित जाति के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए डॉक्टर आंबेडकर उत्सव धाम, अमृत जलधारा और युवा उद्यमी योजना जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । आदिवासी गौरव के लिए तो सरकार ने अभूतपूर्व फैसले किए हैं । पहली बार देश ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के

रूप में मनाना शुरु किया । हाल में ही मानगढ़ धाम में सरकार ने आदिवासी क्रांतिवीरों को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर श्रद्धांजलि दी । आज 36 हज़ार से अधिक आदिवासी बाहुल्य वाले गांवों को प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत विकसित किया जा रहा है । आज देश में 400 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल आदिवासी क्षेत्रों में खुल चुके हैं । देशभर में तीन हज़ार से अधिक वनधन विकास केंद्र आजीविका के नए साधन बने हैं । सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर O.B.C. के welfare के लिए प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है । बंजारा, घुमंतू, अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए भी पहली बार Welfare and Development Board का गठन किया गया है ।

देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण पूरे कर अमृतकाल में प्रवेश किया । अमृत काल के 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता की स्वर्णिम शताब्दी और विकसित भारत के निर्माण का वक्त है । अमृत महोत्सव में तमाम महापुरुष जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन लगा दिया ऐसे महापुरुषों को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया है ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने कामना की है कि देश का हर नागरिक मानवीय दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम हो । गरीबी न हो, मध्यम वर्ग वैभव से युक्त हो । युवा समय से दो कदम आगे चलते हों, भारत ऐसा हो कि जिसकी विविधता और उज्ज्वल और एकता और ज्यादा अटल हो ।

जनकल्याण की ये जितनी भी योजनाएं हैं, ये सिर्फ सुविधाएं भर नहीं हैं । इनका देश के नागरिकों के पूरे जीवन-चक्र पर सकारात्मक असर पड़ रहा है । विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा, मेरी सरकार की योजनाओं के प्रभावों का अध्ययन किया गया है । इनके परिणाम बहुत ही प्रभावकारी हैं और गरीबी से लड़ रहे दुनिया के हर देश को प्रेरित करने वाले हैं । बीते वर्षों में विभिन्न संस्थाओं के अध्ययन में सामने आया है कि 11 करोड़ शौचालयों के निर्माण और खुले में शौच बंद होने से, अनेक बीमारियों की रोकथाम हुई है । इससे शहरी क्षेत्र के हर गरीब परिवार को इलाज पर प्रति वर्ष 60 हजार रुपए तक की बचत हो रही है । प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की वजह से आज देश में शत- प्रतिशत संस्थागत प्रसव हो रहे हैं । इस वजह से माता मृत्यु दर में भी भारी गिरावट आई है । एक और अध्ययन के अनुसार, उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवारों में, गंभीर बीमारी की घटनाओं में कमी आई है ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की तारीफ की और कहा कि कोरोनाकाल में सरकार भारत के नागरिकों को गरीबी रेखा के नीचे जाने से बचाने में सफल हुई है और शॉर्टकट की राजनीति से बचने और एक स्थायी समाधान पेश करने कि सलाह दी जिससे सामान्य जनों की समस्याओं का हल हो । मोदी जी की सरकार में गरीबी हटाओ अब केवल नारा नहीं रह गया है बल्कि सरकार हर किसी को सशक्त बनाने का काम कर रही है । महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि कोरोनाकाल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की तारीफ की कि सरकार ने देशहित को सर्वोपरि रखा है । नीति और फैसलों में इच्छाशक्ति दिखाई है । सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर जवाबी कार्रवाई तक, एलओसी से लेकर एलएसी तक सरकार ने हर तरफ काम किया है ।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने 370 से लेकर तीन तलाक तक हर तरफ काम किया है । आज दुनिया के कई देश संकट से घिरे हैं, लेकिन मोदी जी की सरकार ने जो भी निर्णय लिए, उनकी वजह से भारत की स्थिति उन देशों से अलग है ।

माननीय मोदी जी नेतृत्व वाली सरकार देश में ईमानदारी का पालन करने वाली सरकार है और देश में गरीबी के स्थायी समाधान और उनके स्थायी सशक्तीकरण के लिए काम कर रही है । ये सरकार जनकल्याण को सर्वोपरि

रखने वाली सरकार है । देश में प्रगति के साथ ही प्रकृति को संभालते हुए विरासत के संरक्षण के साथ आधुनिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने विरासत को मजबूती देने और विकास को प्राथमिकता देने की राह चुनी है । एक तरफ देश में अयोध्या धाम का निर्माण हो रहा है और दूसरी तरफ आधुनिक संसद भवन भी बन रहा है । केदारनाथ, काशी विश्वनाथ और महाकाल लोक का निर्माण किया तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं ।

तीर्थों का विकास कर रहे हैं तो भारत दुनिया की बड़ी स्पेस पावर भी बन रहा है । भारत ने पहला प्राइवेट सैटेलाइट भी लॉन्च किया है । एक तरफ आदि शंकराचार्य, बसवेश्वर जैसे संतों के दिखाए रास्ते पर बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ भारत हाईटेक नॉलेज का हब बन रहा है ।

भारत प्राकृतिक खेती की मिलेट्स की परंपरागत फसलों को बढ़ा रहा है । नैनो यूरिया जैसी टेक्नोलॉजी का विकास भी किया । खेती के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सोलर पावर से किसान को ताकत दे रहे हैं । गांव के घरों की ड्रोन से मैपिंग की जा रही है । सैकड़ों आधुनिक वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च की जा रही हैं । नदी-जलमार्ग और बंदरगाहों को भी आधुनिक बनाया जा रहा है ।

मैं पुनः एक बार महामहिम राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करते हुए, उनके अभिभाषण का समर्थन करता हूं और साथ ही मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार तथा पुनः दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के लिए बधाई देता हूँ ।

डॉ. लता वानखेड़े (सागर) **:** मैं सागर लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं जो बुंदेलखंड के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में से एक है । इस क्षेत्र में एक उद्योग चलता है जो बीड़ी उद्योग कहलाता है जिसमें गरीब और गरीब अमीर और अमीर बनता जा रहा है महिलाएं बीड़ी बनाकर घर चलाती हैं । तंबाकू की धस से बड़ी गंभीर बीमारी का शिकार होती थी । इस क्षेत्र में सर्वाधिक आबादी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों की है जिसका मुख्य धंधा कृषि है क्योंकि इस क्षेत्र की जनता अपना पेट भरने के लिए बीड़ी बनाने पर मजबूर थी किंतु विगत वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और मध्य प्रदेश में आने के बाद स्थितियों में सुधार हुआ है । देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश को तब के मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री का विभाग संभाल रहे मान्यवर शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई हेतु अनेकों बाँध तथा बीना परियोजना ?घसान केन सिंचाई परियोजना? प्रारंभ की है जिससे सिंचाई के रकबे में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है । आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेई जी की सुविचारित ?नदी जोड़ो योजना? के अंतर्गत समूचे देश में पहली बड़ी योजना ?केन-बेतवा लिंक परियोजना? भी इस सरकार के कार्यकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से स्वरूप ले रही है । इन सब के परिणाम स्वरुप समूचे बुंदेलखंड और विशेष कर सागर लोकसभा क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लक्षित हो रहे हैं ।

अभी हाल के निर्वाचन (लोक सभा) में पूरे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में अपनी आस्था जताते हुए तीसरी बार का जनादेश दिया है । उसके चंद दिनों बाद ही माननीय कृषि मंत्री जी मंत्रालय संभालते हुए अपनी पहली ही घोषणा में ?महिला सशक्तिकरण? पर जोर देते हुए ?कृषि मित्र सखी योजना? लागू करने की घोषणा की है जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में, विशेष कर पिछड़े हुए कृषि क्षेत्र में महिलाओं की

आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा । इस योजना के माध्यम से देश के तीन करोड़ महिलाओं को जो दुर्गम पिछड़े क्षेत्रों में निवास कर रही हैं उन्हें ?लखपति दीदी योजना? एवं ?कृषि मित्र सखी योजना ?के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त समर्थ और स्वावलंबी बनाने तथा सामाजिक रूप से बराबरी पर लाने में क्रांतिकारी कदमसाबित होगा । इस महान देश की वर्तमान प्रथम आदिवासी महिला महामहिम राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के सारगर्भित, बहुउद्देशीय, विकास परक अभिभाषण का मैं हृदय से समर्थन करती हूं और उनके प्रति ससम्मान आभार व धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ ।

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): I would like to congratulate my fellow Parliamentarians for getting elected to this august House and securing an opportunity to represent the will of 1.4 billion Indians. I am also congratulating the council of ministers for forming the Government. The Hon'ble President has addressed the House, outlining the policy priorities of the new Government. In many ways, we were hopeful that the address would be a reassurance to the people of India. Especially when they have given a strong message to the ruling party that is led by the Prime Minister. The people have categorically stated that they are not happy with the way activities of the Government were carried out.

The ruling party lost 63 seats in this House, falling short of the majority mark by 32 seats. The Prime Minister passed with a very small margin - in fact, the smallest for any Prime Ministerial Candidate since independence. The Government hangs by a tiny thread - on the Support of its coalition partners. The people have clearly communicated a message that they are not happy with the way power was concentrated and democracy sabotaged by the previous Government.

The previous Government went to elections seeking a mandate to continue their agenda. The past ten years were by no means the best years of our democracy. All institutions that held our democracy together was systematically assaulted. Even our esteemed Parliament was not allowed to function properly. The unprecedented suspension of 146 Members of Parliament in December 2023 gave an impression that we are going through an undeclared emergency. Last week, we were discussing the emergency that happened 49 years ago. Need of the hour is that we investigate the undeclared emergency that is going on today. Two opposition Chief Ministers are in jail with no evidence against them. Shri Hemant Soren secured bail two days ago and he was behind the bars for weeks without any evidence against him.

The Presidential Address should have addressed the concerns of the people regarding the situation of our country. Crores of students are going through great

uncertainty due to question paper leaks and malpractices in all prestigious examinations of our country like NEET-UG, NET and NEET-PG. Examinations are cancelled without any notice and question papers and seats are sold for lakhs of rupees. There is absolutely no faith in the system. This has led to young people leaving our country in hoards. When they go to the airport for that, they see that even airports are collapsing over their heads! The infrastructure built by the last Government is shaky, and there is no guarantee that an Indian could reach home safely after going out for work in the morning. Only a few weeks ago, many people died in a hoarding collapse in Mumbai. The great loss of human life in Morbi, Gujarat went unpunished. The airport we all use - Delhi Indira Gandhi Airport also saw a mishap just a few days ago, claiming four precious lives. The utter incompetence and callousness of this Government is brought to the forefront, but there is no mention of all those.

The outgoing Government had a record of giving ?guarantees? to the people with no intention of fulfilling them. First, there was a guarantee that petrol price will become Fifty Rupees if the Prime Minister is voted to power. We know what happened. Then, there was a promise of Rupees fifteen lakhs being deposited in every Indian?s account. We know what happened. There was a guarantee of ?Make in India?, but it failed spectacularly because there was no broad-based consultation. The youth of our country is struggling to find a job, yet the announced policies of Start up India, Stand up India, Job in India - all have failed miserably. The nation has still not recovered from the misadventure of Demonetisation, faulty GST implementation, CAA-NRC, failed farm laws etc. The list is very big, l may need an entire session to list out the failures of the previous Government's guarantees.

Despite all these failed guarantees, now they are giving a new set of guarantees. People of India are certain that these will fail too. The Presidential Address could have mentioned solid steps to build the confidence of people. None was found there. Whatever policies that are outlined have no mention of how it will solve the problems that India is facing in the 21st century.

The policies outlined fail to address the concerns of the people. Climate Change is causing great distress to all people, especially our farmers. Last summer alone, drought and wild animal attacks led to a loss of more than 250 crores in the Idukki district in my Constituency. There is no support to farmers in the form of Minimum Support Price to spices like Cardamom. Procurement systems have failed. The

Government had greatly publicised the PM Krishi Sampada Yojana as a means to promote Food Processing Industries. However, actual progress on ground is close to zero - no farmers have been benefited through increased food processing. The focus of this Government is more on publicity than actually solving issues on the ground. The Presidential Address has failed to address this concern.

The safety and security of women and girl children is a matter very close to our hearts. In the last two days, two brutal murders have surfaced - of girls aged 10 and 16 years old. The complete failure of law and order in many states has a direct bearing in the policy and messaging of the Central Government. The ruling party has a long history of defending sexual offenders. The way our medal winning female wrestlers were treated is a testimony to this.

The Presidential address should have echoed this concern and reiterated a commitment to solving this issue. It is unfortunate that no concrete action was declared for this.

The last years have seen rising attacks against the members of minority communities across the country. The ruling party nurtures a cottage industry of hatred, that creates false narratives and discontent against the minorities. They create narratives that are used to justify violence against the minority communities. The violence in Manipur is one example, but many Muslims were lynched and their houses demolished in the last a few days after the elections. This is only a side effect of the divisive agenda taken forward by the ruling party led by the Prime Minister. I am ashamed to repeat the kind of words used by the Prime Minister during the election Campaign. His party lost in the majority of constituencies where he gave inflammatory Speeches. The people have categorically rejected the communal agenda of the ruling party. The Presidential Address should have reiterated the commitment of this Government to uphold and protect the secular ideals enshrined in the constitution.

Considering all these, I would like to mention that the Government has failed to reflect the concerns of the people of India. It has failed to address the issues faced by the people. The Presidential Address doesn't reflect the solutions that India needs urgently. I urge to vote against the motion of thanks so that the Government may be forced to initiate policy that is in the best interest of the People of India.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) **:** मुझे 18 वीं लोक सभा के पहले सत्र में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में अपने विचार व्यक्त करने का मौका देने के लिए धन्यवाद ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के 23 वें खण्ड में विशेष रूप से नालंदा यूनिवर्विटी के नये कैम्पस की चर्चा की है, इसके लिए मैं नालंदा के सांसद के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ । 19 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी नालंदा में नई नालंदा यूनिवर्सिटी कैम्पस का उद्घाटन किए हैं । नालंदा प्राचीनकाल से ही ऐतिहासिक ज्ञान की नगरी है । नालंदा का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है । तक्षशिला के बाद नालंदा दुनियां का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था और आवासीय परिसर के तौर पर पहला विश्वविद्यालय है । यह भी महत्वपूर्ण बात है कि विश्व के कोने-कोने से विद्यार्थियों को नालंदा में निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी । 450 ई. में स्थापना के बाद करीब 800 वर्षों तक नालंदा यूनिवर्सिटी अस्तित्व में रहा । आज भी इस विश्व प्रसिद्ध नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय का मात्र 10 प्रतिशत भाग जो कि खण्डहर के रूप में करीब 1 लाख 95 हजार वर्ग गज में अवस्थित है, जिसे देखने और रिसर्च करने के लिए विश्व भर से रिसचर्स, स्कालर्स और शैलानियों का लगातार आना लगा रहता है ।

हमारे नेता और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा राज्य सरकार अपने संसाधन से 25 नवम्बर, 2010 को ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर में स्थापित किया गया है और इसी संस्थान को आगे बढ़ाते हुए 19 जून, 2024 को नये कैम्पस का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है । आशा है कि भविष्य में नालंदा यूनिवर्सिटी, भारत को विश्व पटल पर नॉलेज हब बनाने में मददगार सिद्ध होगा । भारत को वैश्विक ज्ञान के केन्द्र के रूप में भारत के गौरवशाली अतीत को प्रमाणित करने का काम करेगा ।

जिस प्रकार प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना काल के बाद गुप्त शासक के उत्तराधिकारियों एवं आगे के शासक वंशों के साथ-साथ विदेशी शासकों से विश्वविद्यालय के समृद्धि में योगदान, संरक्षण और अनुदान मिलता था । उसी प्रकार मेरी आशा है कि केन्द्र सरकार भी नव नालंदा यूनिवर्सिटी को पूर्ण आर्थिक सहयोग, संरक्षण और सहायता देने का काम करती रहेगी ।

अब मैं बिहार राज्य की बात करना चाहता हूँ । बिहार राज्य विकास की दौर में अन्य राज्यों से काफी पिछड़ गया है । आज देश में आर्थिक प्रगति काफी तेजी से हो रही है । सरकार को आशा है कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने वाला है । वर्तमान में भारत जीडीपी रैंक के अनुसार 5 वीं रैंक पर है और 2024 का अनुमानित जीडीपी 8.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है । देश के विकास में बिहार राज्य का योगदान भी काफी अहम स्थान रखता है । वर्ष, 2022-23 में बिहार का ग्रोथ रेट 10.98 प्रतिशत रहा है, किन्तु आज बिहार राज्य नीति आयोग के मानकों के अनुसार देश का सबसे पिछड़ा राज्य कहलाता है । बिहार के विभाजन के बाद राज्य के सभी प्राकृतिक संसाधन, उद्योग धंधे आदि झारखण्ड राज्य के हिस्से में चला गया । बिहार को मात्र बाढ़ और सुखाड़ ही मिला । संसाधन सीमित हो गये और प्राकृतिक आपदायें प्रतिवर्ष बिहार के ग्रोथ पर चोट करता आ रहा है । जिसका परिणाम है कि राज्य विकास की दौर में पिछड़ता ही चला गया ।

हमारे माननीय नेता और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी करीब दो दशकों से राज्य के सीमित संसाधन से ही विकास की हर संभव कोशिश करते आ रहे हैं किन्तु केन्द्र सरकार से अपेक्षित आर्थिक सहयोग नहीं मिला । उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि केन्द्र सरकार से बिहार राज्य को अनुदान के रूप में वर्ष, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में क्रमशः 29,026 करोड़, 54,775 करोड़ और 52,161 करोड़ मात्र बिहार राज्य मिला है । इसी सब परिस्थितियों में राज्य सरकार वर्ष, 2005 से लगातार बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की माँग करता आ रही है ।

जिस प्रकार अब तक अन्य राज्यों को स्पेशल स्टेटस देने से वहाँ की आर्थिक तरक्की और प्रगति देखने को मिली है । अगर बिहार को भी यह मिल जाता है तो राज्य कम समय में देश के अन्य विकसित राज्यों के समकक्ष आ

सकता है । राज्य में औद्योगिकरण होगा । वहाँ उद्योगों को करों में अधिक छूट मिलेगी, जैसे अन्य राज्यों को अभी मिल रही है । यह वहाँ राजस्व के साथ-साथ युवाओं को भी रोजगार के अवसर प्रदान करेगा । बिहार में आर्थिक प्रगति होगी । पर-कैपिटा इनकम में बढ़ोत्तरी होगी जो अभी निचले स्तर पर है । आशा है केन्द्र सरकार बिहार राज्य के सबसे पुरानी और राज्य के हितों की रक्षा के लिए स्पेशल स्टेटस की घोषणा आने वाली पहली बजट में करने का काम करेगी ।

बिहार राज्य अपने संसाधन और खर्च से पिछले वर्ष, 2023 में जातिगत, आर्थिक और समाजिक आधार को लेकर गणना कराने का काम कर चुकी है । यह गणना प्रकाशित भी हो चुका है । इस गणना से राज्य को अपने नागरिकों के लिए योजनाओं को बनाते समय सभी की तरक्की और भलाई को ध्यान में रखने के लिए एक तथ्यात्मक आधार उपलब्ध है । अतः मेरी पार्टी जेडीयू का आग्रह है कि केन्द्र सरकार अगले जनगणना में बिहार सरकार के तर्ज पर ही देश में जनगणना कराने का आग्रह करती है । यह जनगणना महिला आरक्षण कानून को भी लागू करने में सहायक सिद्ध होगा । मेरा मानना है कि समय पर महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए सरकार सभी सार्थक कदम उठायेगी ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने 10 वें खण्ड में उल्लेख किया है कि देश में शहरों को दुनिया के बेहतरीन लिविंग स्पेस बनाने के लिए प्रतिबद्ध है । उसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं । उन्हीं 100 शहरों में बिहार राज्य के चार शहर हैं और मेरा संसदीय क्षेत्र का बिहार शरीफ भी शामिल है । एनडीए सरकार जल्द से जल्द इन सभी शहरों को पूर्णरूपेण कार्य पूरा कराकर 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के सभी मापदण्डों को जमीन पर उतारने का काम करेगी । मैं अपनी बातें समाप्त करते हुए माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के 14 वें खण्ड में उल्लेख किए गये हैं कि विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है, जब देश के गरीब, युवा, नारी-शक्ति और किसान सशक्त होंगे तभी देश विकसित होगा । यही प्रतिबद्धता एनडीए सरकार की है और आगे भी देश को गरीबी से मुक्ति, किसानों की आर्थिक प्रगति और उनके फसल का उचित मूल्य मिले । देश में युवाओं को रोजगार मिले, समय से मिले । तभी देश की आर्थिक प्रगति होगी और आम नागरिकों की खुशहाली होगी । पिछड़े पायदान पर रह रहे नागरिकों को देश की प्रगति के लाभ का कुछ हिस्सा मिलेगा । मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ । धन्यवाद ।

SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD): I thank you very much for giving me an opportunity to express my views on motion of thanks on the Hon?ble President's address. The Constitution provided by Dr.Baba Saheb Ambedkar is not merely a book, it is a guiding tool or principle for every Indian and the Government of the country. For the last nearly a decade we have been witnessing our constitutional agencies have been largely used with an angle of political interest, disrespecting their values and deviating from the very principle for which they were created by our predecessors.

The people of the country largely fear that there is a move to deviate from the very laid down principle of our constitution and the people have reacted Strongly against it through their votes. Abiding Constitution and respect its ideals and institutions are Paramount important for every Indian. The very idea of any

Government is to ensure equal distribution and opportunities for its citizens and the benefit and fruit of development should reach to everyone. But in our country, it is not actually happening and a larger section of our population is neglected and deprived of the above.' Therefore, to ensure equal distribution and opportunities for every citizen, the cast census should be undertaken, so that the share of development and opportunities can be given according to their strength. Many States wanted to have a caste census and some States have already initiated Steps in this regard.

The country becoming a developed nation is a dream of every Indian and they work for it. But when our Government could not conduct an important examination i.e. National Eligibility-Cum-Entrance Test (NEET) being conducted by National Testing Agency concerning the health of the people of our nation as the Papers of the current NEET examination were leaked and more than 24 lakh students future was affected, It is a matter of share. These youths were trying and working on this examination for years. But the leakage has shuttered their hope. Sir, this is not happening for the first time, during the last seven years 70 papers have been leaked and more than 2 crores students were affected. Can't this country conduct a fair examination? Slogan shouting and putting things into perfect are totally different and l think this Government believes in Slogan shouting rather than taking the country into a right path. The failure or leakage of NEET examination papers is a testimony to it.

Unemployment is a big issue the nation is facing. The unemployment level has surpassed all previous records and the youths of our country are losing hope even after attaining higher degrees or qualifications. The unemployment projected to reach 8.3% in 2024 in February this year it has already reached 8.1%. It is predicted to rise in the next few years. The wrong implementation of Goods & Services Tax and demonetization forced closure of job generating avenues which made our youths to roam here and there in search of jobs But in this address, it is saying nothing on the creation of jobs. India is considered as a nation of youths, and if their hope is shattered, mere slogan shouting will not work. Instead of providing 2 crore jobs as guaranteed by the Government, the Government snatched employment opportunities of the youths of the country by following wrong policies and decisions. There are nearly 10,00,000 posts vacant in Central Government Departments. Merely distributing appointment or offer letters to a few thousands of job seekers is of no solution when the backlog is huge. But this address does not

say anything when the Government is going to fill up these vacancies running into several lakhs.

The country has been witnessing continued increase in the price of all essential commodities and the poorer section of our population is mostly affected on this account. On the other hand, the reduced income due to reduction in jobs and on the other side high cost of all essential commodities, all these made the life of the poor miserable and the address does not show any concern towards them. The inflation level is all time high and not a single item is untouched of this inflation. The looting is going on and who is benefiting nobody knows and the Government's intervention is seen nowhere. The Government thinks that by giving five-kilogram foodgrain, it is ensuring a better living for the poorer section of our society. It is not.

The rail is the lifeline of our nation and the countrymen have been thinking this way till a few years ago. But today rail journey is not a safe option. The continued rail accidents has tarnished badly the image of Indian railways. l have a point to Say this. Just after one of the biggest three trains collision that killed nearly 300 people on 2.6.2023, another major rail tragedy took place on 17.06.2024 near Jalpaiguri, killing more than 15 people on board.

The major contribution towards this unabated train accidents in the country is the huge unfilled vacancies especially pertaining to rail Safety. The inquiry reports may say many things on rail accidents, but the fact is that the loco pilots are being forced to restless duties. Many recommendations say that Loco Running Staff should not be compelled to work for more than 2 continues nights at a Stretch and also recommended that grant of periodical rest of 40 hours. But this is not happening as recommended. The reasons put forwarded by many for forcing the Loco Running Staff to perform duties without rest, were because of huge unfilled vacancies of Loco Running Staff. The rail journey was once sure travel of reaching destination without worry, has now become uncertain of reaching destination, despite paying heavy train fare. With regard to other rail safety workforce, there are huge vacancies exist, and the situation is no different. If we have to reduce the rail accident and to ensure safe rail journey, the vacancies of rail Safety workforce should be filled up on a time bound basis. In Railway 3.12 lakh posts are lying vacant. The price on petrol and diesel have nearly doubled since the year 2014 and whereas the international price on crude oil reduced by half per barrel. The

reduced international price of crude oil has no bearing effect on the prices by which petrol and diesel are being sold in India.

The present record price on diesel has led to an increase in the cost of all essential commodities. In the case of cooking LPG Gas, the price of the same has been steady for the last several years and whereas the same was available at Rs 400 or so when the United Progressive Alliance Government was there till May, 2014. Due to this exorbitant cost of cooking gas the households are facing acute problems and are unable to meet both the ends. Even the beneficiaries of Ujala scheme were not able to refill the second cylinders. But in this address these have no place, showing no concern. When this Government came to power in the year 2014, it was assured the nation that the crime against women will be taken care of to reduce. But what happened was that the crime against women has been steadily increasing since then year after year and is going on unabated and according to the National Crime Records Bureau (NCRB), crime against women is happening the most in most of the year since 2014 is in the double engine sarkar of Uttar Pradesh. Not only this, in another State which is Gujarat where also the double engine sarkar is existing, the Government there freed 11 convicts of Gujarat gang rape from jail in Gujarat'?s Godhra town after the state Government approved their application for remission of sentence. So this is the reality. Talks something for the consumption of the general public and contradictory things happen. But this address does not Say anything about the prevention of crimes against women. The farmers who are the anna dhathas of our nation have been demanding guaranteed Minimum Support Price for their produce. It was assured to them that this issue will be addressed, to call off their year long strike in the national capital. But these farmers now feel that they have been cheated and the Government has gone back on its promise. Their demand for guaranteed Minimum Support Price was based on the fact that the cost of all input materials such as fertilizers, etc. and the labour charges wherever required have gone up drastically and there is even a proposal to withdraw or reduce subsidy on fertilizer due to budget deficit as well as on international pressures. Therefore, the farmers fear that the cost of farming will go up to a level which cannot be affordable for small and marginal farmers. But in this address there has been no mention of guaranteed Minimum Support Price, except saying setting up of Farmer Producer Organisations, but the fact is that such an organization is already existing for the same Purpose in the name of Commission for Agricultural Costs & Prices. Most of the political parties and experts have been demanding a debate on the aggression by China at the Line of Actual Control, but the Government is not willing to do so. There are reports that the Chinese Army

PLA is very much inside our territory in some pockets. The locals in Arunachal Pradesh have been complaining about this. The Clashes between our soldiers and the Chinese army have been reported quite often. We lost our 20 brave Soldiers at the hands of the Chinese army in Galwan valley earlier. China is creating all types of infrastructure at the LoAC. Even we were warned by world countries on this issue. But I am sorry to say nothing has been elaborated in detail in the address. Due to implementation of policies without consulting the State Governments, several State Governments are facing huge fiscal stress, forcing many developmental projects halted and social welfare schemes to be put on hold, but at the same time the States are not allowed to borrow money beyond a limit. States had to approach the Central Government/Supreme Court to allow them to borrow money to run their Government. Again this serious issue found no place in the address. With this I conclude. Thank you.

DR. RABINDRA NARAYAN BAHERA (JAJPUR): My heartfelt thanks to Mahamahim President of India for her speech in the Lok Sabha. Thanks to the hon. Prime Minister of India for historic development in India and transforming India into Bharat, and new India into Digital India.

I would like to state that a lot of development work has taken place in my constituency, Jajpur. Jajpur is rich in minerals and is also known for its industries, cultural heritage, Buddhist Conclave, agriculture and river belt. We have seen development in railway sector especially in Haridaspur-Paradip line.

Already survey has been done between Jajpur road and Dhamera rail-line. Development is also done in mines sector. I also wish to congratulate the Government for constructing Ram Mandir, and developing other heritage sites in various parts of the country.

I want to draw the attention of the Government towards a few other very important projects in my constituency.

There is an urgent need for developing railway connectivity between Biraja Khetra (Jajpur town) on Jajpur road and Dhamera rail-line.

There is also a need to revive Pushpagiri Vishwavidyalaya near Ratnagiri and Langudi Buddhist Archeological Site.

There is a lot of scope of development in agriculture sector in my constituency. The Government can also take several initiatives under Digital India in Jajpur constituency. Several river development projects can also be taken up. Thank you very much.

SHRIMATI ANITA SUBHADARSHINI (ASKA): I support the motion moved by hon. Member, Shri Anurag Thakur.

In the past ten years, Modi Government has spent a lot for the development of the common people, but unfortunately, the State Government did not cooperate.

Some things were done, but a lot has to be done for my constituency, Aska in the Ganjam District of Odisha.

There was no railway connectivity in my segment. We need an AIIMS at Aska segment as health facilities there are in a bad shape.

We need to take some initiatives for job creation as migrant labourers are maximum in my district, in the State of Odisha.

Aska sugar factory has to be taken care of as it is going to be a dying industry because of the least interest of the previous State Government.

As we now have a BJP Government in the State, we expect that the development of my parliamentary constituency would be done at double speed.

I would also request to add Aska in Modi ji?s ?Viksit Bharat?. Viksit Aska, Viksit Odisha, Viksit Bharat. Thank you.

DR. PRADEEP KUMAR PANIGRAHY (BERHAMPUR): It was indeed a pleasure to listen to the address of Honourable President Madam Smt. Droupadi Murmu on June 27, 2024.

I am thankful for giving me an opportunity to extend my thanks to the President of India for her address with a warm welcome to the newly elected members of the 18th Lok Sabha. I am one among the very few who got this privilege to be elected as member of Lok Sabha and serve the nation and the people of my Constituency-Berhampur, Odisha. Madam President delivered her address by vesting a lot of

responsibilities on us to fulfil the aspirations of 140 crore Indians and server the country in the spirit of Nation First. On this occasion, I also express my gratitude to the people of my constituency who have full faith on me to fulfil their aspirations.

Madam President has aptly said that the election 2024 has been an election of trust in policy, intention, dedication, strong decision and decisive Government. People's trust in good governance, stability, honesty and hard work of the Modi's Government can only deliver Government's guarantees and making our country in the vision of our Honourable Prime Minister for a Viksit Bharat. The Government's mission of service and good governance delivered during the past 10 years has been the hallmark of development and reflected in the election result.

Truly, this 18th Lok Sabha will witness and script a new chapter on decisions for public welfare. I am glad that I will be part of Modi Government's 3.0 far reaching policies and futuristic vision of appropriate reform, perform and transform in making India as World's third largest economy.

Honourable Prime Minister Modi is committed in striving to make India's overall development keeping people of India at the centre of each policy decision. The commitment of the Government is indeed reflected with the continuation of fund disbursement through PM-Kisan Samman Nidhi to enable farmers to meet their small expenses.

During last 10 years, the Government led by Honourable Prime Minister Modi has been successfully delivering its commitments and promises. Among others, rural connectivity through PM Gram Sadak Yojana-as the lifeline of rural masses, has been the testimony of Modi Government's success. The implementation of New Education Policy, policy on Universal Health Coverage through strengthening health service delivery institutions and focus on infrastructure building and tertiary care, Commitment for Housing for all, Doubling Farmers Income, Swachh Bharat Mission, connecting tap water to each household for safe drinking water under Jai Jeevan Mission, and unleashing the potential of market to drive appropriate policy reform for the welfare of the masses are some of the symbolic development model of the Modi 1.0 and 2.0. The unfinished tasks (due to COVID 19 pandemic) of the Modi Government will be fulfilled in Modi 3.0.

The vision of the Honourable Prime Minister for making India self-sufficient and reliant on defence production, manufacturing needs and to reduce the import cost to the exchequer, ease of doing business policy, startups, make in India and slogan

on vocal for local helped youths of India to think beyond the traditional means of livelihood.

The Krishi Sakhi Initiative trained Krishi Sakhis into modern agricultural practices, the Sukanya Samriddhi Yojana, PM Surya Ghar Muft Bijli are steps in right direction in achieving the goal of Viksit Bharat. In the difficult times of the Corona pandemic, the Government started PM Garib Kalyan Anna Yojana to provide free ration to 80 crore persons.

India has been at the forefront in safeguarding humanity. The way the world now views India was evident during the G-7 summit held recently in Italy. India hosted the G-20 summit and won the confidence of Africa and the entire Global South. Following the Neighbourhood First Policy, India has strengthened its relations with neighbouring countries on various policy matters like trade, investment, bi-lateral and multi-lateral cooperation agreements etc. In the spirit of Sabka Saath-Sabka Vishwas and Sabka Vikas the East Asia, Middle-East and Europe the India Middle East Europe Economic Corridor was set up, which will prove to be one of the biggest gamechangers of 21st century. Jai Jagannath

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Thank you, for giving me the opportunity to express my views in support of the Motion to thank the Hon'ble President for her address to the Parliament.

I take this moment to express my sincere gratitude to the people of India and Odisha, in particular thanking them wholeheartedly for their support and blessings, which have contributed to our significant electoral success.

The Hon'ble President of India, in her address to the joint sitting of Parliament, underscored the significance of India's stable Government, elected with a clear majority for the third consecutive term, with the Kashmir Valley surprising everyone with a massive voter turnout and home voting facility being introduced for the first time to ensure optimum voting. This achievement is due to the leadership and vision of our Hon'ble Prime Minister, in whom the people of India have placed their trust. This is the result of Modi's guarantee. Modi's Guarantee embodies a relentless commitment to the people's welfare. It promises a Viksit Bharat. This guarantee stands for the progress of our youth, the empowerment of our women, the welfare of our farmers, and the upliftment of the marginalized and

vulnerable who have been neglected for decades. Under Modi's Guarantee, what was promised has been delivered; what will be promised will be achieved.

Both the Nation and my state of Odisha stand united in unwavering trust and faith in our Prime Minister. As a result of Modi's Guarantee, we now have a Double Engine Government in Odisha for the first time ever. Viksit Odisha will be a vital growth engine, aligning with the vision of a Viksit Bharat by 2047.

Hon'ble President emphasized the Government's commitment to reform, perform, and transform, highlighting India's economic achievements and its transformation into the world's fastest-growing economy. She noted that in the past 10 years, India has risen from the 11th largest economy to the 5th largest in the world. Between 2021 and 2024, India experienced an average annual growth rate of 8%. She emphasized that India is responsible for 15% of global growth and that the Government is working to elevate India to the position of the 3rd largest economy in the world.

The President also emphasized that the Government accords equal importance to all three pillars of the economy: Manufacturing, Services, and Agriculture. In a bold move to uplift our farming heroes, more than 23,20,000 crore has been swiftly disbursed through PM-Kisan Samman Nidhi. Hon'ble PM, upon beginning his third term, signed his first file authorising the release of the 17th instalment of PM Kisan Nidhi, amounting to more than Rs 20,000 crores to around 9.26 crore beneficiary farmers reaffirming the government's resolute commitment to farmers' welfare.

The Government has enacted a significant rise in MSP for Kharif crops and is developing a wide network of Farmer Producer Organizations (FPOs) and cooperatives such as PACS. The Government is attempting to create the World's largest storage capacity in the cooperative sector.

The Double Engine Odisha Government has pledged the Samrudh Krushak Niti, guaranteeing paddy procurement at Rs 3,100 per quintal. Payments will be expediently transferred to farmers within 48 hours through direct benefit transfers, with procurement conducted using electronic weighing machines across all markets, reflecting the Government's profound care and respect for farmers.

The Hon'ble President underscored that due to the resolute implementation of Government Schemes with a saturation approach over the past decade, 250 million Indians have transcended poverty.

In the face of the Corona pandemic's challenges, the Government promptly launched the PM Garib Kalyan Anna Yojana, extending free rations to 800 million individuals. This steadfast guarantee signifies our leader's unwavering commitment to ensuring no citizen sleeps hungry, embodying our pledge to uplift and empower every Indian towards a prosperous tomorrow.

The Hon'ble President emphasized several groundbreaking programs designed to improve living standards and economic opportunities for different societal groups. One key initiative, the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, aims to eliminate electricity bills and generate income by selling electricity. This program includes installing solar panels on rooftops, with the Government providing up to 278,000 in support for each family.

The Double Engine Odisha Government is launching the transformative Prime Minister Surya Ghar Muft Bijli Yojana, which seeks to provide free electricity for 300 units through rooftop solar installations. This visionary scheme will not only supercharge Odisha's local economy and create numerous jobs but also strengthen our national energy security.

In 10 years, the Government has successfully built over 3,80,000 kilometres of village roads under the PM Gram Sadak Yojana, significantly improving rural connectivity. Additionally, the development of National Highways and Expressways has seen remarkable progress, with the construction pace more than doubling.

The PM SVANidhi scheme will be extended to cover street vendors in rural and semi-urban areas. In 10 years, metros have been built in 21 cities.

Construction of three crore houses has been approved under PM Awas Yojana. Within 24 hours of taking oath as Member of Parliament in the newly constituted 18th Lok Sabha, the Railway Ministry approved Rs 183.89 crore for an 8.11 km flyover at Titilagarh Junction, located within my Bolangir Lok Sabha Constituency. This flyover will enable seamless movement of trains towards Vizianagaram, Sambalpur, and Raipur without the need for crossings. Previously, trains had to stop at Titilagarh to accommodate cross-traffic from these three directions, causing delays and operational challenges. This proves the seriousness of the Modi Government to deliver.

The Hon'ble President of India proudly underscored the Government's unwavering dedication to women-led development and empowerment, heralding a transformative era in the nation's progress. Responding to the long- standing call

for greater representation, the historic enactment of the Nari Shakti Vandan Adhiniyam has empowered women by securing their increased participation in the Lok Sabha and Vidhan Sabha.

A comprehensive initiative has been launched with the goal of transforming 30 million women into 'Lakhpati Didis', supported by increased financial assistance to Self Help Groups. 10 crore women have been mobilised into self- help groups (SHGs), 30,000 women belonging to SHGs have been provided with Krishi Sakhi Certificates in the past decade. The NAMO Drone Didi Scheme is a key initiative contributing to this goal, empowering women from various Self Help Groups with drones and training them as Drone Pilots. Over the last 10 years, majority of the 4 crore PM Awas houses have been allocated to women beneficiaries.

Under Modi's Guarantee, the Double Engine Odisha Government is launching the Subhadra Yojana, providing every woman with a Rs 50,000 voucher to be redeemed over two years. This groundbreaking initiative aims to empower women and boost entrepreneurship among the women of Odisha, heralding a new era of progress and prosperity for our nation.

Hon'ble President highlighted the significant advancements in India's educational sector over the past decade, underscoring its vital importance for the nation's progress. In the last 10 years, 7 new IITs, 16 IIITs, 7 IIMs, 15 new AIIMS, 315 medical colleges, and 390 universities have been established, reflecting a robust expansion of higher education infrastructure.

A new Digital University is to be launched. Under PM Modi's leadership, the New Education Policy strives to create a conducive environment which is inclusive and promotes regional languages. The emphasis on education is pivotal for building a knowledgeable, skilled, and empowered generation that will drive India's future growth & reverse 'Brain Drain'. Nalanda University, rooted in its rich historical legacy as an ancient seat of learning, has been re-established to position Bharat as a Global Knowledge Hub.

Under the visionary leadership of Prime Minister Modi ji, free health services are provided to 55 crore beneficiaries through the Ayushman Bharat Yojana. Our Government has now taken the 'sankalp' that every individual above 70 years of age will now be included in the Ayushman Bharat Yojana, demonstrating our resolve to prioritize healthcare accessibility and affordability for all elderly citizens.

25,000 Jan Aushadhi Kendras are being opened at a fast pace to improve healthcare access, affordability, and quality across India.

Our Government, under Prime Minister's leadership, has always prioritized the needs of our armed forces. As a result, the long-awaited One Rank One Pension scheme has been implemented after four decades, honouring the service and sacrifices of our military personnel.

The creation of the Chief of Defence Staff (CDS) has brought significant reforms and added new strength to India's defence Under the "Make in India' initiative, India's defence manufacturing has exceeded one lakh crore rupees. Last year, around 70% of defence procurement was sourced domestically. The defence forces have had imports of over 500 defence items, and defence exports have soared over 18- fold to Rs 21,000 crore.

The Bharatiya Nyay Sanhita will come into effect across the nation starting July 1st. focussing on justice over punishment, this is in harmony with the foundational principles of our Constitution.

The Government has initiated the process of granting citizenship to refugees through the Citizenship Amendment Act (CAA), offering a dignified life to many families impacted by Partition.

Prime Minister Modi's vision for social justice guarantees inclusive growth and empowerment for all sections of society. The Pradhan Mantri-Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN) Scheme, with an allocation of more than Rs. 24,000 crore, aims to uplift Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs), addressing their unique challenges and enhancing infrastructure for a promising future.

Our Government initiated the celebration of Bhagwan Birsa Munda's birth anniversary as Jan Jatiya Gaurav Divas. Next year, we will enthusiastically mark his 150th birth anniversary nationwide.

The 21st century belongs to India, where unity under Prime Minister Modi's visionary leadership is essential to achieve Viksit Bharat & Viksit Odisha. Together, let us harness our collective strength to drive innovation, sustainable growth, and inclusive development across all sectors. By embracing our cultural heritage and leveraging modern advancements, we can propel India to global leadership, ensuring prosperity and well-being for all our citizens. Let us unite with

determination and dedication to fulfil this transformative vision, shaping a future where India shines brightly on the world stage.

With these remarks, I conclude my speech and I support the Motion of Thanks on the President's Address.

श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही (कंधमाल) **:** मुझे महामहिम राष्ट्रपति महोदया के संसद में दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद । अपने भाषण में राष्ट्रपति जी ने हम सबके साथ देशवासियों का मार्गदर्शन किया है । आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने आदिवासी समाज का गौरव तो बढ़ाया ही है साथ ही देश की कोटि-कोटि बहन-बेटियों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का अवसर भी है ।

आज दुनिया की हर विश्वसनीय संस्था, सारे एक्सपर्ट्स जो वैश्विक प्रभावों को बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं जो भविष्य का अच्छे से अनुमान भी लगा सकते हैं, उन सबको आज भारत के प्रति बहुत आशा है, विश्वास है और उमंग भी है । आज पूरी दुनिया भारत की तरफ बड़ी आशा की नजरों से देख रही है । इसका कारण भारत में आई स्थिरता, भारत की वैश्विक साख, भारत के बढ़ते सामर्थ्य और भारत में बन रही नई संभावनाए हैं ।

पिछले 9 वर्ष में भारत में 90 हजार स्टार्टअप्स और आज स्टार्टअप्स की दुनिया में हम तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं । एक बहुत बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज देश के Tier 2, Tier 3 cities में भी पहुंच चुका है । हिन्दुस्तान के हर कोने-कोने में पहुंचा है । भारत के युवा सामर्थ्य की पहचान बनता जा रहा है ।

हमारी सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से देशभर में कहीं पर भी गरीब से गरीब जनता को भी राशन उपलब्ध कराने में सक्षम है । साथ ही किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों के खाते में साल में 3 बार 11 करोड़ पैसे जमा होते हैं ।

हमारी सरकार ने बेघर के लिए या जो कल फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे, जो झुग्गी-झोपड़ी में जिंदगी बसर करते थे, ऐसे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर देंने का काम किया हैं ।

हमारी सरकार ने महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया हैं और उनके उज्ज्वला जैसे योजनाओं का लाभ देकर 9 करोड़ को मुफ्त गैस के कनेक्शन देने का काम किया है । हर घर जल नल योजना के लाभ देते हुए 8 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करने का काम किया है ।

मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में दूरगामी नीतियों और भविष्य की दूरदर्शिता के साथ संकल्प से सिद्धि तक यात्रा के खींचें गये खाके का अभिनंदन करता हूं । राष्ट्रपति जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं । देश आज यहां से एक नई उमंग- नए विश्वास-नए संकल्प के साथ चल पड़ा है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान (रतलाम) **:** मुझे माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लिखित में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद । ।

18 वीं लोक सभा के नव-निर्वाचित सदस्यों में से एक मैं भी हूँ । मैं ग्रामीण क्षेत्र के उस एरिया से आयी हूँ, जहाँ से पहले कभी कोई बहन यहां तक नहीं पहुंची थी । जहां कृषि प्रधान जिला है, मैं आदिवासी अंचल की रहने वाली महिला हूँ, लेकिन आज मैं यहा पहुंची हूँ तो मोदी जी की वजह से पहुंची हूँ ।

उन्होने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वन्दन अधिनियम बनाया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ ।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र के उन माता, बहनों, भाइयों, सम्माननीय बुजुर्गों का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और क्षेत्र का विकास करने के लिए संसद तक भेजा ।

मुझे गर्व है कि जो महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ, वह एक ऐसी बहन हैं, ऐसी माता हैं, जो एक आदिवासी महिला हैं और वह सिर्फ मोदी जी की सरकार में सम्भव हो पाया है । मेरे लिए यह गर्व की बात है ।

मैं बताना चाहती हूँ कि अभी बरसात का मौसम है । इन दिनों जलाऊं लकड़ी गिली हो जाती है, उससे खाना बनाना, पकाना मुश्किल होता है । मुश्किल ही नहीं, बल्कि बहनों की आंखें और फेफड़े खराब होते हैं । लेकिन मोदी सरकार ने प्रधान मन्त्री उज्ज्वला योजना बनाकर हमारी ग्रामीण बहनों को जीवनदान दिया है । आंखें खराब होने से बचाया है ।

इतना ही नहीं, आज हमारी कई बहनें, गांव में निवास करने वाली बहनें सेल्फ-हेल्प ग्रुफ/आजीविका मिशन समूह के माध्यम से जैविक खाद बना रही है, साबुन बनाने का काम कर रही है, सेनेटरी नेपकीन बना रही है, अगरबत्ती बनाने का काम कर रही है । मोदी जी की सरकार ने बहनों को लखपति दीदी बनाने का कदम उठाया है । आने वाले समय में हमारी बहनें और बाकी काम सीखेंगी तथा आगे बढ़ेंगी ।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (मुजफ़्फ़रनगर) **:** मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की लोक सभा में, मैं आज किसान देवता चौधरी चरणसिहं, धरतीपुत्र श्री मुलायम सिंह यादव, नेताजी और चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत संघर्ष के प्रतीक की नीतियों पर चलकर आदरणीय अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व के कारण आज यहां पहुंचा हूं । इसके लिए मैं उस मुजफ्फरनगर की सम्मानित जनता जहां 2013 में कुछ लोगों के द्वारा दंगे भड़काकर मुजफ्फरनगर को कलंकित किया था का हृदय की गहराईयों से धन्यवाद अदा करता हूं । मुजफ्फनगर की जनता ने न केवल मुझे जिताया है बल्कि उस मानसिकता को हराया है जो लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाती रही है । उन्होंने यह साबित किया है कि वे सब धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक किसानों, नौजवानों अगड़े पिछड़े के नायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों में विश्वास करते हैं और उन्हीं के साथ हैं ।

मैंने इस महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को कई बार पढ़ा । इसमें किसानों की आय दुगुनी करने का उल्लेख किया गया परन्तु कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि आय कैसे दुगुनी की जाएगी । एम.एस.पी. गारंटी कानून बनाने की घोषणा नहीं है । न ही नई मंडी बनाने की घोषणा है । हमें आशा थी कि पूरे देश में किसानों को बिजली सस्ती एवं निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी परंतु ऐसी भी कोई घोषणा नहीं है । ऐसे में कैसे किसान की आय दोगुनी होगी यह समझ से परे है । महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में रोजगार की बात की गई परंतु देश में रोजगार छीने जा रहे हैं केन्द्र सरकार के अधीन ही लगभग 30 लाख पद खाली पड़े हैं जिन्हें

भरा नहीं जा रहा । राज्य सरकारें संविदा पर कर्मचारी रख नौजवानों का शोषण कर रही हैं । परिक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं । बेरोजगारी चरमसीमा पर है । देश का भविष्य नौजवान कभी नीट की परीक्षा का शिकार होता है कभी अन्य परीक्षा का । वह मायूस है । यही हाल बुनकरों का है । मेरे लोक सभा क्षेत्र मुज़फ़्फ़रनगर, लावड, सरधना के बुनकर महंगी बिजली से परेशान हैं । उन्हें सस्ती बिजली देने की कोई घोषणा नहीं है । मुज़फ़्फ़रनगर अत्याधिक जीएसटी देता है परंतु न तो वहां कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज है न सरकारी विश्वविद्यालय ।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मुज़फ़्फ़रनगर में मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए । मुजफ्फरनगर एन.सी.आर. में आता है परंतु वहां एन.सी.आर. की कोई सुविधा नहीं है बल्कि एन.सी.आर. के नाम पर तरह तरह की पाबंदियां वहां स्थापना उद्योगों व नागरिकों को झेलनी पड़ती है । सरकार से अनुरोध करता हूं कि मुज़फ़्फ़रनगर जो एन.सी.आर. में होते हुए भी प्रस्तावित रैपिड रेल सर्विस से मुज़फ़्फ़रनगर को नहीं जोड़ा जा रहा है । ऐसी स्थिति में मेरा सरकार से अनुरोध है कि मुज़फ़्फ़रनगर को एन.सी.आर. से बाहर कर दिया जाए और मुज़फ़्फ़रनगर से सहारनपुर तक एक इंडस्ट्रियल कोरिडोर बनाया जाए तथा एक बड़ी इंडस्ट्री भी केन्द्र सरकार द्वारा वहां स्थापित की जाए ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके ।

महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा महिलाओं के सम्मान की बात की गई । मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मणिपुर की घटना ने देश को शर्मसार किया और अंतराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवान बहनों के साथ जो दिल्ली पुलिस ने व्यवहार किया उससे अधिक शर्म की बात नहीं हो सकती । वैसे भी पूरे देश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं । मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में चुनाव का उल्लेख किए जाने की चर्चा करता हूं । यहां सभी साथी चुनाव लड़कर आए हैं । वर्तमान में चुनाव जिस प्रकार हुए हैं उससे लोकतंत्र को खतरा है । खुद मैं भुक्तभोगी हूं । चुनाव के दिन कोई ऐसा पोलिंग बूथ नहीं रहा जहां दरोगा ने जाकर मतदाताओं को डराया धमकाया ना हो । यही नहीं सत्ता पक्ष से संबंधित उम्मीदवार जो 12 कारों के साथ घूम रहा था उनके परिजन जो अलग अलग काफिलों के साथ घूम रहे थे के फोटोग्राफ व विडियों भेजने के उपरांत भी प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और मेरे सुपुत्र पंकज मलिक जो विधायक हैं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया और खुद मुझे जबकि मैं एक गाड़ी में था रोककर मेरी गाड़ी की तलाशी ली गई, व्यक्ति गिने गए मुझे लगभग आधा घंटा डिटेन रखा गया । यहीं नहीं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भारी पुलिस लगाकर मतदान रोका गया और अंत में जिलाधिकारी स्वयं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जहां से पोलिस स्टेशनों पर रास्ता जाता था, वहां भारी पुलिस बल के साथ एस.एस.पी. को लेकर खड़े हो गए ताकि मुस्लिम मतदाता मतदान करने ना जा सके और वो वास्तव में रूके भी । क्या इस प्रकार लोकतंत्र जिंदा रह पाएगा । कोई ग्राम प्रधान और राशन डीलर नहीं बचा जिसे धमकाया नहीं गया । यही नहीं गिनती पर भी धांधली का प्रयास किया गया और जिन दो विधान सभा क्षेत्रों से अधिक मतों से जीता उन दोनों के ए.आर.ओ. जो एस.डी.एम. के पद पर थे को हटाकर जिला मुख्यालय पर संबद्ध कर दिया गया । उनका कसूर यह था कि उनके क्षेत्र बुढाना और चरखावल में हरेन्द्र मलिक कैसे जीत गया । क्या यह लोकतंत्र है । क्या इस प्रकार लोकतंत्र जिंदा रहेगा । मुझे लोकतंत्र का भविष्य भयावह लग रहा है ।

अंत में मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह ओल्ड पेंशन स्कीम जो कर्मचारियों के बुढापे का सहारा है उसको लागू करने का काम करें और नौजवानों को रोजगार दे, किसानों को लाभकारी मूल्य दें, सस्ती बिजली दें तथा गन्ना किसानों को बकाया का ब्याज सहित भुगतान करायें तथा छोटे पशुओं से किसान को निजात दिलाएं और जो सरकार द्वारा गौशाला में छोटे पशु रखे गये हैं उनके चारे का उचित प्रबंध करें । हमारे व्यापारी भाईयों को जी.एस.टी. के नाम पर रोज उत्पीड़न किया जा रहा है उसे रोकने का काम करें । अगर किसान नौजवान परेशान रहा तो देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा । मुझे अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री सनातन पांडेय (बलिया) **:** मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में निम्न बातों को जोड़ना चाहता हूँ । चूंकि समयाभाव के कारण मुझे बोलने का मौका नहीं मिला । अत: मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण का विरोध करते हुए, लिखित रूप से अपनी कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ ।

मेरा संसदीय क्षेत्र संख्या 72, बलिया है, जो दो नदियों से घिरा हुआ है, जिससे लोक सभा क्षेत्र का अधिकांश भाग बाढ़ की चपेट में रहता है और हर साल तबाही का मंजर लाखों लोगों को बर्बाद करता है । उपरोक्त के संबंध में कोई ठोस योजना नहीं है ।

जनपद बलिया उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी क्षेत्र में बसा हुआ है । वहाँ पर चिकित्सा के लिए कोई सुविधा नहीं है । जनपद बलिया में स्वास्थ्य सुधार के लिए न कोई मेडिकल कॉलेज है, न एम्स है और इसकी कोई ठोस योजना भी नहीं है ।

लोक सभा क्षेत्र संख्या 72, बलिया में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जननायक श्री चन्द्रशेखर के नाम पर विश्वविद्यालय है । उसमें कर्मचारियों एवं प्रोफेसर्स की भर्तियाँ हुई हैं, जिसमें आरक्षण का पालन नहीं किया गया है । एक भी नियुक्ति पिछड़े व दलित वर्ग की नहीं हुई है, न ही इसकी कोई योजना है ।

बलिया जनपद उद्योग शून्य है एवं यहाँ उद्योग लगाने की आगे भी कोई योजना नहीं है ।

बलिया, उत्तर प्रदेश में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, न ही इसे खोलने की कोई योजना है ।

राष्ट्रपति महोदया जी ने महँगाई, बेरोजगारी पर कोई ठोस बात नहीं रखी है ।

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): While the issue of paper leaks was briefly addressed by the Hon'ble President, the proven negligence of the National Testing Agency (NTA) has been overlooked. The sudden and repeated. postponement of several key examinations, all in the name of maintaining the sanctity of the examination process, has raised serious questions about competence and accountability of the NDA Government. In last five years, out of 66 exams conducted by NTA, 12 exams suffered Paper Leaks, affecting 75 Lakh Youths. Multiple arrests are happening now in the states of Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh, interestingly all NDA ruled states, however it is a must for the Parliament to investigate as to why the massive delay in detecting the largescale scam and corruption. The National Testing Agency works in absolute opaqueness involving conducting of exams by private agencies, which remain not disclosed. It is crucial for us to define the purpose of the NTA, and bring in transparency.

The 18th Lok Sabha should make transparency its cornerstone. Professionalism of educational institutions such as the National Council of Educational Research and Training, the University Grants Commission and universities have been damaged in the last 10 years. The recent law brought in as mentioned by the Hon'ble President

is only punitive in nature, neither preventive nor compensatory in terms of the prejudicial impact on the students.

It has been a continuing initiative and demand of the UPA Government for the caste census to be released for the perusal by the people of India & their representatives. It is only basis proper study and analysis of accurate data that adequate policies can made to uplift India. The NDA Government has grossly delayed the holding of a census even of the population of India, gravely affecting policy making at the Parliament Level. 50% Cap on Reservation It is the opportune time for the Parliament of India to pass a law to exceed the 50% cap on reservation.

Be it in Maharashtra, or Bihar, or the southern states, the reality of the Schedule Castes, Schedule Tribes and OBCs cannot be restricted within the 50% cap. There is no logic for such a limit, which is not even provided for in the Constitution, but applicable due to judicial decisions.

Despite the verdict of the country's electorate, the clear signal against the crushing price rise & unemployment, it is crucial for the President's address to include atleast the intent if not the comprehensive action plan of the NDA Government to solve the crisis.

According to the India Employment Report 2024, which was jointly published by the International Labour Organization (ILO) and the Institute of Human Development (IHD), India's youth are facing high unemployment rates. The report indicates that nearly 83 percent of the jobless population in India consists of young people. It is also concerning to note that the proportion of educated young people with at least a secondary education among the total unemployed youth has almost doubled from 35.2 percent in 2000 to 65.7 percent in 20221. According to a report from Hindustan Times, as of April, 712 out of approximately 2,000 students registered for the 2024 placements at IIT-Bombay were still seeking job opportunities. This represents about 36% of the student population.

Several Instances out of which one being the roof of the Delhi Airport has collapsed killing one person and injuring eight. The answer to the question who was responsible for the said roof to collapse, is not the answer that the family of the driver (Mr. Ramesh Kumar) killed, will accept It is to be noted that the Roof of the Jabalpur Airport collapsed, despite it being inaugurated 3 months back by the Prime Minister of India. Rs. 17,843 crore infrastructure project of this scale should be held to the highest standards of engineering and oversight.

This year has marked one of the biggest tragedy caused due to illegal Hoardings which is the tragic incident in Mumbai, where a massive 250-ton hoarding collapsed during a dust storm, leading to the loss of 17 lives, underscores the broader issue of corruption, inadequate regulation and enforcement around public structures. Further the issue of Manholes in Gujarat, Year after year, after the very first rainfall, roads in Gujarat collapse. On 30 June 2024, despite the ruling Government in power in the State, roads have collapsed/sunk in tier 1 cities such as Ahmedabad.

Similar is the crisis that Maharashtra has been facing with water logging in low lying areas and localised flooding of roads. Across these diverse infrastructure failures, a common thread emerges-the need for the Government to take a more proactive, comprehensive, and accountable approach to infrastructure management. Failure to address these systemic issues will only lead to more preventable tragedies in the years to come.

As Hon'ble President emphasised on green energy and jobs. However, the reality today is starkly different. As per the World Air Quality Report, India is ranked 3rd most polluted country. Almost 70% of the Indian Population live in areas that exceed the country's own national air quality standard. On average, every Indian loses 5.3 years of his life due to pollution, which should be seen in comparison with cardiovascular diseases that reduces the average Indian's life by 4-5 years, and child and maternal malnutrition reduces by 1.8 years. Between 2013 to 2021, 60% of the world's increase in pollution has come from India. If we focus and control the pollution crisis, residents in Delhi would gain 12 years of life expectancy.

Recently, Mr. Vijay Warlikar, National Vice-President of the National Association of Fishermen, has appealed for attention to the gathering of devotees and saints from across the country and abroad in preparation for the 29th Palkhi procession of Shri Dnyaneshwar Maharaj to Pandharpur. He highlighted that the river Indrayani is heavily polluted due to the discharge of chemicals from nearby factories, with devotees and pilgrims bathing in this contaminated water. This poses a serious threat to their health and well-being, as well as risking the destruction of aquatic life and the environment.

I would like to add that only if the population is at its optimum efficiency, will India grow. As per the survey done in 2018 by the Indian Council for Medical Research, high expenditure on mental disorders is shooting up the families' healthcare budget. The study highlights a profound mental health crisis in India, with mental

illnesses accounting for one-sixth of all health-related issues, including conditions such as depression, anxiety, bipolar disorders, and schizophrenia.

It is pushing 20 percent of Indian households into poverty. Out of the total household budget on healthcare, almost 20% is on mental care. We need preventive and corrective policy, of reducing work & society related stress, reward compassionate work environment, and also provide financial risk protection to reduce impact of healthcare expenditure on mental illnesses.

The Hon'ble President highlighted the Act East Policy of the NDA Government showing commitment towards the peace and prosperity of the North East region. However, it is global knowledge that Manipur has been experiencing prolonged unrest for the past year, women were raped and paraded, we demanded a discussion even in the 17th Lok Sabha, however, all was done to avoid any discussion let alone devise any comprehensive plan in the face of escalating violence and destruction of social harmony. Therefore, the 'Act East' policy rings hollow unless there is any intent towards accepting our mistakes, and working for regional peace.

Implemented on 1 July 2024 Amidst breach of the parliamentary security and demand for discussion on price rise, the 3 criminal law bills were railroaded in the Parliament without any discussion. Increase in the police remand period from 15 days to 60 or 90 days would prove to weaponise the police by the respective State Governments. Retention of solitary confinement despite it being in absolute violation of human rights. The introduction of the power to handcuff without court permission is again moving towards a police state. The 18th Parliament must reconsider the Criminal Law Bills and revise all the provisions in line with the Constitution of India.

It is high time that the law allows for Governments to weaponize it for their political motives, as seen in the case of Arvind Kejriwal & Hemant Soren. Similarly amendments to forest conservation and biological diversity protection forest laws were railroaded without any discussion. The Great Nicobar Project is deeply concerning. The recent bail of both Arvind Kejriwal and Hemant Soren display the weaponizing of the investigative agencies of the country for political purposes. Huge amount of government resources are focussed only on suppressing the voice of the opposition, this is a fraud on the taxpayers money. The 18th Lok Sabha, must in the spirit of consensus and to move ahead, bring in necessary provisions to

restrict any government be it Centre or State from weaponizing agencies for political purposes.

Honourable President has mentioned about the FPO networks being made but what cannot be neglected is rather than promises, we need a consultative mechanism, where farmers of the country are consulted before taking every decision. The three controversial farm laws, have proven that the approach of the Government is wrong.

First time in history, the "Vote from Home" option was made available. Firstly I would like to congratulate the Election Commission of India for increasing voter penetration, however, there were sizeable cases of malpractices by the NDA leaders and pressure upon the Hon'ble Commission. An important example is that of breaking of parties by defecting and approaching the Election Commission to be called the original party to create a defence to the Tenth Schedule. Weaponising the Hon'ble Election Commission to further the interest of NDA is condemnable as it is insulting to the people of India, and inevitably the Constitution of India.

There is mention that the farmers are unable to take care of expenditure - PM Kisan Samman Nidhi- 3 Lakh 20 Thousand Crores has been launched. I would like to shed some light on The Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) scheme, which provides a meagre Rs. 500 per month to farming families, is grossly insufficient and fails to meaningfully address the significant economic challenges faced by India's agricultural sector. If there were genuine concerns about the wellbeing of farmers, it would take far more substantive measure Foremost, legal status must be granted to Minimum Support Prices (MSP). Additionally, comprehensive loan waiver schemes are necessary to free farmers. Furthermore, the Government should act to reduce the costs of essential agricultural inputs like fertilizers, seeds, and equipment. This could be achieved through higher subsidies and the removal of the Goods and Services Tax (GST) on these critical supplies.

Government has been working on Ease of Doing Business Constantly. But it is to be noted that the region-wise discrimination and bias shown by the NDA Government is against the cooperative federalism.

Even though as mentioned that the Government is continuously working on extension of farming activities including dairy and fishery, the current payment of 22 to 27 per litre to milk producers is significantly lower than the Government-announced rate of 34 per litre. Compared to other states, milk producers in

Maharashtra receive 10 to 12 less per litre, exacerbating their financial struggles. Adding to the discontent, the Government's recent decision to permit the import of 10,000 tonnes of milk powder and remove the import duty has further jeopardised local this move is likely to depress rates even more, causing distress among local producers. It has been claimed that there have been Construction of 4 crore PM Awas Houses but The CAG audit of the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) has revealed several issues, including irregular selection of beneficiaries, diversion of funds, and lack of effective monitoring. These findings suggest that the implementation of the scheme in the state has been plagued by various irregularities, undermining the objective of providing affordable housing to the urban poor. I would like to bring the attention towards Construction of more than 3 lakh 80 thousand kms. of road under PM Gramin Sadak Yojna. PMGSY-III aims to be completed by March 2025. As we enter the final year of this six-year project, it should ideally be 84% complete if progress were uniform each year. However, the reality is quite different. As of now, only 78,492 km of roads have been constructed, which is a mere 63% of the initial target of 1.25 lakh km. To make matters worse, just 1.15 lakh km has been approved so far, casting serious doubts on the scheme's timely completion. The situation is particularly dire in states like Mizoram, Manipur, and Sikkim, where not a single road has been completed under the scheme. This lack of progress is compounded by a damning report from a standing committee on rural development in 2022, which criticized the quality of the roads as "completely unacceptable."

Even if there has been growth in construction of the highways by 2x, the Atal Setu Bridge, which was inaugurated just three months ago, has already developed cracks. Even more alarming, a half-kilometre stretch of road near Navi Mumbai has sunk by a foot. Despite the state pouring a staggering Rs 18,000 crore into the Mumbai Trans Harbour Link (MTHL), these incidents highlight a glaring lack of proper construction practices. These problems underscore that it's not enough to simply build infrastructure; quality and durability are crucial. Moreover, our national rail network, highways, and overall development lag significantly behind other parts of India, reflecting a need for more comprehensive and robust planning and execution in our infrastructure projects.

As stated by the Honourable President that there has been Growth of Tourism, Connectivity, Employment etc. in North-Eastern States, I would like to bring to attention that according to the Ministry of Statistics and Programme Implementation, during the financial year 2018-19, the eight North-Eastern states

had a growth rate lower than the national average. In the financial year 2018-19, the 8 North Eastern States of India contributed only 2.8% to the country's GDP, most of this share came from Assam. Other states together gave 1/3 of the contribution. This region is behind other parts of India in many areas like power use, roads and railways, and social and economic development. Further it is that the Government working for Peace in the North- East. The Northeast of India has historically been a hotspot for secessionist movements, making it imperative for any governing body to prioritize establishing peace, ideally through political negotiations. Manipur incident is a reflection of the dearth of any proper intervention by the Government to establish peace.

The topic of women representation that the Government is working for Women Empowerment The number of women representatives in the cabinet reflects otherwise.

Further claims of 3 Crore Women benefited through Lakhpati Didi Abhiyan but the significant gender gap in workforce participation cannot be overlooked, especially when there's a young and educated female demographic ready to contribute. It's not enough to rely solely on microfinance schemes. We urgently need more affordable childcare options, safe transportation, flexible work arrangements, and measures to address unconscious biases in recruitment and career progression. These are the real barriers that limit women's potential in the Member of Parliament, Lok Sabha Supriya Sule labour force. While rural women self-help groups have their role, the challenges faced by working women in urban areas are markedly different and demand targeted solutions.

The Free Ration and Affordable (Cheap) rates of Cylinder are not as helpful as being. Over the past five years, the cost of meals has surged by a staggering 71%, while salaries have only increased by a mere 37%, highlighting an alarming disparity that disproportionately affects households with regular salaried individuals. In Maharashtra, the average cost of a home-cooked vegetarian thali has risen by 71%, with a recent Crisil report revealing a 7% increase in March compared to the previous year. Particularly troubling are the price hikes of essential ingredients: onions, tomatoes, and potatoes, which have seen increases of 40%, 36%, and 22% respectively. This stark contrast between rising food costs and stagnant wages underscores the mounting financial pressure on ordinary families.

There has been mention of Last Mile Delivery approach of the Government has supported lot of families and specially Adivasis. However, arguably the biggest leader of the Adivasis Mr. Hemant Soren was incarcerated for 6 months for political reasons.

With the support of Government, 25 Crore Indians have come out of poverty. But it's hard to understand how Niti Aayog claims its poverty numbers are accurate when no third party, including the World Bank and the IMF, supports these figures. Niti Aayog has set its own standards for measuring poverty, but why were these particular standards chosen? They seem to be based on the Government's flagship schemes, which raises questions about their objectivity. The national multidimensional poverty measures look at deprivations across three dimensions- health, education, and standard of living each given equal weight. These dimensions are assessed using 12 indicators that align with sustainable development goals. The indicators include nutrition, child and adolescent mortality, maternal health, years of schooling, school attendance, cooking fuel, sanitation, drinking water, electricity, housing, assets, and bank accounts. Niti Aayog's National Multidimensional Poverty Index (MPI) employs the Alkire Foster methodology to gauge the decline in poverty rates. However, while the National MPI uses 12 indicators, the global MPI only uses 10.

In COVID time Government gave free ration to 80 Crore people under PM Garib Kalyan Anna Yojana. The 2023 Global Hunger Index paints a stark and troubling picture of hunger in India, ranking it 111 out of 125 countries. This dismal ranking places India behind all its neighbours: Pakistan is at 102, Bangladesh at 81, Nepal at 69, and Sri Lanka at 60. According to the index, 16.6% of India's population is undernourished, and the under-five mortality rate is 3.1%. Even more alarming is the prevalence of anaemia among women aged 15 to 24 years, which stands at an astonishing 58.1%. These statistics are a clear admission of the severe hunger crisis and nutritional deficiencies plaguing the country. 16. Solar panels are being installed on the rooftops of houses under PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. But there are plethora of complaints made regarding the scheme as they are facing problems ranging from installation to website not working properly. Once we bring in a policy, we must implement it end to end.

I would like to address some critical concerns that have been persistently overlooked, despite the appreciation for the efforts made thus far. While it is commendable that work is being carried out, there are significant underlying

issues that demand more strategic planning and dedicated attention. Merely completing tasks is not sufficient. Maintenance and aftercare are integral parts of any successful project. Unfortunately, this is where we see a glaring deficiency. It is not enough to just perform the work; it must be executed with thoroughness and precision, only then can it be considered truly complete and effective. What we are witnessing is a troubling trend of enacting laws without proper consultation with the opposition. This approach not only undermines the democratic process but also results in legislation that lacks broader acceptability and support. The absence of comprehensive dialogue and consideration of diverse viewpoints leads to laws that are perceived as undemocratic and, in many cases, counter-productive. It is essential to understand that the strength of our democracy lies in inclusivity and collaboration. When laws are passed without the involvement and consensus of all stakeholders, they fail to represent the interests of the entire populace. This exclusionary practice is detrimental to the very fabric of our democratic institution. The only aim is just not to complete the tasks but also ensure they are carried out with the highest standards of quality and inclusiveness.

DR. T. SUMATHY ALIAS THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): I would like to take this opportunity to express my gratitude and Indebtedness to our great leader and mentor Dr. Kalaignar. My sincere thanks to our beloved Chief Minister of Tamil Nadu, Philosopher and Guide Thalapathy Thiru M.K. Stalin for providing me this opportunity to express my views.

We have great pride to say that we belong to the Dravidian Stock. Dravidians have a special trait conqueror of the conquered. It's the Dravidian trail enshrined in the annals of the Periplus of the Erythraean Sea. The same never say die attitude was demonstrated by the people of Tamil Nadu. The hon. Chief Minister of Tamil Nadu is spearheading the Dravidian Model Government in Tamil Nadu.

The present Union Government with a fractured mandate has failed to address the economic and agrarian crisis and rise upto the expectation of the people who gave them a clear mandate in the past ten years. Now they have downsized them to a minority.

First of all I deeply regret that the hon. President's address does not mention several issues which affects the life and nature of the poor middle class people. The insensitive economic policies of the Government have led to the lower GDP and

loss of employment in the country. Hon. President's Address does not mention anything about the growing unemployment and the job loss in the country and also the failure of the present Government in providing employment to the two crore people every year as promised. It is really unfortunate that the President's address fails to mention the reason for mounting miseries on the people due to economic recession and the failure of the Government to tackle the economic crisis. There is no comprehensive policy for the India's 8 million differently-abled population whose interest cannot be protected in the absence of institutional mechanism. The address does not mention about the steps taken by the Government in this important issue. The Government should have statutory plans for compensation to the victims of violence especially the victims of communal riots and rehabilitation to such victims. We Tamil people share an umbilical tie with the Srilankan Tamils and our Leader Dr. Kalaignar has stood his grounds for their rights and welfare. There is a need to amend the Citizenship Amendment Act 2019 to confer citizenship to Sri Lankan Tamils who are staying in refugee and rehabilitation camps in Tamil Nadu as refugees for more than 5 years. They should be recognised as citizens of our country. There is an urgent need to pass a resolution for constituting an International Court of inquiry into the missing of thousands of Tamilians during the ethnic war in Sri Lanka. It is so disappointing to note that the President's Address does not mention about the need to include all the languages listed in the Eighth Schedule of the Constitution as official languages of the Union and also does not mention about the need to amend the Constitution of India in order to transfer the residuary powers, from the Central sphere to the State sphere.

Our Party Leader Thiru M.K. Stalin has submitted a detailed memorandum voicing the concerns and anxieties in implementing the New Education Draft Policy to the Central Minister for Education. D.M.K. Party has always opposed (and will continue do so) the implementation of NEET as it poses a grave threat to the cause of Social Justice and Empowerment. There is an urgent need to discontinue NEET in the State of Tamil Nadu in view of large scale injustice imposed on the rural poor students who do not have the wherewithal to prepare for the costly NEET exams. If you look at the precarious condition and the unfaithful manner NEET is being conducted, plagued by question paper leaks and mishandling it is high time the Government should withdraw the NEET exams and go back to the robust system practised earlier. Otherwise the chaos will continue and genuine. There is a growing intolerance manifesting the violence and spread of communal polarization in the country and this very fact is conspicuously absent in the President's address.

There is no mention in the Address about tackling global economic recession affecting Indian industries and loss of jobs of lakhs of workers and employees especially in our indigenous industries. There is no mention in the Address about lakhs of job lost in India during the last 5 years as a result of privatization of the PSUs as well as disinvestment. The growing incidence of child abuse and trafficking of women and children in the country is really worrying factor. The failure of the Government to take effective measures to tackle this very important problem is unreasonable and unpardonable.

The growing incidence of 'paid news' in every sphere of media viz. print, television and social media that has become a dangerous phenomenon world distorting parliamentary democracy. There is no mention in the Address about the failure of the Government to curb and control the menace of fake news and paid news in the country.

The mounting increase of NPA's in PSU Banks affecting their financial health as well as loss of public faith in the financial system is a great threat to the economic freedom of the people. Government instead of punishing the culprits and wilful corporate defaulters candidly help them to get away with it. There is no mention in the address about this grievous situation arising out of NPAs in PSU Banks.

There is no reason why the price of petrol and diesel were raised, even when the prices of crude oil in the international market is declining. The Government has failed miserably to bring down the petrol and diesel prices that too when the crude oil price is very less in the international markets. Students will be betrayed by the system. when a system is corrupt and unwieldy it is better to abandon than to continue with same corrupt practices. People have lost faith on NEET and other exams conducted by the NTA. The integrity and transparency is missing. Very important issues like the need to find a solution to the Indian fishermen row on the fishing rights in the Palk Bay Strait and Gulf of Manner and the need to provide proper protection to the fishermen from the harassment of Sri Lankan Navy is not mentioned in the President's Address. There is a need for providing proper medical facilities for fishermen and their families.

The appropriate steps and effective measures needed to arrest the steep fall in the ground water level and to encourage rain water harvesting in the country is not addressed in the President's address and we can only regret that it does not mention either about linking rivers, especially Godavari and Cauvery, Krishna to Pennar and Pennar to Cauvery. It is unfortunate that the President's address does

not show any interest in resolving the water disputes among different states in the country.

Baba Saheb Ambedkar has said "My ideal would be a society based on Liberty, Equality, and Fraternity... Democracy is not merely a form of Government... It is essentially an attitude of respect and reverence towards one's fellow men". I consider myself a privileged person for being a product of the Dravidian philosophy propounded by Thanthai Periyar, proposed politically by Perarignar Anna, propagated by Muthamizh Arignar Dr. Kalaignar and protected by our beloved leader Thalapathy Thiru. M.K. Stalin. Tamil Nadu has been the pioneering champion to achieve the social justice, liberty and equality for all people. The Justice party which heralded the Social Justice Movement in India during British Raj, followed by Thanthai Periyar's Dravidar Kazhagam worked on the principles of Self Respect, Social Justice and Equality. Any Government in India should religiously follow these ideals as its motto, the mantra which encompasses social justice, equality, respect and equal opportunities.

A Government which professes so much about the welfare of kisan, farmer has totally ignored about their prosperity. It is unfortunate that the President's Address does not mention about the need to implement fully the recommendations of the M.S. Swaminathan Committee for the welfare of farming community and the need to provide remunerative prices to farmers for their agriculture produce in order to save them from abject poverty and miserable conditions, leading to suicides. It is indeed a great achievement of the farmers of the country whose untiring hard labour has showed the world that farmers feed the people of all walks of life. It's true that many countries have experienced scarcity of foodgrains and faced starvation during the Corona crisis. But we in India have ensured that nobody remained hungry during the worst pandemic. The credit goes to our farmers and sons of the soil. *Uzhudhuntu Vaazhvaare Vaazhvaarmatr Rellaam Thozhudhuntu Pinsel Pavar* which means, they alone live who live by agriculture; all others lead a cringing, dependent life. I would like to give maximum credit to the small farmers of the country for this consistent success and strengthening the agriculture sector. Under the PM-Kisan Samman Nidhi, I would like to suggest that the Government should increase this to Rs. 12,000 per annum and also include the landless agricultural workers who are the backbone of the country.

It is very important to protect the health of all citizens from the risks associated with any future pandemic. To mitigate these risks, the role of the health insurance

sector becomes even more vital, necessitating a collaborative effort to improve health insurance penetration and the development of healthcare facilities across the country.

Dr. Kalaignar has achieved this in Tamil Nadu 15 years back. In Tamil Nadu any patient can enter into most of the hospitals and get proper medical care and come out of the hospital with all the required medicines, all at free of cost. The people of Tamil Nadu are indebted to DMK Government for having created such large number of top-quality medical infrastructure in Tamil Nadu

Tamil Nadu, being a front runner in the field of medical care and medical infrastructure development, has become the Medical Hub of the South Asia. Health facilities are now easily accessible to the common people because of the responsive policies of our State Government. We are ever grateful to the Government of Tamil Nadu in achieving this great success.

Health and Education are the two eyes of the Nation. Health and Education are the real wealth of the Nation. The country which focuses more on good Health and Education will prosper under any crisis. I wish the union Government should allocate 6 per cent of our GDP each for both Health and Education. All we need is, will power with strict discipline, undaunted dedication and the spirited determination to do that.

I would like to record in the august House that after ten years of this Government, the Nari Shakti is in danger; the Yuva Shakti is in deep distress and the elderly population is betrayed. Women of this country are suffering from oppression, gender inequality, deprived of their education and socio-economic rights as the violence against the women is at its highest, but the Government is shying away from its constitutional obligations. From the brute majority enjoyed from 2014 to 2024 the BJP has been reduced to minority. The people of this country have understood clearly that they are betrayed by your hypocritic approach.

Before I conclude my speech, I would like to remind the people in power that now you have somehow managed to form the Government. In Tamil there is a saying "*Thalai Thappiyathu Thambiran Punniyam*" But remember the people of the country are watching. If you continue to betray the aspirations of the people, especially the youth, women, poor labour and middle-class population of the Nation, they will show you the exit door. It will not be far too long for the entire country to follow the footsteps of Tamil Nadu. Thank you.

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) **:** सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है । मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की महान जनता का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिसने एक अहंकार को तोड़कर एक मजबूत सरकार बनाने का काम किया । साथ ही साथ मैं अयोध्या मंडल की महान जनता का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिस महान जनता ने उस मंडल की पांच की पांच सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को तोड़ने का काम किया है ।

मान्यवर, माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा सरकार ने अपनी जो बातें रखी हैं, उनके अंतर्गत चुनाव आयोग का आभार व्यक्त किया है । निश्चित रूप से सरकार को चुनाव आयोग का आभार व्यक्त करना चाहिए क्योंकि यदि यह सरकार बनी है, तो ...

माननीय सभापति **:** श्री लालजी वर्मा जी, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं । आप कह रहे है कि यह सरकार ... आप जानते हैं कि चुनाव आयोग कांस्टीट्यूशनल बॉडी है । आपने स्वयं कहा है कि आप अयोध्या की पांचों सीटें जीत गए हैं । चुनाव आयोग की निष्पक्षता के कारण ही ऐसा हुआ होगा ।

श्री लालजी वर्मा **:** सभापति जी, यदि निष्पक्ष चुनाव हुआ होता, मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हुआ होता और जगह-जगह खुलेआम धन और दारू का प्रयोग न हुआ होता, तो अकेले उत्तर प्रदेश में बीस सीटें इंडिया गठबंधन की ज्यादा आतीं ।

माननीय सभापति **:** आप मतदाताओं पर सवाल उठा रहे हैं ।

श्री लालजी वर्मा **:** सभापति जी, चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ । जिस तरह से 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जो वायदा वर्ष 2014 में किया था, उस वायदे पर पूरी तरह से यह सरकार फेल हुई है । महंगाई को समाप्त करने का वायदा था । बेरोजगारी को समाप्त करने का वायदा था लेकिन इस सरकार ने क्या दिया है? प्रधान मंत्री जी की सरकार ने आम जनता के लिए महंगाई की गारंटी दी है । छात्रों के लिए पेपर लीक की गारंटी दी है । युवाओं के लिए बेरोजगारी की गारंटी दी है । यात्रियों के लिए हादसों की गारंटी दी है । किसानों को कर्जदार बनाने की गारंटी दी है । छोटे उद्योगों को बरबादी की गारंटी दी है । बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर के अथक प्रयासों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिला । बड़े संघर्षों के बाद मंडल आयोग के माध्यम से पिछड़ी जाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी मिली । भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस आरक्षण पर ... डालने का काम किया । विभिन्न वर्गों को आरक्षण का लाभ न मिल सके, इसलिए निजीकरण करने का काम किया और जो नौकरियां बची भी हैं, उनमें आरक्षण पर ?नॉट फाउंड स्यूटेबल? की गारंटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है । किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की लीगल गारंटी नहीं दी ।

मान्यवर, माननीय अनुराग ठाकुर जी के द्वारा लगभग एक घंटे से ज्यादा का समय लेकर महामहिम के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, लेकिन उनकी बात से यह झलक रहा था कि उन्हें मंत्री न बनाए जाने की चिंत सता रही है और इसलिए बार-बार पानी पीकर भी वे सरकार की तारीफ नहीं कर पा रहे थे ।

मान्यवर, आज ओबीसी का जो आरक्षण है, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विभिन्न संस्थाओं में पूरी तरह से खत्म किया है । उत्तर प्रदेश में 34 विश्वविद्यालय हैं । उन 34 विश्वविद्यालयों में जो वाइस चांसलर्स हैं,

उनमें ?पीडीए? के एक या दो हैं, बाकी कोई भी नहीं है । इसी तरह से, विभिन्न जिलों में जो सरकारी अधिकारियों की पोस्टिंग होती है, उसमें भी इन वर्गों की उपेक्षा की जाती है ।

मान्यवर, मैं आपके दृष्टांत में लाना चाहता हूं कि किस तरह से रिज़र्वेशन के साथ अन्याय हो रहा है । दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कॉलेज में ओबीसी श्रेणी के लिए बुलाए गए भर्तियों की संख्या 377 थी । उसके लिए जो क्वालीफाइड थे और 377 लोगों के इंटरव्यू के बाद, कुल विज्ञापित पद में से अनरिज़र्व्ड के 1 पद, ओबीसी के लिए 1, ई.डब्ल्यू.एस. के 1 पद थे । उसमें 377 लोग एलिजिबिल थे । उसके बाद उसमें लिख दिया गया ? ?नॉट फाउंड सूटेबल??, यानी श्रीराम कॉलेज में 377 में से एक भी कैंडीडेट सूटेबल नहीं थे । उसी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हुए पी.एच.डी. और नेट क्वालीफाइड लोगों में से एक भी कैंडीडेट सूटेबल नहीं पाए गए ।

माननीय सभापति **:** माननीय सदस्य, यह आपकी मेडेन स्पीच है, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से 9 सदस्यों के नाम आए हैं । कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

श्री लालजी वर्मा **:** मान्यवर, मैं बस एक-दो मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं ।

मान्यवर, इसी तरह से, उत्तर प्रदेश में एस.जी.पी.जी.आई. एक बड़ी अच्छी संस्था है । अभी वहां इंटरव्यू हुए । 48 पद एस.सी., ओबीसी के लिए रिज़र्व थे । उन 48 पदों में से माइक्रोबॉयोलॉजी का एक पद था, एक पद अनुसूचित जाति के लिए रिज़र्व था । के.जी.एम.यू. से पढ़ी हुई एक लड़की इंटरव्यू देने गयी । उसे के.जी.एम.यू. में 15 गोल्ड मेडल्स मिले थे । पर, उसके लिए उसे ?नॉट फाउण्ड सूटेबल? कर दिया गया । वह उसके लिए भी एलिजिबिल नहीं थी ।

मान्यवर, इसी तरह से, न्यूरोलॉजी में दो पद थे, जिनमें से एक अन-रिजर्व्ड था, एक ओबीसी के लिए रिज़र्व था । वहीं से पास-आउट हुए दो छात्र थे । वे के.जी.एम.यू. में दो साल असिस्टैंट प्रोफेसर रहे । जो अन-रिज़र्व्ड था, उसके लिए जो प्रवेश परीक्षा थी, उसमें उसकी मेरिट नीचे थी । वह जनरल सीट के लिए क्वालीफाइड हो गया, पर ओबीसी सीट के लिए ?नॉट फाउण्ड सूटेबल? हो गया ।

मान्यवर, मैं अपनी बात बस एक मिनट में खत्म कर रहा हूं । मैं अपनी मर्यादा को समझता हूं ।

मान्यवर, जिस तरह से पूरे देश में और प्रदेश में आज अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों के पदों के साथ, जो उसमें एक्सपर्ट बनाए जाते हैं, उसमें तीन के तीन एक्सपर्ट सामान्य वर्ग से बना दिए जाते हैं । उसमें रिज़र्वेशन नहीं है । इस तरह से, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है । इसने मंत्रिमंडल बनाने का भी काम किया । यह कहा जाता है कि माननीय प्रधान मंत्री स्वयं एक ओबीसी हैं, लेकिन उसके बाद भी ओबीसी के लोगों के साथ, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ इस तरह से अन्याय हो रहा है ।

मान्यवर, मैं यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने 30 लोगों को जो कैबिनेट मंत्री बनाया है, उसमें भी हिस्सेदारी देने का काम नहीं कर रही है । आज किसानों की फसलों का जो समर्थन मूल्य है, यह कहा गया था कि किसानों की आमदनी दोगुनी की जाएगी, आमदनी तो दोगुनी नहीं हुई, पर उनकी कॉस्ट-ऑफ-प्रोडक्शन लागत दोगुनी हो गयी ।? (व्यवधान)

मान्यवर, यह मेरी पहली स्पीच थी । मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । चाहे वे बुनकर हों, किसान हों, छात्र हों, आज उनके साथ अन्याय हो रहा है ।

श्री पी. पी. चौधरी (पाली) **:** सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर अनुराग ठाकुर जी के द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचार रखने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ।

सभापति महोदय, बहुत खुशी की बात है कि गुलामी से मुक्ति, अगर हम देखें तो पहली बार पिछले दस सालों में हमें प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देखने को मिली है । मेरा प्रोफेशन वकालत का है । मैंने 43 साल के अपने प्रोफेशन में देखा कि पहल इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड और एविडेंस एक्ट होते थे, ये एक गुलामी की देन थी और उसमें सिर्फ और सिर्फ सज़ा देने का प्रावधान था, वे न्याय की बात नहीं करते थे । क्योंकि अंग्रेज़ों ने कानून अपने हिसाब से बनाए थे । लंबे समय तक किसी ने यह अहसास नहीं किया और पहली बार हम यह देखते हैं कि यह अहसास प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया । नए कानून एक जुलाई से लागू हो गए और पूरे देश में आम जनता में इस बात के लिए हर्ष है कि अब समय पर कार्रवाई होगी । जो हम हमेशा देखते थे कि न्याय में डिले हो रहा है, वह नहीं होगा और ये कानून अब सज़ा के लिए नहीं, न्याय के लिए हैं । दोनों पक्षों के न्याय के लिए हैं । पहले सिर्फ इनकी जो एप्रोच थी, वह सज़ा की थी । यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है ।

सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो पिछले दस सालों में एक संकल्प रिफॉर्म, परफॉर्म एण्ड ट्रांस्फॉर्म का रहा है, जो दस सालों में मोदी जी का विज़न देश के लिए रहा है, अगर हम इन दस सालों की तुलना करें, देश आज़ाद होने के बाद के पीरियड की तुलना करें तो हम पाएंगे कि दस सालों में जो भारत की अर्थव्यवस्था 11 वें नंबर पर थी, वह मोदी जी के राज के दौरान 5 वें नंबर पर आ गई । जिस हिसाब से जो ग्रोथ रेट चल रही है, अगले आने वाले कुछ ही वर्षों में हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे । यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पूरे देशवासियों के लिए बहुत हर्ष की बात है । यही नहीं वर्ष 2021 से 2024 के बीच में आठ प्रतिशत की रफ्तार से विकास और ग्रोथ हुई है । जबकि समय सामान्य नहीं था । सौ सालों के दौरान कोविड जैसी बड़ी आपदा नहीं आई थी और भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी ही है, जो कि प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कहीं भी किसी भी रूप में नहीं लड़खड़ाई । इसलिए साफ जाहिर होता है, आज पूरे विश्व में भारत का 15 पर्सेंट योगदान दुनिया की ग्रोथ में है । यही कारण है कि आज भारत का मान और सम्मान पूरे विश्व में है । यही कारण है कि आज मोदी जी को पूरे देश ने तीसरी बार प्रधान मंत्री बनाया है क्योंकि उनकी लीडरशिप पर, उनकी गवर्नेंस पर जनता को विश्वास है । पिछले दस सालों में जिस हिसाब से चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे युवा सशक्तिकरण हो, भिन्न-भिन्न योजनाओं के द्वारा इनके सशक्तिकरण में हमेशा ध्यान रखा गया है । यही नहीं विश्व की सबसे बड़ी योजना, 80 करोड़ देशवासियों को को मुफ्त अनाज पिछले कई सालों से दिया जा रहा है । यह व्यवस्था विश्व में और कहीं नहीं है, सिर्फ भारत में है और बिना किसी भेदभाव के है । यह अपने में बहुत बड़ी बात है । चाहे हम ग्रामीण विकास देखें, चाहें शहरी विकास देखें । ग्रामीण विकास में पिछले दस सालों में करीब तीन लाख 80 हज़ार किलोमीटर की सड़कें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी हैं । अगर हम इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे नेशनल हाइवे की बात करें, चाहे एक्सप्रेस वे की बात करें, चाहे रेलवेज़ के इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात करें, साफ जाहिर हो रहा है कि पिछले दस सालों में विकास हुआ है । मैं किसानों के बारे में कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूँ तो यह पहली बार हुआ है कि पीएम किसान सम्मान निधि के पिछले दस सालों में करीब तीन लाख 20 हज़ार करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में गए हैं । मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहूंगा कि क्या कभी इस तरह की योजना किसानों के लिए कोई भी सरकार ले कर आई है? यह सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांस्फर द्वारा राशि दी गई जो भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ती है ।

14.00 hrs

अगर हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को देखें तो पहले जो पैसा लिकेज हो रहा था, वह लिकेज होने से बचा है । एमएसपी के ऊपर भी किसानों के लिए रिकॉर्ड स्तर पर काम किया गया । सहकारिता के लिए अलग से मंत्रालय बना है । फार्मर्स प्रोडयूसर्स ऑर्गनाइजेशंस, पैक्स यानि ग्राम सेवा सहकारी समिति का नेटवर्क पूरे देश में बनेगा । इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी । श्रीअन्न यानी मोटे अनाज को आज सुपर फूड के रूप में अपनाया जा रहा है और एक यह फैशन हो गया है । पूरे विश्व में पहले कोई बाजरा नहीं खरीदता था । आज मोटे अनाज खरीदने का फैशन हो गया है । स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लोग मोटे अनाज को यूज कर रहे हैं । अब मोटे अनाज का निर्यात भी होगा और उससे हमारे किसानों को भी फायदा होगा ।

सभापति महोदय, अभी हाल ही के चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से संचार क्रांति का, एक टेक्नोलॉजी का, चाहे इनसाइड इंडिया हो, चाहे आउटसाइट इंडिया हो, दुरुपयोग किया गया । विघटनकारी ताकतों द्वारा लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, समाज में दरारें डालने के लिए अफवाह फैलाई गई, असत्य फैलाया गया, जनता को गुमराह किया गया और भ्रम फैलाया गया । जनता में मिसइंफॉर्मेशन फैलाया गया कि चुनाव में अगर बीजेपी जीत गई तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा । आम जनता में एक तरह से असत्य फैलाया गया । जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इनके असत्य पर विश्वास नहीं किया और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार चुन कर भेजा ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** कृपया *?* को आप असत्य कह सकते हैं । *?* is an unparliamentary word. *?* की जगह पर आप असत्य कहें ।

श्री पी. पी. चौधरी **:** यस, सर । इस तरह से यह बेरोक-टोक नहीं चलने दिया जाएगा । इसमें मानवता के विरुद्ध बहुत गलत उपयोग हुआ है । मैं कहूंगा, क्योंकि यहां कांग्रेस के साथी भी बैठे हैं, विपक्ष के अन्य साथी भी बैठे हैं, इन्होंने असत्य का एक जेनरेटर के रूप में काम किया है ।? (व्यवधान)

सर, कल यहां पर राहुल गांधी जी बोल रहे थे । मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने हिन्दू समाज को हिंसकवादी कहा, नफरत करने वाला समाज कहा, इस बात के लिए पूरे देश का हिन्दू समाज बहुत नाराज है । इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए । यही नहीं, अग्निवीर के मामले में भी उन्होंने पार्लियामेंट में सही तथ्य नहीं रखा है । हमारे रक्षा मंत्री जी ने उसी समय इस बात को बताया । अभी हमने देखा कि हमारे विपक्ष के साथी जब शपथ ले रहे थे तो वे भारत के संविधान को लेकर शपथ ले रहे थे । ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने संविधान के ऊपर सबसे बड़ा हमला किया, संविधान को तार-तार किया, वे संविधान की बात कर रहे हैं । हम इमरजेंसी की बात करते हैं, लेकिन इमरजेंसी क्यों लगी, इस तथ्य में जाना जरूरी है । इमरजेंसी इसलिए लगी कि वर्ष 1971 में कांग्रेस को 352 सीटें मिलने के बाद इंदिरा गांधी जी का चुनाव कोर्ट ने निरस्त कर दिया था । जब कोर्ट ने उनका चुनाव निरस्त कर दिया, तो भारत के संविधान में संशोधन किया गया कि प्रधानमंत्री के चुनाव को चैलेंज नहीं किया जा सकता । इसके लिए आंदोलन हुआ था । मैं अपने सदस्यों को धन्यवाद दूंगा, हमारे समाजवादी पार्टी के साथी बैठे हैं, डीएमके के साथी भी बैठे हैं और आरजेडी के साथी भी बैठे हैं । हमारे नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद जी, करूणानिधि सहित सारे लोगों ने आवाज उठा कर आंदोलन किए । आज मुझे इस बात का अचरज हो रहा है कि इनके लोग इंडिया एलायंस के साथ जुड़े हुए हैं । इनकी विचारधारा इनसे नहीं मिलती है ।

महोदय, जब हमारे माननीय स्पीकर महोदय का भाषण हो रहा था और हम लोग सम्मान देने के लिए खड़े हुए थे, उस समय जो स्थिति थी, उसमें कांग्रेस और आप लोगों की स्थिति से ऐसा लग रहा था कि आप लोगों का मेल-जोल लंबा चलने वाला नहीं है । मैं मानता हूं कि संविधान के प्रति आपकी विचारधारा है । चाहे हमारे

समाजवादी पार्टी के साथी हों, चाहे आरजेडी के साथी हों, चाहे डीएमके के साथी हों, आप सभी की संविधान के प्रति जो विचारधारा है, वह कांग्रेस से मेल नहीं खाती है । जिस तरह से ढोंग रचा गया और भारत के संविधान को दिखा कर शपथ ली गयी, आम जनता जब इमरजेंसी को याद करती है तो उनको पता लगता है कि संविधान पर सबसे बड़ा हमला किसने किया है ।

जब इमरजेंसी लगी, उसके दौरान आप याद करिए कि किस तरह से कमिटेड जुडीशियरी बनाने के लिए, गोलकनाथ के केस में, केशवानंद भारती के केस में, एडीएम जबलपुर के केस में जब सर्वोच्च न्यायालय की संविधान की पीठ ने यह निर्णय दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता, फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं किया जा सकता, आपने इमरजेंसी में बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किया । सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को इमरजेंसी के दौरान जब सारे नेता, मुलायम जी, लालू जी, करुणानिधि जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, देश के सब बड़े-बड़े नेता जेल में थे, तब आपने भारत का संविधान बदला, जो ये संविधान की बात करते हैं । भारत का संविधान बदला, उसमें अमेंडमेंट किए और संविधान बदलकर पार्लियामेंट का टेन्योर एक साल बढ़ाया । भारत के इतिहास में संविधान पर इससे ज्यादा कोई हमला नहीं हो सकता । आम जनता अब इस बात को समझती है । इनकी इस तरह की कार्यवाही आगे चलने वाली नहीं है । जिन जजेज़ ने खिलाफ फैसला दिया, अगर उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, उनको सुपरसीड किया गया । उनके जूनियर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया । उनको रिजाइन भी करना पड़ा । आज तक भारत के इतिहास में जो जुडीशियरी का गला इमरजेंसी के दौरान और इंदिरा गांधी के राज में घोटा गया, कांग्रेस के द्वारा उनके पीरियड में जो हुआ, ऐसा पूरे इतिहास में कभी नहीं हुआ । आज जुडीशियरी लोकतंत्र का बहुत बड़ा भाग है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन उस समय जुडीशियरी कंप्लीटली कमिटेड थी । उन्हीं लोगों का प्रमोशन होता था, वही चीफ जस्टिस आफ इंडिया बनते थे, जो कि सरकार के साथ रहते थे ।

आप दलितों की बात करते हैं । अंबेडकर जी को आपने क्या ट्रीटमेंट दिया? जब मोदी जी उनको आगे लाने लगे तब आप दौड़कर आने लगे । आपने वर्ष 1946 में उनको कांस्टीट्युएंट असेंबली का मेंबर नहीं बनने दिया । उनको बंगाल से, जो कि अभी बांग्लादेश में है, वहां से आना पड़ा । उसके बाद वर्ष 1952 में लोक सभा चुनाव में नेहरू जी ने उनके खिलाफ प्रचार करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हराया । वर्ष 1954 में बाई इलेक्शन हुए, उसमें भी आपने अंबेडकर जी को हराया । आप दलितों की बात करते हैं तो एक मजाक सा लगता है, एक नाटक सा लगता है ।

भारतीय जनता पार्टी ने प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जिस हिसाब से देश के दलित नेता हैं, जिनको हम बहुत मान और सम्मान देते हैं, क्योंकि उनका लेवल ऐसा था । नेहरू जी को हमेशा डर रहता था कि अंबेडकर जी मेरे बराबर के नेता हैं, उनको कैसे दबाया जाए । उनको हमेशा दबाने की कोशिश की गई । प्रधान मंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी जब भी पॉवर में थी, उनके द्वारा हमने पंच तीर्थ तैयार किए । चाहे उनके जन्म स्थान महू में हो, चाहे दिल्ली में उनका घर हो, चाहे 15 जनपथ ऑडिटोरियम हो, चाहे मुंबई में उनका क्रिमिनेशन स्थान हो, चाहे लंदन में जहां वे पढ़े हैं, वह हो, इसके अलावा भारत रत्न किसी ने उनको देने का काम किया तो माननीय अटल बिहारी जी की स्ट्रेंथ पर उनको भारत रत्न दिया गया । कहने का मतलब यह है कि भले ही ये दलितों की बात करें, लेकिन दलितों के लिए कुछ नहीं करते हैं । गरीबी हटाओ तो नहीं, लेकिन गरीबों को जरूर इन लोगों ने हटा दिया है । कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है ।

मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूं कि वे विपक्ष के नेता बने । लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़कर यह निवेदन भी करता हूं कि विपक्ष का रोल बहुत बड़ा है और आप मर्यादा के साथ-साथ परिपक्वता रखें । मुझे पूरा विश्वास है

कि आने वाले टाइम में पूरी परिपक्वता को वे प्रदर्शित करेंगे । इस तरह से इममैच्योरिटी से, जिस हिसाब से सदन की गरिमा पूरे देश में घटी, पूरे विश्व में घटी, इस तरह की बात वे नहीं करेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

_____

14.10 hrs

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT?S ADDRESS-Contd..

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) **:** मोहतरम चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं शुरूआत में बताना चाह रहा हूं कि हुकूमत की तरफ से लाये इस रिजोल्यूशन की मुखालिफत में बोल रहा हूं । मैंने प्रेसिडेंट एड्रेस के लिए अमेंड्मेंट्स भी दिए हैं ।

चेयरमैन साहब, आप उर्दू जानते हैं, किसी एक शायर ने शायद बर सरे इकितदार जमात़ के लिए यह शेर कहा होगा,

ऊसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम

वतन का पास तुम्हें था न होगा कभी अपने हिर्स के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम

इज्ज़ते नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं अब तो अपने ही निगाहबान से डर लगता है,

डंके की चोट पर जालिम को बुरा कहता हूं, मुझे सूली से न जिदांनों से डर लगता है ।

मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं आज इन लोगों की तरफ से बोल रहा हूं जो दिखते तो हैं, जिनके बारे में बात तो होती है लेकिन उनकी नहीं सुनता । मैं उनके बारे में बोल रहा हूं जिनके बारे में वजीरे आजम मोदी ने कहा था कि घुसपैठिए हैं । मैं उन बेटियों और माँ के बारे में कह रहा हूं जिनके बारे में मोदी ने कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मैं उन मासूम नौजवानों के बारे में कह रहा हूं जिनको मॉब लिचिंग के जरिए मारा जा रहा है । मैं उन बेजुबान माँ और बाप के बारे में बोल रहा हूं जिनकी आज औलाद इस हुकूमत के गलत कानून के चक्कर में जेलों में सड़ रही है । मैं इस ऐवान में दस्तूर बन रहा था, संविधान बन रहा था, उस वक्त ऐलिहदा वोटर लिस्ट और इंतखाबी रिजर्वेशन की बात आयी तो उस वक्त के हमारे फाउन्डिंग फादर ने हमारे बुजुर्गों ने दोनों समुदाय हिन्दू और मुसलमानों ने फैसला किया कि हम इस पर राजी नहीं होंगे, बल्कि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ऐलाइहदा वोटर्स लिस्ट और इंतखाबी रिजर्वेशन की मुखालिफत की थी । उन्होंने कहा था, it is the duty of majority community to ensure that minorities are elected in the representative numbers. बीजेपी मुसलमानों की नफरत पर जीतती है और मुसलमानों के नाम-निहाद मसीहा, मुसलमानों के 90 प्रतिशत वोट हासिल करते हैं, फिर भी मुसलमानों के इस ऐवान के दरवाजे नहीं खुलते हैं, सिर्फ चार फीसद मुसलमान जीत कर आते हैं । संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, जिसे चूमा जाए, संविधान एक किताब नहीं है जिसे दिखाया जाए, संविधान एक सिंम्बल भी है ।

HON. CHAIRPERSON : Nothing will go in record.

श्री असादुद्दीन ओवैसी **:** महोदय, संविधान हमारे बुजुर्गों की एक किताब है, हमारे जमूहिरयत को बुजुर्गों ने इस तरह समझा कि इस मुल्क को चलाने के लिए हर समुदाय, मजहब और समाज के मानने वाले लोगों की राय को शामिल किया जाएगा, मगर इस ऐवान में सिर्फ चार फीसद मुसलमान जीत कर आते हैं । जो संविधान से मोहब्बत के दावे करते हैं, उनसे कहूंगा कि कस्टीट्यूएंट्स असेम्बली की डिबेट पढ़ो, नेहरू जी, एच.सी.मुखर्जी और सरदार हुकूम सिंह ने माइनोरिटीज के बारे में क्या कहा था । वतने अजीज़ का मुस्तिकबिल कैसे होगा, जब बीजेपी मुझे गायब करना चाहती है, दीगर हिज्बे इख्तलाफ की पार्टियां के लिए मेरा वजूद सिर्फ वोट डालना, अपनी कब्र में जाकर सो जाना है । इसीलिए आप देखते हैं ये समाजी इंसाफ है कि चार फीसद मुसलमान जीत कर आते हैं । इस ऐवान में ओबीसी समाज के एमपीज अब अपर कास्ट के एमपीज के बराबर हो चुके हैं । ओबीसी समाज के एमपीज अपर कास्ट एमपीज के बराबर हो चुक हैं । 14 फीसद मुसलमान सिर्फ 4 फीसद जीत कर आते हैं । सीएसडीएस का डाटा बताता है कि मुल्क में जो वोट बैंक है, एक मुश्त वोट डालता है वह अपर कास्ट का है । मुसलमान का न कभी वोट बैंक था, न कभी रहेगा । 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिचिंग हुई, 11 घरों को मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजर ने नेस्तनाबूद कर दिया । हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान की दुकान को लूट लिया गया । हिज्बे इख्तिलाफत की पार्टियों की तरफ से सन्नाटा है । ? (व्यवधान) मैं यह बताना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी जी को जो मेनडेट मिला है । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** एक मिनट, आप सब बैठ जाएं ।

मनसुख मांडविया जी ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं ।

? (व्यवधान)

श्रम और रोजगार मंत्री**;** तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री **(**डॉ**.** मनसुख मांडविया**)** : माननीय सदस्य ने अपने प्रारंभिक भाषण में जिस शब्द का प्रयोग किया है, उसे ऑथेंटिकेट किया जाए । उन्होंने उल्लेख किया है कि मोदी के बुलडोजर ने वहां मॉब लिंचिंग की है, उसे भी आथेंटिकेट किया जाए । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** निश्चित तौर से ।

? (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी **:** ठीक है । आप चेयर पर बैठे हैं, मंत्री जी को पेट में दर्द हुआ, माशाअल्लाह, शुक्रिया उनका । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** मंत्री जी की जवाबदेही है ।

? (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी **:** इसमें बुरी बात क्या है? पेट में दर्द हो सकता है ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** यह ठीक नहीं है ।

? (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी **:** ठीक है, दर्द हुआ, दिल का दर्द हुआ । ? (व्यवधान)

सर, नरेन्द्र मोदी जी को जो मेन्डेट मिला है, वह सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की नफरत पर हिंदुत्व की वजह से मिला है ।? (व्यवधान) I would like to say that it is not that Modi is in the dock. Every single person voted him despite his anti-Muslim voice. I would like to tell the Opposition parties that this is not a moral victory for them. This is a victory of majoritarianism. Everyone should contemplate into introspection one thing. Why is it that only the OBCs and upper castes are getting their due representation and not the Muslims? Are we here only to vote for you and not to get elected? If that is the case, please tell us that we are here only to vote for you.

सर, आज भारत के आधे नौजवान बेरोजगार हैं । बेरोजगारी का आलम है कि मोदी सरकार के पांच साल में 75 लाख एस्पिरेंट्स की जिंदगी बर्बाद हो गई । ? (व्यवधान) 6 पेपर्स लीक हुए । बेरोजगारी का आलम यह है कि लोग रशिया जा रहे हैं, वहां जाकर अपनी जान दे रहे हैं । बेरोजगारी का आलम यह है कि नरेन्द्र मोदी सरकार रोजगार का कैम्प नौजवानों के लिए चलाती है कि तुम इज़रायल में जाकर काम करो, उनको कैनन फोडर बना रहे हैं ताकि फिलीस्तीनों की जायदादों को हड़पा जा सके । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आप कन्कलूड करें ।

? (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी **:** अभी मेरा टाइम बचा है । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** कहां बचा है?

? (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी **:** इन्होंने मेरा टाइम ले लिया । आप मुझे दो मिनट दीजिए ।? (व्यवधान)

यह विश्वगुरु की पॉलिसी है कि इज़रायल को 27 टन हथियार जा रहा है । 9 मिलियन भारत के लोग गल्फ में काम करते हैं, क्या असर पड़ेगा? 47,000 इज़रायली फिलीस्तीनी मारे जा चुके हैं । क्या है हमारी पॉलिसी? क्यों हथियार दे रहे हैं? नस्ल कैसी हो रही है?

माननीय सभापति **:** आप महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलिए ।

? (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी **:** मैं उसी पर बोल रहा हूं । इस पर लिखा हुआ है, फॉरेन पॉलिसी में पैराग्राफ 25 देख लीजिए । ? (व्यवधान) सद्र-ए-जमूरिया में सैचुरेशन एप्रोच है ।? (व्यवधान) क्यों नहीं मोदी सरकार माइनोरिटीज़ के लिए फ्री स्कॉलरशिप डिमांड ड्रिवन करती? ? (व्यवधान) आपने इसका बजट कम कर दिया । बनारस के बुनकर 18 महीने से मंदी का शिकार हैं, सूरत और बेंगलुरू जा रहे हैं ।

आखिरी बात, मैं कन्कलूड कर रहा हूं । पन्नू केस में निखिल गुप्ता ? (व्यवधान) मोदी जी ने कहा था कि हमने घर में घुसकर मारा तो निखिल गुप्ता को किसने पन्नू को मारने का ऑर्डर दिया था? ? (व्यवधान) अगर नहीं दिया जो उसे बचाइए । अगर दिया नहीं, तो फिर उस पर पीएमएलए क्यों नहीं लगाते? आपने कमेटी बनाई तो उसका क्या हुआ? हम एससीओ को नहीं जा रहे । मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी इस तकरीर को टीपू सुल्तान की नज़र कर रहा हूं, यह टीपू सुल्तान की फोटो है । क्या आप इससे भी नफरत करेंगे? संविधान में टीपू सुल्तान की फोटो है जिस पर वल्लभ भाई पटेल जी ने साइन किए, श्याम प्रसाद मुखर्जी जी ने साइन किए । यह आपकी नफरत है । ? (व्यवधान)

आखिर में, मैं अपनी बात को शेर के साथ खत्म कर रहा हूं ।

क्या दिन दिखा रही सियासत की धूप-छांव

जो कल सपूत थे, वो अब कपूतों में आ गए ।

जो थे इस कदर अज़ीम कि पैरों में ताज थे,

इतने हुए ज़लील कि अब जूतों में आ गए ।

[جناب اسدالدین اویسی (حیدرآباد): ، محترم چیرمین صاحب، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا میں شروعات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کی طرف سے لائے گئے اس ریزولیوشن کی مخالفت میں بول رہا ہوں۔ میں نے پریزیڈینٹس ایڈریس کے لئے امینڈمینٹس بھی دئے ہیں۔

چیرمین صاحب، آپ اردو جانتے ہیں، کسی شاعر نے شاید برسرِ اِقتدار جماعت کے لئے یہ شعر کہا ہوگا۔

اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں نگاہِ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم

وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی کہ اپنی حرص کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم

عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں

اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے

ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں

مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے

محترم چیرمین صاحب، میں آج اُن لوگوں کی طرف سے بول رہا ہوں جو دکھتے تو ہیں، جنکے ، بارے میں بات تو ہوتی ہے، لیکن کوئی ان کی سُنتا نہیں ہے۔ میں ان کے بارے میں بول رہا ہوں جن کے بارے میں مودی نےکہا تھا کہ گھُس پیٹھئیے ہیں، میں اب بیٹیوں اور ماؤوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں مودی نے کہا تھا کہ زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، میں اب معصوم نو جوانوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کو ماب لنچنگ کے ذریعہ مارا جا رہا ہے۔ میں ان بے زُبان ماں اور باپ کے بارے میں بول رہا ہوں جنکی اولاد اس حکومت کے غلط قانون کے چکر میں جیلوں میں سڑ رہی ہے۔ اس ایوان میں جب دستور بن رہا تھا، آئین بن رہا تھا ، اس وقت علیحدہ ووٹر لِسٹ اور

انتخابی ریزرویشن کی بات آئی تو اس وقت کے ہمارے فاؤنڈنگ فادر نے ہمارے بزرگوں نے دونوں جماعت ہندو اور مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس پر راضی نہیں ہوں گےبلکہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ انہوں نے علیحدہ ریزرویشن لسٹ اور انتخابی ریزرویشن کی مخالفت کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ **It is the duty of majority community to ensure that minorities are elected in the representative numbers.** ۔ بی۔جے۔پی۔ مسلمانوں کی نفرت پر جیت تی ہے اور مسلمانوں کے نام و نہاد مسیحا مسلمانوں کے 90 فیصد ووٹ حاصل کرتے ہیں، پھر بھی مسلمانوں کے اس ایوان کے دروازے نہیں کھُلتے ہیں، صرف چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں۔ آئین صرف ایک کتاب نہیں ہے، جسے چوما جائے، دِکھایا جائے وہ ایک سِمبل بھی ہے۔

محترم چیرمین صاحب، آئین ہمارے بزرگوں کی ایک کتاب ہے، ہماری جمہوریت کو بزرگوں نے ، اس طرح سمجھا کہ اس ملک کو چلانے کے لئے ہر طبقہ، مذہب اور سماج کے ماننے والے لوگوں کی رائے کو شامل کیا جائے گا، مگر اس ایوان میں صرف 4 فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں۔ جو آئین سے محبت کے دعوے کرتے ہیں ان سے کہوں گا کہ کنسٹیٹیوینٹس اسمبلی کی ڈیبیٹ پڑھو، نہرو جی، ایچ۔سی۔ مکھرجی اور سردار حکم سنگھ نے مائینوریٹیز کے بارے میں کیا کہا تھا ۔ وطنِ عزیز کا مستقبل کیسے ہوگا، جب بی۔جے۔پی۔ مجھے غایب کرنا چاہتی ہے، دیگر حزبِ اختلاف کی پارٹیوں کے لئے میرا وجود صرف ووٹ ڈالنا اور اپنی قبروں میں جا کر سوجانا ہے۔ اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سماجی انصاف ہے کہ 4 فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں۔ اس ایوان میں اوبی۔سی۔ سماج کے ایم۔پیز اب اپر کاسٹ کے ایم۔پیز کے برابر ہوں گئے ہیں۔ 14 فیصد مسلمان صرف 4 فیصد جیت کر آتے ہیں۔ سی۔ایس۔ڈی۔ایس۔ کا ڈاٹا بتاتا ہے کہ ملک میں جو ووٹ بینک ہے، ایک مُشت ووٹ ڈالتا ہے وہ اپر کاسٹ کا ہے۔ مسلمان کا نہ کبھی ووٹ بینک تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ 4 جون کے بعد 6 مسلمانوں کی ماب لنچنگ ہوئی، 11 گھروں کو مدھیہ پردیش میں مودی کے بلڈوزر نےنیست و نابود کر دیا۔ ہماچل پردیش میں ایک مسلمان کی دوکان کو لوٹ لیا گیا۔ حزبِ اختلاف کی پارٹیوں کی طرف سے سنّاٹا ہے۔

ٹھیک ہے درد ہوا، دل کا درد ہوا (مداخلت)۔ سر، نریندر مودی جی کو جو مینڈیٹ ملا ہے، وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی نفرت پر اور ہندوتو کی وجہ سے ملا ہے (مداخلت)

سر، آج بھارت کے آدھے نوجوان بے روزگار ہیں۔ بے روزگاری کا عالم یہ ہے کہ مودی سرکار کے پانچ سال میں 75 لاکھ ایسپرینٹس کی زندگی برباد ہو گئی (مداخلت)۔ 6 پیپرس لیک ہوئے۔ بے روزگاری کا عالم یہ ہے کہ لوگ روس جا رہے ہیں، وہاں جا کر اپنی جان دے رہے ہیں۔ بے روزگاری کا عالم یہ ہے کہ نریندر مودی سرکار روزگار کا کیمپ نوجوانوں کے لئے چلاتی ہے کہ تم اسرائیل میں جا کر کام کرو، ان کو کینن فوڈر بنا رہے ہیں تاکہ فلسطینیوں کی جائیداد کو ہڑپا جا سکے (مداخلت) ابھی میرا ٹائم بچا ہے۔ یہ وِشو گرو کی پالیسی ہے کہ اسرائیل کو 27 ٹن ہتھیار جا رہا ہے۔ 9 ملین بھارت کے لوگ گلف میں کام کرتے ہیں، کیا اثر پڑے گا؟ 47000 اسرائیلی فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ کیا ہے ہماری پالیسی؟ کیوں ہتھیار دے رہے ہیں؟ نسل کُشی ہو رہی ہے ۔

میں اسی پر بول رہا ہوں، اس پر لکھا ہوا ہے، فورن پالیسی میں پیراگراف 25 دیکھ لیجئے۔ (مداخلت) صدرِ جمہوریہ میں سیچوریشن ایپروچ ہے۔ (مداخلت) کیوں نہیں مودی سرکار مائینوریٹیز کے لئے فری اسکالرشِپ ڈیمانڈ ڈریون کرتی ؟ (مداخلت) آپ نے اس کا بجٹ کم کر دیا۔ بنارس کے بُنکر 18 مہینے سے مندی کا شکار ہیں، سورت اور بنگلور جا رہے ہیں۔

آخری بات میں کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ پنّو کیس میں نِکھل گُپتا (مداخلت) مودی جی نے کہا تھا کہ ہم نے گھر میں گھُس کر مارا تو نِکھل گپتا کو کس نے پنّو کو مارنے کا آرڈر دیا تھا؟ (مداخلت) اگر نہیں دیا تو اسے بچائیے۔ اگر دیا نہیں تو

پھر اس پر پی۔ایم۔ایل۔اے۔ کیوں نہیں لگاتے؟ آپ نے کمیٹی بنائی تو اس کا کیا وا؟ ہم ای۔سی۔او۔ کو نہیں جا رہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنی اس تقریر کو ٹیپو سلطان کی نظر کر رہا ہوں، یہ ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے۔ کیا آپ اس سے

بھی نفرت کریں گے؟ آئین میں ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے، جس پر ولبھ بھائی پٹیل جی نے سئن کیئے، شیام پرساد مکھرجی جی نے سائن کئے۔ یہ آپ کی نفرت ہے (مداخلت)۔

آخر میں، میں اپنی بات کہ شعر کے ساتھ ختم کر رہا ہوں۔

کیا دِن دِکھا رہی سیاست کی دھوپ چھاؤں

جو کل سپوت تھے وہ، اب کپوتوں میں آ گئے

جو تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے

اتنے ہوئے زلیل کہ اب جوتوں میں آ گئے]

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : माननीय सभापति जी, धन्यवाद । मैं आपके समक्ष खड़ा तो हूं लेकिन वर्तमान में मेरा मन और मेरा ध्यान असम में हो रही बाढ़ पर है । मैं आशा करता हूं कि सरकार अपनी चिंता व्यक्त करे और असम में आज तुरंत ही एनडीआरएफ टीम भेजे । इसके साथ ही जलशक्ति मंत्री वहां जाएं । वहां जिस प्रकार से एम्बेंटमेंट चारों तरफ टूट रहे हैं, जिस तरह से पानी बढ़ रहा है, इससे बहुत ही खतरनाक वातावरण बन रहा है । आप बिहार और यूपी में देखते हैं कि किस तरह से बाढ़ के कटाव से लोगों को परेशानी होती है । मैं चाहता हूं कि सरकार असम में बाढ़ के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए आज की एनडीआरएफ टीम भेजे और जलशक्ति मंत्री जी तुरंत वहां जाएं ।

मैं शुरुआत में भाजपा के सांसदों और हमारी इंडिया अलायंस के सांसदों व अन्य सभी सांसदों को विशेष रूप से अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि वे इस चुनाव में जीतकर आए । विशेष रूप से मैं भाजपा के सांसदों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि इस चुनाव में उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा । इससे पहले जो वर्ष 2014 और 2019 के चुनाव हुए, उनमें ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर सत्ता व सदन के अंदर आए । इस चुनाव में इन्होंने खुद अनुभव किया होगा कि इस बार इनको वोट प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नहीं, बल्कि इनके काम व परिश्रम पर मिले हैं । आप में से कई सांसद घिस-घिसकर 30 हजार, 5 हजार वोट से जीतकर आए हैं । आप अपने बल पर जीतकर आए हैं, किसी प्रधान मंत्री के नाम पर नहीं आए हैं । इसीलिए मैं आपको शुभ कामनाएं देना चाहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा कि भारत की अवाम इस वोट से यह कहना चाहती है कि वह इंसान जो खुद को भगवान समझता है, वह भगवान नहीं, सिर्फ इंसान है । यह संदेश आज देश के जनादेश में हमें दिखाई देता है ।

महोदय, मैं इस देश के आम नागरिकों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने आज एक प्रधान मंत्री को नहीं, बल्कि एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष को चुना है । आज देश ने सत्तापक्ष को नहीं, एक मजबूत विपक्ष को चुना है । इसीलिए मैं देश के लोगों का आभार प्रकट करता हूं और देश के लोगों को आपके माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि आपके होते हुए हम यह संघर्ष जारी रखेंगे । लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष, संविधान को बचाने का संघर्ष, पिछड़े, दलित, वंचित अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार बचाने का जो संकल्प हमने लिया है, यह मुहिम छेड़ी

है, इस रास्ते पर हम चलते जाएंगे । हम आवाज बनकर रहेंगे उन देशवासियों की, जिनकी समस्या न आज इस सदन में व्यक्त होती है, न अखबारों में व्यक्त होती है । हम आवाज उठाएंगे उन गरीब लोगों की, जिनको अस्पताल में लगभग छ:-छ: साल रुकना पड़ता है, लेकिन उनको सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है । हम आवाज उठाएंगे, सड़क पर सोते हुए युवाओं की, लोगों की, जिनको एक अमीर बाप के बेटे की गाड़ी रौंदते हुए मार देती है और फिर वह बेटा बाद में बेल पर निकल जाता है । जो लोग सड़क पर सोते हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचता । हम बात उठाएंगे उन छोटे दुकानदारों की, जिनकी सालों पुरानी दुकान टूट जाती है, जब एक मंदिर का विस्तार होता है । हम बात उठाएंगे उन बेरोजगार युवाओं की, जो वीजा के संघर्ष में पनामा के रूट्स अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूरोप जाते हैं, मिडिल ईस्ट जाते हैं । आज यूपी, हरियाणा, पंजाब, गुजरात के युवा को देश में नहीं, बल्कि विदेश में रोजगार मिलता है । हम आवाज उठाएंगे उन बच्चों की, जो आज रो रहे हैं । उनकी सालों की मेहनत आज व्यर्थ हो गई है, जब नीट का पेपर लीक हुआ । हम बात उठाएंगे उन जवानों की, जम्मू में जिनकी शहादत हुई है । हम बात उठाएंगे उन ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स की, जिनका पैसा पुल गिर जाने पर व्यर्थ हो जाता है । कहीं एयरपोर्ट का टर्मिनल लीक होने पर उनका पैसा व्यर्थ होता है । हमें यह भी पता है कि प्रधान मंत्री मोदी जी अपना रवैया नहीं बदलेंगे । प्रधान मंत्री मोदी जी के पास दो ही अस्त्र हैं । एक भय का और एक भ्रम का है । इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई से वह भय दिखाते हैं । देशवासियों ने इस बार कह दिया है कि हम इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई से नहीं डरते हैं ।

महोदय, उनका दूसरा अस्त्र भ्रम का है । हमने प्रचार में भी देखा कि बांसवाड़ा, बनासकांठा में उन्होंने क्या कहा । जिस प्रकार से प्रधान मंत्री मोदी जी के भ्रम को देशवासियों ने लोक सभा चुनाव में नकारा, उसी तरीके से आज भी आप राहुल गांधी जी के भाषण पर जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश को भी देशवासी नकारेंगे । इसीलिए मैं देशवासियों के प्रति बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि देश बदल चुका है, सदन बदल चुका है । आज आप देख रहे हैं कि विपक्ष जब अपनी बात उठाता है, तो प्रधान मंत्री को भी, कैबिनेट को भी अध्यक्ष महोदय से संरक्षण मांगना पड़ता है । मैंने ऐसा नजारा पिछले 10 सालों में नहीं देखा कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है, विपक्ष बोल रहा है और गृह मंत्री उठकर बोल रहे हैं कि हमें संरक्षण दो, हमें संरक्षण दो । यह है ताकत लोकतंत्र की । अगर आपके पास सत्ता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सही हैं । अगर हम विपक्ष में हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम गलत हैं । सत्तापक्ष और विपक्ष लोगों की दो राय रखता है ।

यह जनता-जनार्दन निर्धारित करती है कि वह किसकी राय को स्वीकार करेगा, चाहे वह सत्तापक्ष हो या विपक्ष हो । आज देश बदल चुका है । बदल चुका है उत्तर पूर्वांचल से जहां से आज हम मणिपुर के दो सांसद जीतकर आए हैं । नागालैंड में कांग्रेस पार्टी पिछली बार वर्ष 1996 में जीती थी । अब हम दोबारा वर्ष 2024 में जीतकर आए हैं । मेघालय में इनकी तुरा लोक सभा सीट से हम जीतकर आए हैं । हम वह सीट पिछली बार वर्ष 1996 और 1998 में जीते थे । आज हम दोबारा तुरा लोक सभा सीट जीतकर आए हैं । आज एनडीए को उत्तर पूर्वांचल के लोगों ने नकारा है । ये मणिपुर में दोनों सीटें हारे हैं, नागालैंड में एक सीट हारे हैं और मेघालय में दोनों सीटें हारे हैं । मैं आपके द्वारा जोरहट के लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने एक मुख्यमंत्री को हराया है । मैं धन्यवाद करना चाहता हूं धुबरी के लोगों को, जिन्होंने एक साम्प्रदायिक शक्ति को 10 लाख वोटों से हराकर एक संदेश दिया है कि चाहे वह अल्पसंख्यक हो या कोई भी व्यक्ति जो अपने-आप को धार्मिक गुरु कहता है, लेकिन अगर वह धर्म के नाम पर समाज को बांटता है तो प्रजा उसके साथ नहीं होगी । इसलिए, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा । यह बदलाव लाने के लिए सारे समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं । वे हजारों लोग जो राहुल गांधी जी के साथ ?भारत जोड़ो? न्याय यात्रा पर चले, मैं उनका धन्यवाद

करना चाहता हूं । मैं उन पत्रकारों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने निष्पक्षता से अपनी पत्रकारिता की जिम्मेदारी उठाई । आज उन पत्रकारों को एक संदेश गया है, जिनको हौले-हौले प्रधानमंत्री मोदी जी से प्यार है । एक संदेश उन पत्रकारों को गया है, जो कहते हैं कि यह तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है कि अपनी पत्रकारिता पर ध्यान दें, नहीं तो लोग आपको देखना बंद कर देंगे । आज मैं युवाओं का आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने वाट्सऐप का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल किया । मैं उन सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने आज नफरत और हिंसा पर नहीं बल्कि धर्म जो हमें सिखाता है इंसानियत, चाहे हिन्दू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या सिख हो, हर धर्म हमें सिखाता है कि हम एक अच्छा इंसान बनें । वह हमें इंसानियत के आदर्शों को सिखाता है । समाज एक आदर्श बने, वह हमें सिखाता है ।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा गुजारिश करना चाहता हूं । ? (व्यवधान) मैं अंत में आ रहा हूं । मैं अंत में दो-तीन चीजों के बारे में बोलना चाहता हूं । मैं आपके द्वारा गुजारिश करना चाहता हूं कि ये बार-बार बात करते हैं कि हमने एक नया सदन बनाया, लेकिन क्या यह उचित नहीं होता कि चाहे पुराना सदन हो या नया सदन हो, इन दोनों सदनों के सामने डॉ.भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति हमारे सदन के सामने होनी चाहिए थी । क्या यह उचित नहीं था?

माननीय सभापति **:** यह स्पीकर का प्रमिसेस होता है ।

श्री गौरव गोगोई **:** सर, मैं आपसे गुजरिश कर रहा हूं । मैं अपनी व्यथा गुजारिश कर रहा हूं । मैं स्पीकर महोदय को आपके द्वारा गुजारिश कर रहा हूं कि पहले की तरह सदन के सामने आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को रखिए और पहले की तरह डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को रखिए । मैं गुजारिश कर रहा हूं । मैं स्पीकर के निर्णय का सम्मान करते हुए उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वे हमारी भी बात सुनें ।

माननीय सभापति **:** मैं चेयर पर हूं । अगर आपने स्पीकर से गुजारिश की तो सुन लीजिए । आपने कहा कि यहां जो बाबा भीमराव अम्बेडकर की एक मूर्ति स्थापित थी, वह फिर से स्थापित होनी चाहिए । आपको भी निमंत्रण गया होगा । इस पार्लियामेंट में पहली बार सारे महापुरूषों का, बाबा भीमराव अम्बेडकर से लेकर महाराणा प्रताप तक के लिए एक बड़ी वेदिका संविधान हॉल के साथ बनाई गई है, जिसका उद्घाटन पिछले दिनों हुआ है । शायद आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसी चीज हो गई है कि कोई भी बाहर का डेलिगेशन्स, हमारे खुद मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट या बाहर के लोग आएंगे तो उनको इस संविधान भवन और इस पार्लियामेंट के साथ-साथ अपने देश के महापुरूषों को एक साथ देखने का मौका मिलेगा । अपने देश के महापुरूषों की सारी प्रतिमाओं को ढंग से रखकर पार्क बनाया गया है ।

श्री गौरव गोगोई **:** सभापति महोदय, मैं बस गुजारिश कर रहा हूं कि आप हमारी बात भी सुनिए । अगर सदन के सामने प्रेरणा स्थल बनाना भी हो तो सदन के सामने जहां पर उनका स्थान है, जहां पर इतने सालों से डॉ.भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को स्थापित करने के लिए पूरे देश में एक आंदोलन हुआ था, उस स्थान को एक वजह से चुना गया था कि वह सदन के सामने हो । क्या यह उचित नहीं है? क्या यह हमारी गरिमा के अनुसार नहीं होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान के निर्माता डॉ.भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी हमारे सदन के

सामने हो? मैं दोबारा आपसे गुजारिश करता हूं । मैं हाथ जोड़कर आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप इन दोनों महापुरूषों की मूर्तियों को सदन के सामने रखें ।

माननीय सभापति **:** अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री गौरव गोगोई **:** महोदय, हमने एक मांग रखी है कि ?नीट? पर एक चर्चा हो ।?(व्यवधान) शिक्षा विभाग को लेकर आज एक बहुत ही असमंजस?(व्यवधान)

माननीय सभापति **:** नेता प्रतिपक्ष ने वह बात कह दी है ।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई **:** महोदय, ?नीट? पर चर्चा हो, आप उस चर्चा पर अमल करें ।?(व्यवधान) आज जो आदरणीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने वर्ष 2021 में जिम्मेवारी संभाली थी, वर्ष 2021 से जिम्मेवारी संभालने के बाद आज तक इतने सारे पेपर्स लीक हुए हैं । शिक्षा मंत्री एक और दिन?(व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आपने चर्चा की मांग की है ।

डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा जी ।

डॉ**.** इन्द्रा हांग सुब्बा **(**सिक्किम**) :** सभापति जी, मैं आज यहां राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं सिक्किम की ओर से सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देता हूं । सबसे पहले सिक्किम के जितने भी वोटर्स हैं, मैं हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं । उन्होंने फिर एक बार मुझे इस सदन में सिक्किम और सिक्किम की जनता के मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है ।

जैसा कि राष्ट्रपति जी ने कहा कि 18 वीं लोक सभा ऐतिहासिक है, क्योंकि भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा है । 18 वीं लोक सभा सिक्किम के लिए भी अत्यंत ऐतिहासिक है । यह बहुत ही स्पेशल है । भारत के 22 वें राज्य के अभिन्न अंग के रूप में वर्ष 2025 में सिक्किम को 50 साल पूरे हो जाएंगे । एसकेएम पार्टी और हमारी सरकार इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर, हमारे राज्य को स्वर्णिम और समृद्ध बनाने के कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रही है ।

पिछले 10 सालों में एनडीए सरकार ने सिक्किम को हर सेक्टर में सहयोग दिया है । सिक्किम के विकास के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं । सिक्किम एक हिमालयी राज्य है और वहां की रोड्स बहुत संकीर्ण हुआ करती थीं । सिक्किम में एक ही नेशनल हाइवे था, जो कि सेवोक से लेकर गंगटोक था, वह टू लेन है । आज भी सेवोक से लेकर रंग्पो तक एनएच-10 का जो स्ट्रेच है, उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं । हमने और हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट की है कि एनएच-10 को चाहे एनएचआईडीसीएल हो या किसी भी सेन्ट्रल एजेन्सी को दिया जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नेशनल हाइवे-10 को ठीक से मेंटेन न करने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान सिक्किम को हो रहा है ।

मेरा राज्य एक सुंदर राज्य है । आपमें से कई सदस्य सिक्किम घूमने के लिए गए होंगे । पिछले 10 सालों में एनडीए सरकार बनने के बाद हमारे मंत्रीगण हर महीने या तीन महीने में सिक्किम जाते हैं । सिक्किम एक बहुत ही शांत राज्य है । उसको मेंटेन करने के लिए सिक्किम सरकार ने हर एक काम किया है ।

सभापति महोदय, जब रोड की बात आती है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूं कि सिर्फ सिक्किम की ही बात नहीं है, चाहे कोई भी हिमालयी रीजन हो, उस रीजन में टिपिकल इश्यूज़ होते हैं । वहां पर पांच से छः महीने तक मानसून रहता है । मानसून के कारण वहां पर बहुत ज्यादा लैंड स्लाइड्स होती हैं, जिसके कारण रोड्स डिस्टर्ब होती ही हैं । इसलिए मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ सिक्किम ही नहीं, बल्कि पूरे हिमालयी रीजन के लिए जो पॉलिसीज़ बनती हैं, तो उनमें एक्सेप्शन रखना चाहिए । उसके लिए फंड्स हो और अलग से पॉलिसीज़ बननी चाहिए । मैं यह भी निवेदन करता हूं कि हिमालयी रीजन के लिए जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं, तो उसके लिए अलग से कमेटी बननी चाहिए, ताकि उसमें हिमालयी रीजन के टिपिकल इश्यूज़ डिस्कस हो सकें । जैसे कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं । हम भी सिक्किम से कुछ करना चाहते हैं । सिक्किम हमेशा से पीसफुल स्टेट रहा है । पिछले दिनों में आपने देखा कि क्लाइमेट चैंज कितना विज़िबल हो गया है । इस क्लाइमेट चैंज की वजह से सबसे ज्यादा किसी पर असर हो रहा है तो हिमालयन रीजंस को हो रहा है । जबकि हमने सबसे ज्यादा ग्रीनरी बनायी हुई है । सिक्किम के बारे में बताना चाहता हूं ।

माननीय सभापति **:** कृपया समाप्त कीजिए, क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं । आपका जितना समय है, उससे अधिक बोलने का समय मैंने दे दिया है । आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए ।

डॉ**.** इन्द्रा हांग सुब्बा **:** महोदय, मैं एक-दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा ।

महोदय, क्लाइमेट चैंज बहुत विजिबल हो गया है । हीटवेव, अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हो रहा है । ऐसा रेनफॉल हमने कभी नहीं देखा है । सिक्किम में पिछले साल बहुत बड़ा फ्लड आया, जिसकी हमें एक्सपैक्टेशन नहीं थी । हमने इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर सरकार को दे दी है । एनडीए की सरकार इसमें हमें पूरा सहयोग कर रही है । हम इतना चाहते हैं कि सिक्किम और हिमालयन रीजन के लिए अलग से पॉलिसी बनाने के लिए एक कमेटी बनायी जाए । जिस कमेटी में हमारे टिपिकल इश्यूज़ हों । इस डिलिमिटेशन के साथ विमन इम्पावरमेंट को भी आगे बढ़ाया जाए । इसी के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्रीमती लवली आनंद (शिवहर) **:** सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

महोदय, मैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में शिवहर की महान जनता के द्वारा चुनकर आयी हूं । मैं यहां से शिवहर की महान जनता का आभार व्यक्त करती हूं, उनको धन्यवाद देती हूं । महोदय, यह मेरा दूसरा टर्म है ।

महोदय, माननीय अध्यक्ष को दूसरी बार अध्यक्ष के पद पर चुने जाने के लिए मैं हृदय की गहरायी से बधाई और शुभकामनाएं देती हूं ।

महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन के लिए खड़ी हूं । मैं कामना करती हूं कि यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और हमारे नेता, विकास पुरुष, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा देश और प्रदेश ?दिन दूनी; रात चौगुनी तरक्की करे ।?

महोदय, मेरा परिवार स्वतंत्रता सेनानी परिवार रहा है । आनंद मोहन जी के दादा जी स्वर्गीय राम बहादुर बाबू जी, जिन्हें कोसी के लोग ?गांधी? कहते थे और मेरे दादा जी, स्वर्गीय रामेश्वर बाबू जी, स्वतंत्रता आंदोलन में साथ थे । इस देश में आजादी और लोकतंत्र की स्थापना में हमारे पुरखों का बहुत योगदान रहा है । परंतु खेद है कि

आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो ठीक आज से 50 साल पहले 25 जून, 1975 को एक काली अंधेरी रात को, जिनको उस समय में हिटलर की उपाधि दी जाती थी । इंदिरा जी की जो हिटलरशाही थी, उस तर्ज पर इमरजेंसी थोप दी गयी । इमरजेंसी के चरणों ने सीमित तानाशाही की वकालत की गयी । किसी ने कहा ? ?Indira is India; India is Indira.? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, श्री मोरारजी देसाई, श्री राजनारायण, श्री मधु लिमये, श्री चंद्रशेखर, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री जॉर्ज फर्नांडिस, श्री नीतीश कुमार, ललन जी और आनंद मोहन जी जैसे लाखों लोगों को, उस समय लालू जी भी थे, जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया । पूरे देश को जेल में तब्दील कर दिया गया । न्यायपालिका पर पहरा बैठा दिया गया । प्रैस पर सेंसरशिप की तलवार लटका दी गयी । संविधान के साथ अनेक छेड़खानियां की गयीं । तीन वर्ष की कठिन लड़ाई, जिसमें हजारों को लाठी, गोली, जेल और मौत का वरण । लाखों लोगों के द्वारा अपनी जवानी गंवाने के बाद देश उस खौफनाक मंजर से बाहर निकला और नाम पड़ा दूसरी आजादी ।

आज आश्यर्च यह है कि जिन लोगों ने देश को कैदखाने में तब्दील कर दिया, लोकतंत्र का गला घोटा, प्रेस और न्यायपालिका की स्वतंत्रता छीनी, संविधान को जूतों तले रौंदा, वही चुनाव में चिल्लाते रहे कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे मे हैं । इस तरह से हमने संविधान का मजाक उड़ाते हुए देखा । ये संविधान की कॉपी हाथ में रखकर शपथ लेते रहे ।

सभापति जी, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हमें यह जनादेश मिला है । हम न्यायपालिका और प्रेस की आजादी को हर कीमत पर अक्षुण्ण रखने का काम करेंगे । देश को संबल, समृद्ध और श्रेष्ठ बनाने का काम करेंगे । महिलाओं को शक्ति सम्पन्न करने का, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का तथा चोरों, लुटेरों और बेईमानों से देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने की दिशा में माननीय प्रधान मंत्री जी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं । उन्होंने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया है । महिला सशक्तिकरण के लिए उसी तरह से बिहार के माननीय मुख्य मंत्री जी ने पंचायती राज में 50 परसेंट महिलाओं को आरक्षण दिया है और इस तरह से महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया है । पूरा देश माननीय प्रधान मंत्री जी के तीसरी बार प्रधान मंत्री बनने पर हार्दिक बधाई देता है । दिनकर जी ने कभी कहा था :-

?सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है

ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है ।?

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माता सीता की जन्मभूमि पुनौरा धाम में जमीन अधिग्रहण और सौन्दर्यीकरण के लिए माननीय मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 72 करोड़ 47 लाख रुपये के आवंटन और माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा माँ जानकी के भव्य मंदिर निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपये प्रदान करने के लिए शिवहर, सीतामढ़ी सहित सभी मिथिलावासियों की तरफ से कोटि-कोटि आभार प्रकट करती हूँ । मैं आपके माध्यम से पुरजोर मांग करती हूँ कि शिवहर को रेल मार्ग से जोड़ा जाए और वर्षों से बंद पड़ी रीगा चीनी मिल को चालू किया जाए । छोटा जिला त्वरित विकास की तर्ज पर ढाका को जिला बनाने का भी काम किया जाए । कृपया आप इस पर ध्यान देने का कष्ट करें ।

अंत में, मैं आपके माध्यम से मांग करती हूँ कि आयोध्या-सीतामढ़ी-जनकपुर के बीच स्पेशल कॉरिडोर बनाकर श्रद्धालुओं के लिए यातायात को सुगम किया जाए । इसके साथ ही मेरी पार्टी को जो मांग है कि जब बिहार और झारखंड बंटा है तो बिहार में संसाधनों की कमी हो गई है इसलिए हमारी पार्टी की जो पुरानी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले । इसकी मैं पुरजोर मांग करती हूँ । मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का अनुमोदन करते हुए आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ ।

एडवोकेट चन्द्र शेखर **(नगीना) :** माननीय सभापति जी, जय भीम । महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ ।

सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूँ, जिनमें महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉ. बाबा साहेब अम्बेड़कर जी और मान्यवर कांशीराम साहब को मैं आज के दिन याद करता हूँ । इसके साथ ही साथ नगीना की महान जनता, भीम आर्मी और हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी, कांशीराम के साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ । इसके साथ अपने कुल गुरु, जगतगुरु रविदास महाराज जी को भी मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने दुनिया को लगभग 600 साल पहले बेगमपुरा शहर के रूप में दुनिया का सबसे महान लोकतांत्रिक दर्शन दिया ।

सभापति महोदय, 14 अगस्त, 1947 को यह देश अंग्रेजों के अधीन था । 15 अगस्त, 1947 को हम लोग आजाद हुए । 16 अगस्त 1947 को देश आजादी में था, लेकिन धन, धरती और राजपाट में बँटवारा नहीं हुआ । जो साधन-संसाधन थे, उनमें सही रूप से बँटवारा नहीं होने के कारण एक बहुत बड़ी आबादी सुविधाओं से वंचित रह गई । उनको सम्मान देने और अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, उसके लिए लोकतंत्र की व्यवस्था हुई, लेकिन आजादी के 70 सालों के बाद भी हम कहां खड़े हैं, यह चिंता का विषय है । मैं मानता हूँ कि सामाजिक न्याय तभी होगा, जब जातीय जनगणना पूरी होगी । जातीय जनगणना कराई जाएगी और इसके साथ-साथ संख्या के आधार पर वंचित वर्गों का आरक्षण बढ़ाया जाएगा । उसके साथ-साथ जब वह राष्ट्रपति अभभिभाषण पर बात रख रही थी, तो उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात कही । उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया में हमारे यहां सबसे उत्तर शहर बनें ।

माननीय सभापति जी, 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है, तो गांवों की आबादी के बारे में भी सोचना होगा कि उनका जीवन कैसे बदले? माननीय सभापति जी, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में बहुजन समाज के छात्रों के साथ कास्ट एट्रोसिटी हो रही है । निरंतर, उनकी हत्या हो रही है । साथ-साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं, दफ्तरों में एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का भी जातिगत और धार्मिक शोषण किया जा रहा है । इसलिए मेरी मांग है कि पुरानी पेंशन को भी बहाल किया जाए । जो कर्मचारी देश की सेवा में लगे हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए ।

माननीय सभापति जी, भाजपा ने चुनावी लाभ के लिए ?सबका साथ ? सबका विकास? का नारा दिया, जो खोखला है, क्योंकि 10 सालों में दलित, आदिवासी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक पर जो अत्याचार हुए हैं, वे किसी से छिपे हुए नहीं हैं । ये गलत हैं । ये बंद होने चाहिए ।

सभापति महोदय जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में निजी क्षेत्रों में एससी, एसटी और ओबीसी को रिजर्वेशन देने का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, जो कि आज चर्चा का विषय है । क्योंकि 98 प्रतिशत प्राइवेट सेक्टर है, दो प्रतिशत सरकारी सेक्टर है । 98 प्रतिशत प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए ।

माननीय सभापति जी, आशा कार्यकताओं, आंगनवाड़ी वर्करों और भोजन माताओं के वेतन वृद्धि में भी कोई उल्लेख नहीं हुआ है, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा । माननीय सभापति जी, मैं नगीना लोक सभा क्षेत्र से चुन कर यहां आया हूं । वह बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोई विशेष आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया है ।

रोजगार की सेवाएं नहीं है, नौजवान पलायन करते हैं, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, केन्द्रीय विद्यालय और चिकित्सा संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए, जो कि नहीं हैं ।

माननीय सभापति जी, मानसून सत्र आ गया है । मेरा क्षेत्र बाढ़ से बहुत प्रभावित है । इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहां के लोगों को बाढ़ से निजात दिलाई जाए । माननीय सभापति जी, हमें चीन आंख दिखा रहा है और हमारे देश की सीमाओं में लगातार घुसपैठ कर रहा है । इसलिए ?अग्निवीर योजना? को हटा कर पुन: सेना भर्ती शुरू की जाए । साथ-साथ भारत की सबसे प्राचीन और बहादुर रेजिमेंट्स में से एक ?चमार रेजिमेंट? को पुन: बहाल किया जाए । ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है ।

माननीय सभापति जी पिछले सारे माननीय प्रधान मंत्रियों ने मिल कर जितना कर्ज लिया है, उससे दोगुना कर्ज हमारे वर्तमान के प्रधान मंत्री जी ने लिया है । अगर किसान अपना कर्ज माफ कराने के लिए जाता है, तो उनको लाठी झेलनी पड़ती है, जबकि सरकार ने धन्नासेठों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया है । हमें इस ओर ध्यान देना पड़ेगा । हमारी आने वाली पीढ़ियों को यह कर्ज चुकाना पड़ेगा ।

माननीय सभापति महोदय जी, किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी तथा किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए । साथ-साथ, 2 अप्रैल, 2018 को एससी-एसटी वर्ग के बच्चों पर बहुत बड़े पैमाने पर मुकदमें लगे थे । हमारी वह लड़ाई सही थी । यह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और बाद में सरकार ने भी माना । वे मुकदमें तुरंत वापस होने चाहिए ।

माननीय सभापति जी, प्रेस पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, जो पत्रकार सरकार के खिलाफ बोलता है, उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है । हमारा हथियार सोशल मीडिया है, उस पर तरह-तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और विरोध करने वालों के सोशल मीडिया हैंडल से सस्पेंड करा दिए जा रहे हैं ।?(व्यवधान)

सभापति जी, पेपर लीक और परीक्षओं के कैंसिल होने से देश के नौजवानों का भविष्य खतरे में है । नीट, यूपी-सिपाही भर्ती, 69 हजार शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है । उनसे कोई पूछने वाला नहीं है । बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं । युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति **:** कृपया आप समाप्त करें ।

एडवोकेट चन्द्र शेखर **:** माननीय सभापति जी, मैं पहली बार बोल रहा हूं । आप कहेंगे, तो मैं बैठ जाऊंगा । मैं संवैधानिक मर्यादा का पालन करूंगा ।

माननीय सभापति **:** आप एक मिनट बोलिए ।

एडवोकेट चन्द्र शेखर **:** माननीय सभापति जी धन्यवाद । नारी सम्मान की बात करने वाली सरकार, हमने मणिपुर देखा, हमने पहलवान बेटियों का हश्र देखा, हमने हाथरस की बेटी का हश्र देखा । सरकार ने हाथरस के परिवार को जो वादा किया था, वह भी पूरा नहीं किया । महिलाओं में भी स्पेशली, दलित, पिछड़े और मुस्लिम वर्ग एवं आदिवासी वर्ग की महिलाओं के साथ आज भी एनसीआरबी का डाटा कहता है, जो जूल्म हो रहा है, वह सहनीय नहीं है । साथ-साथ, हमने कोविड में गंगा में तैरती हुई लाशें भी देखी और मजदूरों का हाल भी देखा है ।?(व्यवधान) नोटबंदी पर छोटे- मंझोले उद्योग की जो कमर टूटी, हमने वह भी देखी है ।

सभापति जी, शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और चिकित्सा संस्थानों में ओबीसी और एसी-एसटी के योग्य अभ्यर्थियों को एनएफएस करके निकाला जा रहा है, लेटरल एंट्री करके हमारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं । हम यह भी देख रहे हैं । मेरा यह भी कहना है कि यह सबका इश्यू है कि प्राइवेट कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी कई जगहों पर आठ से ज्यादा घंटे काम करते हैं । उनको उचित वेतन नहीं मिलता है । उनका न्यूनतम वेतन 20 हजार रुपये तय हो । उनको 24 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है । उदाहरण के तौर पर यूपी पुलिस वाले हैं, जो बहुत काम करते हैं ।

माननीय सभापति **:** वह राज्य के विषय हैं ।

? (व्यवधान)

एडवोकेट चन्द्र शेखर **:** सर, मैं राज्य सरकार के विषय को आपके संज्ञान में डाल रहा हूं । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आप यहां पर केन्द्र सरकार के विषय बोलिये ।

एडवोकेट चन्द्र शेखर **:** पुलिस सब जगह है । लेकिन सवाल यह है कि वे बहुत पसीना बहाते हैं । आठ घंटे की ड्यूटी और वेतन में विसंगति है । उनको बॉर्डर स्कीम से बाहर किया जाए । माननीय सभापति जी, मुझे एक मिनट दीजिए । राष्ट्रपति जी ने धर्म के बारे में बात की थी । राम मंदिर से पहले तुगलकाबाद में स्थित हमारे गुरुघर का फैसला आया था । अभी तक दिल्ली में स्थित सद्गुरु रविदास जी महाराज का गुरुघर नहीं बना है । साथ ही साथ अपनी बात को खत्म करते हुए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जितना यह देश दूसरों का है, उतना हमारा भी है । हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, जो चाहता है, हमारी हत्या कर देता है । मूंछे रखने पर, घोड़ी पर बैठने पर, मटकी छूने पर हमारी हत्या हो रही है । 70 साल बाद भी क्या बदला है? दलित, पिछड़े, मुसलमानों पर हिंसा नहीं रुक रही है । मेरा आपसे संरक्षण के साथ यह आग्रह है कि इन घटनाओं को रोका जाए और देश किसी की बपौती नहीं है । देश संविधान से चलता है और संविधान से चलेगा । संविधान से छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी ।

धन्यवाद । जय भीम, जय भारत ।

श्रीमती अपराजिता सारंगी **(भुवनेश्वर) :** आदरणीय सभापति महोदय, आपने माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्ति करती हूं । अभी जब मैं आपके समक्ष खड़ी हूं तो बहुत प्रसिद्ध दो पंक्तियां याद कर रही हूं-

?कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,

सदियों रहा है दुश्मन दौर-ए-ज़मां हमारा॥?

हम सब ने फिर एक बार मोदी सरकार का नारा दिया था । जनता के आशीर्वाद ने, जनता की दुओं ने इस नारे को यथार्थ में परिणत किया । सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की विचारधारा को आधार करके तीसरी बार मोदी सरकार भारत देश की जनता की सेवा में जुट चुकी है । मुझे यह कहते हुए फख्र हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा राज्य में पूर्ण बहुमत, जहां से मैं आती हूं, वहां हासिल किया है । हमने अभी ओडिशा राज्य में लोगों की सेवा का कार्य शुरू कर दिया है । 18 वीं लोक सभा का मेरा यह जो वक्तव्य है, उसे मैं

भुवनेश्वर लोक सभा क्षेत्र के आदिवासियों, मेरे भाइयों और बहनों को समर्पित करती हूं, जिन्होंने दूसरी बार मेरे ऊपर आस्था दिखाई तथा मुझे लोक सभा में भेजा ।

Hon. Chairperson, Sir, since yesterday, I have been sitting here and hearing all the Opposition leaders one after the other. They all have been accusing the BJP of spreading hatred and violence in the country. The Bhartiya Janata Party is being projected as a political party which has sinister designs and which is creating disharmony in the society.

Dear friends from both the sides, the fifth largest economy in the world and its GDP does not grow at around eight per cent in 2023-24 per annum with a kind of doomsday scenario that all of you are painting about the country. We have become the 5th largest economy, and our GDP grows at around eight per cent because there is good governance in the country, there is peace in the country, and there is stability in the country. We must understand this. If we have seen the record exports of 780 billion dollars in 2023-24, if India has become the second largest exporter of mobile phones in the world, if India has emerged as the biggest exporter of rice in the world, if the Indian engineering goods are finding place in every nook and corner of the world, and if the Bombay Stock Exchange sensex points cross 79,000, then my dear friends it does not happen in a society ripped by violence and hatred.

It happens in a society where there is strong, able, decisive and efficient Government, and that is why, we all need to acknowledge this particular aspect. Our Government has been pursuing the setting up of IIMs, IITs, NISERs all across the country with, I would say, a single-minded devotion. The Government has been spending around Rs. 10 lakh crore on infrastructure development every year, and I must tell you that because of this infrastructure development focus, we have been able to get a lot of private investments. I am delighted as a part of the Government and as part of Modi Ji?s team that today, 27 per cent of the GDP is the private investment in our country. This particular figure of 27 per cent was down by six per cent in 2016. It is going up every day because we are trying to create a very positive environment in the country. Private investments are coming. Infrastructure development is taking place. There is a lot of stability and peace in the country.

My dear friends, I have heard all of you. In fact, I have been hearing all of you all the while I have been sitting here. In regard to price rise and inflation, one after the other, you have been accusing the Government of Prime Minister Modi. I am delighted that the hon. Finance Minister, for whom I have tremendous regard and

respect, is sitting here. The Opposition leaders have been talking about inflation, price rise in the country. I am giving you a data. Let us talk with figures. Let us talk with data. Let us talk with statistics. Dear friends, only two months back, sugar was being sold at Rs. 120 per kg in the neighbouring countries, whereas our Government could manage to keep it between Rs. 35 and Rs. 40 per kg. When onion was being sold at Rs. 100 to Rs. 120 per kg abroad, our Government was good enough, efficient enough, able enough, and prompt enough to manage to keep it between Rs. 30 and Rs. 35 per kg. I am talking about the price of onion. It is because of the Russia-Ukraine conflict when the wheat was selling in the global market at Rs. 40 to Rs. 45 per kg, our efficient Government brought it down to Rs. 20 to Rs. 25 per kg. My dear friends, instead of appreciating the Government?s efforts at controlling the prices despite very adverse and very volatile geo-political situation, I heard a number of Opposition leaders cribbing about the price rise and not appreciating the role of the Government in handling these crucial matters.

Friends, while pursuing the goals of Viksit Bharat by 2047, I would urge the hon. Leaders of the Opposition to be positive; to give concrete ideas; to offer solutions, rather than indulging in mudslinging.

This Government of Prime Minister Modi has been moving with a lot of purpose and steadfastness, and I would definitely like to bring to your kind knowledge that all the Ministries have been asked to prepare their 100 days? action plan and we are all moving with heart within and God overhead towards creating a better India, towards creating a developed India that we all have been talking about. We are talking of economic development; we are talking of strategy for women, poor, youth and farmers. Friends, we are on our way to becoming a USD 5 trillion economy by 2027 despite your negativity and pessimism. We have been able to provide four crore houses. In the last 10 years, 10 crore women have been integrated with self-help groups, three crore Lakhpati Didis are coming in the country. They are actually being promoted. 100 per cent saturation approach is being adopted as far as provisioning of water supply system is concerned.

15.00 hrs

So, I think, we all need to be positive. We all need to give concrete solutions. We all need to be a part of the development process. We are all moving towards Viksit Bharat by 2047. मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करने से पहले निश्चित तौर पर एक वाक्य हिंदी में कहना चाहूंगी ?

?साजिशें लाखों बनती हैं मेरी हस्ती मिटाने की

बस दुआएं आपकी उन्हें मुकम्मल होने नहीं देतीं ।?

I support the Motion of Thanks tabled by Shri Anurag Singh Thakur ji. Many, many thanks.

श्री आनंद भदौरिया **(धौरहरा) :** सभापति जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखने का अवसर दिया ।

मान्यवर, पहली बात लोकतंत्र के इस मंदिर में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिलना मेरे लिए गर्व का विषय है । मैं इसका श्रेय अपनी समाजवादी पार्टी, मेरे लोक सभा क्षेत्र धौरहरा की महान जनता तथा पीडीए की एकता को देना चाहता हूं । मैं उस वृहत्तर समाज और उसे एकता के सूत्र में बांधकर समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का वंदन-अभिनंदन करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं ।

माननीय सभापति जी, मुझे उम्मीद थी कि महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसानों की आय दोगुनी करने का जो एक दशक पुराना वादा है, उसका कुछ तो उल्लेख होगा । याद रखना, बिना किसानों की समृद्धि के अमृतकाल और विकसित भारत जैसे शब्द बेमानी हैं । मुझे अदम गोंडवी साहब की चार पंक्तियां याद आ रही हैं ?

?तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है,

मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है,

लगी है होड़ सी देखो, अमीरी औ गरीबी में,

यहां जुम्मन के घर में आज भी फूटी रक़ाबी है ।?

आज किसानों की क्या हालत है? किसान कर्ज तले दबा हुआ है । आवारा पशुओं और सांडों ने खेतों में तबाही मचा रखी है । सड़क पर किसान और आम आदमियों की सांड जान ले रहे हैं । तेंदुओं ने मेरे पूरे लोक सभा क्षेत्र में आतंक मचा रखा है । वर्ष 2022 के विधान सभा के चुनाव में स्वयं माननीय प्रधान मंत्री जी ने बहराइच की जनसभा में कहा था कि 10 मार्च के बाद आवारा पशुओं की जिम्मेदारी मेरी होगी । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को उनका वादा याद दिलाना चाहता हूं ।

नव गठित 18 वीं लोक सभा की पहली बैठक ऐसे कालखंड में हो रही है, जब भारत की तरुणायी अपनी जायज़ मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी हुई हैं । अति महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक होने जैसी परंपरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में पड़ी है । देश भर के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की जायज़ मांग कर रहे हैं । यूपी में शिक्षा मित्र सैकड़ों की संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं । महंगाई, बेराजगारी ने आम आदमी का जीना दुश्वार कर रखा है ।

मैं देश के इन युवाओं को, इन सभी कमेरा वर्ग के लोगों से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, यह विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी आपकी आवाज बुलंद करती रहेगी ।

?हमने यह सोचकर तलवार उठा ली,

बढ़कर जुल्म सहना भी तो ज़ालिम की तरफदारी है ।?

सभापति जी, यहां आने से पहले नई संसद के बारे में काफी कुछ सुना था, लेकिन अंदर घुसते ही कदम ठिठक गए, जब फर्श पर हमने मोरपंख की प्रतिक्रति देखी । हमारे हिंदू धर्म में मोरपंख को पवित्र माना गया है, जो ऊर्जा देता है । स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने अपने माथे पर इसको मान देने का काम किया था । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** अपने सदन की आलोचना नहीं करते हैं । पार्लियामेंट का यह जो सदन या परिसर है, यह स्पीकर के डोमेन में है । आप सुझाव दे दीजिए, आप यहां सरकार की आलोचना

? (व्यवधान)

श्री आनंद भदौरिया **:** माननीय सभापति जी, इसको हटाना चाहिए, इसलिए मैं इसको हटाने की मांग करता हूं । ? (व्यवधान)

सभापति जी, आपने मुझे बीच में टोक दिया । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** मैंने आपको टोका नहीं, बल्कि करेक्ट किया है ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आपकी मेडिन स्पीच है, इसलिए मैं टोक नहीं रहा था ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आपने तो अपने जज्बात की तर्जुमानी अदम गोंडवी की पंक्तियों से की है ।

? (व्यवधान)

श्री आनंद भदौरिया **:** माननीय सभापति जी, चूंकि मैं सरकार पर ज्यादा हमलावर था, इसलिए शायद आप मुझे टोक रहे थे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि सत्तापक्ष भले ही महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के मार्फत यह दावा करे कि उसकी बहुमत की सरकार बनी है, लेकिन देश हकीकत जानता है कि कैसे यह बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है ।

यहां दुष्यंत कुमार जी की चार पंक्तियां मुझे बरबस याद आ रही हैं ?

?तुम्हारे पांव के नीचे कोई ज़मीन नहीं,

कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यक़ीन नहीं,

मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं,

मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं ।?

अंत में मैं नैमिषारण्य की पवित्र पुण्यभूमि, छोटी काशी गोला की पवित्र पुण्यभूमि, महाराजा छीता पासी की पवित्र पुण्यभूमि को नमन करते हुए, आदरणीय नेता जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद ।

SHRI SUBBARAYAN K. (TIRUPPUR): Hon Chairman Sir, Vanakkam. People have given a clear mandate. Now there is a weak ruling party and a strong opposition. We should see how intelligent the people are to give such a verdict. We can look at this result with the experience we had during the last 10 years. What is the concern of the ruling party towards social, political and economic life? After considering the policies implemented by the Government, the people have given such a historic mandate. That is why, the ruling party, which is expected to be strong, is weak whereas the Opposition which is expected to be weak is strong. The wrong approaches made by the Government during the past 10 years are the reason behind such a decision of the people. I do not have much time to talk in detail about that. On the political front, the ruling side does not have belief on Constitutional democracy. They have learnt from their masters who have no belief on democracy. According to them, they were taught that democracy is not an Indian material but of a foreign origin. That is why they have learnt not to accept democracy in any way. As a result, the ruling party is dismantling and destroying democracy by using the Constitutional and democratic institutions. The verdict has shown that people of this nation have not accorded their approval to such activities of the ruling side. What is democracy? It is to win over the Opposition. Fascism is nothing but killing the other side. It is clearly evident that from the activities at the topmost level of the Government, the hon. Prime Minister, to all the levels, they do not have an approach to win over the hearts of the Opposition. They will face failures again and again till they do not leave the path of fascism. On the economic front, what this government wants to say? They are supporting privatisation in all fields such as education, employment and health. What is the status in these three fields? Education should be offered free of cost. Similarly, the Government has the responsibility to provide employment opportunities and healthcare facilities. But the Government has given up its responsibilities. It is now in the hands of the private sector and the private parties are looting in the name providing such services. Who is behind this? The wrong economic policies of the Government are

the reason behind this downfall. Besides the economic policy, the Government?s FDI policy, it is also allowing the foreign corporate giants to exploit the resources and the hard work of the Indian people. The Economic policy is therefore giving a big chance to the foreign companies in expanding their exploitation. Natural resources such as sea, land and mountain resources are being looted by the foreign companies. The economic policy of the Union Government paves the way for such an exploitation. On the social aspect, what is the view of this Government? They want to divide the society on the basis of caste. On the political front they follow a fascist attitude. On the economic side they are destroying the domestic industries by way of allowing the foreign companies to loot in the name of liberalisation, and on the social front they have tried to divide this society on the basis of caste. These activities have made an impact on the people. They are detrimental to the growth of this country. Have you ever asked the view of the people before privatising the PSUs? Are you not ashamed to talk about Pandit Jawaharlal Nehru? Due to his long and rich experience that he derived from his association with the freedom struggle Pandit Nehru created more than 245 PSUs in our country. They are considered and protected as temples. But the ruling side is continuously engaged in privatising and disinvesting these PSUs. Who gave you the right to disinvest these PSUs? Did the people of this country permit it? Why are you allowing disinvestment? This is wrong. But they are so adamant enough on this aspect of privatisation. After seeing all your wrongdoings, the people of this country have given this verdict. Who are all parties to it? *?* was in alliance with BJP. ED, IT Department, CBI and other agencies were also working in tandem with the BJP. They have weakened the system and the opposition parties. But the people of this country have strengthened us. Their wrong policy is the reason for such a debacle. Who is providing employment in India?

Hon. Chairperson Sir, I will conclude in two minutes. This is the problem. In a democracy, they are not even allowing to speak. The ruling side should have all ears to listen to the Opposition parties and others in a vibrant democracy. But you are not allowing to speak for even a minute. I will conclude by saying one thing. What is the view of this Government on labourers and farmers? All the four anti-labour laws have to be repealed and withdrawn. What is the agreement you in the WTO about our farmers? That is against the welfare of the farmers. But this Government is not ready to do away with all those agreements and laws. I will conclude by saying this. You see their taxation policies. The MPs are given Rs. 5 crore per year. In that, 18 per cent is the GST which comes to around Rs. 80 lakh. Whose money is this? This is the money of the tax payers. We have to give back Rs.

80 lakh to the Union Government, 18 per cent as GST out of Rs 5 crore in one year. This is improper and should be changed. The hon. Finance Minister is here. Sir, through you, I make this request to the hon. Finance Minister. With this I conclude. Thank you.

DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon Chairperson Sir, Vanakkam. I thank the voters of Chidambaram Parliamentary Constituency for electing me to this House. I thank the voters of both Chidambaram and Villupuram Parliamentary Constituencies for according victory to Viduthalai Chiruthaigal Party, VCK. This has led to recognition of VCK as a State Party. I thank the voters of Tamil Nadu and Puducherry for giving a grand victory of 40 MPs out of 40 seats to the DMK led alliance. I thank the voters of our nation for making INDIA bloc win in 234 constituencies through a historic mandate. The hon. President in her address has stated that the BJP with 240 MPs in this Lok Sabha has secured majority, which is totally wrong. This Government is duty bound to thank her. But the Opposition is duty bound only to thank the people of this great nation. INDIA bloc had only one stand and in single voice they opined that the obstructive forces against the Constitution of India are to be opposed and defeated. Shri Rahul Gandhi and all other leaders of the INDIA bloc have, in one voice, stressed that the Constitution of India is in danger and the Political Parties led by the BJP want to destroy our Constitution. We all made an appeal to the people of India to vote for the INDIA bloc not just to come to power but to protect the Constitution and the democratic fabric of our country as they are to be protected always. Respecting the appeal of the leaders of this INDIA bloc, people of 234 constituencies have given us victory and we are now a strong Opposition in this House of People. The people have also taught a lesson to the ruling side. Like a snake without teeth and a bull without horns, the BJP is weakened and sitting in this House without absolute strength. I am once again thanking the voters of this country for giving such a historic mandate. Many MPs spoke here about NEET. Many irregularities have taken place in NEET. The NTA, the National Testing Agency should be dismantled in the first instance. After NTA came to existence, many such irregularities have come to the fore. I urge upon you that not only NTA should be dismantled but also NEET should be abolished at the national level.

15.13 hrs (Kumari Selja *in the Chair*)

The State Legislative Assembly of Tamil Nadu, not once but twice, passed a resolution to exempt Tamil Nadu from NEET and this resolution was sent to the approval of the hon. President of India. But such a resolution has been kept aside. This is seen as disregard and disrespect for a resolution passed by the State Legislative Assembly of Tamil Nadu whose Government has elected by the people of that State. NEET should be abolished at the national level. Article 47 of the Constitution talks about directive principles. This gives an important direction. It directs the Union Government to bring about prohibition of consumption of drugs and intoxicating drinks which are injurious to health. On this basis, a Prohibition Enquiry Committee was set-up in the year 1954 and its report should have been implemented in the year 1958 itself. But the Union Government has not made any effort to implement the report of this Prohibition Enquiry Committee. Rather this Government is very keen in making all efforts to implement the Uniform Civil Code as explained in Article 44 of the Constitution. But it has set aside Article 47. The youth of this country are affected at the national level. Is the Government concerned about this? The future of our youth is a question mark due to intoxicating drugs. Human resources are affected very much. Drugs and intoxicating substances are not said to be available in some States or in some select places in the country. They are freely available in almost every State of the country. Illicit liquor is also being manufactured. Other than 4 States in the country, all the State Governments are selling liquor to the people. This is a betrayal to the nation and the younger generation of this country. This is affecting the human resources as well. This Government should bring a policy to check this menace. Prohibition of liquor should be implemented throughout the country. I urge the Government that it should come forward to stop selling of intoxicating drugs and to check its use. Thank you for this opportunity.

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Dr. Thol Thirumaavalavan, a very senior Member has just spoken. In this respect, if you allow me, I want to say something both in English and Tamil.

He is requesting the Union Government to invoke the provisions given in the Constitution, particularly in reference to the Preamble to bring in prohibition and also to ensure that there should be no drug available in the country. It is a very noble idea.

I really appreciate the point that he has raised. But the Party which is in power in Tamil Nadu and with which he is in alliance saw the death of 56 people due to the consumption of illicit liquor ? (*Interruptions*)

He should first preach there. ? (*Interruptions*) He should first preach there. ? (*Interruptions*) He should first talk there. Drug is rampant in Tamil Nadu. He should talk there rather than ask us like that. ? (*Interruptions*)

DR. BYREDDY SHABARI (NANDYAL): Respected Chairman Madam and hon. Members, I am extremely happy to make my maiden speech on the occasion of the Address of the hon. President of India.

Firstly, I would like to object to the words of Kalyan Banerjee ji. Today, he has commented on our hon. Chief Minister Nara Chandrababu Naidu garu and misled the House that he was arrested by ED and CBI. Our hon. Chief Minister Nara Chandrababu Naidu garu was arrested by APCID in my own parliamentary constituency Nandyal. Nandyal parliamentary constituency has been ruled for many decades either by the Congress or by the YSRCP. I would like to question Banerjee ji. Why does he think that we won seven out of seven assembly seats in Nandyal? Why does he think I have won with more than the majority he was boasting about today? Why does he think that the people of Andhra Pradesh have given clear mandate to Telugu Desam Party, Jana Sena and the NDA alliance wining 164 seats out of 175 seats and 21 parliamentary seats out of 25 parliamentary seats? He was very sarcastic. I wish he was here today at this session. He was very sarcastic today. He mentioned that our hon. Narendra Modi ji is working with two crutches where one crutch is Telugu Desam Party.

I regard him as a senior leader with immense knowledge but please remember that the crutch you are talking about is not a crutch but it is a sword. As you can see, the world has witnessed our leader Nara Chandrababu Naidu garu who has transformed Hyderabad and Secunderabad into an IT hub. Everybody knows how he has improved the lives of the farmers and how our per capita income was increased.

I would also like to remind that the youths of our State have been employed under the rule of Telugu Desam Party. Our country is going to be coronated the third largest economy very soon and I am sure our Party is going to become the jewel in

that crown under the leadership of Nara Chandrababu Naidu garu, Pawan Kalyan garu, and the future of Andhra Pradesh, Nara Lokesh garu.

I would like to remind every citizen of Andhra Pradesh that when the country was developing, the last Government of YSRCP had missed the bus of development during the last five years. Due to the unhealthy fiscal policy of YSRCP party, now, when we have acquired this State, the State of Andhra Pradesh is in severe economic crisis. I would like to know whether there is any State without its capital in this country. It is our State, Andhra Pradesh.

I need one minute, Madam. This is the first time I am speaking in this House. ? (*Interruptions*) This is my maiden speech. I will take just one minute. ? (*Interruptions*)

Talking about Amaravati, the foundation was laid by our hon. Prime Minister and also by our hon. Chief Minister, Nara Chandrababu Naidu Garu. Then, after YSRCP came to power, they opted for three capitals for which not even a single stone was laid.

As regards Polavaram Project, about 33,000 acres of fertile land was donated by our farmers of Amaravati which has gone to waste. About 70 per cent of this Polavaram Project was completed by the Telugu Desam Party but not even one per cent of it was built by the YSRCP. About 13,000 crore were given on July 15th, 2022 to the YSRCP but that amount was completely used for corruption. About Rs. 8,000 crore were given by the Central Government to the Panchayati Raj out of which not even a rupee was used for our village panchayats. Not even a single industry, not even a single IT company, especially in my Rayalaseema region, was brought by the YSRCP. All we saw was vendetta politics, liquor mafia, sand mafia, land mafia and nothing else.

As you can see, during the regime of YSRCP, that is, Yuvajana Shramika Rythu Congress Party, we have seen youth of our State have gone begging. We have also seen hunger suicides of shramiks and farmer suicides. ? (*Interruptions*) So, my only request is this. ? (*Interruptions*) I would like the Union Government to support our State. ? (*Interruptions*)

श्री अवधेश प्रसाद (फैज़ाबाद) **:** माननीय सभापति जी, मैं आपके प्रति बहुत ही आभारी हूं कि आपने दुनिया के इस विशालतम लोकतंत्र के मंदिर में मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया । मैं आपके प्रति बहुत ही आभारी हूं ।

मान्यवर, आज मैं इस आदरणीय सदन के उन तमाम माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं, जो इस महान सदन में अपने-अपने क्षेत्रों से जीत कर आए हैं ।

माननीय सभापति जी, मैं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं । हमारा जो अयोध्या है, वह मर्यादापुरुष प्रभु श्रीराम जी की धरती है । इस सीट (फ़ैजाबाद) पर देश और दुनिया की निगाहें लगी थी । आज चुनाव हो गया है और वहां की देवतुल्य मतदाताओं ने मुझे चुनाव में जीता कर भेजा है । आज केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया में इसकी चर्चा है ।

मान्यवर, मैं देवतुल्य मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं । मैं प्रभु श्रीराम के प्रति अपनी आस्था और आभार प्रकट करता हूं । मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को सुना और देखा है ।

मान्यवर, यह अभिभाषण 29 पृष्ठों का है, लेकिन मुझे खेद है कि महामहिम राष्ट्रपति जी का नाम यहां पर नहीं है । उनका नाम यहां पर जरूर होना चाहिए था । इस संसद के समक्ष भारत के राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है । इससे दुनिया में किस तरह का मैसेज जाएगा । हमारे देश में कौन-से राष्ट्रपति हैं, उनका क्या नाम है, यह इसमें जरूर होना चाहिए था ।

मान्यवर, मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इस 29 पेजों के अभिभाषण में कहीं पर भी अयोध्या का नाम नहीं है, मर्यादापुरुष प्रभु श्रीराम की धरती का नाम नहीं है । मर्यादापुरुष प्रभु श्रीराम का नाम केवल अयोध्या में ही नहीं, बल्कि सारे देश में उनका नाम हुआ है, लेकिन इस अभिभाषण में उसका कहीं भी चित्रण नहीं है ।

महोदया, मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि अभी परसों मैं अयोध्या गया था, तो वहां गलियों को देखा था कि वहां कीचड़ भरा है । हमारे देश के आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने 6 महीने पहले एक रेलवे स्टेशन का, जो अयोध्या के नाम से है, का उद्घाटन किया । डेढ़ सौ फुट से ज्यादा बाउंड्री वॉल ढह गई है । स्टेशन से आकर केवल हिंदुस्तान के ही नहीं, दुनिया के न जाने कितने लोग प्रभु श्रीराम के मंदिर का दर्शन करने के लिए जाते हैं । सबसे दुखद पहलू है कि वहां एक किलोमीटर की सड़क है, वहां इतनी गंदगी है कि लगता है कि सारी दुनिया की गंदगी अयोध्या में आ गई है । कैसे-कैसे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं । प्रभु राम के मंदिर में जाएंगे तो सारी गंदगी को पैर से छप-छप करके जाएंगे ।

महोदया, मैं और आगे बढ़ा तो वहां पर जलायन देखा । अयोध्या का, प्रभु श्रीराम के मंदिर के पास का जो मोहल्ला है, वहां बहुत पानी भरा है । वह गरीबों का मोहल्ला है, कमजोरों का मोहल्ला है, दलितों का मोहल्ला है और वहां पानी भरा है । सुना है कि उसकी निकासी के लिए 35 करोड़ रुपये अलॉट हुए हैं । लेकिन पता नहीं है कि यह पैसा कहां गया, किस पर खर्च हो रहा है?

महोदया, वहां पर एयरोड्रम बना है, लेकिन एयरोड्रम बनने में, गरीबों को, किसानों को पैसे नहीं दिए गए । यह अफसोस की बात है कि हर साल मार्च के एंड में सर्कल रेट बढ़ता है । सर्कल रेट के द्वारा जमीनों के मूल्य का निर्धारण होता है । लेकिन, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के हर जिले में सर्कल रेट बढ़ा है, लेकिन आज सात साल हो गए हैं, फैजाबाद के, अयोध्या के किसानों की जमीनों के सर्कल रेट न बढ़ने के कारण उनकी जमीनों को कौड़ियों के दाम पर बाहरी लोगों को बसाने का काम किया है ।

हमारे नेता के पास न जाने कितने लोग आए । हम कहकर आए हैं कि हम उनको मुआवजा दिलायेंगे । हमारे नेता ने कहा था, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिला । यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है । वहां की मर्यादा को तोड़ा गया है । ? (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) **:** सभापति महोदया, धन्यवाद । मैं अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैंने कल से लेकर आज तक सारे विपक्ष के भाषण को सुना । सारे विपक्ष के भाषण में असत्य, गुमराह करने वाले तथ्य, निराशावादी, डर और डर की जो पराकाष्ठा हो सकती है कि डर के आगे कुछ नहीं है, हम कभी जीत नहीं सकते, उस तरह के भाषण को देखा । यहां विपक्ष के नेता ने भाषण दिया, मैं वो नहीं हूं, जो हूं, जो मैं दिखता हूं, वह मैं नहीं हूं ।

पिछली बार मैंने कहा था कि यहां प्रेत आकर भाषण देकर चला गया । एक फिल्म हमने मिस्टर इंडिया देखी थी । इसमें अनिल कपूर किसी को दिखते नहीं हैं, फिर दिख जाते हैं । यदि लाल कहीं दिखाई देगा, तो वह मिस्टर इंडिया के अनिल कपूर हैं, जो कभी दिखते हैं और कभी नहीं दिखते हैं । विपक्ष को क्या डर है, यह आप समझिए । गास्पल ट्रुथ के आधार पर असत्य को सत्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं । पूरा विपक्ष जो मुस्लिम की राजनीति करता रहा, आज हिंदू, हिंदू चिल्ला रहा है । ? (व्यवधान) जिस लोक सभा से अवधेश पासी एमपी हैं, उसका नाम फैजाबाद है । किसी ने फैजाबाद नहीं कहा, सबने अयोध्या कहा । यही भारतीय जनता पार्टी की जीत है, यही मोदी की जीत है ।

मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं । ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : If there is anything unparliamentary, it will be expunged by the Speaker.

? (*Interruptions*)

डॉ. निशिकान्त दुबे **:** रामायण की एक चौपाई है

?राम रमापति कर धनु लेहू, खैचहु चाप मिटहि संदेहूं? ।

उन्होंने पूरे देश को यह मैसेज दे दिया, यह देश हिन्दू है, हिन्दू राष्ट्र है । मुसलमान के नाम पर कोई राजनीति नहीं हो सकती है । फैजाबाद का नाम अपोजिशन के किसी आदमी ने नहीं लिया । क्या सत्य है? हमारे ऊपर ईडी आ गई, हमारे ऊपर सीबीआई आ गई, हम किसी से नहीं डरते । आप बांसवाड़ा चले गए, आपने क्या भाषण दे दिया ।

मैं एक ऐसा शख्स हूं, अखिलेश जी आराम से सुनिए, मेरे ऊपर कांग्रेस और जेएमएम ने 44 केस किए । मेरे 80 साल के माँ और पिताजी पर केस हुए, गैलरी में मेरी वाइफ बैठी हुई है, बच्चे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर केस हुआ, भाई के ऊपर केस हुआ । मैंने आरटीआई मंगाया है, दस करोड़ रुपये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मेरे से केस लड़ने के लिए किया । मैं जब चुनाव लड़ने गया, राहुल जी की यात्रा हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का दो कार्यक्रम हुआ, प्रियंका गांधी जी गई, उन्होंने कहा कि मैं चेंबर में बैठा रहता हूं । मैंने कहा कि मैं मोदी का सिपाही हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, मैंने प्रण लिया कि मैं जनता के पास वोट मांगने नहीं जाऊंगा, दो मार्च को

पार्टी ने मेरा टिकट अनाउन्स किया । मेरा चुनाव 1 जून को हुआ, 90 के दिन के पूरे अभियान में मैंने जनता से वोट नहीं मांगा और मैं यहां पार्लियामेंट में जीत कर आया, आपको हराकर आया हूं । जिस क्षेत्र से हेमंत सोरेन विधायक हैं, उस जिले का मैं सांसद हूं । आदिवासी बाहुल्य इलाके से 10 हजार वोट से जीत कर आया हूं । मेरा समय है, आप सुनिए, 5 मिनट में ये बातें खत्म नहीं होंगी ।

किस तरह की सत्य और असत्य की बात कर रहे हैं । आप कह रहे हैं मुस्लिम की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने घुसपैठिए कह दिया, हां, प्रधानमंत्री जी ने घुसपैठिए कह दिया ।

सभापति महोदया, वर्ष 2009 में आप मंत्री थीं । 2009 से इस संसद में मैं 200 बार बोल चुका हूं । मैं जिस इलाके से आता हूं संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़े हुए हैं, चाहे जामताड़ा हो, पाकुंड हो, साहबगंज हो, मुर्शिदाबाद हो, मालदा, किसनगंज हो, अररिया हो, हालत यह है, हमारी स्थिति यह है, यहां विजय हाँसदाक बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछ रहा था, गोपीचक एक गांव है, गाय काट दिया और गाय काटने पर मुसलमानों ने जब प्रतिरोध किया, अभी 15 दिन पहले बांग्लादेशी घुसपैठिए जो अपने को पश्चिम बंगाल का नागरिक कहते हैं । हमारी बहु बेटियों की इज्ज़त लूटा, उनके घर को जलाया, उन्हें घर से भगाया । आप कह रहे हैं कि आप बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं हैं । उनकी जनसंख्या नहीं है । मैं गोपीचक की बात कर रहा हूं ।

पूरे देश में परिसीमन हो गया, आप आदिवासी की बात करते हैं, पिछड़े की बात करते हैं । हमारे यहां परिसीमन नहीं हुआ, आदिवासी की संख्या जो 36 परसेंट थी वह 26 परसेंट हो गई, यह पूरे देश को जानने की आवश्यकता है । एक लोक सभा की सीटें और तीन विधान सभा सीटें घट रही हैं । परिसीमन नहीं हुआ और घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, आदिवासी लड़कियों के साथ शादी हो रही है, धर्मान्तरण हो रहा है । इसके बाद भी आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी घुसपैठिए की बात नहीं करेंगे । किस तरह की आप राजनीति कर रहे हैं ।

शिव की बात होती है । हम उस विचारधारा के लोग हैं-अधजल गगरी छलकत जाए । जिसको कुछ समझ में नहीं आता, यदि आपको शिव का ही दिखाना था, गुरू नानक का दिखाना था, मंदिर चले जाते, गुरूद्वारा चले जाते । इस पार्लियामेंट में फोटो क्यों दिखा रहे हैं? जिस अभय मुद्रा की बात कर रहे हैं, मैं ब्राह्मण हूं और मुझे गर्व है । जिस अभय मुद्रा की बात करते हैं, भगवान शंकर के चार हाथ है, एक हाथ नहीं होता है, हस्त मुद्रा में ऐसे भी होता है, ऐसे भी हाथ हैं, 28 मुद्राएं हैं, 28 मुद्रा क्या हैं, जो माननीय मोदी जी कह रहे हैं, सबको जानने की आवश्यकता है ।

आप जिस अभय मुद्रा की बात कर रहे हैं, उसमें भगवान शंकर के चार हाथ हैं, एक हाथ नहीं होता है । हस्त मुद्रा में ऐसे भी हाथ है और वैसे भी हाथ है, 28 मुद्राएं हैं । 28 मुद्रा क्या है, जो माननीय मोदी जी कह रहे हैं और इसे सबको जानने की आवश्यकता है । एक मुद्रा वह है जिसमें हाथ में डमरू है, डमरू मतलब स्टार्ट करिए, प्रकृति को स्टार्ट करिए, जीवन को स्टार्ट करिए और गरीबों के लिए काम करना स्टार्ट करिए । दूसरे हाथ में क्या है? डिस्ट्राए करना यानी भगवान शिव के हाथ में अग्नि है । वह हाथ कहता है कि चाहे ? हो, चाहे ? हो, जो भ्रष्टाचारी है, जिसने जनता का पैसा लूटा है, उसे जेल भेजिए । ? (व्यवधान) तीसरा हाथ कहता है कि जनता को खाना खिलाइए । चौथा हाथ है यानी विकसित भारत के लिए, भविष्य के लिए, इनसॉल्वेशन के लिए भगवान शिव हैं । आपको यदि धर्म ही नहीं पता है, आप कहां से धर्म के बारे में पता करेंगे? त्रिशूल भूत, भविष्य और वर्तमान की व्याख्या करता है इसीलिए वह त्रिशूल है । हमारे प्रधान मंत्री भूत, भविष्य और वर्तमान को देखकर विकसित भारत संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको यह बात समझ में नहीं आएगी । ? (व्यवधान)

सभापति महोदया, ये संविधान की बात करते हैं । अभी मैंने कहा कि मीसा जी, मैं आपके बारे में बोलूंगा । मीसा भारती जी जब पैदा हुईं तब वह जेल में थे । मेरे गुरु गोविंदाचार्य उस वक्त जेल में थे । राम बहादुर राय जी भी जेल में थे और लालू जी को राम बहादुर राय जी ने सजेस्ट किया कि अपनी बेटी का नाम मीसा रखो,इसीलिए उनका नाम मीसा भारती है । जिस किताब का विमोचन राहुल गांधी जी ने किया, एम.के. स्टालिन की आत्मकथा का, पता है उसमें सबसे बढ़िया टॉपिक क्या है कि इमर्जेंसी में मेरे पिताजी ने पुलिस को हैंडओवर कर दिया । ? (व्यवधान)

यहां अखिलेश यादव जी बैठे हैं, इनके पिताजी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, वह बहुत बड़े आदमी थे । इतने बड़े आदमी थे कि हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हारा भाषण सुनता हूं । उन्होंने मुझे इमर्जेंसी की कहानी सुनाई कि जिस दिन इमर्जेंसी में जेल गए थे, उनकी वाइफ के पास परिवार को खिलाने के लिए खाना नहीं था । आप संविधान की बात करते हैं ।

आपने कहा राज्य का डिवीजन कर लिया । आपको पता है कि क्या हुआ? सातवां संशोधन, वर्ष 1956 में जब नेहरू जी ने किया ।? (व्यवधान) आपने नरेन्द्र मोदी कहा इसलिए मैंने नेहरू कहा । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आप चेयर को एड्रेस कीजिए ।

? (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे **:** सभापति महोदया, सातवां संशोधन किया कि राज्य को अपनी बाउंड्री चुनने का कोई अधिकार नहीं होगा । यही कारण है कि सातवें संशोधन के बाद 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बन गए । आप संविधान की बात करते हो? आप संविधान बचाने की बात करते हो? इमर्जेंसी में सारे बड़े नेता, चाहे लालू प्रसाद जी हों, मुलायम सिंह यादव जी हों, करुणानिधि जी हों, आडवाणी जी हों, अटल जी हों, हेमवती नंदन बहुगुणा हों, कांग्रेस के चंद्रशेखर जी हों या बाबू जगजीवन राम जी हों, मैं एमपीज़ की बात कर रहा हूं, जब सारे लोग जेल में बंद थे तो स्वर्ण सिंह कमेटी वर्ष 1976 में बनी । हम धार्मिक हैं, हम हिंदू हैं, बिट्टू जी यहां बैठे हैं, वह सिख हैं, रिजीजू जी बौद्धिस्ट हैं, यहां ओवेसी बैठे हुए हैं, इस्लाम उनके लिए धर्म का विषय है । 42 वां संशोधन हुआ और 42 वें संशोधन ने हमारे धर्मपरायण देश को धर्म निरपेक्ष कर दिया, रातोंरात बदल दिया । आपने उसमें इंटीग्रिटी शब्द जोड़ दिया । ? (व्यवधान) पूरा देश ईमानदार है, इसी कारण ईमानदारी से चलता है, आपने ईमानदार जोड़ दिया और आपने सोशलिस्ट जोड़ दिया । हम कैसे सोशलिस्ट हो सकते हैं, यार? कोई कम्युनिस्ट हो सकता है, कोई कैपेटलिस्ट हो सकता है । आपने पूरी प्रिएम्बेल को बदल दिया । आप संविधान बनाने की बात करते हो? उन्होंने कहा कि हम कानून बनाएंगे, जो फंडामेंटल राइट्स थे, हमारे फोरफारदर्स ने जो फंडामेंटल राइट्स दिए थे, आपने उसके साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ अलग शब्द जोड़ दिए । आप संविधान बनाने की बात करते हो?

सभापति महोदया, इंदिरा जी की सदस्यता खत्म हो गई थी, उन्होंने कहा कि हम फिर से रिइनस्टेट होकर देश के प्रधान मंत्री बन जाएंगे, आप मेरे ऊपर कोई क्वैश्चन नहीं कर सकते । लोक सभा की समय सीमा पांच साल थी, उन्होंने कहा अब छ: साल होगी । ?खाता न बही, इंदिरा गांधी जो कहे वह सही ।? संविधान वही है, मोदी जी ने संविधान बदला, धारा 370 के लिए बदला । शेड्यूल कास्ट के लिए बदला, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने के लिए बदला और जब भी एससी, एसटी, ओबीसी की बात होगी, हम संविधान बदलेंगे और हमें कोई संकोच नहीं । यह आर्य और अनार्य की बात करते हैं । राजा ऋषि-मुनि की बात करते हैं । राजा साहब, आप हमारे मित्र हैं । मैं एक ऐसा आदमी था, जो तिहाड़ में आपसे मिलने गया था । कांग्रेस ने आपको जेल भेजा । आपको पता है कि

गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त मुनि में कोई भी ब्राह्मण नहीं था । रामायण, महाभारत, गीता लिखने वालों में कोई भी ब्राह्मण नहीं था । कोई भगवान ब्राह्मण नहीं है । रामायण वाल्मीकि ने लिखी । महाभारत वेदव्यास ने लिखा । चारों वेद और 13 उपनिषद सभी वेदव्यास ने लिखे, जो मछुआरे के बेटे थे । चाहे ऋषि अगस्त हों, चाहे ऋषि कन्नन हों, कोई ब्राह्मण नहीं था । आप आर्य और अनार्य की बात करते हैं । वर्ष 1952 में कांग्रेस के सांसद रामधारी सिंह दिनकर जी को नेहरू जी सांसद बनाकर लाए, जो 12 साल सांसद रहे, वह देश के बहुत बड़े कवि थे । उन्होंने संस्कृति के चार अध्याय लिखे थे । उस संस्कृति के 4 अध्याय में उन्होंने लिखा कि न कोई आर्य है, न कोई अनार्य है । जो हरिजन तमिलनाडु का है, वही कोलकाता का ब्राह्मण है और जो कोलकाता का ओबीसी है, वही पंजाब का सिख है । यह उन्होंने लिखा, कांग्रेस ने लिखा, आपके सांसद ने लिखा । हमें तो गर्व है कि यह देश एक है । न जाति है, न बिरादरी है । आप जाति प्रथा की बात करते हैं । मैं एक बात कहना चाहता हूं । यहां जितने बुजुर्ग बैठे हैं, उनमें सौगत राय जी भी बैठे होंगे । आज से 50 साल पहले किसी बड़े घर में, किसी गांव में शौचालय नहीं होता था । चाहे बड़े परिवार की महिलाएं हों, चाहे छोटे परिवार की महिलाएं हों, वे खेत में जाती थीं । जब वे खेत में जाती थीं, तो मेहतर प्रथा कहां से आ गई? जो मुगलों ने दिया, उसे आप सही मान रहे हैं । आप पूरे देश को हिंदुत्व के नाम पर, आर्य के नाम पर, अनार्य के नाम पर, इस्लाम के नाम पर केवल गुमराह करने की कोशिश करते हैं । इस गौसपेल ट्रुथ को बंद करो, यह कहना बंद करो और देश को साथ लेकर चलने की बात करो ।

अंत में, मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा । कल कहा गया कि स्पीकर साहब ने झुककर प्रधान मंत्री जी को अभिवादन किया और राहुल जी को ऐसे करके किया । आज मैंने थल सेनाध्यक्ष की एक फोटो देखी । कहा जाता है कि वर्दी में किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए । आज सारे अखबारों में थल सेनाध्यक्ष का फोटा छपा है और वह वर्दी में अपनी मां के पैर छूकर उनको प्रणाम कर रहे हैं । नेत्रोपनिषद् का एक श्लोक है ?

अभिवादन शीलस्य नित्यं वृधोपसेविन |

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् ||

आपसे जो भी बड़े आदमी हैं, पद की, मर्यादा की कभी परवाह न करें । मैं फरवरी माह की बात कर रहा हूं, जब पार्लियामेंट का सत्र खत्म हुआ था । उस दिन मैं बाहर गाड़ी का वेट कर रहा था । मैं सबसे ज्यादा कांग्रेस पर अटैक करता हूं । राहुल जी, सोनिया जी, पूरा कांग्रेस और गांधी परिवार मेरा टॉपिक है, क्योंकि मेरे फादर वर्ष 1975 की इमरजेंसी में सैक कर दिए गए । उनकी जिंदगी में नौकरी नहीं लगी । 19 महीने मेरे परिवार के लोग इमरजेंसी में बंद रहे, इसलिए कांग्रेस के प्रति इतना विद्रोह और यह भाव मेरे मन में बचपन से है, क्योंकि मेरा बचपन मैंने देखा ही नहीं । हम सभी देशद्रोही परिवार के माने जाते थे । सोनिया जी आईं और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा । सबके सामने पब्लिक में यह काम हुआ, इसलिए मैं पब्लिक में यह बात कह रहा हूं । उन्होंने मुझे कहा कि निशिकांत आज मेरी तबियत खराब थी । तुम्हारे जैसे लोगों को पार्लियामेंट आना चाहिए । मैंने उनको प्रणाम किया । मैंने यह नहीं सोचा कि वह सोनिया गांधी हैं । वह बड़ी हैं । आप किस तरह के डिस्कोर्स में ले जाना चाहते हैं? माननीय मोदी जी हमारी पार्टी के बड़े आदमी हैं । पार्टी ने टिकट दिया तो श्री ओम बिरला इस कुर्सी पर बैठे हैं । यदि उनको पैर छूकर भी बिरला जी प्रणाम कर लेते, तो उस कुर्सी की ताकत कम नहीं होती । आपको भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में नहीं पता है । यदि आपको इस बारे में नहीं पता है, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं । ? (व्यवधान) आज आप 98 पर हैं, अगले चुनाव में आपको लीडर ऑफ द अपोजीशन का भी मौका नहीं मिलेगा । आपने मुझे मौका दिया, इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत ।

DR. PRABHA MALLIKARJUN (DAVANAGERE): I would like to express my views on the highly important discussion on the Motion of Thanks to her Excellency the President of India for the joint address to both the Houses of the Parliament on 27.06.2024.

First of all, I would like to thank our hon. President Smt. Droupadi Murmu Ji. I, as a woman, feel proud and have high regard for her as she occupied the top post of the world's largest democracy as second women President of India.

At this juncture, I would like to mention with pride that Shrimati Pratibha Devisingh Patil was the first woman President of India to hold the highest office in 2007. It is my Congress Party which had created a new history by electing her as the first women President of India.

I would like to thank my Congress Party leaders, my people of Davanagere Lok Sabha Parliamentary constituency well-wishers and my mentors and for their support and blessings to make me a Member of this august House for the first time.

As I understand the President's Address to the Joint session of the Parliament is the most important occasion in our democracy. It is not an ordinary document or a piece of paper. It is a policy statement of the Government of India. It plays a vital role in informing the Parliament, I mean, to the elected representatives of 140 crore people of the country. It is a great opportunity for the first time MPs like me, as we are 52 per cent newly-elected MPs in this 18th Lok Sabha. It helps us to understand the activities and achievements of the Government as well as its initiatives, policies and plans envisaged for the ensuing year.

However, I am surprised that there is no mention of the burning issues such as constantly rising unemployment, increase in the number of crimes against women and children, and incidents of lawlessness have only added to the miseries of the common people. Also there is no promise made in the Address of the President about what measures are going to be taken to find a solution to all those problems.

The President in her address highlighted that the people of India have full faith that only my Government can fulfill their aspirations. Therefore, this election of 2024 has been an election of trust in policy, intention, dedication and decisions.

The fact is that the BJP failed to win the hearts and minds of the people of the country. That is why they got only 240 and it falls short of 32 seats to assume

power on their own. I just want to highlight that the BJP Government failed to uphold the trust of the people. The best example is the NEET exam scam.

The NEET-UG controversy has spotlighted the widespread issue of paper leaks, a malpractice that has plagued India. For the past seven years, there have been 70 confirmed exam leaks across 15 States, casting serious doubts on the integrity of the nation's examinations. These leaks have disrupted the schedules of 1.7 crore applicants. The recent NEET-UG 2024 paper leak, affecting an all-India exam with over 24 lakh aspirants, underscores the considerable influence of the paper leak mafia over India's examination system.

It is the failure of the Union Government in the implementation and compliance of comprehensive Standard Operating Procedures (SOPs) to ensure a transparent examination system in the country.

In 12th para of her speech Hon. President mentioned that the Government is committed to women-led development has started a new era of women empowerment and also the enactment of Nari Shakti Vandan Adhiniyam. I congratulate the Government for this.

However, I want to remind them that our Congress Party made effort to bring Women Reservations Bill in 2014 itself and passed it in Rajya Sabha and could not get through it in Lok Sabha as it had gone to election.

I am of the opinion that enacting the law is not enough. We need to ensure the law is implemented in its letter and spirit. Facts and figures of our recent Lok sabha elections are before us. Only 74 MPs (means 14 per cent) elected to the 18th Lok Sabha are women, whereas 78 women MPs were there in 17th Lok sabha. So, it is marginally lower than in 2019. Even though the Women Reservation Bill is enacted, our society still needs to encourage the women to get elect to become legislators. So, we all irrespective of Political Parties need to create an atmosphere in the society and also to provide more opportunities to women to come forward to serve as legislators of the country.

Hon. President in 4th paragraph mentioned that the 18th Lok Sabha is historic in many ways. This Lok Sabha has been constituted in the early years of Amrit Kaal and it will script a new chapter on decisions for public welfare.

As a Member of Parliament from the state of Karnataka, I welcome and I am also happy to mention that my state Karnataka is actually one of the most developed

States in India, with a strong economy, a rich cultural heritage, and significant contributions in various fields such as technology, education, and industry. However, there are many areas the co-operation of the Union Government is highly needed for the overall development of Karnataka. In a federal structure of our Indian democracy, I believe my State Karnataka is not ignored while disbursing resources from the Government of India.

Before concluding my speech, I would like to draw the kind attention of the Union Government about the facts and figures indicating that Karnataka has experienced steady economic growth over the past 5 years, with a consistent GSDP growth rate above 7 per cent and a rising per capita income. The State's economy is largely driven by the services sector, particularly the IT and ITES industries, as well as other high-growth sectors. Karnataka also continues to rank high in the ease of doing business, making it an attractive destination for investments. So, considering all these facts I once again hope my State Karnataka would get a better deal in the next Budget for the year 2024-2025.

With these few words, I conclude.

श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल (अहमदाबाद पूर्व) **:** 18 वीं लोक सभा के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने पर माननीय अध्यक्ष जी को हार्दिक शुभकामनायें ।

18 वीं लोक सभा के पहले संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने भारत सरकार की विगत 10 साल के उपलब्धियों और आने वाले समय में विकसित भारत बनाने के लिए सरकार किस दिशा में आगे बढ़े का उल्लेख किया है जिसके पक्ष में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं ।

महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण से स्पष्ट है कि पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी सरकार जी के नेतृत्व में भारत सरकार की नीतियों से अर्थव्यवस्था, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संसाधन, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास और सामाजिक कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में शानदार उपलब्धियों को प्राप्त किया है ।

जब देश स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तो उसी समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने "अमृत काल" संकल्पना रखी । उन्होंने बताया कि 2022 से 2047 तक जो कालखंड होगा वह भारत के लिए अमृतकाल होगा और भारत के अमृतकाल के तौर पर आदरणीय मोदी साहब ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा । महामहिम के भाषण में जो उपलब्धियां गिनाई गयी हैं और आगे का जो रोडमैप दर्शाया गया है उससे भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का विश्वास दृढ़ होता है । देश के युवाओं की अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर देने के लिए सरकार एक डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में काम कर रही है । मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में उनके परिश्रम और प्रयासों से भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम बन चुका है ।

25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था । तब पूरे देश में हाहाकार मच गया था लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही हैं । राष्ट्रपति महोदया के भाषण में आपातकाल को काला अध्याय बताना ये दर्शाता है कि वर्तमान सरकार का नेतृत्व संविधान के प्रति श्रेष्ठ और गहरी श्रद्धा और सम्मान रखता है । आज मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता से उतरे हैं । भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकॉनमी है । भारत इतना बड़ा चुनाव निष्पक्षता, बिना बड़ी हिंसा और अराजकता से पूरा कराता है तो हमें गर्व होना चाहिए । पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं । इसमें एससी-एसटी हर क्षेत्र के लोग शामिल हैं । विशेषकर आदिवासी समाज में ये बदलाव और भी समझ में आ रहा है । 20 हजार करोड़ रुपये की योजना अति पिछड़े जनजातीय समूह के माध्यम रही है । सरकार की योजनाओं में देश के गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसानों को महत्व दिया जा रहा है । देश तभी विकास कर सकता है । इसीलिए सरकार की योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता इन्हीं चार स्तंभों को दी जा रही है । माननीय मोदी जी की कोशिश इनको हर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की है । देश के हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम बन रहे हैं । भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुनिया में बेहतरीन हो इस मानदंड पर भारत काम कर रहा है । इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इस दिशा में बदलते भारत की योजना को दिखा रही है । गांव में 3 लाख 80 हजार किलोमीटर से ज्यादा सड़क बनाई है । आज भारत में नेशनल हाइवे का जाल बिछ रहा है । नेशनल हाइवे बनाने की गति में दोगुना वृद्धि हुई है । सरकार बुलेट ट्रेन के लिए पूर्वी, उत्तर भारत में फिजिबलिटी स्टडी शुरु कर चुकी है । सरकार के शुरुआत के दिन से ही किसानों को 3 लाख 20 हजार करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की जा चुकी है । आज का भारत अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा है । सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नीतियां बना रही हैं । भारत सरकार दलहन और तिलहन में दूसरे देशों की निर्भरता खत्म करने के लिए बड़ी कोशिश कर रही है । सरकार सार्वजनिक सेक्टर को भी मजबूत करने में जुटी है । आज भारत आईटी से लेकर हेल्थ सेक्टर में बड़ी शक्ति बन रहा है । इन सेक्टरों में रोजगार और स्व रोजगार के अवसर मिल रहे हैं । गांव में कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है । सरकार किसानों के उत्पाद संघ का बड़ा नेटवर्क बना रही है । छोटे किसानों की बड़ी समस्या भंडारण से जुड़ी होती है । मोदी सरकार दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना पर काम शुरू कर चुकी है । वैश्विक महामारी के बाद भी और दुनिया के अलग-अलग देशों में चल रही मुश्किलों के बाद भारत ने ये विकास हासिल किया है । आज भारत अकेले ही दुनिया की अर्थव्यवस्था में 15 फीसदी का योगदान कर रही है । आज भारत को दुनिया को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने में मोदी जी की सरकार जी जान से जुटी है ।

लगातार तीसरी बार जनादेश, देश को विकसित बनाने के लिए मिला है । राज्यों का विकास देश का विकास है और मोदी सरकार इसी भावना के साथ आगे बढ़ रही है । भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है । 10 साल में भारत 11 वें नंबर की अर्थव्यवस्था से उठकर 5 वें नंबर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचा है ।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने विकसित भारत की जो गारंटी दी है, वह गरीब, किसान, महिला एवं युवा के सशक्तिकरण से संभव है, जिसे भारत सरकार पूरी शिद्दत से कार्यान्वित कर रही है । महामहिम राष्ट्रपति महोदया के भाषण से उसके पूर्णाता की दिशा में भारत अग्रसर है । इसका विश्वास दृढ़ होता है । भारत की जनता के विश्वास पर सरकार के खरे उतरने की पुष्टि करने वाले इस अभिभाषण के लिए मैं राष्ट्रपति महोदया का आभार प्रकट करता हूं एवं सरकार के नेतृत्व को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं ।

श्रीमती मालविका देवी (कालाहाण्डी) **:** मैं इस नयी लोक सभा के गठन के बाद, महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा दिए गए अभिभाषण पर अपने विचार रखती हूँ ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जिन बातों का उल्लेख किया है, मैं प्रयास करूंगी कि क्रमवार कुछ बिन्दुओं पर अपना एवं पार्टी का पक्ष रखने का प्रयास करूं ।

आज मैं प्रथम बार सांसद होने पर बहुत गर्व महसूस करती हूं कि प्रथम बार जीती हूं और वह भी भाजपा की सरकार की तरफ से, भाजपा यानी कि बहुमत की सरकार, वह सरकार जिसने पूरे भारत की शक्ल दस सालों में बदल दी । वह सरकार, जिस पर भरोसा करके लोगों ने जिताया है । एक बात जो मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है, वह यह है कि उस तरफ के लोगों को, जो 99 यानी 100 सीट्स भी नहीं ला जाए, वे हमारी बहुमत की सरकार के बहुमत पर प्रश्न किस हिसाब से लगा रहे हैं । उन्होंने या तो स्कूलों में मैथ्स नहीं पढ़ा है या फिर कुछ भी बोलने के पहले सोचना ठीक नहीं समझते हैं । आज अगर भारत के लोग गर्व करके विश्व के सामने अपना सिर उठाकर चल सकते हैं तो वह हमारे मोदी जी की सरकार और उनके कामों की वजह से ही है । आज दुनिया के बड़े नेता हमसे हमारे विचार, हमारे सुझाव मांगते हैं । आज हमने सिर्फ केन्द्र में ही नहीं, बल्कि ओडिशा में भी बहुमत की सरकार बनाई है । 21 में से 20 सांसद भाजपा के हैं । यह कोई मामूली बात नहीं है । मोदी जी के भरोसे और भाजपा पर भरोसा करके ओडिशा के लोगों ने बहुमत से डबल इंजन सरकार बनाई है । यह वह सरकार है, जो सिर्फ बोलती ही नहीं है, बल्कि करके दिखाती है । जैसे हमारे पास के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के प्रांतों में काम हुआ है । इकोनॉमी, जो 11 नम्बर पर थी, आज वह 5 नम्बर पर पहुंच गयी है और आने वाले पाँच सालों में नम्बर-तीन पर पहुंचने वाली है । 64 करोड़ मतदाताओं ने वोट किया और वह भी दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में तीसरी बार बहुमत से भाजपा को जिताया । वह भी शांत और सक्सेसफुल मतदान हुआ । मैन्यूफैक्चरिंग सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दिया जाएगा, हरित युग को बढ़ावा दिया जाएगा । 32,000 करोड़ रुपये पी.एम. किसान सम्मान निधि में किसानों की मदद करने के लिए दिए गए हैं । नेशनल हाईवेज़ दोगुना बढ़ गए हैं । Today we export defence equipments, unlike never before. 3,80,000 किलोमीटर ग्रामीण रास्ते बनाए गए हैं । पी.एम. ग्राम सड़क योजना में नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण किया गया है । दस सालों में 4 करोड़ प्रधान मंत्री आवास महिलाओं को दिए गए हैं ।

मोदी जी की सरकार ने दस सालों में भारत को बदल दिया है । मोदी जी की सरकार अम्बेडकर जी की बात पर विश्वास करती है कि समाज की प्रगति समाज के निचले क्रम से पता चलती है । मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आज हम सब सांसद यहां लोगों के लिए हैं और भले ही हमारे सुझाव कई मुद्दों पर अलग-अलग हों, पर एक बात पर हम सबकी सहमति है कि हम सबका एकमात्र लक्ष्य भारत का विकास करना है । लोगों की वजह से ही हम हैं ।

मैं आशा करती हूं कि यह 5 साल भारत के विकास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएगें और हम सब एक होकर भारत के लोगों के लिए काम करेंगें ।

कालाहांडी और नुआपड़ा के लोगों का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे जिता कर मुझ पर विश्वास दिखाया है । मोदी सरकार की हैट्रिक जीत पर मैं अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को हार्दिक बधाई देती हूं ।

श्री अरुण कुमार सागर **(**शाहजहाँपुर**) :** मैं राष्ट्रपति महोदया द्वारा गुरुवार को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में दिए गए अभिभाषण का हृदय से समर्थन और उनके द्वारा नव-निर्वाचित सांसदों को दी गई बधाई पर उनका

हार्दिक अभिनंदन करता हूं । उन्होंने अपने अभिभाषण में अमृत काल के 25 वर्षों के कालखंड में देश को विकसित राष्ट्र बनाने का खाका पेश किया है, जो केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण आकांक्षा को दर्शाता है ।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से यह परिलक्षित होता है कि केन्द्र सरकार "सबका साथ सबका विकास" के अपने वायदे के अनुरूप देश को तेजी से आर्थिक विकास की नई राह पर ले जा रही है । देश के गरीब, दलित, शोषित, वंचित, किसान, श्रमिक और युवा सरकार के इस समावेशी आर्थिक विकास के केन्द्र में है ।

यह हम सभी के लिए गौरव की बात है कि छह दशकों के बाद देश में पूर्ण बहुमत वाली एक स्थिर सरकार बनी है । देश के नागरिकों ने लगातार तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी पर भरोसा दिखाया है । चूंकि, उन्हें मालूम है कि केवल श्री नरेन्द्र मोदी जी की केन्द्रीय सरकार ही उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है । इस लोकसभा का गठन अमृत काल के शुरुआती वर्षों में हुआ । इसलिए, 18 वीं लोक सभा कई मायनों में ऐतिहासिक है ।

हमारा देश विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रुप में जाना जाता है, जिस पर सदियों तक विभिन्न राजाओं, सम्राटों तथा यूरोपीय साम्राज्यवादियों द्वारा शासन किया गया । भारत 1947 में अपनी आजादी के बाद एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया था । उसके बाद भारत के नागरिकों को वोट देने और अपने नेताओं का चुनाव करने का अधिकार मिला । भारत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनियां का सातवां सबसे बड़ा देश और आबादी के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है, इन्हीं कारणों से भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रुप में भी जाना जाता है । 1947 में देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था । हमारे देश में केंद्र और राज्य सरकार का चुनाव करने के लिए हर 5 साल में संसदीय और राज्य विधान सभा चुनाव आयोजित किए जाते हैं ।

देश की 18 वीं लोक सभा का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था । करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है । इस चुनाव में सुखद तस्वीर विशेषतः जम्मू-कश्मीर से भी आई है, जहां कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों से रिकॉर्ड टूटे । पिछले चार दशक में बंद और हड़ताल को देखा गया, जिसकी वजह से काफी कम मतदान हुआ ।

यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने 18 वीं लोक सभा के लिए चुनाव को बहुत ही कुशलतापूर्वक सम्पन्न कराया है । जम्मू-कश्मीर में इस बार घाटी में दशकों का रिकॉर्ड टूटा है तथा काफी संख्या में लोगों ने वहां मतदान किया । राष्ट्रपति महोदया ने भी इसके लिए आयोग की प्रशंसा की है, जो स्वागत योग्य है ।

राष्ट्रपति महोदया का यह कथन सही है कि विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब देश के गरीब, युवा, महिलाएं और किसान सशक्त होंगे । इसलिए सरकार द्वारा उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है । सरकार का लक्ष्य उन्हें हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना है तथा इस इच्छा शक्ति के साथ काम किया जा रहा है कि एक भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने कुशल कार्यकाल के दौरान 10 लाख गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है । यह सच्चाई है कि उनके कार्यकाल में पिछले एक दशक में गरीबों का जितना उत्थान हुआ है, उतना आजादी के बाद इससे पहले कभी नहीं हुआ है ।

श्रद्धेय श्री नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण के नए दौर की भी शुरुआत हुई है । 24 हजार करोड़ रुपए से अधिक की पीएम-जनमन जैसी योजना आज अति पिछड़े जनजातीय समूहों के उत्थान का माध्यम बन रही है ।

ऋषितुल्य श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के चहुमुखी विकास के लिए कृतसंकल्प है । उनके द्वारा देश की अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों - रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफोर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है । 10 साल में 11 वीं अर्थव्यवस्था से पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है । भारत ने साल 2021 से लेकर साल 2024 के बीच औसतन 8 फीसदी की रफ्तार से विकास किया है ।

केन्द्र सरकार मैन्युफेक्चरिंग, सर्विस और एग्रिकल्चर को भी बराबर महत्व दे रही है । पीएलआई स्कीम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं । देश के किसान अपने छोटे खर्चे पूरे कर सकें, इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें 3 लाख 20 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी जा चुकी है । सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी पर रिकॉर्ड वृद्धि की है ।

पारंपरिक सेक्टर के साथ-साथ सनराइज सेक्टर को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है । इसका उल्लेख भी राष्ट्रपति महोदया ने अपने भाषण में किया है, जो स्वागत योग्य है ।

देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा किसानों पर विशेष फोकस देकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है । केन्द्र सरकार कई ऐसी योजनाएं लेकर आई जो उनके लिए काफी लाभकारी साबित हो रही हैं ।

केन्द्र सरकार कृषि उत्पादों के भंडारण की दिशा में भी काम कर रही है । कृषि उपजों के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) बढ़ाया गया है । दुनिया भर में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ रही है । देश के किसान इस मांग को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम हैं । किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी तेजी से कार्य किया जा रहा है तथा उनको 20 हजार करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं ।

आने वाला समय ग्रीन एरा यानि हरित युग का है । केन्द्र सरकार इसके लिए भी हर जरूरी कदम उठा रही है और हरित उद्योगों पर निवेश बढ़ाये जा रहे हैं, जिससे ग्रीन जॉब भी बढ़े हैं ।

आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के विगत 10 वर्षों के कार्यकाल में बैंकिंग सेक्टर भी पिछली सरकारों की तुलना में काफी मजबूत हुआ है । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का लाभ 2023-2024 में 1.4 लाख करोड़ को पार कर गया । यह पिछले वर्ष की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है । बैंकों की मजबूती उन्हें ऋण आधार का विस्तार करने और राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए सक्षम बनाती है ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने पहली बार गरीबों को ये अहसास कराया कि सरकार उनकी सेवा में है । पिछले 10 वर्षों में राष्ट्र की उपलब्धियों और विकास का आधार गरीब का सशक्तिकरण रहा है । कोरोना कठिन समय में सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए पीएम गरीब कल्याण योजना शुरू की । आज केन्द्र सरकार 55 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ उपलब्ध करा रही है ।

केन्द्र सरकार द्वारा दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए स्वदेशी सहायक उपकरण बनाये जा रहे हैं । वंचितों की सेवा का ये संकल्प ही सच्चा सामाजिक न्याय है । आज केन्द्र सरकार की योजनाओं में देश के गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसानों को अहम महत्व दिया जा रहा है । देश तभी विकास कर सकता है । इसलिए सरकार की योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता इन्ही चार स्तंभों को दी जा रही है । ताकि इनको हर सरकारी योजनाओं का लाभ सरलता से मिल सके ।

यह हम सभी के लिए प्रसन्नता की बात है कि देश का पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुनिया में बेहतरीन हो इस मानदंड पर कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है । इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इस दिशा में बदलते भारत की योजना को दिखा रही है । गांव में 3 लाख 80 हजार किलोमीटर से ज्यादा सड़क बनाई गई है । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में आज भारत में नेशनल हाइवे का जाल बिछ रहा है । नेशनल हाइवे बनाने की गति में दोगुना वृद्धि हुई है तथा बुलेट ट्रेन के लिए पूर्वी, उत्तर भारत में फिजिबलिटी स्टडी शुरू की जा चुकी है ।

केन्द्र सरकार ने युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भागीदारी और बढ़ाने के लिए मेरा युवा भारत MY Bharat अभियान की शुरुआत भी की है । Start-up India और Stand-up India जैसे अभियान देश के युवाओं का सामर्थ्य बढ़ा रहे हैं । इस प्रकार से युवाओं को भी स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में विगत दस वर्षों में देश में 10 नए आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 15 नए एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, जो एक कीर्तिमान है ।

यह हम सभी के लिए प्रसन्नता की बात है कि देश में 25 हजार जन औषधि केंद्रों को खोलने का काम भी जल्दी से चल रहा है तथा अब आयुष्मान भारत योजना की तहत मुफ्त इलाज का लाभ 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी मिलेगा । यह सरकार की देश के गरीब समुदाय के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल है ।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी पूर्वोत्तर राज्यों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं तथा नॉर्थ-ईस्ट के आवंटन में 10 गुना की वृद्धि की है । सरकार द्वारा उत्तर-पूर्व में हर क्षेत्र में विकास कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है । असम में 27 हजार करोड़ रुपये की लागत से सेमी कंडक्टर प्लांट बनाया जा रहा है तथा नॉर्थ-ईस्ट में स्थायी शांति के लिए निरंतर काम किया जा रहा है । पिछले 10 साल में अनेक पुराने विवादों को हल किया गया है । नॉर्थ ईस्ट में अशांत क्षेत्र में तेज विकास कर चरणबद्ध तरीके से अफस्पा हटाने का काम भी जारी है । इस तरह से देश के हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम बन रहे हैं ।

मैं राष्ट्रपति महोदया के इस कथन का पूरजोर समर्थन करता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था । उस समय पूरे देश में हाहाकार मच गया था क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही हैं । इसलिए, ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया ।

राष्ट्रपति महोदया का यह कथन भी सही है कि जब संविधान बनाया जा रहा था तब भी दुनिया में ऐसी ताकतें थीं जो भारत के असफल होने की कामना कर रही थीं । देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए, जिनमें वर्ष 1975 में देश में लगाया गया आपातकाल घोर निंदनीय और हमारे पवित्र संविधान के अनुरूप नहीं है ।

महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में केन्द्र सरकार के बीते 10 साल की अवधि में हुए कामकाज का विस्तार से जिक्र किया है, जिसमें हमारी लोकप्रिय सरकार की आत्म छवि का एक अंदाजा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ।

मैं पुनः महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन में दिए गए अभिभाषण का हार्दिक अभिनंदन और पूरजोर समर्थन करता हूं । सधन्यवाद ।

SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR): I would like to extend my sincere thanks to the hon. President of India for highlighting the remarkable strides our Government has made. The unwavering commitment to inclusive growth has been emphasised through this Address, and I am heartened by the significant progress we have made towards becoming a ?Viksit Bharat?.

In 2014, when this Government under the leadership of hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji came to power, the country was facing enormous challenges. With ?Sabka Saath, Sabka Vikas? as its mantra, the Government overcame those challenges. Structural reforms were undertaken; pro-people programmes were formulated and implemented and conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. It is through these initiatives that we have witnessed India?s remarkable transformation from being one of the ?Fragile Five? to one of the ?Top Five? economies globally.

Today, India is at a turning point contributing 15 per cent to global growth with the fastest growth rate among the major economies. Our Government is committed to making India the third largest economy in the world, bringing us closer to becoming a developed nation.

Farmers play an invaluable role in driving our economy forward. The strength and vitality of our nation?s farmers, also referred to as *annadatas*, are closely linked to the overall empowerment and prosperity of India. Through the PM-Kisan Samman Nidhi, over 3.2 lakh crore rupees have been disbursed to farmers to help them for their cover small expenses. Moreover, the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is now the largest crop insurance scheme in the world by way farmer enrolments and the third largest by way of insurance premiums.

To further empower rural communities, a vast network of Farmer Producer Organisations (FPOs) and Primary Agricultural Credit Societies (PACS) have been created. Recognising the storage challenges faced by small farmers, the Government has also initiated a scheme to create the world?s largest storage capacity in the cooperative sector. In the effort to boost exports, the first-ever Agricultural Export Policy was implemented leading to 24 lakh crore rupees in agricultural exports.

Soil health cards which provide farmers with the nutrient status and composition of their soil, have been distributed to 23.58 crore farmers as of December 2023. These initiatives reflect the Government's commitment to strengthening the agricultural

sector and ensuring that farmers across India experience a new-found sense of economic security and stability.

With rural connectivity being paramount, 3.80 lakh kilometres of new roads under the PM Gram Sadak Yojana have been constructed. Today, our country boasts of a growing network of National Highways and Expressways and the rate of National Highway construction has more than doubled.

In rail modernisation, 25,000 kilometres of new tracks have been laid with 100 per cent electrification. Vande Bharat trains are operating on over 39 routes and 1,300 stations have been upgraded under the Amrit Bharat Station Scheme.

Additionally, significant strides have been made in air travel infrastructure. The UDAN scheme has doubled the number of airports from 74 to 149 improving air travel connectivity across the nation. India is now the world?s third largest domestic aviation market, with airline routes increasing from 209 in April, 2014 to 605 by April, 2024. This expansion has not only improved accessibility but it has also increased economic growth and development in smaller cities, creating new opportunities and enhancing the quality of life.

Similarly, the SagarMala Project has doubled the cargo handling capacity at major ports, enhancing maritime infrastructure. These infrastructural changes are driving India towards a prosperous and inclusive future, ensuring every citizen benefitting from the nation's progress.

In our journey towards a developed India, this Government has left no stone unturned. Since 2017, we have witnessed record-breaking GST collections, exceeding 22 lakh crore rupees in April 2024. The dream of Digital India is unfolding before our eyes, as we become one of the fastest-growing digital economies with a record number of UPI transactions. In addition to digital advancements, the Government has introduced impactful schemes to support the families. More than 1 crore families have registered under the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, which aims to reduce electricity bills to zero and by installing rooftop solar electricity systems. The Government is also providing soft loans to disadvantaged groups through the PM-SURAJ portal, creating new livelihood opportunities.

Moreover, for disabled people in India, the Govermment is developing affordable indigenous assistive devices and expanding PM Divyasha Kendras across the country. In the pursuit of equity in education, the Government has taken steps to

address unfair situations faced by students due to language barriers. With the implementation of new National Education Policy, students can take up engineering courses in Indian languages. Moreover, this Government has established seven new IITs, 16 IIITs, 7 IIMs, 15 new AIIMS, 315 medical colleges and 390 universities over the past decade. It is this Government's endeavour to further strengthen these institutions and ensure that quality education is accessible to all.

Women's economic empowerment has been a cornerstone of this Government?s agenda. The PM Awas Yojana has allotted the majority of four crore houses to women beneficiaries. Schemes like Lakhpati Didi, Namo Drone Didi and the Krishi Sakhi Programme further support this effort. Over 10 crore women are now part of Self-Help Groups. These transformative initiatives not only empower women economically but also position them as key contributors to the nation?s growth and prosperity.

Representing a constituency with a thriving MSME sector, I understand the vital role these enterprises play in our economy. The Government?s focus on supporting MSMEs and small entrepreneurs is evident through various initiatives. Over 3.5 crore MSMEs are now registered on the Udyam portal. The Government has also launched the MSME Trade Enablement and Marketing (TEAM) initiative. which helps small businesses participate in online trade through the Open Network for Digital Commerce (ONDC) platform. Additionally, the newly launched Yashaswini campaign will support informal women-led businesses by providing them with better access to capital and trade opportunities with large corporations, helping them become more formalised.

The world?s perception of India has significantly transformed, as shown by our G20 Presidency where the African Union's permanent membership was facilitated. India's pioneering spirit can be seen during the first flag hoisting on the Moon's southern pole and the successful Aditya Mission, which has ventured 15 lakh kilometres into space. Our human-centric approach has positioned us as a first responder in global crises. This proactive stance has established India as a strong voice for the Global South.

Furthermore, India?s leadership in traditional wellness practices has gained global recognition. The establishment of the International Day of Yoga and the promotion of traditional medicine by this Government shows our contributions to global health. It is a matter of pride that India is now home to WHO's Global Centre for Traditional Medicine whose headquarters is in my constituency at Jamnagar. These

achievements reflect India?s growing influence and leadership on the global stage, demonstrating our dedication to fostering international cooperation and well-being.

As we reflect on the remarkable progress our nation has made, I extend my heartfelt congratulations to the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji for his dedication and visionary leadership. His efforts have transformed India, increased economic growth, and established our country as a leader in the global arena. As we stand on the brink of a new era filled with opportunities and promise for every Indian, I urge all of you to support the Government's initiatives that aim to shape a brighter and more inclusive future.

At the end, I support the Motion of Thanks on the President's Address in its entirety.

SHRI VIJAY KUMAR HANSDAK (RAJMAHAL): I would like to put forward my views on the President?s speech on behalf of my party JMM.

Release of Shri Hemant Soren, ex-Chief Minister of Jharkhand from jail has shown the misuse of the Central agencies by the present BJP Government. Central Government and State Government should have relation like big and small brother but the present Government, in whichever State they are not in power, behave like big country and small country.

BJP lost in Ayodhya, Chitrakoot, Sitapur, Basti, Sultanpur, Prayagraj, Ramtek, Nasik, Kopal, and Rameshwaram. The people have given their decision on these seats and proved a vital point and the BJP if ever now do not stop misusing God?s name, then I can only say pride has grown even worse and will be broken in future. Constantly relations are weakening with neighbouring countries, which is a raising concern. Long pending demands of our State of Jharkhand are GST, mining, royalties, Sarna Code, DM Awas, railway demands and many more which I have been raising for the last ten years but yet have not been fulfilled. I have been saying about falling job opportunities, inflation for the last ten years but the NEET leak has proved that this Government is not serious about the youth of this country.

We are going to celebrate 75 years of Constitution of India. We talk about manufacturing services and agriculture but the falling food standards of India has

seen many increases in medical cases. I find this Government has been only selling lies to the country and I oppose the President?s speech.

DR. C. N. MANJUNATH (BANGALORE RURAL): I would like to lay my maiden speech on the discussion on Motion of Thanks to Her Excellency the President of India for her Address to both the Houses of Parliament on 27th June 2024. I wholeheartedly support the Motion moved by Shri Anurag Singh Thakur ji and seconded by Kumari Bansuri Swaraj.

At the outset, I would like to thank my Party leaders, my people of Bangalore Rural Lok Sabha Constituency, my well-wishers and my mentors for their support and blessings so that I could become a Member of this august House, the Parliament of India for the first time.

In the last decade (2014-2024), the country has seen how our NDA Government under the leadership of hon. Prime Minister worked day and night to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our Government strengthened its 'mantra' to 'Sabka Saath, Sabka Vikas, and Sabka Vishwas'.

In India, our strength lies in our diversity, our vastness and our vibrancy. We have people of every religion here. Hundreds of types of food, hundreds of ways of living are our identity. Hundreds of languages and dialects are spoken in our country. We have hundreds of problems being faced by our people in their day-to-day life.

Despite global economic challenges, India's GDP is projected to surpass 7.2 per cent in 2024 marking the third consecutive year of over 7 per cent growth. FDI inflows are increasing at an annual rate of 5.9 per cent to 6 per cent. Our Prime Minister, with all his administrative machinery, is working to make India a 'Vikasit Bharat' by 2047. The Vikasit Bharat covers all sections of the people at all levels. For achieving that goal, there is a need to improve people's capability and empower them. It can be made a reality with our dynamic Prime Minister, Shri Narendra Modi ji.

He has set many examples before us by taking the historic decision for implementation of GST, abrogation of Article 370 related to Jammu & Kashmir, Amendment to Citizenship Act, etc. Nari Shakti Vandan Adhiniyam was brought by Shri Narendra Modi ji, which is one of the best examples for how he works for the overall progress of the country.

India is becoming stronger and stronger under the leadership of Shri Narendra Modi ji. It is only because he is committed to take a strong decision for the country. The concept of 'One country, One tax, One market' has become a reality because of our Prime Minister who not only advocates for "Nation first" idea, but also follows it in letter and spirit.

Nearly, 13 per cent deaths in India is caused due to road accidents. Most of them suffer from multiple injuries. Hence, there is a need to establish Polytrauma Centre, NIMHANS, Bangalore. The proposal is pending for many years. I would like to draw the attention of the Health Ministry to accord approval for this 300-bedded Polytrauma Centre to treat patients during the ?Golden Hour?.

Since 2014, the Modi ji Government has overcome a number of challenges in the right earnest by introducing structural reforms. Pro-people programmes were formulated and implemented promptly. Better conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigour. The fruits of development started reaching the people at all levels. The country got a new sense of purpose and hope.

The National Education Policy, 2020 is ushering in transformational reforms. PM Schools for Rising India (PM SHRI) are delivering quality teaching, and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India Mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of new institutions of higher learning, namely seven IITs, 16 IIITs, seven IIMs, 15 AIIMS and 390 universities have been set up. PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans aggregating to Rs. 22.5 lakh crore for entrepreneurial aspirations of our youth.

Development programmes, in the last ten years have targeted each and every household and individual through 'housing for all', 'har ghar jal', electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Minimum Support Price for the produce of 'Annadata' is periodically increased appropriately.

On environmental protection, the hon. Prime Minister of India, Shri Narendra Modi had presented the idea of Lifestyle for Environment (LiFE) to the world. Mission LiFE is a comprehensive approach to environmental protection that inspires every person to adopt behaviours that promote the culture of reduce, reuse and recycle

in their life. That is why, today, we need to adopt such a lifestyle and approach which is not harmful for our environment. This is the individual and collective responsibility of all of us. LiFE Mission has given us a new way to deal with contemporary challenges like climate change, sustainable development, health security, food security and energy security. Today, this idea has become a global movement.

There are certain issues like climate change, lifestyle change, behavioural change and social change that cannot be addressed by making policies and laws alone. Rather, we all need to contribute collectively by incorporating changes in our daily routine. I am confident that we will be successful in achieving the goal of building a better India by incorporating the values and messages passed on to us from the rich Parliamentary democracy of our country.

With this hope, I once again thank the hon. Speaker for allowing me to lay my maiden speech. I support the Motion.

SHRI KOTA SRINIVASA POOJARY (UDUPI CHIKMAGALUR): I would like to express my views on the Motion of Thanks to the President's Address.

The Address delivered by the President is not only our parliamentary procedure and culture but also a manifestation of the spirit and expectations of the common man, women force, farmers, labourers and different sections of our society. Moreover, it has also reflected the Government's objectives of comprehensive development of each and every section of the society living in every nook and corner of the country. Her Excellency the President has listed the achievements of the Government in the last 10 years.

We did not just become the fifth largest economy in the world from being the 11th largest, leaving behind U.K, but we also became the fourth largest stock exchange and third largest automobile manufacturer in the world. Today India's domestic Civil Aviation sector has become number three in the world. We are number two country that manufactures mobile handsets. We are the first in the world to touch the untouched corners of the Moon and the South Pole. As mentioned by Madam President, our scientists played a big role in it. President Madam has mentioned in point five - Reform, Perform and Transform. Our Government had done this after coming to power: Started giving LED bulbs, 37 crore LED bulbs distributed till now, more than the total population of America.

Under the leadership of our Prime Minister, regarding power, the target was set that by 2030, India's installed capacity of power, 40 percent of generation will be from clean energy/renewable energy. I want to tell that for the first time in the history of India that 40 percent target of installed capacity by clean energy was achieved 8 years earlier, i.e. in 2022. We have become the third largest country in terms of solar energy. In the context of solar energy, in the year 2014, solar energy was 2.6 GW; whereas in the year 2023, it is 66.7 GW, and not only this, now the Government has launched 'Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana'. People have installed rooftop solar connections. This helps bring the electricity bill of households to zero. Free health services are provided to 55 crore beneficiaries under Ayushman Bharat Yojana.

25,000 Jan Aushadhi Kendras are being opened at a fast pace. Seven new IlTs, Seven IIMs, 15 AIIMS, 16 IIITs, 315 Medical colleges, and 390 Universities have been established in the last decade. Students can now study engineering in Indian languages. PM JANMAN has been allocated more than Rs. 24,000 crore. It focuses on the development of backward tribal communities.

To enable livelihood opportunities, soft loans are being provided to disadvantaged groups through the PM SURAJ Portal. Majority of the four crore houses built under the PM Awas Yojana have been allotted to women beneficiaries. Over the last decade, 10 crore women have been mobilised into Self Help Groups.

The Government has started a campaign to make three crore women Lakpati Didis. To achieve this, financial assistance to SHGs is being increased. People will drive electric scooter or electric car, and charging of their vehicles will also be free. There is no impact on the environment. Free energy is available and that too without putting any burden on the Government exchequer.

Madam President mentioned that we are the world leader in Startups. We have become the third largest eco-system. We have become the third largest civil aviation sector in terms of domestic flights. Madam President mentioned that in the year 2014, 209 airline routes were there, but now there are 905 airline routes. This has directly benefitted Tier-2 and Tier-3 cities. Now, almost every State has an airport.

The pace of construction of National Highways has more than doubled. In 10 years, more than 3.58 lakh Kms of village roads have been constructed under the PM Gram Sadak Yojana.

PM SVANidhi will be expanded to include street vendors in rural and semi-urban areas. Construction of three crore houses has been approved under PM Awas Yojana.

See what kind of change has taken place that today the highest world class bridge was completed over the Chenab River, Reasi district of J&K. Asia's longest bridge over the sea was completed in Mumbai during the time of our Government. The biggest bridge has been built in Gujarat during the time of our Government and the metro running under the river was launched recently in Kolkata.

Honey is commonly used in Indian households. Honey exports were worth Rs. 445 crore in 2014 and in 10 years, it has increased to Rs. 1,623 crore. In the last 10 years, we have exported toys worth Rs. 1,844 crore.

The Khadi market which was worth Rs. 31,000 crore in 2014, now it has increased to Rs. 1 lakh 35 thousand crore, which means we have increased the investment in Khadi by four times.

Madam President has mentioned about two defense corridors built in Uttar Pradesh and Tamil Nadu. They have developed India's first Intermediate-Range Ballistic Missile, which we have started exporting.

Only a year and a half ago, there was a lot of controversy that SBI is sinking, LIC is sinking, and public sector banks are going down. Madam President said that this year public sector banks have disbursed Rs. 1,40,000 crore, and earned a profit of Rs. 1,000, which had never happened till date. Non-performing assets of these banks have reduced.

I also wish to inform that HAL has earned revenue of Rs. 29 thousand crores and orders worth Rs. 80 thousand crores. This indicates that SBI, LIC and HAL have achieved the highest position during the tenure of our Government.

The Government started PM Garib Kalyan Anna Yojana to provide free ration to 80 crore persons. Benefits under this Scheme are also being extended to families that have come out of poverty, to prevent them from slipping back into poverty. More than Rs. 3.2 lakh crore has been disbursed to farmers under the PM-KISAN Samman Nidhi. The Government has effected a record increase in MSP for Kharif crops.

In the last point, Madam President said that in 2047, India will be developed. Nation has to be built and for the developed nation, she explained how our

Government is moving forward. The digital revolution that has come after Modi ji's arrival, is a major influence on the things happening in the world today. Forty-six percent of digital transactions take place in India, which is the fourth largest in the world after USA.

I welcome and support the Address delivered by the hon. President. With these words, I once again thank Her Excellency, the President for addressing and enlightening the country through Joint Session of Parliament.

Thank you.

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर) **:** मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने विचार रखता हूं । मुझसे पूर्व बहुत सारे विद्वान नेता अभिभाषण पर अपने विचार रख चुके हैं और मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूँगा ।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा गया है कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर तीनों पर ध्यान दे रही है । यह कहना सत्य प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे किसान अनेकों मुसीबतों से अभी भी जूझ रहे हैं और सरकार उन्हें कोई सहायता नहीं दे रही है । महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने कहा है कि उनकी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत अधिक काम कर रही है, लेकिन हम छोटी जगह से आने वाले लोग यह महसूस करते हैं कि सड़कों का निर्माण गाँवों तक नहीं पहुँचा है ।

इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में रेलवे की एक बड़ी समस्या है । वर्तमान सरकार हाई स्पीड रेल और बुलेट ट्रेन पर बहुत अधिक ध्यान दे रही है, जिसमें भारी निवेश होगा, लेकिन उसका उपयोग सिर्फ समाज के संपन्न लोग ही कर पाएंगे । मेरा यह मानना है कि सरकार को हाई स्पीड ट्रेन और बुलेट रेल की बजाय मौजूदा रेल नेटवर्क को और अधिक सुगम और सुरक्षित बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि देश में रेल से संबंधित घटनाओं पर रोक लग सके और साधारण लोगों को जरूरत के अनुसार रेल में टिकट मिल जाए ।

राष्ट्रपति महोदया ने कहा है कि देश में पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि सरकार गरीबी दूर करने का लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह नारा पिछले 70 वर्षों से चल रहा है, पर गरीबी अभी भी दूर नहीं हुई है । सरकारी आंकड़ों से यह पता चलता है कि पिछले 10 वर्षों में देश में अमीर लोग ज्यादा अमीर हो गए हैं और गरीब लोग अधिक गरीब हो गए हैं । गरीब और अमीर के बीच की खाई बड़ी होती जा रही है । सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि सरकार जन औषधि केन्द्र खोलकर दवाइयाँ कम कीमत पर मुहैया करा रही है, लेकिन चिकित्सकों का मानना है कि जन औषधि की दवाइयाँ अपेक्षित कार्य को पूरा नहीं कर पा रही हैं और दवाइयों की खुराक को 4 से 5 गुना तक बढ़ाना पड़ता है, ताकि वह रोगी पर असर कर सके । इसलिए जन औषधि केन्द्र खोलने के साथ-साथ सरकार को दवाइयों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि मरीज उचित दवा खाकर स्वस्थ हो जाए ।

सरकार की मंशा जन सरोकार पर संवेदनशील नहीं है । सरकार ने बढ़ती बेरोजगारी से बर्बाद हो रहे नौजवानों के भविष्य पर कोई ठोस उपाय नहीं किया है । महँगाई का ?म? बोलने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है । सरकार इस महँगाई के समय में 1,20,000 (एक लाख बीस हजार रुपये) का आवास बनाती है, यह गरीबों को आवास देना नहीं, बल्कि उनका मजाक बनाना है । 400 पार का नारा देने वाली सरकार आज तक मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी रुपये 400 प्रतिदिन नहीं कर पाई है । मिड डे मील के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में खाना बनाने वाले रसोईया, आशा बहू, रोजगार सेवक, चौकीदार, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका की मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन नहीं हुई है । इस पर भी सरकार मौन है और गरीबों पर बार-बार गरीब मजदूर के कल्याण का झूठा भाषण करती है । अभिभाषण में इनके लिए कोई ठोस उपाय नहीं है ।

देश का कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए आंदोलित है, लेकिन सरकार कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है । किसान कर्ज से परेशान है, सरकार किसान का कर्ज माफ नहीं कर रही है । शिक्षा महँगी कर छात्रों के भविष्य के प्रति सरकार गंभीर नहीं है । बाढ़ और दैवीय आपदा से आहत परिवारों के लिए ठोस उपाय नहीं है । कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार बिल्कुल निरंकुश हो गई है ।

कोरी घोषणाओं और लोक लुभावने नारों के बल पर सरकार जन सरकारों पर बहस नहीं करती है । अग्निवीर योजना से नौजवान निराश हुआ है । आउटसोर्सिंग नौकरी में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण खत्म किया जा रहा है ।

महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में कहा है कि सरकार युवाओं के लिए बहुत काम कर रही है और उनकी भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए बहुत तरह की प्रोत्साहन योजनाएं चला रही है, लेकिन जब आप सच्चाई को देखते हैं तो यह पाएंगे कि पिछले 10 वर्षों में देश में बेरोजगारी बढ़ी है, करोड़ों युवा रोजगार की तलाश में आज भी बड़े-बड़े शहरों में भटक रहे हैं । बीटेक, एमटेक, एलएलबी जैसी उच्च स्तरीय डिग्री लेकर युवा मात्र दस हजार रुपये की नौकरी के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं । मेरा मानना है कि सिर्फ योजनाएं चलाने से कुछ नहीं होगा । यह देखना होगा कि योजनाएं कितनी अपने उद्देश्य में कारगर हैं । इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि एक ओर इतनी बरोजगारी है, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार के 40 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं और इन्हें भरने के लिए सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है । सिर्फ प्रधानमंत्री जी यह दिखाते हैं कि मैं एक लाख लोगों को ऑनलाइन नौकरी दे रहा हूँ, लेकिन पिछले 10 वर्षों में इनकी नौकरी देने की संख्या रिटायर होने वाले लोगों से बहुत ही कम हो गयी है । यही कारण है कि आज हर विभाग में, हर मंत्रालय में पदों की रिक्तियाँ बनी हुई है । मैं एक और महत्वपूर्ण विषय नए आपराधिक कानूनों के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि एक जुलाई से लागू हो गए हैं । पता नहीं सरकार ने किन कारणों से आनन-फानन में इन्हें संसद में पास करवाया और उन्हें कार्यान्वित कर दिया है । बड़े-बड़े कानून के जानकार एवं विश्लेषकों ने इनमें कई सुधार के सुझाव दिए पर सरकार ने इन पर विचार किए बिना ही इन्हें लागू कर दिया । संसदीय समिति में विचाराधीन इन कानूनों पर भी कई सदस्यों ने अपनी असहमति व्यक्त की पर सरकार ने सबकी अनदेखी करके उन्हें पारित करा दिया । मैं सरकार के उत्तर पूर्व क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के संदर्भ में यह कहना चाहता हूँ कि सरकार उत्तर पूर्व में राज्य सरकारों को बदलने के लिए सभी प्रयास कर रही है । सरकार का सही मायने में क्षेत्र के विकास से कोई लेना देना नहीं है । मणिपुर में कई महीनों तक होने वाली हिंसा और केंद्र सरकार का मूकदर्शक बने रहना इसका उदाहरण है ।

धन्यवाद ।

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख) **:** मैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा गुरुवार को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में दिए गए अभिभाषण का हृदय से समर्थन और उनके द्वारा नव-निर्वाचित सांसदों को दी गई बधाई पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं । यह देशवासियों के लिए गौरव की बात है कि छह दशकों के बाद देश में पूर्ण बहुमत वाली एक स्थिर सरकार बनी है । देश के नागरिकों ने लगातार तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी पर भरोसा दिखाया है । चूंकि, उन्हें मालूम है कि केवल श्री नरेन्द्र मोदी जी की केन्द्रीय सरकार ही उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है । इस लोक सभा का गठन अमृत काल के शुरुआती वर्षों में हुआ । इसलिए, 18 वीं लोक सभा कई मायनों में ऐतिहासिक है । भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रुप में जाना जाता है, जिस पर सदियों तक विभिन्न राजाओं, सम्राटों तथा यूरोपीय साम्राज्यवादियों द्वारा शासन किया गया । भारत 1947 में अपनी आजादी के बाद एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया था । उसके बाद भारत के नागरिकों को वोट देने और अपने नेताओं का चुनाव करने का अधिकार मिला । भारत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनियां का सातवां सबसे बड़ा देश और आबादी के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है, इन्हीं कारणों से भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रुप में भी जाना जाता है । 1947 में देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था । हमारे देश में केंद्र और राज्य सरकार का चुनाव करने के लिए हर 5 साल में संसदीय और राज्य विधान सभा चुनाव आयोजित किए जाते हैं ।

देश की 18 वीं लोक सभा का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था । करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है । इस चुनाव में सुखद तस्वीर विशेषतः जम्मू-कश्मीर से भी आई है, जहां कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे । पिछले चार दशक में बंद और हड़ताल को देखा गया, जिसकी वजह से काफी कम मतदान हुआ ।

यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने 18 वीं लोक सभा के लिए चुनाव को बहुत ही कुशलतापूर्वक सम्पन्न कराया है जम्मू-कश्मीर में इस बार घाटी में दशकों का रिकॉर्ड टूटा है तथा काफी संख्या में लोगों ने वहां मतदान किया । राष्ट्रपति महोदया ने भी इसके लिए आयोग की प्रशंसा की है, जो स्वागत योग्य है ।

ऋषितुल्य श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के चहुमुखी विकास के लिए कृतसंकल्प है । उनके द्वारा देश की अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफोर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है । 10 साल में 11 वीं अर्थव्यवस्था से पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है । भारत ने साल 2021 से लेकर साल 2024 बीच औसतन 8 फीसदी की रफ्तार से विकास किया है ।

केन्द्र सरकार मैन्युफेक्चरिंग, सर्विस और एग्रिकल्चर को भी बराबर महत्व दे रही है । पीएलआई स्कीम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं । देश के किसान अपने छोटे खर्चे पूरे कर सकें, इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें 3 लाख 20 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी जा चुकी है । सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी पर रिकॉर्ड वृद्धि की है ।

पारंपरिक सेक्टर के साथ-साथ सनराइज सेक्टर को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है । इसका उल्लेख भी राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में किया है, जो स्वागत योग्य है ।

देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा किसानों पर विशेष फोकस देकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है । केन्द्र सरकार कई ऐसी योजनाएं लेकर आई जो उनके लिए काफी लाभकारी साबित हो रही हैं ।

केन्द्र सरकार कृषि उत्पादों के भंडारण की दिशा में भी काम कर रही है । कृषि उपजों के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) बढ़ाया गया है । दुनिया भर में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ रही है । देश के किसान इस मांग को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम हैं । किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी तेजी से कार्य किया जा रहा है तथा उनको 20 हजार करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं ।

राष्ट्रपति महोदया का यह कथन सही है कि विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब देश के गरीब, युवा, महिलाएं और किसान सशक्त होंगे । इसलिए सरकार द्वारा उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है । सरकार का लक्ष्य उन्हें हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना है तथा इस इच्छा शक्ति के साथ काम किया जा रहा है कि एक भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने कुशल कार्यकाल के दौरान 10 लाख गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है । यह सच्चाई है कि उनके कार्यकाल में पिछले एक दशक में गरीबों का जितना उत्थान हुआ है, उतना आजादी के बाद इससे पहले कभी नहीं हुआ है ।

श्रद्धेय श्री नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण के नए दौर की भी शुरुआत हुई है । 24 हजार करोड़ रुपए से अधिक की पीएम-जनमन जैसी योजना आज अति पिछड़े जनजातीय समूहों के उत्थान का माध्यम बन रही है । आने वाला समय ग्रीन एरा यानि हरित युग का है । सरकार इसके लिए भी हर जरूरी कदम उठा रही है और हरित उद्योगों पर निवेश बढ़ाये जा रहे हैं, जिससे ग्रीन जॉब भी बढ़े हैं ।

केन्द्र सरकार द्वारा दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए स्वदेशी सहायक उपकरण बनाये जा रहे हैं । वंचितों की सेवा का ये संकल्प ही सच्चा सामाजिक न्याय है । आज केन्द्र सरकार की योजनाओं में देश के गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसानों को अहम महत्व दिया जा रहा है । देश तभी विकास कर सकता है । इसलिए सरकार की योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता इन्ही चार स्तंभों को दी जा रही है । ताकि इनको हर सरकारी योजनाओं का लाभ सरलता से मिल सके ।

आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के विगत 10 वर्षों के कार्यकाल में बैंकिंग सेक्टर भी पिछली सरकारों की तुलना में काफी मजबूत हुआ है । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का लाभ 2023-2024 में 1.4 लाख करोड़ को पार कर गया । यह पिछले वर्ष की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है । बैंकों की मजबूती उन्हें ऋण आधार का विस्तार करने और राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए सक्षम बनाती है । केन्द्र सरकार ने युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भागीदारी और बढ़ाने के लिए मेरा युवा भारत - MY Bharat अभियान की शुरुआत भी की है । Atal Tinkering Labs, Start-up India और Stand-up India जैसे अभियान देश के युवाओं का सामर्थ्य बढ़ा रहे हैं । इस प्रकार से युवाओं को भी स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में विगत दस वर्षों में देश में 10 नए आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 15 नए एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, जो एक कीर्तिमान है । यह हम सभी के लिए प्रसन्नता की बात है कि देश का पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुनिया में बेहतरीन हो इस मानदंड पर कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है । इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इस दिशा में बदलते भारत की योजना को दिखा रही है । गांव में 3 लाख 80 हजार किलोमीटर से ज्यादा सड़क बनाई गई है । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में आज भारत में नेशनल हाइवे का जाल बिछ रहा है । नेशनल हाइवे बनाने की गति में

दोगुना वृद्धि हुई है तथा बुलेट ट्रेन के लिए पूर्वी, उत्तर भारत में फिजिबलिटी स्टडी शुरू की जा चुकी है । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने पहली बार गरीबों को ये अहसास कराया कि सरकार उनकी सेवा में है । पिछले 10 वर्षों में राष्ट्र की उपलब्धियों और विकास का आधार गरीब का सशक्तिकरण रहा है । कोरोना के कठिन समय में सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए पीएम गरीब कल्याण योजना शुरू की । आज केन्द्र सरकार 55 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ उपलब्ध करा रही है । देश में 25 हजार जन औषधि केंद्रों को खोलने का काम भी जल्दी से चल रहा है । अब आयुष्मान भारत योजना की तहत मुफ्त इलाज का लाभ 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी मिलेगा ।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी पूर्वोत्तर राज्यों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं तथा नॉर्थ-ईस्ट के आवंटन में 10 गुना की वृद्धि की है । सरकार द्वारा उत्तर-पूर्व में हर क्षेत्र में विकास कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है । असम में 27 हजार करोड़ रुपये की लागत से सेमी कंडक्टर प्लांट बनाया जा रहा है तथा नॉर्थ-ईस्ट में स्थायी शांति के लिए निरंतर काम किया जा रहा है । पिछले 10 साल में अनेक पुराने विवादों को हल किया गया है । नॉर्थ ईस्ट में अशांत क्षेत्र में तेज विकास कर चरणबद्ध तरीके से अफस्पा हटाने का काम भी जारी है । इस तरह से देश के हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम बन रहे हैं । मैं राष्ट्रपति महोदया के इस कथन का पूरजोर समर्थन करता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था । उस समय पूरे देश में हाहाकार मच गया था क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही हैं । इसलिए, ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया ।

राष्ट्रपति महोदया का यह कथन भी सही है कि जब संविधान बनाया जा रहा था तब भी दुनिया में ऐसी ताकतें थीं जो भारत के असफल होने की कामना कर रही थीं । देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए, जिनमें वर्ष 1975 में देश में लगाया गया आपातकाल घोर निंदनीय और हमारे पवित्र संविधान के अनुरूप नहीं है । मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति महोदया ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के पिछले 10 साल की उपलब्धियों का जिक्र अपने अभिभाषण में किया है । उनके अभिभाषण में केन्द्र सरकार के विगत 10 वर्षों के कार्यकलाप की झलक स्पष्ट मिलती है तथा यह परिलक्षित होता है कि केन्द्र सरकार "सबका साथ - सबका विकास" के अपने वायदे के अनुरूप देश को तेजी से आर्थिक विकास की नई राह पर ले जा रही है और देश के सभी गरीब, दलित, शोषित, वंचित, किसान, श्रमिक और युवा सरकार के इस समावेशी आर्थिक विकास के केन्द्र में है । अंत में, मैं पुनः महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण का हृदय से समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

DR. K. SUDHAKAR (CHIKKBALLAPUR): I would like to express my views on the Motion of Thanks to Hon'ble President's address and like to refer to an editorial ? ? India: Another Tryst with Destiny,? which was published in the UK?s The Guardian newspaper. On 18th May 2014, John Crace wrote ?Today, 18 May 2014, may well go down in history as the day when Britain finally left India. Narendra Modis victory in the elections marks the end of a long era in which the structures of power did not differ greatly from those through which Britain ruled the subcontinent. India under the Congress party was in many ways continuation of the British Raj by other

means.? Well, the editorial is a profound piece of truth and one that has stood the test of time.

After 10 years one can safely say Bharat has been undergoing a complete decolonization of sorts on various parameters and is still an ongoing process cleaning up the colonial mindset. Mindset is a framework, a set template of rigid notions and a big and diverse country like ours cannot be governed by archaic western constructs.

A nation marred by monumental scams was cynical and yet hopeful of a new dawn when Shri Narendra Modi was announced as the Prime Ministerial candidate on 13th September 2013. Real Leaders always rise and make places powerful around them by making structural changes filled with conviction and transform lives.

Starting June 2014 India that is Bharat under Shri Narendra Modi had undertaken rapid reforms on a wide spectrum of governance areas which have a common thread tied to one another ?Atmanirbharta (meaning self-reliance). The farsighted financial inclusion program Jan Dhan Accounts (using Jan Dhan bank accounts, Aadhaar, and Mobile) ? banking for the unbanked was the first mega initiative by the Modi Government. It looked trivial for many, but it was a mega step towards initiating savings and corruption free delivery to the masses. Many economists failed to see the huge impact Jan Dhan could bring about ? as we write this piece 51.42 Crore (514 million) beneficiaries banked so far with Rs 213,798.10 Crore (25 billion USD) balance in beneficiary accounts. The Mudra loan scheme too has been a great game changer providing loans up to Rs 10 lakh (1 million) to the non-corporate, non-farm small/micro enterprises. The ?Swachh Bharat Abhiyan? has led to significant progress in improving sanitation and hygiene across the country. Millions of toilets have been built, reducing open defecation, and improving public health. A staggering 409 million toilets were built in rural India since the launch of Swachh Bharat in October 2014. The programme led to the construction of over 40 crore individual household toilets, taking sanitation coverage from 39% in 2014 to 100% in 2019 when around 6 lakh villages declared themselves Open Defecation Free (ODF). While studies indicate that the SBM-G campaign led to significant economic, environmental and health impacts, contributing to the empowerment of women, it also led to the achievement of SDG 6.2 (Sanitation and Hygiene), 11 years ahead of the stipulated timeline. This should be global case study on how to implement mass programs for social welfare.

Digital India was aimed at democratising internet, 4G rollout was being done at a scorching pace with per GB data in India costing just Rs 13 (0.16 USD) ? one of the cheapest in the world, governance delivery took a new leap. The most impending Tax reform ? Goods & Services tax was courageously brought forward and implemented on 1?st July 2017 and ensured One Nation One Tax and ease of moment of goods with minimum delays and processes leading to improved ease of business.

Foreign policy too stood out with Prime Minister connecting with ease with Indian diaspora in every country he would visit in his first term, it was logical for world Governments to forge a friendly relationship with India under Narendra Modi. So many successful missions over the past years ? Operation Ganga, Operation Dev Shakti, Operation Raahat, Operation Maitri and notably Vande Bharat Mission in which India brought back 6.76 million stranded passengers with the help of special international flights. This was apparently India?s biggest evacuation mission since 1990, when it rescued 170,000 civilians from Kuwait during the Gulf War. India?s G20 Presidency witnessed the largest ever in-person participation with over 100,000 participants, from 135 nationalities attended our G20. Organised under the theme ?One Earth, One Family, One Future,? drawing upon our age-old belief of ? Vasudhaiva Kutumbakam? India?s Presidency was the most inclusive of sorts representing 85% of global GDP, 75% of world trade and 2/3rd of world population, it witnessed the highest profile international gathering in the history of independent India.

Infrastructure push has been stellar with massive investments in building roads, railways, ports, and airports. The ?Smart Cities? initiative aims to create modern urban centres that offer a high quality of life for citizens. Highway construction is happening at a scorching pace of around 40Km/ day as compared to around 3 Km/ day in earlier regimes. Railways has been greatly transformed with 41 semi-high-speed Vande Bharat trains being introduced, not only reducing travel time between cities but also offering passengers greater comfort and experience Bharat?s diverse countryside through expansive glass windows.

Adversity brings the best out of a great leader?as the world was grappling in hopelessness, India under the able leadership of Prime Minister Modi stood out as a ray of hope ? with the Digital connect and Jan Dhan Accounts, the fund transfers were eased up ensuring last mile delivery. During the COVID-19 pandemic, Modis leadership was evident in the swift implementation of measures to protect public

health. Initiatives like ?Aatmanirbhar Bharat? supported the economy during these challenging times. Vaccine rollout through Co-Win ? a real-time digital framework for vaccine delivery has been applauded and implemented by many countries across the world. The live vaccination data in the country would have crossed 2,20,67,56,592 doses ? a staggering achievement considering how once black marketing and hoarding featured governance delivery.

Prime Minister Narendra Modi understands Bharat like no other leader in recent memory has, from celebrating every Diwali with our armed forces in the border to renovation of age-old temples like Kashi Vishwanath temple with the grand Kashi corridor, Somnath, Kedarnath, Ujjain, Chardham project, Ayodhya. PM Modi has celebrated what the common man of Bharat has held close to his heart always. National Education Policy in 2020 was a much-needed reform in the school education sector preparing young India for jobs of tomorrow. The National Education Policy aims at an education, system rooted in Indian ethos that contributes directly to transforming India, that is Bharat, sustainably into an equitable and vibrant knowledge society, by providing high quality education to all children. Learning in mother tongue and emphasis on holistic education have made the policy a truly transformative vision in action for New India.

National security too has been a top priority ? one can safely say that since Modi has assumed the Prime Minister's office there has not been a single terror attack on any civilian in the country. From revoking article 370 to the Citizenship Amendment Act the thread remains India First policy**.** From International Day of Yoga to the successful Chandrayaan 3 landing and solar mission, India has shown it has all the right ingredients of the making of a super power, have highlighted some of the key measures, schemes, governance methods, but few may ask what does it translate for the nation ? the common man? The NITI Aayog discussion paper has many answers and will leave many spell-bound for what an efficient Government is capable off. As many as 24.82 (248.2 million) crore people moved out of multi dimensional poverty in nine years to 2022-23, with Uttar Pradesh, Bihar and Madhya Pradesh registering the largest decline according to the NITI discussion paper, multi dimensional poverty in India declined from 29.17 per cent in 2013-14 to 11.28 per cent in 2022-23, showing a reduction of 17.89 percentage points, with about 24.82 crore people moving out of the bracket during this period. In Artha Sastra Kautilya has clearly specified the rules for an Ideal King or ruler. Such ideal kings were called Raja Rishis meaning Sage like King. On 28th May 2023, Prime Minister installed the Sengol or the Raja Dhanda in the new Parliament?a reminder

to the ruler that Dharma needs to be upheld on all accounts. This is when we start to understand PM Modi as a whole, a towering world leader, leading as a socio ? economic reformer to a cultural ambassador of Bharat, to a whole new dimension of a Dharmic Leader ? a true Raja Rishi. Prime Minister Narendra Modi is indeed the ideal Philosopher King or Raja Rishi.

As the nation of 140 crore (1.4 billion) celebrated the Prana Pratishta (grand opening) of the Ram temple in Ayodhya on 22nd January 2024, we are but compelled to draw an analogy to the emotion and jubilation that is perhaps closest to the moment when Lord Rama returned to Ayodhya after Vanavaas. Prime Minister Modi?s speech during the Prana Pratishta ??Ram is not a fire, Ram is energy. Ram is not a dispute; Ram is the solution. Ram is not only ours, Ram is for everyone. Ram is not just the present, Ram is eternal?, needs to be internalized for it encompasses Bharatiya ethos and true inclusivity.

This is India?s Moment. Thanks to the phenomenal work by Prime Minister on policy making, structural economic reforms, development for all and all of this has happened in less than 10 years of Prime Minister Narendra Modi. One can only be awe inspired by the modern Raja Rishi Shri Narendra Damodardas Modi.

I would like to conclude by mentioning the change that every common man has witnessed in the last decade. Ten years ago, when PM Modiji embarked on the mission to transform our great nation, India's challenges were monumental - our economy was in the doldrums, the nation was among the fragile five, pessimism and despair was all-pervasive, and corruption was rampant. There were serious doubts in the minds of many about India's ability to fulfil the dreams and aspirations of her citizens.

But, if challenges were enormous, so was PM Modiji?s resolve to build a stronger, safer and prosperous nation. Powered and inspired by the strengths and skills of 140 crore Indians, PM Modiji did convert obstacles into opportunities, decay into development and pessimism into positivity. One can clearly see how development has become a mass movement. Numerous people friendly decisions have led to the empowerment of 140 crore Indians and the safeguarding of our strategic interests. Today, India stands tall at the international level. The world recognizes India's immense potential, which is clearly reflected in a record rise in foreign investment. India's stand on subjects like terrorism, climate change and prevention of money laundering are setting the global narrative. Our nation has witnessed both the

challenges of the yesteryears and the indomitable efforts made by your Government to overcome those challenges over the last decade.

This historic mandate is a testimony to the unwavering trust and confidence that people of India have on PM Modiji?s leadership. In 2047, our nation would complete a hundred years of independence. The dream of 'Viksit Bharat? has resonated across the length and breadth of India. That is why, the support BJP and NDA have received has been historic and unprecedented as New India has broken from the shackles of the past. Thanks to PM Modiji?s inspiring leadership, today, we are a nation that is daring to dream and dreaming to dare. There is an air of hope and a spirit of aspiration among the youth.

I am confident that under PM Modiji?s leadership the NDA Government will strive to build a strong and inclusive India, whose citizens are assured of dignity, prosperity, security and opportunity. Thank You, Jai Hind, Jai Karnataka.

SHRI NAVASKANI K. (RAMANATHAPURAM): I would like to express my views on the Motion of Thanks on the President's Address.

The Hon'ble President addressed the First Session of the Eighteenth Lok Sabha. She mentioned many achievements and prides of this Government. But it is disappointing that in that speech there is nothing about the challenges the country is facing today, about the future of the country with vision, about the problems faced by the people in different parts of the country, about the poor, minorities, dalits and other oppressed people. The reality is that the Bharatiya Janata Party, which has been in power for ten years, has not made any achievements to speak of.

This Government is not ready to discuss the NEET exam today. The malpractices in the NEET exam have shocked the country. We continue to demand that Tamil Nadu be exempted from NEET. In Tamil Nadu, the ruling party, the opposition party, all the parties except the Bharatiya Janata Party, and all the general public have been saying that we do not want the NEET exam for many years. But this Union Government is forcing something on us that we say we don't want.

The Government is making our students who are appearing for the NEET examination suffer/undergo mental stress in the name of examination. The Government has committed a great crime by asking the students to remove even

Thali "Mangal sutra', which is highly respected in Tamil Nadu. I would like to question why this Government, which claims to be taking various measures to prevent such malpractices, is now refusing to discuss the massive malpractice that may have taken place in the NEET examination. I would also like to raise the question whether the Government is afraid that any connection between the malpractice and the party will be revealed if we discuss it like that.

The Government suddenly postponed the post graduate NEET exam a day before without any prior notice. Doctors who have come with various preparations for that exam are faced with various difficulties. Tamil Nadu is constantly asking for the complete cancellation of this ambiguous NEET exam. The voice of Tamil Nadu has become the voice of India today. I request to cancel this illegal NEET exam completely.

This Government is keeping silence on the problem of Tamil Nadu fishermen. This Government created an image of caring for the welfare of fishermen only for the sake of fishermen's votes during elections. But after the elections, this Government has left the fishermen in a helpless state. We have been asking for a permanent solution to the Tamil Nadu Sri Lankan fishermen problem for years. In the last five years, I have spoken about this and raised questions many times in this House. But then no response was given. When the elections were approaching, all the Union Ministers came to our constituency and made various promises and took various measures for the liberation of the fishermen. But now 25 fishermen and four boats have been captured by the Sri Lankan Navy. Why the Government is not taking the immediate action as it took during the election, now? I would like to ask why this Government is now refusing to show the same concern that was shown during the election. Sri Lanka is a smaller country than us, dependent on us for business and other needs. Why is it that our country has not yet been able to reach a permanent solution to the Sri Lankan Tamil Nadu fishermen problem? I request this Government to take immediate action to protect our fishermen by negotiating with the Sri Lankan Government and to put an end to the problem of fishermen permanently.

Hon'ble Prime Minister has not yet visited Manipur which was on fire. Our Prime Minister goes to various countries and addresses all about world peace and world unity, But he refuses to open his mouth about Manipur, which has been burning in our country for more than a year. This Government only continues to show its hatred towards minorities. This Government has formed a cabinet without

Muslims. This Government has made the Ministry of Minority Welfare useless. This time the Muslims who went for Haj have faced various difficulties. Haj pilgrims are suffering without proper coordination and proper guidance.

A key reason for this is the apathetic attitude of the Ministry of Minority Affairs. Similarly, this Government has done a great betrayal to the minorities in the last 10 years by stopping various funds including Maulana Abdul Kalam Azad Education Foundation which was given to the minorities. I request you to give up that trend in the future and focus on the development of minorities.

The National Emergency was mentioned in the President's speech, but we must not forget that the Bharatiya Janata Government is imposing an undeclared emergency.

It should not be forgotten that this Government created an undeclared state of emergency by passing various laws including the Citizenship Amendment Act, the cancellation of the special status granted to Kashmir, disrupting the peace of the country, oppressing all those who raised their voices against it.

We cannot forget the tendency of this Government to use all the Government machinery like Enforcement Department, CBI, Income Tax Department etc. for political revenge.

This Government dealt with the situation where the Chief Ministers of the state themselves could make arrests without warrant.

If this is the case for the Chief Ministers of the state, the question arises what kind of condition can be expected for the common people. Those who question this Government, those who raise their voice against their policy and those who stand in the field in support of the people are oppressed by this Government.

They are threatened by Government machinery like CBI, Income Tax Department, Enforcement Department etc. This poses a great danger to democracy. I request this Government to abandon such a situation. This minority Government should give the answer to the people in this House.

This time is definitely not going to be like last time when you sat in power with a brute majority and did everything you thought of.

With the support of the people, India Alliance is currently sitting strong as the opposition. It sits with the audacity to challenge you.

Therefore, I request that we should focus on the development work needed by the people who elected us, the effects on the people, and the removal of laws against the people, and we should discuss here. I also request that the power of Government given by the people should be used without anti-democracy respecting the constitution and focusing on the development of the country.

Thank you.

SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): I oppose the Address by Hon'ble President of India to the Parliament delivered on 27th June, 2024. The huge gap between the promise made by the previous Government and the actual performance has already reflected on the result of the General Election, 2024. The high-flown slogans used in the General Election has made present 'Modi Government' a weakened one and the opposition has become stronger.

The increasing number of suicides by the farmers is stark reality. The Government policy to generate two crore employment each year remained only an election plank. Youth are running from pillar to post in search of jobs. The inflation is sky rocketing leaving the hapless poor hopeless and cross-fingered.

Needless to say, the policy and programme of Government projected for 'Viksit Bharat' in the 'Amrit Kaal of Independence' remains a mere dream in the absence of efficient and effective execution of development projects. Government Economic Policy has led to concentration of wealth in few hands and the poor has become the poorer. The Government policy to give 5 kg free grains to 80 crore people under PMGKY is not a fight against poverty but a guarantee for continuance of poverty. 'Nari Shakti Vandan Adhiniyam' is a long drawn dream. High price of Gas Cylinders is affecting the household management.

The personality cult in Governance and naked scramble for power has disrupted social fabric, fraternity, harmony, faith in democratic culture and constitutional provisions.

The uneven and imbalanced distribution of resources between Centre and States is causing stress and strains on co-operative federalism. The economic policies of Government emphasizing on privatization all along, including Airports and other PSUs does not match Government's claim 'Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas'.

Therefore, I find failure of Government's policy and programmes/schemes on all fronts.

SHRI VIJAYAKUMAR *ALIAS* VIJAY VASANTH (KANYAKUMARI): I would like to express my views on the Motion of Thanks to the President's Address.

I thank Madam Soniaji and my leader Rahulji and the people of my constituency, who have been kind enough to send me to this temple of democracy.

I have come here with greater aspiration with many new innovations and initiatives to develop the nation and to strengthen the democracy and economy of the nation. Everybody is aware that recent elections were fought on communal, caste, linguistic and what not basis. We all faced a tough time during campaign. I take this opportunity to congratulate all Members who have been elected to this Lok Sabha.

I have some issues, which I want the Government should focus on and take corrective measures for a solution.

My Constituency, Kanyakumari is one of the coastal areas and situated in the southernmost part of the country. It is a place where three oceans meet and frequented by lakhs of tourists, both national and international. Three lakh persons in my constituency are engaged in fishing out of the total population of 18 lakhs. I certainly need to share their concerns to this House.

Everyone knows that when there is a ban on fishing or when there is a high tide or storm or difficult situation, fishermen are not allowed to go for fishing for at least 60 days in a year. Though they get subsistence allowance, it is a paltry sum and it has to be enhanced.

After 2012, licenses given for deep sea fishing have been withdrawn. Kanyakumari is the one place where there is ample scope for deep sea fishing. Therefore, I urge upon the Government to review this and provide licenses for deep sea fishing. Fishermen are also given diesel on subsidized rates by the State Government, but it is not sufficient.

Therefore, I request the Government to increase the quantity of diesel to 2000 litres for bigger boats and 500 litres for smaller boats and the expenditure can be reimbursed to the State Governments. Due to sea erosion and high tide, the

houses of fishermen are damaged and destroyed. Government should give adequate compensation.

A helipad with Coast Guard Station should be constructed in order to locate missing fishermen.

The House is aware that Kanyakumari is a very important tourist destination in the country. Every year, crores of people are visiting both from India and abroad. But, I am sorry to say that infrastructure facilities are very very poor. We are talking about Swacch Bharat but we do not have toilets even in important tourist places like Kanyakumari. Even hotels are not sufficient to meet the requirements of the tourists.

The transport facility is almost nil. I request Government to set up the Airport to attract the tourists. The whole constituency depends on tourism and fishing. If there is no facility for tourism, which also give considerable revenue to the Government, how do we expect the tourists to arrive there.

Due to natural calamities or when there is storm or when there are high tides or due to sea erosion, the high tides coming into places where people are inhabited and houses are destroyed. But, as on today, there is no mechanism for providing compensation for the houses damaged or any provision is there to rebuild the houses. I take this opportunity to demand that a scheme should be evolved to provide for compensation for the houses damaged due to natural calamities.

I am sure everybody would appreciate the importance of Kanyakumari as a tourist destination. In Mumbai, we have a Gateway of India structure, from where one can go into Arabian Sea. But, three oceans meet at Kanyakumari and it is befitting that Gateway of India like structure should be set up in Kanyakumari. Everybody would appreciate the great work done by the then Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. Kamaraj. He was instrumental in the development of Tamil Nadu, especially in the sectors of education and irrigation. He was also instrumental in launching Mid Day Meal Scheme for children, and in fact, he was the first Chief Minister to do this, and later on, other chief ministers followed. He was very much anxious to ensure that no child was left uneducated in Tamil Nadu. Under his able leadership, many major and minor dams were built and he took efforts in the interest of farmers for irrigation, power supply and good harvesting. He also took several steps for industrialisation of the state. He was respected and regarded by everyone cutting across the party lines not only in Tamil Nadu, but the whole India. Today, we have a

giant statue of Sardar Vallabhai Patel in Gujarat. In the same way, it would be befitting to install a statue of the late Chief Minister Mr. Kamaraj at Kanyakumari like Gateway of India structure with a height of 1000 feet so that our young generation would remember him forever.

Neyyar River Left Bank Canal will help to irrigate an area of 9200 acres in Vilavancode Taluk in Kanyakumari. In 2012 Tamil Nadu government filed a petition against Kerala Government seeking uninterrupted water supply from Neyyar River, and the matter is now pending in Supreme Court. The Tamil Nadu government has contended that the Neyyar is an Inter State River because a portion of the river's catchment area lies in the territory of Tamil Nadu. Tamil Nadu government has not received water since 2004, which has caused serious hardship to the farming community. Previously, in 1999, the Kerala government took a stand that Neyyar was not an Inter State River. However, in its own draft agreement, Kerala informed Tamil Nadu in 2010 that the water shall be supplied subject to realization of water charges and payment of distribution charges and making the agreement valid for five years to be renewed by mutual consent. The Supreme Court, in November 2016, had framed certain issues including whether the river can be classified as an inter- State river, and also whether the legal obligation is imposed on the Kerala government to supply water from Neyyar to Kanyakumari under the States' Reorganisation Act, 1956. The matter is pending in Supreme Court now. I request the Central Government to ensure water supply from Neyyar to Kanyakumari to help farmers in the district for irrigation purposes.

Kanyakumari belt is an Education Hub, but unfortunately, there is no University there. Therefore, I request a Central University to be set up. I also take this opportunity to request the Central Government to extend financial assistance for conversion of the General Hospital at Nagercoil on the lines of Madurai, Salem & Tanjore. A Cancer Research Institute may also be set up to provide assistance to the patients in and around Kanyakumari. As you all know a large number of tourists visit Kanyakumari every year. They enjoy the sun rise and sun set and also whenever possible they go for boating upto Vivekananda Rock. There is a statue of Saint Thiruvalluvar located there. Public also want to visit the statue, but due to paucity of boats they are unable to go there. There should be adequate boat services so that the people can enjoy. A rope car between Vivekananda Rock and Saint Thiruvalluvar statue over the sea would also boost the tourism.

Tamil Nadu Government has formulated a Chennai- Kanyakumari Industrial Corridor. But, there has been no progress. Detailed project report is not even in place and financial provision is also not there. Considering that southern districts of Tamil Nadu are backward in industries and rampant unemployment in those districts, I urge upon the Government to set up the Chennai-Kanyakumari Industrial Corridor on priority basis by providing adequate funds or direct the state government to implement it immediately.

My Constituency Kanyakumari consists of coastal areas and thousands of fishermen go into sea for catching fish as it is their only livelihood. But due to natural calamities, especially in storm, high tides they get lost in the deep sea. Because of non-availability of satellite phones, it is very difficult to locate them. Therefore, I request that satellite phones should be provided to fishermen so that they can be located during the emergency. I also take this opportunity to request that a helipad may be constructed at Kanyakumari so that in emergencies it can be used to locate fishermen. During non-emergency times helicopters can be used for tourism purposes. Government can also consider the setting up of a Naval Base with Coast Guard facility so that it will be easier for locating the fishermen who are lost in the mid sea.

I therefore, demand that a package should be extended immediately by the Central Government for the development of tourism in Kanyakumari. There are natural resources like honey and rubber, which are available in plenty in Kanyakumari. This can be exploited by setting up of a Rubber Park and Research Institute and Ayurveda Hospital to utilize the availability of honey.

A rosy picture is being given for economy of the country. It is said that there is a growth rate of 7.6% of GDP, but experts and economists say that there is only a growth rate of 4.5%. I do not know why the Government is giving such a rosy picture. The whole country is aware that after GST, small and medium enterprises have been affected and harassed. Every small entrepreneur has to file innumerable applications with a result that they are not able to focus on the development of their companies. Though there have been a demand for simplification of GST, nothing has been done by the Government. On many items, the GST rate is 28% even now with the result that the prices have gone up. I urge upon the Government to take a decision to reduce the rate so that the consumers, businessman and the Government can be benefitted. The real estate sector has been the most affected due to the GST. Thousands of flats are not sold and builders

are facing lot of problems. Recently, just before elections with a popular move in mind, Government reduced the rate to 5% in case of under construction houses. But, here is also a catch. The Government would not reimburse the tax credit inputs to the builder with a result that the prices of houses have not come down. Millions of our youth have lost their jobs due to demonetisation GST and Covid-19 impact. There is no concrete action on the part of the Government to provide employment. The skill development which was started 3-4 years back has not moved an inch forward. I do not know why crores of money is being wasted on skill development/Make in India when nothing has come out of it. I want to demand from the Government - is there any plan to provide employment to our millions of youth?

With a full heart, I wish to express my views on the Internal Security. Hundreds of our soldiers are getting killed, hundreds of our security forces including police are getting killed through Naxalite/Terrorist activities. But what action has been taken by the Government? Is there any preventive action taken by the Government? If so, please come up. This Government does not have a clear policy regarding Jammu & Kashmir, nothing has been specified clearly by this Government regarding Jammu & Kashmir. We hear only media reports. I demand the government should come up with a White Paper regarding the situation in Jammu & Kashmir.

In the recent years the agriculture has seen its worst phase. Farmers are committing suicide, they are not getting fertilizers. Water is not available. The subsidies and facilities given by the earlier government have been withdrawn and farmers are facing lot of difficulties. They are not getting loans from banks and even in case of a single default they are harassed, their houses are confiscated and sometimes they are thrashed by the bank agents. I want to know from the government why poor farmers are humiliated, harassed and beaten by agents of banks when big ticket industrialists go scot free even after taking crores of rupees as loans. I, therefore, urge upon the Government to come out immediately with a farmer user friendly scheme and to provide further welfare of farmers.

In business medium and small enterprises have taken loans from banks and after GST many of them are not able to continue their operations and they have defaulted in loan repayment. To give the boost to small scale sector, I urge upon the government to waive off the interest taken from the banks and to give a Tax Holiday for 10 years.

Taxation Law is very complicated and the government has done nothing to simplify it. The tax burden is very heavy, both on the consumers as well as industrialists. I request the government to reduce the tax burden to improve our economy.

In 2023, over a sudden surge in prices of flight tickets, flyers in India expressing their dissatisfaction with rising airfares, it is pain point for flyers. I request the government to possibility of implementing a fare ceiling method for all routes.

Our Hon'ble Chief Minister MK Stalin says the decision vindicates Tamil Nadu's stand against NEET. NEET gives an undue advantage to those who can afford expensive coaching, thereby giving very little chance for those students from poor and rural backgrounds. So, we seek exemption from NEET for Tamil Nadu. I am requesting you to stop the paper leak issues and to re setup the NTA because the students lost their faith with this government.

Undermining the important pillar of democracy and freedom of speech, India's press freedom is on the decline, with the country ranking 159 out of the 180 in the 2024 World Press Freedom Index by Reporters without Borders. I request the Government to address this issue.

The most important issue is question about the future of Students in India, I would like to seek your attention about the recent Exam Paper leaking issue like NEET, CUTE, UGC, etc., and also more than 40% vacancies are not filled in IIT, IIM, Central Universities etc, It will damage the futures of millions of students, I also request the government to address this issue.

Another most important issue is Change of Security forces in Parliament, Even the MP's are questioned/ misbehaved by the CISF security staff (CISF personnel asking to MP: Why you are coming here?) during the Oath ceremony time family members of MP's are harassed, Whether the Government is aware about this issue or not, why this urgency to changing forces in Parliament, if you need to change give the necessary/proper training to security personnel at least equal or better than before. Now it is completely mess. I personally feel the change of security force is not a success one. I request to address this issue.

Many of the ministries sending reply letter to the MP's in Hindi, We are from Tamil Nadu non Hindi speaking state, we are unable to understand the text of the letters, So I request the Government to address this issue.

In a parliamentary democracy the views of the opposition should also be seriously taken and implemented wherever possible. I request the government to take our views on every issue and seriously try to implement the same. With these words I conclude.

Thank you.

श्री राहुल कस्वां (चुरू) **:** सबसे पहले मैं फिर से सदन के अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित होने पर माननीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनायें प्रेषित करना चाहता हूँ । आशा करता हूँ कि उनके निर्देशन में इस सदन में हम विपक्ष के सभी सदस्यों को सरकार के ध्यानाकर्षण हेतु उचित समय दिया जाएगा ।

मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने विचार रखता हूं ।

हमारे देश में वर्तमान में अनेक समस्याएँ हैं जिन्हें हल करने के लिए हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए । गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और अन्य कई मुद्दे हमारे समाज को जोड़ रहे हैं । हमारे पार्टी का संकल्प है कि हम सरकार को जवाबदेही में लेकर आगे बढ़ेंगे । हम उन नीतियों का समर्थन करेंगे जो सामाजिक न्याय, विकास, और प्रगति को सबके लिए सुनिश्चित करें ।

आज देश को एक नई दिशा की जरूरत है, जो सभी के लिए समान संवैधानिक अधिकार, समान अवसर, और समान विकास सुनिश्चित करे । हमारा लक्ष्य है कि हम सब मिलकर एक ऐसे भारत की तरफ बढ़ें, जिसमें अंत में किसी को पीछे छोड़ा नहीं जाएगा ।

पिछले दस साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा अनेकों कार्य किये गए, लेकिन अधिकतर कार्यों को सिर्फ फोटो opportunity में बदलने के लिए समय से पहले पूर्ण करवाने का कार्य किया गया, जिसमें कार्य की गुणवत्ता एवं सुरक्षा संबंधी सभी मुद्दों को गौण कर दिया गया**,** जिसका परिणाम आज हमारे सामने है ।

भारत सरकार द्वारा पिछले काफी समय से देश में आधारभूत संरचना पर ऊपरी तौर पर कार्य किया जा रहा है, जबकि इसके स्थान पर मूलभूत संरचनाओं का प्रभावी व उचित निर्माण किया जाना आवश्यक है । आज सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि पिछले 10 सालों में 75 हजार किमी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है । यह बहुत ही अच्छी बात है । लेकिन जिस सरकार के द्वारा हमेशा से हर कार्य में ROI निकाल कर कार्य किया जाता रहा है, उनके द्वारा इन सभी राजमार्गों का निर्माण किस आधार पर किया जा रहा है । दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर सबसे कम ट्रैफिक है, यही हाल भारतमाला परियोजना का है, जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन सड़कों पर किया जा रहा है, उस के अनुपात में इन पर ट्रैफिक बिलकुल भी नहीं है । इसके उलट हमारे द्वारा पिछले दस साल से सिरसा से चुरु राष्ट्रीय राजमार्ग बनाये जाने हेतु सरकार से मांग की जा रही है, स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 26 फरवरी 2019 को चुरु आकर इस राजमार्ग को बनाये जाने की घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद भी आज तक इस सड़क का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया जा सका है । इसके साथ साथ मेरे लोक सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का फोर लेन का कार्य किया जा रहा है । लेकिन हमारे बार बार मांग किये जाने के बावजूद भी भारत सरकार द्वारा आमजन की अत्यंत महत्वपूर्ण मांग को देखते हुए VUP व CUP की स्वीकृति जारी नहीं की जा रही है । हमारे द्वारा पिछले काफी समय से गाँव भांगीवाद, बाघसरा आथुना, खोटिया, ढाणी डीसपुरा, रामसरा, ढाढर, लाखाऊ, सिरसला, लादडीया, सादुलपुर बाईपास पर खेमाणा, ढढाल व गुलपुरा के रास्ते

पर, श्योपुरा व इन्दासर आदि में VUP व CUP बनाये जाने की मांग की जा रही है । अतः सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ।

इसी प्रकार मेरे लोक सभा क्षेत्र के चुरू जिला मुख्यालय व सादुलपुर तहसील मुख्यालय पर बाईपास बनाए जाने हेतु माननीय मंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है । एक स्थान पर तो सरकार द्वारा बिना किसी विचार के लाखों करोडों रूपये अनावश्यक ही लगाये जा रहे हैं और जहाँ आवश्यकता है उन स्थानों पर केवल राजनैतिक हितपूर्ति की जा रही है ।

भारत सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि देश में हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क के तहत मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का कार्य प्रगति पर है**,** साथ ही अन्य सर्किट पर भी बुलेट ट्रेन चलाये जाने का विचार किया जा रहा है । मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्ग पर 1 लाख करोड़ से अधिक व्यय किया जाना प्रस्तावित है । पिछले दस वर्षों से हमारे द्वारा चुरु लोक सभा क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर सर्वे करवाकर नई रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव बनवाया गया, लेकिन हर बार रेलवे बोर्ड के द्वारा नेगटिव ROI की बात बोल कर अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग पर रेलवे लाइन बिछाने से मना कर दिया गया ।

मेरे लोक सभा क्षेत्र के जिन मार्गों की हमारे द्वारा लगातार मांग की जा रही है वे सभी मार्ग आर्थिक व सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनके बार बार सर्वे भी किये जा चुके हैं । अतः भारत सरकार को आमजन की महत्ती मांग को देखते हुए सीकर से नोखा वाया बीदासर, सादुलपुर से गजसिंहपुर वाया तारानगर सरदारशहर, सरदारशहर से हनुमानगढ़**,** भादरा से बैर वाया आदमपुर आदि अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गों पर नई रेलवे लाइन डालने का कार्य किया जाए ।

भारत में सरकार द्वारा हाई स्पीड ट्रेन चलाये जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है, इसके उलट पहले से चल रही सेमी हाई स्पीड ट्रेन वन्दे भारत की गति को कम किया जा रहा है, नेगेटिव ROI व कम occupancy का बोल कर हमारे क्षेत्र में विभिन्न ट्रेन चलाये जाने से मना किया गया, यहाँ तक कि ट्रेन के ठहराव तक नहीं दिए गए | क्या सरकार ने कभी विचार किया कि वंदे भारत ट्रेन में कितना occupancy आ रही है और क्या इनका RO । पोजीटिव में है । मेरे लोक सभा क्षेत्र के आमजन की सुविधा को देखते हुए हमारे द्वारा हनुमानगढ़ से दिल्ली वाया नोहर सादुलपुर इंटरसिटी, श्रीगंगानगर से जयपुर वाया सादुलपुर इंटरसिटी, श्रीगंगानगर से उदयपुर वाया सादुलपुर नई गाड़ी चलाने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक इस ओर कोई कार्य नही किया गया ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुवात जब से की गई है तभी से मैंने इस योजना पर गहन अध्ययन कर इसका लाभ मेरे क्षेत्र के किसानों को दिलवाने के लिए प्रयास किया है, जिसका इतना लाभ हुआ है कि मेरे क्षेत्र के किसानों को पिछले 6 सालों में 7800 करोड़ से अधिक का बीमा क्लेम मिला है लेकिन सरकार की ढुलमुल नीतियों व बीमा कंपनियों को संरक्षण दिए जाने के कारण, बीमा कंपनियों द्वारा जानबूझकर आपतियां लगाकर किसानों को उनके लाभ से वंचित करने का कार्य किया जा रहा है । पिछले समय तक सरकारी कंपनी SBI के द्वारा हमारे क्षेत्र में फसल बीमा किया जाता रहा था, जिसके कारण उनसे सीधे संपर्क हो रहा था और वे कार्य भी कर रहे थे । लेकिन अब एक निजी कंपनी को चुरु लोक सभा क्षेत्र में फसल बीमा का कार्य दिया गया है, जिनका कोई प्रतिनिधि भी हमारे क्षेत्र में नहीं बैठता है । जिस कारण किसानों की बात सुनने वाला कोई नहीं है और पिछले 1 साल से किसानों को उनके नुकसान का बीमा क्लेम अभी तक नहीं मिल पा रहा है । इसके साथ साथ रबी 21-22, खरीफ 22 के बकाया क्लेम को भी अभी तक जारी नहीं किया गया है ।

भारत सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पिछले 10 साल में 3.50 लाख किमी नई सड़कों का निर्माण किया गया है । यह देश की एक अत्यंत आवश्यक योजना है जिसके तहत ग्रामीण

क्षेत्र के वंचित गाँवों को सड़क से जोड़ने का कार्य किया गया है । हमारे द्वारा लगातार मोनिटरिंग किये जाने के कारण क्षेत्र को इसका बहुत लाभ मिला है, और क्षेत्र के अधिकतर गाँवों को सड़क से जोड़ने का कार्य किया गया है लेकिन इस योजना की कुछ कमियों के कारण क्षेत्र के अधिकतर गाँव अभी भी कनेक्टिविटी से वंचित हो रहे हैं । इस योजना के तहत किसी भी गाँव को अगर एक तरफ से सड़क से जोड़ दिया जाता है तो उसे दूसरे ओर से नहीं जोड़ा जा सकता है जिसके कारण थोड़ी दूरी पर होने के बावजूद भी ग्रामीणों को घूम कर जाना पड़ता है । अतः सरकार को फेज 4 के तहत मिस्सिंग लिंक और कच्चे रास्तों को भी शामिल करते हुए गावों को जोड़ने का कार्य किया जाना चाहिए ।

भारत सरकार द्वारा विद्युत तंत्र को मजबूत किये जाने हेतु RDSS योजना की शुरुवात की गई, लेकिन मेरे लोक सभा क्षेत्र में राजनीति से प्रेरित होकर जानबूझकर इसके तहत किये जाने वाले कार्यों को रोका जा रहा है । मेरे लोक सभा क्षेत्र चुरु में हमारे द्वारा सर्वे करवाया गया, जिसके (46) तहत ज्ञात हुआ कि चुरु लोक सभा क्षेत्र में 46 हजार से अधिक ढाणियों में विद्युत कनेक्शन करवाए जाने की आवश्यकता है, विद्युत विभाग के प्रस्ताव भिजवाये जाने के बाद केवल 6 (40) हजार ढाणियों को विद्युतिकृत किये जाने की स्वीकृति जारी की है । अभी भी 40 हजार से अधिक परिवार विद्युत सुविधा से वंचित रह रहे हैं । इसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा प्रत्येक ढाणी के कनेक्शन हेतु 50 हजार रूपये की अधिकतम राशी जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन मेरे लोक सभा क्षेत्र में ढाणियों की दूरी अधिक होने के कारण 50 हजार की राशी अत्यंत ही कम है । अतः सरकार को इस पर पुनर्विचार कर इस राशी को बढाया जाना चाहिए ।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश में विभिन्न योजनाओं के उचित क्रियान्वन की बात कही गई है, मैं आशा करता हूँ कि भारत सरकार बिना किसी भेदभाव के महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का अनुसरण करते हुए देश के समुचित विकास हेतु कार्य करेगी ।

SHRI OMPRAKASH BHUPALSINH ALIAS PAVAN RAJENIMBALKAR (OSMANABAD): First of all, I would like to thank you for giving me the opportunity to express my views. I would also like to congratulate the hon. Speaker for being elected as the Speaker of the 18th Lok Sabha.

In all the States, which are leading in the production of soybean crop, including Maharashtra, the price of soybean is Rs.4,900 per quintal. Last year the price of soybeans was close to Rs 10,000 per quintal, but the Government, which gave the slogan of 'Sabka Saath Sabka Vikas', has trampled on the development of the farmers. By increasing the market price of soybeans, the price of soybeans for farmers is brought down by importing soybean oil and DOC. Also, it is imperative to change the onion export policy followed in respect of farmers in the State of Maharashtra. The export of Gujarat's white onion variety is allowed by the Centre while it is fighting with the farmers of Maharashtra. No decision is taken regarding the onion export in Maharashtra. So, it is necessary to take a proper decision regarding the export policy.

The Government should take necessary action to complete the Dharashiv-Tuljapur-Solapur line railway project. The Union Government has started many trains like Vande Bharat, Bullet train having modern facilities but it is not taking care of the common passenger. The condition of all the general coaches is very pathetic. It lacks cleanliness and basic amenities. These coaches are always overloaded and packed with passengers. Hence, the number of general coaches needed to be increased and the basic facilities should also be provided. The number of general coaches on the trains passing through my constituency should also be increased.

Under the Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme, the farmers have been paid Rs. 3,981.99 crore. Out of which, the State Government's share is Rs. 14,764.65 crore and the Central Government's share is Rs. 14,313.58 crore, during the years 2016-2023 from my Maharashtra State. Rs 33,060.21 crore has been paid to various companies. The insurance companies have paid Rs. 23,874.51 crore to farmers as crop insurance compensation, out of which a net profit of Rs. 9,185.07 crore has accrued to the insurance companies. This scheme is not being run for the benefit of the farmers but for the benefit of the companies.

As per the circular dated 30/04/2024 issued by the office of the Ministry of Agriculture, under the Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme with reference to Maharashtra only, the farmers of 32 Revenue Circles in my constituency are ineligible for the Prime Minister Crop Insurance Scheme 2023 (Kharif Season). In fact, drought like conditions have been declared in the State by the State Government. This circular is unfair to the farmers of Maharashtra, and it has knowingly deprived the farmers from claiming insurance compensation.

During the year 2003, around 5, 60,468 farmers had assured their crops under the PM Crop Insurance Scheme. The insurance companies had given 25 per cent advance on account of disrupted rainfall for 21 days. On the basis of the circular issued by the Union Government dated 30.04.2024, out of 57 revenue circles, the farmers belonging to 25 revenue circles were sanctioned Rs.39.52 crore. The farmers of the remaining 32 circles were deprived of insurance benefits. Around 5,19,000 farmers are still waiting for the compensation.

The National Testing Agency, New Delhi, conducted the exam on 05.05.2024 at 4750 centers. 67 students got 720/720 marks in this examination. More than 1500 students have been given grace marks due to malpractices in this examination. Due to the malpractice in this exam, many students have suffered and the UGC NET exam conducted by the National Testing Agency has been cancelled. There has

been malpractice in both the above examinations. Both the examinations need to be investigated.

Due to unfavourable natural conditions in Maharashtra, sometimes heavy rainfall causes damage. Sometimes due to drought and sometimes due to lack of water, the farmers face a lot of troubles.

Some east channel rivers in Maharashtra should be connected with the west channel rivers. Connecting rivers will solve all the water problems, including drinking water. The rivers Tapi, Girna, Darna etc., in Maharashtra under the river linking project of Godavari and its tributaries need to be connected to reduce the impact of drought situation in Marathwada, and thereby the water scarcity will also be reduced forever.

21 TMC water will be available to Dharashiv and other districts. This will permanently solve the problem of drinking water and also the water needed for agriculture. This project should be given special status and completed immediately.

The slogan ?Nation First? is given, but this Government never fulfills its promises. The slogans, Modi Government and Modi Government's guarantee, were spread in the campaign instead of Indian Government, but all the Indian people as a nation are not first, only Modi is shown first. This is wrong. It is necessary to discuss this in the House because national loyalty is different from personal loyalty.

The Digital Payment Scheme was launched by the Central Government with great fanfare. But the installments under the PM Kisan Scheme are not available without e-KYC. The farmers get only Rs 12,000 per year. A large number of farmers have not received the Pradhan Mantri Kisan Yojana installments even after updating through the e-KYC.

In a democracy, the Election Commission has been given autonomy. But there needs to be some restrictions on how the Election Commission has been helping those in power over the years.

The concession given to the houses being built under the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) should also be given to the houses under the Ramai Awas Yojana in Maharashtra. The relaxation given is not mentioned. So, this mention needs to be made, and the amount given for the houses should also be increased.

There is no mention of Maratha reservation, Dhangar reservation and Lingayat reservation in the President's Address. So, it should be included.

Dharashiv has been included in the aspirational districts. So, due to its inclusion in the backward district, there are many developmental schemes or if any such projects are implemented by the Centre in the district, they will provide direct employment to its citizens. The Government has not mentioned about any such projects being implemented in the district of Dharashiv. So, the projects being set up by the Central Government in Dharashiv should be mentioned.

The Prime Minister Crop Insurance Scheme is there to cover the losses due to natural calamities. There is no mention of stopping the arbitrariness of contractual companies. Therefore, there is a need to stop the arbitrariness of insurance companies. New rules are mentioned for that. They should be implemented.

There is a participation subsidy of 60 per cent of the Central Government and 40 per cent of the State Government under the Pradhan Mantri Krishi Sinchan Yojana. Every Drop plus Income Scheme is pending. An amount of Rs 17, 70,65,244 for a total of 8,328 beneficiaries in Dharashiv District till April 2023 is pending. It is necessary to take the right decision regarding its distribution.

Dharashiv is included in the list of ambitious districts. Therefore, it is necessary to promote the industry by setting up textile industry in Kaudgaon and Vadgaon MIDC of Dharashiv. There is a need to set up industrial clusters in other places too.

Dharashiv being an ambitious district, the only effective means of bringing about a change in the situation here is education. There is an urgent need to repair 527 classrooms and construct 594 new classrooms to spread and disseminate education here, and raise the standard of education. There is a dearth of resources for higher education. It is very important to establish educational institutes like IIMs and IITs here. Being an ambitious district, there is a need to establish an independent university in this district.

Crores of rupees of common man's investment has been looted through various chit fund companies across India. Many companies like Pulse Star in this cheat fund scam have defrauded the common citizens. This also needs to be investigated.

A hundred-year-old Barshi Textile Mill in my Osmanabad Constituency has been closed during the Corona period. Other yarn mills in India have started working whereas the yarn mill at Barshi is currently closed. The salary of the mill workers has not yet been paid. A proper decision should be taken to start the said mill immediately by paying the workers' salary.

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) **:** मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार रखना चाहता हूं ।

बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीया राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में पिछड़ों, गरीबों, किसानों, दलितों, युवा, महिला, बेरोजगारों और समाज के अंतिम तबके का संपूर्ण विकास कैसे हो उनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए इसके लिए इस अभिभाषण में कोई विशेष चर्चा नहीं की गई है और न ही इनके लिए कोई विशेष योजना या कार्यक्रम लाने की बात की गई है ।

माननीया राष्ट्रपति जी की अभिभाषण में किसानों को राहत देने हेतु कोई विशेष मद योजना या पैकेज की भी चर्चा नही की गई है । आज देश का किसान बहुत परेशान हैं । कितने किसान रोजाना आत्महत्या करने को मजबूर हैं । सरकार को किसानों के बकाया लोन माफ करने, कृषि में उपयोग होने वाले उपकरणों के टैक्स में 100% छूट देने और बिजली की बचत हेतु सोलर पम्प में 100% सब्सिडी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी । साथ ही MSP लागू करने, प्रकृतिक आपदा के कारण हुए फसलों की नुकसान की भरपाई की व्यवस्था करने और किसानों के लोन माफ करने के लिए विशेष मद की व्यवस्था करनी चाहिए थी ।

सरकार से मेरी मांग है कि किसानों को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत करने हेतु उपरोक्त मांगों के साथ-साथ MSP लागू किया जाए और किसानों का बकाया लोन माफ किया जाए । साथ ही फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने हेतु स्मार्ट खेती का प्रक्षीक्षण की व्यवस्था, एवं दूर दराज के क्षेत्रों में उचित भंडारण की व्यवस्था करने, उन्हें उनकी फसलों का सही और उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाए ।

अभिभाषण में NEET पेपर लीक परीक्षा मामले को लेकर कोई विशेष चर्चा नहीं की गई है । आज पूरे देश मे NEET परीक्षा को लेकर रोष व्याप्त है । देश के हजारों छात्र अपने परिवारों के साथ भयंकर गर्मी में सड़कों पर हैं । देश के भविष्य कहे जाने वाले छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है । पेपर लीक एवं परीक्षा सेंटर को हाइजेक कर और ग्रेस मार्क घोटाला कर कुछ परीक्षा माफिआयों द्वारा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ।

मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि NTA जो भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी मात्र है । क्या वो देश के सभी बड़ी परीक्षाओ को सुचारु रूप से सफलता पूर्वक सम्पन्न कराने में सक्षम है? क्या उसके पास अपने सभी पर्याप्त संसाधन/मैन पावर उपलब्ध हैं? क्या सरकारी एजेसिया एक्जाम कराने में सक्षम नहीं हैं? एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में 2019 से 2024 के बीच करीब 65 बड़ी परीक्षाओ के पेपर लीक और रद्द हुये हैं । जिनमे भारतीय सेना भर्ती परीक्षा कॉमन एंटरेंस एग्जाम (सीईई) 2023, सीटीईटी 2023, जेईई मेन्स 2021 और नीट यूजी 2023 जैसी परीक्षाएं शामिल हैं <u>जिनमें कुछ मुख्य पेपर लीक के मामले इस प्रकार हैं **:-**</u>

2024

· NEET-UG पेपर लीक ।

· NET-UG और NET-PG परीक्षा रद्द ।

· Uttar Pradesh RO-ARO पेपर लीक मामला ।

2023

· असम हाई स्कूल लिविंग सेर्टिफिकेट के दौरान दो विषयों के पेपर लीक ।

· महाराष्ट्र मे हायर सेकंडरी सर्टिफिकेट गणित का पेपर लीक ।

· राजस्थान एलीमेंट्री टीचर्स परीक्षा (REET) लीक ।

2022

· उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती परीक्षा लीक ।

· राजस्थान में वन रक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम सोशल मीडिया पर लीक ।

· बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) लीक के बाद परीक्षा रद्द ।

· उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा ।

· अरुणाञ्चल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक अभियंता परीक्षा ।

· ओड़ीसा कर्मचारी चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर (जेई) सिविल मुख्य परीक्षा ।

2021

· UPTET पेपर लीक ।

· महाराष्ट्र आवास एवं विकास प्राधिकरण मे इंजीनीयर एवं अन्य परीक्षा ।

· गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र लीक 2020 ।

· बंगलौर विश्वविध्यालय बी. काम परीक्षा लीक ।

· UP board कक्षा 12 वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक एवं अन्य कई परीक्षाएँ लीक और रद्द हुई ।

सरकार को तत्काल प्रभाव से NTA को रद्द कर देना चाहिए । और छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक सख्त से सख्त कानून लाया जाए । जिससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से पहले परीक्षा माफिया सौ बार सोचे ।

अभिभाषण में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने के लिए कोई चर्चा नहीं की गई है । करीब 20 वर्षों से सरकारी कर्मचारियों की OPS को बहाल करने की मांग को सरकार दरकिनार करती आ रही है । जिससे केंद्र और राज्य सरकारों के करीब 6 करोड़ कर्मचारी और उनके आश्रित सीधे प्रभावित हो रहे है । नई पेंशन स्कीम के तहत उनका तथा उनके आश्रितों का भविष्य सुरक्षित नहीं है । कोरोना रूपी वैश्विक महामारी के दौरान शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारियों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए पूरी लगन से मानवता की सेवा की है । नई पेंशन व्यवस्था NPS के तहत सेवानिवृत हुए कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नाम पर नाममात्र किसी को 1800 रुपए, किसी को 3500 रुपए, किसी को 4000 रुपए इसी

तरह ही प्रति माह मिल रहा है, जो आज के महंगाई के दौर में ऊंट के मुह में जीरा के समान है । सरकार से मेरी मांग है कि जनहित में कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा हेतु पुरानी पेंशन व्यवस्था को जल्द से जल्द बहाल किया जाए ।

महामहिम जी की अभिभाषण में सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना को लेकर कोई जिक्र नही किया गया है । वर्ष 1931 के बाद से अब तक कोई जाति जनगणना नहीं हुई है । वर्तमान समय की मांग है की समाज के सबसे निचले तबके और वंचित वर्ग के लोगों को, गरीब, किसान, युवा और महिलाओ को, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और देश से बेरोजगारी को दूर करने के लिए सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना कराना अत्यंत आवश्यक हो गया है । ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वास्तव में जो पात्र लाभार्थी है उनकी पहचान कर उनके अनुरूप संसाधनो की व्यवस्था और नीति का निर्धारण किया जा सके और सरकार द्वारा उन तक ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके । और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में और उच्च पदों व अन्य सभी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का उचित लाभ मिल सके । जिससे SC, ST, पिछड़ा वर्ग तथा विभिन्न जाति सामुहों के लोग भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रुप से मजबूत होकर, मुख्य धारा से जुड़ कर देश की अर्थव्यवस्था के विकास में अपना योगदान दे सकें और देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सके ।

सरकार ने जिस प्रकार कोरोना काल में हेल्थ सेक्टर में सराहनीय कार्य करने का प्रयास किया था उसी प्रकार हेल्थ सेक्टर में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु सरकार को विशेष पैकेज की व्यवस्था करनी चाहिए थी ।

बढ़ते कमरतोड़ महंगाई के दौर में बच्चों की शिक्षा आज बहुत ही महंगी हो गयी है सरकार को बच्चों को मुक्त शिक्षा देने और उच्च शिक्षा में सुधार करने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए था ।

हमारे देश में पिछले 10 वर्षों में बेरोजगारी का स्तर बहुत बढ़ गया है अभिभाषण मे बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है । वर्तमान मे बेरोजगारी दूर करने और रोजगार के अधिकार के लिए कानून लाने की आवश्यकता है ।

चुनाव में पारदर्शिता लोगों का संवैधानिक अधिकार है । पूरी दुनिया में अपनी तकनीकी का लोहा मनवाने वाले विकसित देशों इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और अमेरिका जैसे देशों में भी बैलट पेपर की मदद से चुनाव कराया जाता है । EVM मशीनों के माध्यम से चुनावों की सुरक्षा, सटीकता, विश्वसनीयता और सत्यापन के बारे में गंभीर आरोप भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में लगाए जाते रहे हैं । अतः सरकार से मांग है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और बिना किसी धांधली के चुनाव संपन्न कराने हेतु वैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए ।

धन्यवाद !

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारडोली) **:** मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी को लोक सभा का अध्यक्ष चुने जाने पर हृदय से बधाई देता हूँ ।

मैं बारडोली संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ और महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखता हूं । हमारे राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता वास्तव में प्रेरणादायक है । आपका नेतृत्व, दृष्टिकोण और समर्पण ने हमारे देश को अनेक चुनौतियों से उबारते हुए एक उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर किया है । आपके कार्यों का प्रभाव हमारे राष्ट्र के हर कोने में महसूस किया

जाता है, आपके अथक प्रयासों, दृढ़ संकल्प और देश के जन कल्याण के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद । आपके नेतृत्व में हमारे राष्ट्र ने अनेक उपलब्धियों को प्राप्त किया है ।

मैं पिछले 10 वर्षों से इस महान संसद का सक्रिय सदस्य हूँ । पिछले 10 वर्षों मे हमारी सरकार ने अनेक ऐतिहासिक फैसला लिए है, मा० प्रधानमंत्री जी श्री नरेंन्द्र मोदी जी के नेतृत्व मे हमारे भारत देश का विकास हर क्षेत्र मे अग्रसर है, जिससे पूरे विश्व मे हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है और विश्वगुरु बनने की दिशा मे प्रगति पर हैं । विशेषकर कृषि, इलेक्ट्रोनिक टेकनोंलोजी, रक्षा संबधी, एयरक्राफ्ट, स्वास्थ संबधी, आयुर्वेद संबधी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे आदि का विकास देश को नई प्रगति दे रहा हैं ।

हमारी सरकार जो महामहिम राष्ट्रपति दत्तक समाज कहलाता है, ऐसे अति पिछड़े समाज को Primitive Tribes ग्रुप को प्रधानमंत्री पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत 24 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक बजट का प्रावधान करके पहली बार इस समाज के विकास के उत्थान का माध्यम बन रही है ।

हमारी सरकार, विकास के साथ ही विरासत पर भी उतना ही गर्व करते हुए काम कर रही है । विरासत पर गर्व का ये संकल्प आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वंचित वर्ग और सर्वसमाज के गौरव का प्रतीक बन रहा है । और भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की ।

हमारी सरकार ने किसानों को ध्यान में रखकर किसानों को उनकी छोटी-मोटी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत ₹3,20,000 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की है । अपने नए कार्यकाल के प्रारंभिक दिनों में ही, सरकार ने किसानों को ₹20,000 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की है । सरकार ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में रिकॉर्ड वृद्धि भी की है । इसके साथ ही, सरकार एक बड़े पैमाने पर किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और PACS जैसी सहकारी संगठनों का नेटवर्क बना रही है ।

हमारी सरकार ने महिलयों को ध्यान में रखकर महिलयों के लिए स्त्री-नेतृत्वित विकास और सशक्तिकरण के प्रति स्थिर प्रतिबद्धता को उजागर किया, जो राष्ट्र की प्रगति में एक नये युग की निशानी है ।

लंबे समय से बढ़ती मांग को पहचानते हुए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रावधान से लोक सभा और विधान सभा में महिलाओं की अधिक सांसदीय प्रतिष्ठान सुनिश्चित करके महिलाओं को सशक्त किया गया है ।

हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है 3 करोड़ महिलाओं को 'लाखपति दीदी' बनाना, स्व-सहायता समूहों को अधिक वित्तीय सहायता के साथ समर्थन देकर । इस पहल का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक कौशल और अवसरों में सुधार करने के लिए नहीं है, बल्कि समाज में महिलाओं के स्थान और सम्मान को भी बढ़ाने के लिए भी तैयार किया गया है ।

हमारी सरकार ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कृषि सखी पहल शुरू की है । अब तक, स्व-सहायता समूहों से 30 हजार महिलाओं को कृषि सखी प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण कृषि कौशल और संसाधनों से सशक्त किया गया है । हमारी सरकार दिव्यांगों के लिए सस्ती स्वदेशी सहायक उपकरण विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है । इस पहल का उद्देश्य देश भर में दिव्यांग व्यक्तियों की पहुंच और समर्थन को बढ़ाना है ।

हमारी सरकार देश में शिक्षा और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए एक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना भी आगे बढ़ा रही है । पिछले 10 वर्षों में 7 नए IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 नए AIIMS, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं ।

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): On behalf of the constituents of Darjeeling Lok Sabha Constituency, I am thankful to President Madam. Your speech lays down the direction and vision with which your Government is working to ensure a "Vikshit Bharat?.

I am also taking this opportunity to draw your kind attention, to the absolute discrimination against our Darjeeling hills, Terai and Dooars region by the West Bengal Government. In 2023 Oct, we got massive flood on Teesta River. Nearly 400 families were impacted severely due to these floods. People lost their homes, their agricultural land, their livelihood, and 12 people even lost their lives. Yet the West Bengal Government has refused to acknowledge this as a "disaster". West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee made a public announcement of Rs 25 crore being allocated for disaster relief but that money has gone missing. They promised allocation of land for rehabilitation, but no allocation has been made till date. They announced construction of new homes, only 3 are being constructed, but even those are sub-standard. We are also part of India. Our people also pay taxes. In fact, our region contributes the highest amount of revenue to the West Bengal Government. From Teesta river alone, the West Bengal Government earns over Rs 750 crores from Hydro-dams situated there. West Bengal is the sole beneficiary of hydro dams on Teesta river and they have earned over Rs 7500 crores so far in the past decade. Yet, these funds have never been used by the West Bengal Government to ensure the welfare of the local communities. There is a deliberate discrimination against our region by West Bengal Government. This is why, people have been demanding a Separate State Gorkhaland because people feel West Bengal Government will always discriminate against our region.

Padma Shree awardee, scientist Dr. Eldavya Sahrma ji has made the following observations on Teesta:

Teesta Bazar's vulnerability is a humanitarian issue; therefore, it needs attention from all sections of the society and Government systems; The sediment regulation, guideline and clearing plans have to be designed and implemented by each and every hydropower projects in upstream and downstream, which are obstructing

the river flows the Teesta river. Dam safety plans have to be reviewed and corrected from time to time with the changing river conditions, and implemented; Landslides, land subsidence and flooding are likely to be a regular feature in these areas including Teesta Bazar; The townships and cities in the upstream are likely to face frequent disruption on road connection and commuting. The land cutting by river water on road sides and submergence of roads in low lying areas (now, because of raising of river beds) are likely to damage the roads. Therefore, in many places of the national highway along the Teesta river the roads have to be shifted to higher ridges; Disaster risk assessment of entire township and roads need to be carried out by technical institution with support from authorities keeping in view long term scenarios and potential impacts; Safety of the people can only be ensured if dwellers of lower areas are rehabilitated in safer higher ridges or elsewhere; The rehabilitation of people and households have to be compensated and executed with support of authorities, and helped by voluntary and non-governmental organizations; It is evident, that we need intervention from the Central Government along with interventions by the State Government; and I am therefore, requesting for Teesta floods to be declared a "National Disaster," since the impacts are not confined to one state alone, and request for immediate intervention by the Central Govt.

There is mass influx of illegal Rohingys and Bangladeshi immigrants in our region. This settlement is actively supported by the State Administration, for their "Vote Bank?. We have seen recently how the TMC MLA from Chopra, in North Dinajpur District referred to the incident of TMC cadres brutalizing a woman as being "social norms of a Muslim Rashtra". This is not a random incident. Majority of our border districts are seeing massive demographic changes. I fear, such incidents are happening everywhere in the border regions, but don't get reported due to the fear of State Administration persecuting the victims, as we have seen in the case of Sandeshkhali. This massive infiltration and settlement of "Vote Bank" by state administration is causing the indigenous people - Gorkha, Rajbangshi, Adivasi, Bengali, Hindi Bhasi and others to become marginalised in our own land. This also poses a grave threat to National Security in the "Chicken Neck" region There is urgent need for Central Intervention here.

Revenue over 50000-70000 crores are drained out of our Darjeeling hills, Terai, Dooars region every year by West Bengal Government. Not even a fraction of this is returned as investment for development in our region. West Bengal Budget of 2024-25 is Rs 3.7 lakh crores. Out of this, they have allocated only Rs 861 crore for

North Bengal Development. This is for the 7 districts of North Bengal - Darjeeling, Kalimpong, Alipurduars, Jalpaiguri South Dinajpur, North Dinajpur, Cooch Behar. It is less than 0.002% of the budget allocation. Even out of this, they will only spend around 20-30% of the allocation. How can any development take place?

North Bengal is a hub of tea production, and cinchona gardens; Central Government brought Four New Labour Laws; It ensures-Higher Wages, Better Social Security, Better Facilities; However, till date, the WB Govt has not implemented this Code till date; West Bengal Government has refused to give Parja Patta land rights to the workers; Minimum Wages Act is not implemented; and Workers kept deprived.

Under the succeeding West BengalGovernments, Darjeeling hills, Terai and Dooars has suffered; 1988-2010-Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC) ; 2011-Gorkhaland Territorial Administration (GTA) ; Both supposed to be autonomous - but has been made to fail by West Bengal Government; Because of this, there has been massive deprivation; Zero investment was made towards augmenting infrastructure in the region Internet, Mobile, Conmmunication and Transport Connectivity was severely lacking; Schools and Colleges Infrastructure crumbling-Lack of qualified teachers ; We don't have proper medical facilities - AIIMS North Bengal was taken to South Bengal by TMC Government; and We don't have technical colleges - No IITS, NITS, IIMS in the entire North Bengal region.

Darjeeling is perhaps the only place in India, where three-tire Panchayat elections haven't been conducted since 1988; Recently only elections to two tier were held; Elections to Three out of 5 Municipalities - Kurseong, Kalimpong and Mirik; have not been held since 2022; We don't have grass roots governance system; and Our constitutional rights are not recognized; and We are kept deprived and subjugated.

Forest Rights Act passed by Parliament in 2006, still not implemented in our region; No Parja Patta for DI Fund land residents; Corruption in PMGSY, RIDF, BADP, AMRUT, Har Ghar Jal; Teachers Ghotala, Coal Ghotala, Ration Ghotala, even asking questions in Parliament Ghotala; and Post Poll Violence.

Darjeeling hills, Terai and Dooars is a frontier region; As a mountain region Darjeeling has been a pioneer in many aspects; 1st Municipality in Mountain Region of India-1850; 1st mountain region to have industry; Tea Industry 1841-75, Cinchona 1865; 1st mountain region to be connected with railways-1871; 1st city in entire Asia

to get electricity connection-1897; 1st English school in mountain region 1823 Darjeeling; and Darjeeling hills, Terai and Dooars had many firsts to its name.

1954-Merged into West Bengal through The Absorbed Areas (Laws) Act, 1954; Till 1954, Darjeeling was the most prosperous region in entire Eastern and North Eastern India; and However, when our region was merged with West Bengal in 1954, it was done without any consultation with the local populace, and because of this our deprivation began.

Administratively, Darjeeling hills, Terai and Dooars were always governed as a tribal region. Prior to 1861-Non Regulated Area; 1861-70-Regulated Area; 1870-74-Non Regulated Area; 1874-1919-Scheduled District; 1919-1935-Backward Tract; and 1935-47-Partially Excluded Area.

The Gorkha contribution to nation building is immense; Freedom Fighters Helen Lepcha, Dal Bahadur Giri, Sahid Durga Malla, INA Capt Ram Singh Thakuri, Dalbir Singh Lohar, Bhakta Bahadur Pradhan, and hundreds of others; But we are labelled as Foreigners; Sir we did not immigrate our birders changed; How can we be considered foreigners in our own country? ; We are indigenous to these land; But every time we ask for our constitutional rights we are labelled as "foreigners; and It is this "crists of identity which needs to be addressed.

Darjeeling hills, Terai, and Dooars people eagerly await justice for the 11 left out Gorkha sub-tribes; These sub-tribes are Bhujel, Gurung, Mangar, Newar, Jogi, Khas, Rai, Sunwar, Thami, Yakha (Dewan) and Dhimal; Until 1947, these communities were considered Hill Tribes, as per the census of 1931 and 1941; The region was governed as a Scheduled District and Excluded Area, a form of governance applied only to Tribal regions; However, after Independence, their Scheduled Tribe (ST) status was revolved without consultation, depriving them of their tribal heritage; I want to ask the Parliament, have the Gorkhas not sacrificed enough for our nation? ; The indigenous Gorkhas are suffering, compromising their language, culture, and traditions; and Protection of the Gorkha community is vital for national security, achievable by promptly reinstating ST status for the 11 sub-tribes.

It is because of this systematic deprivation and "crisis of identity", the people from our region have struggled for a state of our own called Gorichaland; They believe in the leadership of Hon'ble PM Modi ji; Our party has committed to Permanent Political Solution for the Darjeeling hills, Terai and Dooars region; Our constitution guarantees equality for all and justice for all; But people from Darjeeling hills, Terai

and Dooars are waiting for justice for the past 77-years since Independence; and Hence, I request the Union Government to fulfil these commitments.

I therefore request the Government for re-Inclusion of 11 left-out Gorkha sub-tribes as ST, and Constitutional Solution for Darjeeling Hills, Teral and Donars.

श्री राजकुमार रोत **(**बांसवाड़ा**) :** राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद, जोहार संत सूमाल गोविंदगुरु महाराज मावजी महाराज एवं मामा बालेश्वर को नमन एवं समस्त भक्तों को धन्यवाद । साथ ही बांसवाड़ा-डूंगरपुर की आम जनता को खूब-खूब आभार आपने मुझे भारी बहुमत से जिताया । मैं उसे पल को याद करना चाहूंगा जब संविधान का ढांचा तैयार हो रहा था ।

1946 के समय जयपाल मुड़ा जी ने संविधान सदन में कहा कि जल -जंगल -जमीन -आदिवासी जीवन का आधार है । आदिवासी इस देश का मूल मालिक है लेकिन आज देश आजाद हुए 75 साल के करीब हो गए लेकिन आदिवासियों की जल -जंगल- जमीन की लड़ाई जारी है । आज देश में आदिवासियों को जमीनों से बेदखल किया जा रहा है आदिवासियों की पुश्तैनी जमीन एवं वर्षों से कब्जे शूदा जमीन को विकास के नाम से उजाडा जा रहा है जैसे हंसदेव छत्तीसगढ़ में कोयले खदान के नाम से बस्तर में उद्योगपतियों का फायदा पहुंचाने के लिए आदिवासियों को नक्सलवादी के नाम से मारा जा रहा है बांसवाड़ा में सोने की खदान के नाम पर आदिवासियों के आशियाने उजाड़ना बंद करें । आदिवासियों की पहचान के साथ खिलवाड़ करना बंद करें । आदिवासियों को आदिवासी ही रहने दो हमें वनवासी हिंदू-ईसाई या अन्य पहचान दिलाने की कोशिश नहीं करें । आदिवासियों के लिए कुछ करने की मंशा है तो शिक्षा सुविधा सुनिश्चित करें । जिस जमीन पर बैठा है उसे जमीन का मालिकाना हक़ दें । यंहा बैठे हुए लोग सत्ता और पावर की लड़ाई लड़ रहे हैं हमें सत्ता या पावर नहीं चाहिए हमें तो हमारे आदिवासी समुदाय के अस्तित्व एवं स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है ।

राजस्थान में भाजपा सरकार के शिक्षा मंत्री आदिवासियों के डीएनए की जांच करवाने की बात करते हैं और हमारे आदिवासी समुदाय के पुरखों का पता लगाने की बात करते है । इस तरह भद्दा बयान दिया है इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और पूरा आदिवासी समुदाय इस मंत्री से इस्तीफे की मांग करता है ।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नवी कक्षा के पाठ्यक्रम में राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा पुस्तक के 42 पेज पर भील प्रांत स्थापित करने की मांग की गई साथ ही 12 वीं के समाजशास्त्र की पुस्तक के पेज संख्या 41, 42, 43 पर आदिवासी समुदाय की अपनी अलग धर्म व्यवस्था के बारे में उल्लेखित किया गया है । आदिवासी धर्म पूर्वी समाज है अतः सरकार से अनुरोध है कि आदिवासियों के विकास के नाम पर विस्थापित करना बंद करें साथ हमारे बांसवाड़ा- डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर राजस्थान के आदिवासी समुदाय व अन्य एससी एवं ओबीसी वर्ग के गरीब मजदूर मजदूरी के लिए गुजरात राज्य में जा रहे हैं उनके साथ बच्चे भी जाते हैं उनके रहने एवं बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था करें धन्यवाद जोहर ।

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर) **:** माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रोपदी मुर्मू जी के अभिभाषण दिनांक 27 जून, 2024 पर मैं अपने विचार रखता हूं । माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रोपदी मुर्मू जी ने वर्ष 2024 के लोक सभा चुनाव को चुनाव नीति**,** इच्छा और निर्णयों के विश्वास का चुनाव बताया और इसे एतिहासिक बताते हुए लोकसभा मतदान में हुए रिकार्ड मतदान का उल्लेख किया ।

अभिभाषण में महिलाओं, किसानों, अर्थव्यवस्था के साथ साथ सरकार के 3.0 के विजन को समझाया और सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया एवं आपातकाल, वैश्विक चुनौतियों, बजट, देश की ग्रोथ, किसानों समेत अन्य मुद्दों पर भी प्रमुखता से प्रकाश डाला ।

वर्तमान सरकार के सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के संकल्प पर जोर दिया । वर्तमान सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों विर्निमाण, सेवाएं एवं कृषि को समान महत्व दे रही है । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 3,20,000 करोड़ से अधिक राशि के वितरण का जिक्र किया । हरित रोजगार के अवसरों में वृद्धि । भारत विश्व का तीसरा बड़ा विमानन बाजार । ग्रामीण क्षेत्रों में 3,80,000 किलोलीट से अधिक गांवों में सड़कों का निर्माण । असम में सेमीकंडक्टर प्लांट का निर्माण जो कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देता है । भारत सरकार के स्त्री - नेतृत्त्विक विकास और सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबध्दता । 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना । एक महत्वपूर्ण योजना- नमो ड्रोन दीदी योजना । महिलाओं के सश्सक्तिकरण के लिए कृषि सखी पहल । पी एम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना । पिछले 10 वर्षों में 10 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया है । करोना काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन प्रदान करने के लिए पी एम गरीब कल्याण योजना । डिजिटल इण्डिया, डाकघर नेटवर्क का उपयोग और जीवन बीमा की कवरेज को व्यापक बनाने मे प्रयास । डिजिटल विश्वपिवद्यालय की स्थापना की योजना को बढ़ावा । पिछले 10 वर्षों में 7 नए आई आई टी 16 नए आई आई आई टी, 7 आई आई एम 15 नए AIIMS 315 मेडीकल कॉलेज और 360 विश्वविद्यालयों की स्थापना । भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और अटल टिंकरिंग लेब्स, स्टार्ट-अप इंडिया जैसे कार्यकमों से देश के युवाओं की क्षमता को बढ़ावा । आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 55 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य योजनाएं । राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मेरा युवा भारत अभियान की शुरूवात । नागरिक संशोधन अधिनियम (CAA) के अंतर्गत शरणार्थियों को नागरिकता देने की शुरूवात से विभाजन से प्रभावित परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित हो रहा है । जी -20 अध्यक्षता के दौरान विश्व को एकजुट किया और विश्व बंधु की भूमिका को रेखांकित किया ।

जम्मू कश्मीर में संविधान के पूर्ण एकीकरण का उल्लेख करते हुए वास्तव में अभिभाषण में तरक्की और सुशासन का रोडमेप प्रस्तुत किया गया । इसमें भारत की प्रगति और भविष्य में आने वाली संभावनों को शामिल किया गया ।

अभिभाषण में राम मंदिर, महिला आरक्षण, विभिन्न बिलों के पास होने से लेकर तीन तलाक, अनुच्छेद 370 और डिजिटल कान्ति तक की उपलब्धियों का जिक्र प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का विश्वास दिलाया ।

अभिभाषण में राष्ट्र प्रथम की भावना प्रकट की गई । मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को इस हेतु धन्यवाद प्रेषित करता हूं ।

CAPTAIN BRIJESH CHOWTA (DAKSHINA KANNADA): I support the motion of thanks to the President's Address. The President's speech has eloquently encapsulated the hopes and dreams of 1.4 billion Indians, and I am privileged to add my voice in support of this vision. As a proud representative of the Dakshin

Kannada Parliamentary Constituency, I am committed to the service of our nation and its people.

As someone who has served on the frontlines, I understand the critical importance of a robust defence infrastructure. Her Excellency, the President rightly highlighted our continued focus on modernizing our armed forces and ensuring their readiness to meet any challenge. Achieving Atmanirbharta in defence production, strengthening border Infrastructure, utilising Nari Shakti and ensuring Ex-Servicemen Welfare have been at forefront of the NDA government. In the year 2023 alone, 118 infrastructure projects of Border Roads Organisation (BRO) were dedication to the Nation by our government, ensuring last mile connectivity to not only our forces but also to our citizens.

As a result of the right intent meeting decisive actions, we have witnessed historic milestones being achieved in our armed forces. The glass ceilings that once limited the roles of women in the military are now being shattered with each passing day. We have seen women officers not only being granted Permanent Commissions and command of frontline combat units but also being deployed in some of the most challenging operational posts, including the formidable Siachen Glacier.

These developments are not just symbolic but represent a profound shift towards gender equality and empowerment in our military. They inspire countless young girls across the nation to dream big and break barriers and are manifestation of the vision of Sabka Saath Sabka Vikas of our Prime Minister.

India is blessed with a demographic dividend, a youthful population that is eager, energetic, and ready to contribute to the nation's progress. The President's Address emphasized the importance of harnessing this potential through comprehensive youth and skill development programs. Our Government's initiatives like the National Skill Development Mission and Skill India have been instrumental in transforming the landscape of employment and employability in our country. Additionally, the establishment of vocational training institutes and polytechnic colleges has provided our young people with practical skills that are in high demand. By integrating industry-relevant curriculum and fostering partnerships with local businesses, we are ensuring that our youth are job-ready and equipped to excel in the modern workforce.

Sports play a crucial role in the holistic development of our youth. They foster discipline, teamwork, and a sense of achievement. The President's Address

underscored our nation's growing prowess in sports, and I am proud to highlight the strides we have made in this arena. Programs like Khelo India have revolutionized grassroots sports, providing young athletes with the support and infrastructure needed to excel. In 2023 alone, we witnessed Indian Sportspersons flying Indian Tricolour flying across the world in several international events. India achieved a historic milestone at the Asian Games held in Hangzhou, China, clinching a total of 107 Medals comprising of 28 Gold, 38 Silver, 41 Bronze Medals. This was followed by the triumph of Indian contingent in the Asian Para Games which finished with historic 111 Medals including 29 Gold Medals, surpassing all previous records. This could be achieved because of sustained support extended towards our athletes.

Beyond skill development and sports, youth empowerment is about creating an environment where young people can actively participate in the nation's development. The National Youth Policy aims to provide our youth with opportunities to engage in social, economic, and political spheres. The policy is a roadmap for the development of youth today to ensure a bright future for India tomorrow.

As I conclude, I am filled with a sense of pride and optimism for the future of our nation. The President's Address has laid out a comprehensive vision for India's development, and I am confident that under the leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi and the active participation of all my colleagues here, we will achieve these goals.

From strengthening our defence to empowering our youth, fostering sports excellence to harnessing technology, we are on a path of transformative growth. As a Member of Parliament, I am committed to supporting these initiatives and ensuring that the aspirations of the people of Dakshin Kannada and the nation are realized. Let us move forward with determination and unity, working together to build a prosperous, secure, and vibrant India. Thank you.

श्री कुलदीप इंदौरा (गंगानगर) **:** राजस्थान में प्रदूषित जल के संबंध में सिंचाई परियोजना पंजाब से सतलुज नदी से श्रीगंगा नहर हनुमानगढ़ व अन्य जिलों में बहता हुआ पानी समस्या का कारण प्रस्तुत करते हुए जनग धनौल भाखड़ा नांगल, इंदिरा गांधी नगर नहर द्वारा राजस्थान के बड़े क्षेत्र और सिंचाई के लिए आपूर्ति करती है । पंजाब लुधियाना शहर की faitar से निकलने वाला प्रदूषित पानी कचरा और शीवरेज सतलुज नदी में बुज नाला और जालंधर नकोदर, फगवाड़ा और सर्जिकल अपशिष्ट को काला सिंधिया नाला और चिन्तिवाई नाले के माध्यम से छोड़ा जा रहा है इसके अलावा उक्त क्षेत्र के विभिन्न चमड़ा या औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला कचरा भी

विभिन्न माध्यमों से सतलुज नदी में जा रहा है । प्रदूषित पानी हरिके बैराज के ऊपरी हिस्से से सतलुज नदी के माध्यम से आ रहा है जिसके कारण हरिके बैराज से गंगनहर, इंदिरा गांधी नहर, सरहिंद फीडर और बीकानेर नहर में प्रदूषित पानी जा रहा है । प्रदूषित पानी के कारण राजस्थान के लगभग 10 जिले वह एक करोड़ से अधिक आबादी जल-जनित रोगों जैसे केसर, संधिवात रोग, लीवर और पेट रोग और अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित हैं । केंद्र की सरकार शुद्ध जल व स्वास्थ्य समस्या की बात कर रही है वर्तमान के हालातो के लिए सख्त कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है । सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण समिति और अन्य बनाम भारत संघ 22.2.2017 को निर्णय सुनाया गया| पंजाब प्रदूषण बोर्ड द्वारा प्रदूषित पानी का उपचार किया जाए । पंजाब प्रदूषण बोर्ड द्वारा औद्योगिक इकाई व अन्य को इस संबंध उपचार का नोटिस दिया गया परन्तु सर्वोच्च न्यायालय व केंद्र सरकार द्वारा कोई उपचार नहीं हुआ जिसके कारण प्रदूषित जल से राजस्थान के लोग कैंसर व अन्य बीमारी के कारण लोग मर रहे हैं ।

आदरणीय केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी की समस्या का समाधान कहां है परंतु आज भी एमएसपी को लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की सीमाओं पर आंदोलन व संघर्ष चल रहा है । मेरे लोकसभा क्षेत्र गंगानगर में व हनुमानगढ़ में रहने वाले हरियाणा बॉर्डर पर काफी लंबे समय से धरना चल रहा है । किसान पड़ाव डालें बैठे हैं आंदोलन व संघर्ष करते हुए एक नौजवान शहीद हो गया व 80 वर्ष के बुजुर्ग को लाठियां से पुलिस द्वारा पिटा गया । हमारी मांग है कि किसानों की एमएसपी की मांग को पूरा किया जाए । सिंचाई पानी की समस्या माननीय राजस्थान के गंगा नहर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले में तीन सिंचाई परियोजना जहां सिंचाई पानी को लेकर हमेशा किसान आंदोलन रहता है । जब भी फसल बिजाई व पकाई का समय आता है तो सिंचाई पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है ।

31 दिसंबर 1981 को हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की अध्यक्षता में नदी जल बटवारे पर सहमति बनी थी । इस समझौते के आधार पर भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट (BBMB) राज्यों को शेयर निर्धारित करता है । जून माह में सिंचाई परियोजना सिंचाई पानी का शेयर निर्धारित किया जाता है । परंतु वर्तमान में निर्धारित शेयर में कटौती के कारण नरमा, कपास, मूंग, ग्वार की फसलों की बिजाई मेंसंकट खड़ा हो रहा है आईजीएनपी जो की 18000 क्यूसेक नहर है इस प्रकार से गंगा कैनाल 2500 क्यूसेक पानी दिया जाना चाहिए । पानी कम पहुंच रहा है इस प्रकार से भाखड़ा में निर्धारित सिंचाई पानी की कमी है । राजस्थान सरकार द्वारा फिरोज फीडर के निर्माण के लिए 200 करोड रुपए दिए गए हैं| परंतु निर्माण कार्य शुरू नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है । मेरा अनुरोध है इसे गंभीरता से लिया जाए ।

नदी जल बंटवारे के तहत जब भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) राज्य वाईज शेयर तय करता है तो उसका नियंत्रण (BBMB) का होना चाहिए जबकि हैण्ड बक्सों पर पंजाब सरकार का नियंत्रण रहता है जल वितरण व्यवस्था बीबीएमबी के अधीन हो व राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि की भी इसमें आवश्यकता है । राजस्थान का प्रतिनिधि होगा तो अपने क्षेत्र की सिंचाई पानी का समाधान हो सकता है ।

सिंचाई नहरों पर पंजाब के किसानों द्वारा चोरी होती है जो गंभीर है जिससे नहर में पानी कम हो जाता है इसका खामियाजा राजस्थान के किसानों को झेलना पड़ता है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन (गोरखपुर) **:** मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में अपने विचार रखता हूँ । महामहिम ने 27 जून, 2024 को संसद के समक्ष इस सरकार के कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी थी । अभिभाषण के अध्ययन से पता चलता है कि यह सरकार राष्ट्र निर्माण की अपनी शपथ को पूरा करने की दिशा में पक्के इरादे और ठोस नीति के साथ आगे बढ़ रही है ।

इस अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्मरण करना चाहूँगा जिन्होंने कहा था कि जब तक समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति सशक्त नहीं हो जाता तब तक हमारा देश विकास नहीं कर सकता । हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने न केवल समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान किया बल्कि उसे देश का प्रथम नागरिक बना दिया । हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच कितनी व्यापक है ये उसका उदाहरण हैं । फ़ैशन परेड समाज के अति समृद्ध एवं कुलीन वर्ग के लोगों से जुड़ा हुआ है । मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पहली बार आदिवासी लड़कियों ने फ़ैशन शो आयोजित किया जो आदिवासी समाज के उत्थान और उनके बढ़े हुए मनोबल को दर्शाता है ।

हमारी सरकार शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है । हमारी सरकार की सोच है कि अर्बन एरिया को डेवलप किया बिना देश के विकास और सशक्त भारत सपना पूरा नहीं हो सकता है । इसके लिए ज़रूरी है कि इज़ ऑफ़ लिविंग यानी जीवन को सुगम बनाना । यही कारण है कि यह हमारी सरकार के प्राथमिक लक्ष्यों में शामिल रहा है । शहरों में गटर की सफ़ाई का काम हमारे वाल्मीकि भाई अपने हाथ से करते हैं । कई बार हादशा होने के कारण वे ज़ख्मी हो जाते हैं, उनकी मृत्यु तक हो जाती है । इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति अब गटर में नहीं उतरेगा । शहरी इंफ्रा को विकसित करने के लिए उन्होंने 10 हज़ार करोड़ रुपये के अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट फण्ड की स्थापना की घोषणा की है । यह फण्ड दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों पर खर्च किए जाएँगे । यह फण्ड ग्रामीण विकास के लिए स्थापित किए गये फण्ड की तर्ज पर स्थापित किया जाएगा । 50 हज़ार से 1 लाख की आबादी वाले शहर टियर टू में आते हैं और 20 हज़ार से 50 हज़ार की आबादी वाले शहर तीतर श्री में आते हैं । हमारी सरकार चाहती है कि शहरी निकाय आत्मनिर्भर बनें यानी अपने खर्चे खुद उठायें । इसके लिए प्रॉपर्टी टैक्स में प्रशासनिक सुधार करने और अर्बन इंफ्रा के लिए यूज़र चार्ज प्रणाली अपनानी होगी । शहरों को लोगों से धन जुटाने के लिए म्युनिसिपल बॉण्ड की दिशा में आगे बढ़ना होगा और अपनी साख ठीक रखनी होगी जिसके आधार पर शहरी निकायों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी । उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा " अमृत काल का विजन तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थ व्यवस्था का निर्माण करना है । इसके लिए सरकारी फंडिंग और वित्तीय क्षेत्र से मदद ली जाएगी ।

बीते दस वर्षों में हमारी सरकार ने जैसा कार्य कर के दिखाया है उस से देशवासियों में यह विश्वास जगा है कि सरकार हमेशा उनके साथ है और उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है । आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार राष्ट्र निर्माण की उस सोच के प्रति संकल्पित है, जिसकी नींव वर्ष 2014 में रखी गई थी । यह सरकार नागरिकों की मूलभूत जरूरतें पूरी करते हुए एक सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है । 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" इस सरकार का मूल मंत्र है ।

हमारी सरकार समाज के हर तबके, चाहे वो किसान हो, जवान हो, छात्र हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, मध्यम और लघु उद्योगों को चलाने वाले लोग हो सबके विकास और समृद्धि के लिए कार्य कर रही है, परन्तु हमारा सबसे बड़ा संकल्प समाज के उस आखिरी व्यक्ति को सशक्त करने का है, जो आज तक वंचित रहा है । हमें निर्धन से निर्धन, वंचित से वंचित व्यक्ति को यह एहसास दिलाना है कि यह देश उनका है और इस देश का विकास तभी हो सकता है जब वे भी समृद्ध हों ।

किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को, देश के प्रत्येक किसान के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है । साथ ही, अपने खेत में दिन-रात काम करने वाले किसान भाई-बहन 60 वर्ष की आयु के बाद भी सम्मानजनक जीवन बिता सकें, इसे ध्यान में रखते हुए किसानों से जुड़ी पेंशन

योजना भी लागू की । इस प्रकार की पेंशन योजना छोटे दुकानदार भाई-बहनों के लिए भी आरम्भ की जा रही है जिस का लाभ देश के लगभग 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को मिलेगा ।

सरकार देश के सुरक्षा बलों को और आधुनिक एवं सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है. यूँ तो भारत हमेशा से एक शांतिप्रिय देश रहा है पर हमारे अस्थिर पड़ोस को देखते हुए हम राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे और देश सभी प्रकार से खतरों से निपटने के लिए तैयार है. हमारे जवान जो अपनी हर खुशी, हर सुख, हर त्योहार को त्याग करके, देशवासियों की सुरक्षा के लिए स्वयं को समर्पित कर देते हैं, उनके लिए नेशनल डिफेंस फंड 'से वीर जवानों के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि बढ़ा दी गई है । इस पहल में इस बार राज्य पुलिस के जवानों के बेटे-बेटियों को भी शामिल किया गया है ।

हमारी सरकार का मानना है कि मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर ही सशक्त राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण संभव है । ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है । वर्ष 2022 में देश के किसान की आय दोगुनी हो करने के लिए पिछले 5 वर्षों में अनेक कदम उठाया गया है । MSP में बढ़ोतरी का फैसला हो, या फूड प्रोसेसिंग में 100 प्रतिशत FDI को मंजूरी दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का काम हो या फिर फसल बीमा योजना का विस्तार; 'सॉयल हेल्थ कार्ड' हो या फिर यूरिया की 100 प्रतिशत नीम कोटिंग; सरकार ने किसानों की छोटी-बड़ी आवश्यकताओं को समझते हुए, अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं । सरकार ने कृषि नीति को उत्पादन केंद्रित रखने के साथ-साथ आय-केंद्रित भी बनाया है । इन्हीं प्रयासों की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' आरम्भ किया गया है । इसके माध्यम से सिर्फ तीन महीने में ही 12 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के पास पहुंचाई जा चुकी है । हर किसान को इस योजना के दायरे में लाए जाने के बाद, अब इस योजना पर प्रतिवर्ष लगभग 90 हज़ार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है । कृषि उपज के भंडारण की सुविधा से किसानों की आर्थिक सुरक्षा को बल मिलता है । अब ग्रामीण भंडारण योजना के माध्यम से किसानों के अपने गांव के पास ही भंडारण की सुविधा प्रदान की जाएगी । कृषि क्षेत्र में सहकारिता का लाभ, डेयरी व्यवसाय से जुड़े किसानों को मिल रहा है ।

इस सरकार की मान्यता है कि देश के निर्धन परिवारों को गरीबी से मुक्ति दिलाकर ही, संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है । पिछले दस वर्षों के दौरान देश में किसानों, मजदूरों, दिव्यांगजनों, आदिवासियों और महिलाओं के हित में लागू की गई योजनाओं में व्यापक स्तर पर सफलता मिली है । सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय के विज़न का अनुसरण करते हुए गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों को आवास, स्वस्थ्य जीवन की आवश्यक सुविधाओं, आर्थिक समावेश, शिक्षा, कौशल तथा स्वरोजगार के जरिए उन्हें सशक्त करने का मार्ग अपनाया है । देश के सबसे पिछड़े 1 लाख 15 हज़ार गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास से करोड़ों गरीब परिवारों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ।

सरकार ने जनधन योजना के रूप में विश्व के सबसे बड़े आर्थिक समावेशन के अभियान की सफलता के बाद सरकार बैंकिंग सेवाओं को देशवासियों के द्वार तक पहुंचाने का काम भी कर रही है । देश के गांव-गांव में और नॉर्थ- ईस्ट के दुर्गम क्षेत्रों में भी, बैंकिंग सेवाएं आसानी से उपलब्ध हों, इसके लिए तेज़ी से काम हो रहा है । इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से देश के लगभग डेढ़ लाख डाकघरों को बैंकिंग सेवाओं के लिए तैयार किया जा रहा है ।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस सरकार का संकल्प है निर्धन से निर्धन व्यक्ति को इस प्रकार से सशक्त करना कि वह अपने और अपने परिवार के चिकित्सा के लिए आर्थिक लाचारी से मुक्त हो जाये । इस उद्देश्य से 50 करोड़ गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान करने वाली विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत

योजना लागू की जा चुकी है । इसके तहत, अब तक लगभग 26 लाख गरीब मरीजों को अस्पताल में इलाज की सुविधा दी जा चुकी है । सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध कराने के लिए 15000 से अधिक जन औषधि केंद्र' भी खोले जा चुके हैं । सरकार का प्रयास है कि दूर- सुदूर इलाकों में भी लोगों को जन औषधि केंद्रों से सस्ती दरों पर दवाइयां मिल सकें ।

सरकार ने जनधन योजना के रूप में विश्व के सबसे बड़े आर्थिक समावेशन के अभियान की सफलता के बाद सरकार बैंकिंग सेवाओं को देशवासियों के द्वार तक पहुंचाने का काम भी कर रही है । देश के गांव-गांव में और नॉर्थ- ईस्ट के दुर्गम क्षेत्रों में भी, बैंकिंग सेवाएं आसानी से उपलब्ध हों, इसके लिए तेज़ी से काम हो रहा है । इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से देश के लगभग डेढ़ लाख डाकघरों को बैंकिंग सेवाओं के लिए तैयार किया जा रहा है ।

महिला तथा युवा सशक्तीकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है । मुझे इस बात का गर्व है कि हमारी सरकार की यह सोच है कि न केवल महिलाओं का विकास हो, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो । महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, राज्योंके सहयोग से अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं । महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के दंड अधिक सख्त बनाए गए हैं और नए दंड प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जा रहा है । बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान से भ्रूण हत्या में कमी आई है और देश के अनेक जिलों में सेक्स-रेशियो में सुधार हुआ है । उज्ज्वला योजना' द्वारा धुएं से मुक्ति, 'मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से टीकाकरण, सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन, इन सभी का सर्वाधिक लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिला है । ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने घरों की रजिस्ट्री में भी महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है । इस योजना में अगले तीन वर्षों के दौरान गांवों में लगभग 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे । असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों के लिए भी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं । दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं । राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण अंचलों की 3 करोड़ महिलाओं को अब तक 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण दिया जा चुका है । वहीँ हमारी युवा पीढ़ी की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बीते पांच वर्षों में युवाओं के कौशल विकास से लेकर उन्हें स्टार्ट-अप एवं स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद देने और उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त सीटें उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है, स्कॉलरशिप की राशि में भी 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है । इससे उन्हें नियुक्ति तथा शिक्षा के क्षेत्र में और अवसर प्राप्त हो सकेंगे । सर्कार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि समाज के हर वर्ग का युवा अपने सपने पूरे कर सके, इसके लिए समय पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने पर बल दिया जा रहा है । प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, स्वरोजगार के लिए लगभग 19 करोड़ ऋण दिए गए हैं । इस योजना का विस्तार करते हुए अब 30 करोड़ लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा । इसके अलावा अर्थ-व्यवस्था को गति प्रदान करने वाले क्षेत्रों में समुचित नीतियों के माध्यम से, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए जाएंगे ।

रोज़गार के और अधिक अवसरों का सृजन करने हेतु एक और जहां सरकार स्वरोज़गार को बढ़ावा दे रही है वहीं दूसरी तरफ भारत को ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने के लिए तेज़ी से काम हो रहा है । 'Ease of Doing Business' की रैंकिंग में वर्ष 2014 में भारत 142 वें स्थान पर था और दस वर्षों में हमारी सरकार के प्रयत्नों से हम 63 वें स्थान पर पहुंच गए हैं । जल्दी ही हम विश्व के शीर्ष 50 देशों की सूची में आ जायेंगे । आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए GST तथा आय कर प्रणाली में सरलीकरण किया जा रहा है ।

इस सरकार के कार्यों के सबसे अधिक प्रभाव भ्रष्टाचार निवारण और सुशाशन के क्षेत्र में दिखा है । हमारा मानना है की सुशासन सुनिश्चित करने से भ्रष्टाचार कम होता है, नागरिकों का आत्म-सम्मान बढ़ता है और वे अपनी प्रतिभा एवं क्षमता का पूरा उपयोग कर पाते हैं । यह सरकार, भ्रष्टाचार के विरुद्ध Zero Tolerance की कड़ी नीति को व्यापक तथा प्रभावी बनाने के लिए कृतसंकल्प है । भविष्य में सार्वजनिक जीवन और सरकारी सेवाओं से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का अभियान और तेज किया जाएगा, Minimum Government Maximum Governance पर और अधिक बल दिया जाएगा और टेक्नॉलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा । काले धन और आर्थिक अपराध का समूल नाश अब निश्चित है ।

गंगा की धारा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए हमारी सरकार ने जितने कार्य किये हैं, उतना पहले कभी नहीं हुआ है । इसके परिणाम मिलने आरम्भ हो गए हैं और हाल ही में, जगह-जगह से गंगा में जलीय जीवन के लौटने के जो प्रमाण मिले हैं, वे काफी उत्साहवर्धक हैं । सरकार 'नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी में गिरने वाले गंदे नालों को बंद करने के अभियान में और तेज़ी लाने जा रही है और सरकार का प्रयास रहेगा कि गंगा की तरह ही कावेरी, पेरियार, नर्मदा, यमुना, महानदी और गोदावरी जैसी अन्य नदियों को भी प्रदूषण से मुक्त किया जाए ।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित कुछ माँग रखना चाहता हूँ । उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी महाराज के नेतृत्व में उत्कृष्ट कार्य कर रही है लेकिन राज्य के पास संसाधनों की कमी होती है । इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से माँग करता हूँ कि गोरखपुर में स्थित रामगढ़ ताल में सोलर पैनल लगाया जाय जिससे बड़े पैमाने पर बिद्युत उत्पादन किया जा सके । रामगढ़ ताल काफ़ी बड़ा है और कई सौ एकड़ में फैला हुआ है ।

मैंने अपने कैरियर की शुरुआत भोजपुरी फ़िल्म उद्योग से की थी । उसके बाद मैं देश की विभिन्न भाषाओं की लगभग 700 फ़िल्मों में काम कर चुका हूँ । मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि गोरखपुर में एक भोजपुरी फ़िल्म निर्माण नगर स्थापित किया जाय ताकि पूर्वांचल के मेधावी युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिल सके । इससे पूर्वांचल के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे ।

जय हिन्द ।

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): I've been observing the speeches made by our friends from the opposition regarding the President's Motion of Thanks. It's quite amusing that they speak as if they have won the election, not us, the NDA members. Let's remind the INDI Alliance that in 2014, after a decade of power from 2004-2014, the UPA was reduced to 70 seats. However, even after 10 years of the NDA, the BJP secured 232 seats in 2024. This mandate is a clear endorsement of PM Shri Narendra Modi Ji's leadership and his vision of Sahka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. It is a rejection of the divisive and misleading politics of the INDI Alliance. Congress, which always divided the country on the basis of region and tried to muster a new division of North vs South, was able to secure only 99 seats in 2024. Despite the Congress being in power and spending significant money on elections, the BJP is the single largest party in Karnataka with

the NDA securing 17 seats. In Andhra Pradesh, we won 3 seats while the Congress secured none. In Telangana, we won 8 seats even though Congress is in power there. We opened our account in Kerala and also increased our vote share in Tamil Nadu tremendously. This clearly shows that the people of the country are with PM Modi and it is his leadership that is poised to take Bharat to greater heights in the next 5 years.

Yesterday, in his extended monologue, Rahul Gandhi engaged in extensive self-promotion about the election results. However, he conspicuously avoided offering any substantive policy suggestions for reforming the National Testing Agency (NTA). His 90-minute address was nothing more than political rhetoric, frequently interrupted by fact-checks from Sri Narendra Modi Ji, Sri Amit Shah Ji, Sri Rajnath Ji, Shivraj Singh Chouhan Ji, and others, without a single constructive idea on how to advance our nation or improve the NTA's conduct of NEET-UG. In contrast, it is the Sri Narendra Modi Government that believes in accountability and is committed to the students welfare and their future Her Excellency, the Honourable President of India, in her Joint Address to Parliament, outlined how the Modi Government is actively tackling the issue of paper leaks and bringing about more transparency in public exams. Let me remind the Members of the Opposition once again that it was under the leadership of Prime Minister Modi Ji that the National Education Policy (NEP) was introduced in 2020, replacing a 34-year-old outdated policy. This NEP was a game-changer, modernising our education system and equipping our students with skills for the 21st century. Yet, due to their irrational hatred for Modi Ji, the Congress-ruled state government in Karnataka reversed the implementation of the NEP, clinging to the archaic policy of 1986. For decades, there was a demand for a unified testing agency to conduct exams with independence and transparency. Despite ruling the country for years, Congress never took steps to establish the NTA. Various committees and stakeholders, including the Ashok Mishra Committee in 2015, recommended such an agency. The Programme of Action 1992, to implement the National Policy on Education (NPE) 1986, envisaged the establishment of a National Testing Service (NTS). Again, in 2010, IIT Directors submitted an interim report to the Ministry recommending a single testing agency to ensure independence and transparency in testing. In 2015, the Ashok Mishra Committee, chaired by Shri Ashok Mishra, Chairperson, BoG, IIT Roorkee, recommended establishing a National Testing Service or a similar agency. It was finally PM Sri Narendra Modi who set up a unified testing agency in 2017 and called it the National Testing Agency.

Before NTA, 10 different agencies used to conduct 30 different exams. Multiple entities such as CBSE, IITS, AICTE and state Governments conducted different exams for entry into medicine, engineering and other courses across various fields. Until 2012, the CBSE conducted the All-India Engineering Entrance Exam (AIEEE), while the IITs administered the IIT-JEE for admissions into IITs and other engineering institutions. Until 2013, the UGC-NET was conducted by the UGC, and from 2014 to 2018, the exam was administered by the CBSE. Up to 2015, the CBSE was also responsible for the All-India Pre-Medical Test (AIPMT), with various state governments and their organizations conducting their own state-specific medical entrance exams. Additionally, until 2019, the AICTE conducted the Common Management Admission Test (CMAT) and the Graduate Pharmacy Aptitude Test (GPAT). Government boards such as CBSE, AICTE, we can see, were involved in conducting exams for higher education even though that's not their core mandate. And this situation resulted in various problems. The exam used to be on multiple dates and cities which had a huge logistical and travelling cost across the country. Many exam dates used to clash and the students had to choose between the different exams. Each examination had its unique syllabus and pattern, requiring students to prepare separately for each, increasing their workload and stress. Variations in exam difficulty and evaluation standards across different exams and states created disparities in the admission process. All these issues were addressed when the NTA was formed in 2017 and registered in 2018.

Following the establishment of the NTA, the JEE-mains and UGC-NET became a computer-based test, marking the first time that computer-based exams were introduced in the country. It contributed to a reduction in malpractices that were noticed in the exam earlier. Previously, all India Pre-Medical Tests were conducted only in 2 languages - English and Hindi. Currently, the NEET-UG is being held in 13 languages, including many regional languages like Kannada. Tamil. Telugu, Bengali, Assamese, Marathi. Malayalam and others, JEE-Mains was being conducted in 3 languages and is now being held in 13 languages similarly. In the last 5 years, NTA has conducted 234 exams of Engineering. Medical, Pharma, Research, Fellowship and other fields and the exams have witnessed more than 5 crore registrations. With 1.23 crore students registering for exams through NTA, it is now the 2nd largest exam conducting agency in the world after China's Gaokao, which held exams for 1.29 crore people last year. NTA conducts 15 entrance and fellowship exams, of which NEET-UG is the highest subscribed exam with 23 lakh students this year. Rahul Gandhi was saying that the NEET-UG is for the rich kids of the country, but the reality is different. Qualified candidates from the EWS in the

last 5 years increased by 102%, while ST category was 93%, 78.7% and OBC by 65% - indicating a much higher representation.

Increase in medical seats in 2014, when the BJP government took over.

The number of UG medical seats in the country were 54,352.**.** Similarly, with respect to PG medical seats, the number of seats in the country were 24,242. There is an increase of 82% in medical colleges from 387 before 2014 to 704 as of now. Further, there is an increase of 112% in MBBS seats from 51,348 before 2014 to 1,09,170 as of now, there is also an increase of 117% in PG seats from 31,185 before 2014 to more than 67,802 as of now. AIIMS, before 2014, were only 7 and today, there are more than 20 AIIMS set up across the country. It was only thanks to the Modi Govt that the number of seats available in medical colleges across the country increased by this extent Congress did nothing even after being in power for more than 7 decades.

Modi Ji's Government also brought into implementation the Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024, to ensure transparency, fairness and credibility in public exams. The Act imposes penalty for offenders and syndicates, including of fine of up to Rs 1 crore and imprisonment of up to 10 years. The Government has also set up a High-Level Committee to suggest reforms for the NTA. PM Modi Ji's Government also removed the interviews for recruitment of Class C and Class D posts and went only with the merit list because it was during this interview stage that recruiters succumbed to political interference in appointments from Congress leaders and associates.

Congress's shoddy record of conducting exams, Speaker sir, will be exposed in the next 2 minutes. Between 2004-2014, there were multiple times when exams conducted by the Central Agencies were cancelled due to malpractices or paper leaks. In 2006, there was an incident of paper leak and malpractice reported of the AIIMS PG exam. In 2007, the ICAI's Common Proficiency Test exam paper was leaked. In 2009, the CLAT exam in which lakhs of budding lawyers of the country appear, was postponed and held again due to a question paper leak. Even in the Railway Recruitment Board exam in 2009, a paper leak was reported, resulting in the cancellation of the exam. The AIEEE in 2011 was rescheduled amid allegations of a paper leak. Following another paper leak before the SSC CGL in 2013, the

examination was cancelled and reheld. Such is the record of the Congress and the UPA when it comes to conducting and ensuring transparency in exams.

As BJYM President, I have travelled to all the states across India, and in the last few years, I have realised a pattern. All these scams only took place in INDIAlliance-ruled states. Another commonality was the sentiments of the youth. They were depressed, had lost faith in the system, and saw no light at the end of the tunnel as long as Congress or these Governments were in power.

Between 2018-23, Chhattisgarh became Congress hub for experiments in mastering scams. It is said that there were more than 19 paper leaks and scams in 5 years. The biggest one was the State PSC recruitment scam for State Administrative and police services. The whole merit list is a plot to give entry to children and relatives of Congress leaders, officers and businessmen, just like Congress imposes leaders in national politics, without having any merit and by crushing others. Seven out of the first 10 rank-holders were direct relatives of Congress and their close bureaucrats. The top-ranked candidate was the daughter of the Education Director, belonging to the same community as CM Baghel and reportedly a distant relative. The second and third rank holders were a married couple, with the wife being the daughter of a Congress leader. The seventh-ranked candidate was listed simply as "Nitesh," with his surname conspicuously hidden. He was later revealed to be the adopted son of the then PSC Chairman, Mr. Taman Sonwani. Mr Sonwani had 5-6 family members along with his daughter in law inducted into government jobs in 2-3 years period. Another brother-sister duo, children of a retired Governor's secretary, both ranked in the top 10 recording the same marks down to the decimals. Several other candidates were identified as children of Congress leaders, including the daughter of the then PSC secretary. It was reported that each selected candidate allegedly paid Rs. 75 lakhs to Mr. Sonwani and others to secure their positions, highlighting the depth of the corruption and inefficiency in the recruitment process. In another entrance of Vanrakshak (Forest guards), the results of a girl were tempered unhesitatingly. She was shown to complete the 200 mtrs run in 14 seconds in records. 5 seconds less than Usain Bolt's world record.

The Bhupesh Government has revoked all computerized and standardized procedures of earlier Dr. Raman Singh's Government to ensure nepotism and their control over the selections.

State public service commissions in any part of the country are known for doing appointments for Class 1, Class 2 and executive appointments in Class 3. Bhupesh Baghel govt changed the entire structure of PSC in CG also to appoint class 4 peons. The gang in PSC sold each and every position for lakhs of Rupees.

We announced that when our Government will come to power, we will conduct an inquiry on all bogus appointments, punish the wrongdoers and make transparent rules, I am happy to inform you that the new Govt under CM Vishnu Deo Sai ji has cleared the way for CBI enquiry, Soon these people will be behind the bars.

Under Congress Since 2019, over three paper leaks have happened every year in Rajasthan, which has affected over 40 lakh students. No serious action has been taken by the Gehlot-led Congress Government to prevent these incidents. The situation became so worse that the Government imposed an emergency like situation to shut down the state's internet to stop cheating during exams.

Rajasthan has suffered from numerous exam scandals. The exams conducted for recruitment of Patwari, Junior Engineer (JEN), Forest Guard, Police Constable and Rajasthan Teacher Eligibility Test (REET), all of them experienced leaks which caused massive disruption and cancellations affecting lakhs of aspiring candidates. For example, the Patwari exam had 5,378 vacancies with 1.562 million applicants, and the Junior Engineer exam had 533 vacancies with 31,752 candidates. The REET exam saw 2.6 million applicants, with the paper leaked from the strong room three days before the exam.

It was found that the Rajiv Gandhi Study Circle (RGSC), a Congress-backed NGO, played a role in the REET paper leak scandal. The RGSC had several of its members involved in the REET exam leak scandal. This included sacked RBSE chairman DP Jaroli, RGSC advisory committee member Subhash Yadav, and other key coordinators like Dhyan Singh Gotwal and Pradeep Parashar. When BJYM organized a protest against the REET scam, I remember that masses of youngsters joined the protest on their own accord.

Youth of Rajasthan suffered from massive unemployment and distress in last 5 years and lead to various suicides due to unemployment under Gehlot Government . The Government under Shri Bhajan Lal Sharma has announced a probe in all public recruitments under the Gehlot Government, which is a welcome move.

Under TMC, West Bengal has experienced systematic destruction of its education system, with over 60,000 teaching posts remaining vacant due to politically

motivated appointments. Thousands of youths who have cleared B.Ed and DLED degrees are sidelined while unqualified or underqualified TMC supporters are given teaching jobs, undermining the merit-based recruitment system. In colleges, instead of hiring NET-qualified teachers, the West Bengal Government allows posts to be filled by those without NET qualifications but affiliated with TMC, degrading the quality of higher education. The SLST merit list was manipulated to include over 1,000 TMC cadres, with more than 400 allegations of rank jumps and recruitment of candidates who were not even on the merit list, leading to 119 court cases. Despite the Hon'ble High Court ruling in favour of the initial merit list candidates, the TMC Government has refused to comply, resulting in no recruitment for six years and leaving qualified teachers secking justice for 400 days. Nearly 13,000 non-teaching staff were recruited illegally in state-aided schools, with 2,300 recruitment challenges in court and the Hon'ble High Court ordering the dismissal of 320 Group C and 593 Group D employees. Between 2013 and 2016, 42,000 primary teacher recruitments were challenged, leading to 132 cases in the High Court and a halt in recruitment processes since 2016, adversely affecting primary education.

Hemant Soren Government did not even conduct exams for thousands of vacancies across the state. They only conduct exams when they need money. The Jharkhand Staff Selection Commission (JSSC) exam. It was an open secret that each seat was being sold between Rs. 35 lakhs to 50 lakhs. Thereafter, the paper of the exam was leaked which infuriated the entire state. Allegations are that paper was leaked already and candidates were made to sit and learn the answers. The ED report states that the mobile and house of Hemant's close friend and architect Binod Singh was used in the question paper leak scam. A. large number of admit cards of students have been recovered during investigations by the ED against Hemant Soren.

Kerala Public Service Commission (PSC) has another level of tech innovations. There have been significant scams in Kerala entrance exams, particularly involving PSC exams. SFI leaders used Bluetooth devices and smartwatches to cheat, securing high marks illicitly. (SFI)two leaders of the Students' Federation of India (SFI) R Shivaranjith and A N Naseem, who were also accused of stabbing a student at University College in Thiruvananthapuram, used hi-tech methods and modern gadgets to cheat in the civil police officer test. Nepotism and illegal appointments have been rampant, undermining the credibility of the recruitment process. Tragically, some youths on the PSC shortlist, who were not appointed, have

resorted to suicide. These scandals have led to widespread disillusionment among the youth, shaking their faith in the system.

If this is the case where you are or were in Government, you don't have the moral authority to lecture the Modi Government. This is a serious issue that all Governments, agencies, stakeholders should come together and solve the problem. How can we expect this from the Congress party, which divides the country on all possible segments?

It is disheartening to see Rahul Gandhi, in yesterday's speech, calling Hindus as violent. This comes from a party that has repeatedly tried to equate Hinduism with terrorism, even attributing the horrific 26/11 Mumbai attack to so-called "Hindu terror." This rhetoric is part of a calculated international conspiracy to defame Hindu society, and Rahul Gandhi is merely a pawn advancing this agenda. चुनावी हिंदु हमें धर्म ना सिखायें.

I would like to conclude by quoting Bharat Ratna and former PM Atal Bihari Vajpayee's poem on Hindus:

होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम?

मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम ।

गोपाल-राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए?

कब दुनिया को हिन्दू करने घर-घर में नरसंहार किए?

कब बतलाए काबुल में जा कर कितनी मस्जिद तोड़ीं?

भूभाग नहीं, शत-शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय ।

हिन्दू तन-मन, हिन्दू जीवन, रग-रग हिन्दू मेरा परिचय!

We do not need lectures on Hindu Dharma. And let me add one more thing, directly to Rahul Gandhi: हिंदु अहिंसक तो है, पर नपुंसक नहीं है । Thank you.

DR. MALLU RAVI (NAGARKURNOOL): I would like to express my views on the motion of thanks to the Honourable President's address. I also congratulate and convey my best wishes to all the newly elected members of this House. The Honorable President in her address only praised the 10 years of rule of Shri Modiji and conveniently avoided the burning issues of the country like unemployment,

cast wise census, MSP to Farmers through parliament bill, removal of ceiling on 50 per cent reservation to SC, ST, BC and Minorities, high-level prices of essential commodities and diesel, petrol and cooking gas.

Honourable President has given a certificate to Modiji's 10years rule by saying all is well. Yesterday Mr. Thakur from the treasury benches said that Shri Nehruji has killed the sole of Democracy, reality Shri Nehruji has saved the sole of Democracy. He for the sake of a Democratic Government and for the freedom of India he relentlessly fought with Britishes and went to jail several times After becoming prime minister he has done his best to save the parliamentary democracy.it is because he laid the foundation for strong democracy that today we are enjoying the fruits of democratic government. Mr thakur also said that Indira Gandhi's slogan of "Garibi Hatao" is a big failure. this also is a blatant lie. Smt. Indira Gandhi not only gave that slogan but also brought Land Ceiling and Nationalization of Banks because of which there was and is a great change in the lives of poor people. It is congress government which brought agricultural revolution, Dairy revolution, industrial revolution, IT revolution and education revolution in this country. Modiji Government gave tax cut to the chosen corporates for nearly an amount of 2Lakh Crore Rupees. In the Modiji government Scheduled Commercial Banks have written off nearly Rs 10.6 lakh crore in the last 5 years, out of which nearly 50 per cent belong to large industrial houses but they haven't written of any farmer's loans in these days. Modiji's government brought 3 draconian laws against the farmers and withdrew after long agitation by the farmers. Modiji's Government has brought new labour laws which are not friendly to labour.

Demonetization has not brought any black money to the RBI rather it has facilitated people to change their black money into white money. It is mentioned in Hon'ble president's address that Modiji's government has brought more number of airports, national highways, IITs, IIMs and medical colleges. All these things require infrastructural and human resources are not made available. In 10-year tenure of Modiji opposition leaders and CMs were sent to jail by using CBI, ED, and Income Tax. This is a great threat to democracy and Constitution.

In the past 10 years of Modiji's government, the constitution has been dishonoured. SC, ST, BC and minority reservations are systematically avoided from being implemented.

I am elected from Nagar Kurnool Parliamentary Constituency of Telangana State. I request the Hon'ble Prime Minister through you sir that all the guarantees be given

to Telangana during division of Andhra Pradesh State like ITIR, IIM, Railway Coach factory in Kazipet, Bayyaram Steel Factory and National Status to Palamuru Rangareddy Lift irrigation scheme etc.

I conclude my speech while opposing the motion of thanks to presidential address.

SHRI JOYANTA BASUMATARY (KOKRAJHAR): At the outset, I thank you for giving me the opportunity to express my views. I represent the Kokrajhar (ST) Constituency of Assam - one which is also the Gateway to India's North Eastern Region, under BTR Sixth Schedule Area. I represent United Peoples' Party Liberal - the UPPL Party - one of the leading Regional Parties of Assam. The UPPL Party has one representative in the Upper House Rajya Sabha, it is leading the Government of Bodoland Territorial Region (BTR) in alliance with Bharatiya Janata Party under the NDA umbrella, and is also a partner in the NDA Government of Assam.

In addition to reiterating our unwavering support for the NDA government led by our charismatic Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji, let me also promise our support for his vision of Vikshit Bharat, as embodied in the spirit of the National Democratic Alliance, which has been blessed by the nation's citizens to commence its historic third term.

I come from Bodoland Territorial Region (BTR) one of the largest Sixth Schedule Regions of the country with a population of over 3 (three) million encompassing an area of around 9 thousand square kilometres. With the initiative of Hon'ble Prime Minister and the guidance, support and presence of Hon'ble Home Minister Amit Shah Ji, the historic BTR Peace Accord was signed on 27th January 2020 between the Government of India, Government of Assam and various Bodo Stakeholder groups led by All Bodo Students' Union (ABSU), various factions of the National Democratic Front of Bodoland (NDFB), among others. The signing of this Accord paved the way for permanent peace in Bodoland Region after a prolonged period of struggle, unrest, and intermittent violence for over forty years. Hon'ble Prime Minister who visited Kokrajhar on 7th February 2020 to commemorate this historic Accord declared the dawn of a new era of Peace and Development in the Bodoland Region-rebuilding the confidence of millions of people of the Region. And in these past four years, I am happy to inform the August House, that true to the spirit of this Accord, not a single incident of violence has been reported in the Region. Also, with the joint efforts of the Centre, State Government, and the Government of

Bodoland Territorial Region (BTR), almost sixty per cent of the various provisions of the Accord have been implemented.

Under the constant guidance of Hon'ble Home Minister, Hon'ble Chief Minister of Assam Dr. Himanta Biswa Sarma Ji and ably led by my leader Shri Pramod Boro, Hon'ble Chief of Bodoland-the Region has entered this new phase of possibility development, and lasting Peace.

There was a time when people from our Region were in many ways alienated from the scope of participating in our Democratic Process. Today, even after 77 years of our country's independence, we face the challenge of making our voices heard when required.

The spirit of the Sixth Schedule embodies the essence to bridge the gap for overcoming backwardness of the Sixth Schedule Administered Regions.

Therefore, it becomes imperative that we create an atmosphere of a more and regular engagement with the Government of India just like in the manner that the States and Union Territories have a framework for periodic interactions with the Centre.

I am hopeful that this temple of Democracy will be the proper forum to begin this journey of realizing the spirit as well as working of the Sixth Schedule in true letter and spirit.

We, the people of Bodoland also believe in our Hon'ble Prime Minister's dream to make India one of the most developed nations in the world. In many ways we have also benefitted from the rapid strides our country has made in the areas of Technology, Infrastructure, Digitization, Industry, Education, and many other areas of national development.

In conclusion, on behalf of the people of Bodoland Territorial Region, though your respected presence I pay my humble tributes to Father of the Bodos, the revered Bodofa Upendranath Brahma whose non violent struggle for emancipation paved our journey towards the Bodoland of today.

Bodofa's lifelong commitment to safeguard the language, identity and culture of the Bodos - the largest and the oldest tribes of North Eastern Region through his non-violent struggle within the values enshrined in the Constitution of the Country - stands as an exemplary journey of a leader who gave a new dimension to the collective history of the struggle for tribal emancipation in India.

In view of his outstanding contributions for the Bodo people in particular and to the tribals of the North Eastern Region in general, Hon'ble Speaker Sir, it is through your Chair that I appeal to the Government of India for conferring Bharat Ratna to Bodofa Upendranath Brahma.

I end by paying my tributes to the most respected universal Guru of Non-Violence and Peace, Father of our Nation Mahatma Gandhi whose lessons of Non-violence remains the lifeline in our quest for a Peaceful, Smart and Green Bodoland of the 21st Century.

Thank you.

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): I would like to lay my speech on the Motion of Thanks on President's Address.

Thank you very much for giving me the opportunity to express my views on the Motion of Thanks on the President's address and also my greetings to the newly elected members in this House. Special thanks to the beloved voters of Alathur who helped me to elect to this Lok Sabha I support this motion not because I and my party CPI (M) concur with the contents of the President's Address but only as a mark of respect for the Hon'ble President.

I wish to express my concerns and criticisms regarding the government's performance. While it is important to acknowledge the achievements and progress made by any government, it is equally important to hold them accountable for their actions and policies.

Hon'ble President said many things here especially about the growth of the country to become the third economic power in the world. Does this Government have a view on who should get the third position when it comes to the first position. When come to the hunger index India ranking is 111th place. In equality the place of our country is coming behind before our country was ruled by the British, In happiness index the place is on 126%. The country democracy, secularism, federalism and freedom are all are at risk. Now we are living in a world of Artificial Intelligence, but we still we can't free the people from caste and religion narrow mindedness.

I must address the issue of the Government's handling of the economy. While the President mentioned that India has become the fastest growing economy and has risen in the global rankings, it is crucial to note that economic growth alone does

not necessarily translate into improved living conditions for all citizens. The gap between the rich and the poor continues to widen, and the government's focus on big businesses and corporations often neglects the needs of the marginalized and vulnerable sections of society.

Furthermore, the President highlighted the government's efforts in the agricultural sector, such as the increase in Minimum Support Price (MSP) for Kharif crops and the establishment of storage facilities. However, the reality is that farmers across the country are still struggling with debt, low incomes, and lack of access to resources. The Government's policies have failed to address the root causes of agrarian distress and provide sustainable solutions for farmers. Another area of concern is the Government's approach towards social justice and inclusivity. While the President mentioned the empowerment of women, scheduled castes, scheduled tribes, and other marginalized communities, it is important to critically examine the impact of Government schemes and policies on these communities. Many of these initiatives have been marred by implementation challenges, corruption, and lack of transparency. The Government must do more to ensure that the benefits of these schemes reach the intended beneficiaries and truly uplift their lives.

Moreover, the President spoke about the Government's commitment to democracy and the electoral process. However, recent events have raised serious questions about the integrity of our democratic institutions. The use of electronic voting machines (EVMs) has been a subject of controversy and concern, with allegations of tampering and lack of transparency. It is Imperative that the Government addresses these concerns and restores faith in our electoral system. Toward the end, we could see the tall claims of setting up of All India Institute of Medical Sciences (AIIMSs) in the country whose number rose from 7 to 16 in the last decade. But even then, an AIIMS was not allotted to the State of Kerala, though the State Government made suitable available land, only to political vendetta against the ruling LDF Government there.

It is crystal clear that what guides this Government is political nepotism and skewed interest to make political gains with scant regard for the federal and democratic principles. So, all together the Hon'ble President failed to convince this august House about the progress her Government made over the years and made an unimpressive effort to defend the failures of it.

Yet, as expressed in the beginning, for the sake of political propriety, I support the motion with the amendments proposed and objections raised herewith.

श्री विजय कुमार हाँसदाक (राजमहल) **:** सभापति महोदया, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है ।

HON. CHAIRPERSON : Under which Rule?

SHRI VIJAY KUMAR HANSDAK : I want to raise a point of order under Rule 352. Our leader?s name was taken. हाई कोर्ट के द्वारा उनको बरी किया गया, उसके बाद उनको यहां पर भ्रष्टाचारी कहा जा रहा है । ? (व्यवधान) It should be expunged.

श्री विजय कुमार हाँसदाक **:** कोर्ट द्वारा उनको बेल मिला है और सीधे तौर पर कहा गया है कि उन पर आरोप तय नहीं होता है । ? (व्यवधान) ये उनको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, जबकि कोर्ट से उनको बेल मिला है ।

सभापति महोदया, इसको एक्सपंज करना होगा । ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: It will be deleted.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The name will be deleted.

Adv. Francis George.

ADV. FRANCIS GEORGE (KOTTAYAM): Madam, when our country is completing 75 years as a republic, we are fortunate to be present in this House and we have to be grateful to the people of India for giving us a chance to be Members of Parliament at a very critical and glorious time in the history of our country.

The President in her Address mentioned several things about what the Government is doing for the agriculture sector. I would like to tell the Government the basic demand of the farming community. The farmers are again on the agitation path. They are demanding not all these fancy things but a legal framework for minimum support price. Ever since the NDA Government came to power, the hon. Prime Minister has been promising that the Government will give MSP to the farmers under the C2+50% formula that has been recommended by the Swaminathan Commission. So far, the Government has not done anything about it. In the first agitation of farmers, almost 700 farmers gave their lives and now also, the agitation is going on. But the Government has prevented the farmers from

entering the Capital. Who are we to prevent the farmers of this country, who feed the country, to enter the Capital? The poet, Thiruvalluvar said:

?Uzhudhuntu vaazhvaare vaazhvaar matrellaam

Thozhudhuntu pinsel bavar?

The farmer, who tills the land, should be hailed. Instead of hailing them, we are despising them; we are ignoring them. We are not giving any consideration tothe basic demands of the farming community of this country.

15.54 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

I would like to quote one issue. My constituency of Kottayam is known as the rubber capital of India. The rubber farmers of this country have been reeling under price fall for the past twelve years but the Government did not invoke the basic safeguards duty when there are large-scale imports. To control the unabated large-scale imports of natural rubber, it is very good that the Commerce Ministry acts on it. There is a provision under the GATT. Under Article XIX (1a) of GATT 1994, if there is a large-scale import of a particular commodity affecting the economic situation of a particular area, like income of a particular section, we can invoke article 19 under the WTO regime. The Government always says that we are under the WTO dispensation and we cannot do anything about imports, but there is a particular provision saying that if there is income loss or job loss, the Government can rightfully invoke this particular section. The Government of India has not done anything about it. We are told that the DG of Foreign Trade proposed to extend the export obligation period of the DEPB passbook holders. In the case of the exporters, who export goods like natural rubber and make value added products, presently, the period is six months for them to export these commodities after value addition.

Now, the DGFPS recommended that it can be extended to 12 months. This will create serious problems not only for rubber farmers, but also for any other commodities. There will be large imports. These imports are done under duty free. This will create a glut in the market. This will cause price to fall. I do not have to tell the hon. Commerce Minister. It is going to affect 1.2 million rubber farmers of our country. ? (*Interruptions*) Sir, I will conclude within one minute. ? (*Interruptions*)

Sir, India is the only country where you cannot touch the wild animal even if it attacks, kills you and destroys your crop. There are rules world over prohibiting the same. There is a well-known scientific study which says that in a particular forest area, there is a term called carrying capacity. If the wild animals exceed the carrying capacity, they have to be culled and removed. India is the only country where it is not done. The poor farmers and the people, who live in the forest range, are being left at the mercy of the wild animals. Every day the wild animals are killing people and destroying crops. But nothing is being done by the Central Government to address the issue. Professor Madhav Gadgil has recommended that the Wildlife Protection Act should be scrapped. We do not say that. We only say that the particular provisions have to be amended, and there has to be a mechanism to cull these wild animals which destroy crops and kill people.

Sir, I am concluding.

SHRI DURAI VAIKO (TIRUCHIRAPPALLI): Hon. Speaker, Sir, I thank you for this opportunity to make this maiden address in this temple of democracy. I come from a State where faiths over the Lords Vishnu, Siva, Jesus and Allah co-exist with the rationalism of Thanthai Periyar; a State where social justice and secularism have shielded the oppressed and the downtrodden; a State wherein its people would rather die than live without self-respect and honour; a State where we have always stood united irrespective of caste, creed and religion just as our great King Veerapandiya Kattabomman fought alongside Veeran Sundaralingam, Vanthiyathevan and Thanathipathi Pillai against the British imperialism. I bring along with me the expectations and hope of more than a million people from my constituency, Trichy. I represent a small political Party but a Party and a leader with a big heart, that is, MDMK and Shri Vaikoji.

Sir, I would like to emphasise on certain issues that have not been given the due importance in the hon. President?s Speech. Though there are a thousand burning issues concerning my fellow citizens, I would like to use my maiden speech to highlight five important aspects concerning my country, State and constituency. The first one being revitalizing India's energy engineering powerhouse-Trichy. Trichy boasts a rich legacy as India's engineering powerhouse. Public sector giants like BHEL, Ordnance Factory, Golden Rock Railway Workshop, and HAPP have been the pillars of this success story. However, a concerning trend has emerged in recent years. Firstly, a decline in work orders for public sector units has impacted

the entire ecosystem. BHEL, for example, has seen a worrying 50 per cent drop in employment potential, mirroring a similar decline across other PSUs. This, in turn, has had a domino effect on ancillary MSMEs which rely heavily on BHEL's work orders. A once-thriving network of 600 MSMEs has shrunk to just 60, highlighting the human cost of this situation. In the past 10 years, the employment capacity of MSMEs has declined from 50,000 to a mere 10,000 in 2024. I request the Government to take necessary steps to revitalize the public sector units in my constituency. ? (*Interruptions*) Sir, please give me two minutes. This is my maiden speech. Secondly, I would like to emphasise the plight of the Tamil Nadu fishermen who have faced aggression and violence from the Sri Lankan Navy for more than three decades. I urge upon the Union Government, especially the hon. Prime Minister, Modi Ji and the hon. External Affairs Minister, Shri S. Jaishankar Ji, to take immediate steps to retrieve Katchatheevu or restore the rights of our fishermen in the traditional fishing areas by signing an MoU with the Sri Lankan Government.

-

16.00 hrs

श्री मनोज तिवारी (उत्तर-पूर्व दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है ।

महोदय, मैं इस सदन में तीसरी बार आया हूं और मैं दिल्ली में नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली की जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमें तीसरी बार चुनकर भेजा है । सिर्फ मुझे ही चुनकर नहीं भेजा है, बल्कि हमारी दिल्ली के सात की सात लोक सभा सीटों पर तीसरी बार चुनकर भेजा है ।

नरेन्द्र मोदी जी में वह विश्वास जनता ने दिखाया कि आज तक दिल्ली में किसी भी पार्टी के सात सांसद तीसरी बार जीतकर नहीं आए हैं, लेकिन हमारे आए हैं । मैं पूरी दिल्ली सहित अपनी लोक सभा के लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष जी, जब हम वर्ष 2014 में इस सदन में चुनकर आए थे, तब हम एक दूसरी दुनिया से आए थे । जिस समय हम सदन में घुसने जा रहे थे, तो मेरी नजर पड़ी कि देश का प्रधान मंत्री बनने जा रहा एक व्यक्ति, जिन सीढ़ियों से लोग चप्पल-जूते पहनकर जाते हैं, नरेन्द्र मोदी जी उन सीढ़ियों पर सिर झुकाकर माथा रख रहे हैं । हमारे जैसे लोग, जो किसी और दुनिया से राजनीति में आते हैं, उनके लिए एक बड़ा एग्ज़ाम्प्ल था । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं दूसरी बार वर्ष 2019 में संसद में आया तो मैंने देखा कि देश के प्रधान मंत्री ने सबसे पहले संविधान को माथा झुकाकर प्रणाम किया । वह दृश्य हमारे लिए और मैं समझता हूं कि मेरे सभी साथियों के लिए, हाथ में संविधान लेना भी ठीक है, लेकिन संविधान लहराना और संविधान की पूजा करने में अंतर है । हमने नरेन्द्र मोदी जी को संविधान की पूजा करते हुए देखा है । इसलिए मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के साथ ही साथ दिल्ली की भी कुछ बातें करूंगा ।

दिल्ली के ही सौभाग्य के बारे में बताना चाहूंगा । जब कोई द्वारका एक्सप्रेस-वे पर गाड़ी चलाता होगा, तब उसको समझ में आता होगा कि सरकार क्या होती है और कैसे लोगों का काम होता है । एनएच-24 पर जाते होंगे, आज दिल्ली मेरठ तक चली गयी है । आज लोग मेरठ से दिल्ली में काम करने आते हैं और 35 से 40 मिनट में पहुंच जाते हैं । इसमें हम सभी को गर्व होना चाहिए । हमें गर्व इसलिए होना चाहिए कि देश के 4 करोड़ 22 लाख लोगों को पहली बार घर मिला है । हमें गर्व इसलिए होना चाहिए कि 12 करोड़ घरों में टॉयलेट बन गए हैं । मैं गांव का आदमी हूं और हमारी माँ ने गाँव में काम करने वाली महिला के लिए 20000 रुपये की मांग कर दी थीं । हमारी माई एक दिन हम से कहती है- ए मनोज*!* तू जानतरा, झुरी तिवारी के मेहरारू के घर मिल गइल, मोदी जी घर देले बाड़े ।

अध्यक्ष जी, हम जानते हैं कि गांवों के घरों में टॉयलेट न होने का क्या दंश होता था । हम लोग साइकिल से जाते थे तो सड़क पर महिलाएं खड़ी हो जाती थीं । अगर उस दंश को किसी ने दूर किया है तो वे नरेन्द्र मोदी जी हैं, हमारी सरकार है तो हम इस पर क्यों न गर्व करें? 13 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया है । दिल्ली के घरों में पाइप से गैस जा रही है । पाइप से गैस जा रही है और दिल्ली में बैठी हुई एक आम आदमी पार्टी की सरकार नल से जल तक नहीं दे पा रही है । हम यह भी दंश इसी दिल्ली में देख रहे हैं ।

अध्यक्ष जी, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि आप कभी भारत मंडपम देखिए । मेरे विपक्ष के साथी लोग, आप वहां पर जाइए । आप जब जाएंगे तो आपको गर्व होगा ।? (व्यवधान) हाँ दादा, गर्व होता है और होगा । आप कभी यशोभूमि को देखिए । आप कभी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्टडी सेन्टर को देखिए । इसी दिल्ली में जिस बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को अंतिम क्रिया के लिए जमीन नहीं दी गई, बुरा मत मानना, नाराज मत होना, लेकिन उसी दिल्ली के हृदय में नरेन्द्र मोदी जी ने 5 एकड़ में बाबा साहेब का स्टडी सेन्टर बनाकर दिया है । यह होता है सम्मान ? संविधान के प्रति और संविधान को बनाने वालों के प्रति ।

मुझे बहुत वेदना के साथ कहना पड़ रहा है । टीएमसी के हमारे एक सांसद, मेरे एक प्रिय साथी हैं । आज आपने एक एक्ट्रेस के नाम पर क्या बोल दिया?? (व्यवधान) कल्याण दा, आपको इस तरह से महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए ।? (व्यवधान) मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप एक्ट्रेस को सिर्फ एक देखने वाली वस्तु मत समझिए । यह हम आपसे प्रार्थना करते हैं ।? (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मुझे गर्व तब होना चाहिए? (व्यवधान) नहीं, हम गुमराह नहीं कर रहे हैं ।? (व्यवधान) दादा, ऐसा नहीं करना चाहिए ।? (व्यवधान) देश में 70 साल के बुजुर्गों को अब वृद्धाश्रम भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।? (व्यवधान) हमें वंदे भारत जैसी ट्रेन में बैठकर गर्व होता है । हमें गर्व होता है, जब 70 साल के बुजुर्ग को अब किसी वृद्धाश्रम में भेजने की जरूरत नहीं पड़ती । अब उसका इलाज करवाने के लिए मोदी सरकार खड़ी है । जब भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जाती है तो हमें गर्व होना चाहिए । इसलिए मैं अपने सभी साथियों से प्रार्थना करता हूँ? (व्यवधान) हाँ, गाना तो गाते हैं दादा ।? (व्यवधान) आज जब हम यहां से निकलते हैं तो अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगाने का जो अभियान शुरू हुआ है, उसमें हम सबको साथ देना चाहिए । चलिए मिलकर माँ के नाम से एक पेड़ लगाते हैं ।? (व्यवधान) दादा, माँ के नाम से पेड़ लगा दीजिए ।? (व्यवधान) माँ के नाम से एक पेड़ लगाइए । ?(व्यवधान) अध्यक्ष जी, इस देश की जनता ने नरेन्द्र मोदी सरकार को तीसरी बार, चुन कर भेजा है ।?(व्यवधान) अध्यक्ष जी, मैं दो पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं । नरेन्द्र मोदी जी को तीसरी बार देश ने ऐसे ही नहीं चुना है । हमारे संस्कृत में एक श्लोक है :-

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ।

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम । ।

नरेन्द्र मोदी जी की आयु बढ़े, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की भी आयु बढ़े, यह इस देश की जनता चाहती है । आपने हमे बोलने का मौका दिया । मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को बहुत ही उत्तम मानता हूं, समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं ।

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** नहीं, यह तरीका ठीक नहीं है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** प्लीज, आप बैठिए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, माननीय प्रधान मंत्री जी बोलेंगे । मैंने मणिपुर के एक माननीय सदस्य को पहले ही बोलने का मौका दे दिया है ।

?(व्यवधान)

श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर (खीरी) **:** माननीय, राष्ट्रपति महोदया का आज का भाषण सरकार की गाल बजाने की बीमारी से मुक्त नहीं हो सका । जिन उपलब्धियां के दम पर 400 पार का नारा देकर चुनावी मैदान में उतरी सरकार को देश की जनता ने निकाल दिया और ऐतिहासिक निर्णय दिया| यह अभिभाषण उस जनमत की उपेक्षा करता दिख रहा है । सरकार के अहंकार की बीमारी अभी दूर नहीं हुई है अभिभाषण के तथ्यों पर माननीय सदस्यगणों में काफी कुछ कहा है । उन सभी विपक्षी दलों के माननीय सदस्यों से सहमति रखते हुए मुझे इस भाषण में बहुत महत्वपूर्ण विषयों को जानबूझकर छोड़ देने की मंशा दिख रही है । पूरा 2024 का चुनाव सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा के नाम पर लड़ा गया| सत्ता ने सबका साथ और सबका विकास का नारा दिया लेकिन भारत दुनिया के उन चंद देशों में है जो गत 13 वर्षों से अपनी जनगणना को सार्वजनिक नहीं कर पा रहा है । जातीय जनगणना की अभिभाषण में चर्चा तक नहीं थी । बिना आकड़ों के, बिना जनता के सामाजिक और आर्थिक स्तर को जाने यह सरकार किस प्रकार से संसाधनों का वितरण कर सकेगी| इस पर खामोशी है सत्ता में हिस्सेदारी की भूख समाज के अंतिम छोर तक पहुंच चुकी है और सत्ता में भागीदारी की गारंटी सिर्फ संविधान देता है लेकिन इसके लिए जरूरी है जाति आधारित सामाजिक आर्थिक जनगणना बिहार में जातिगत जनगणना ने सार्थक बस को जन्म दिया लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर चुप्पी साधकर जातिगत जनगणना की आवाज को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की ।

यह सरकार सिविल सोसाइटी किसान आंदोलन और विरोध के स्वरूप को बड़ी ताकत से दबाती है और संविधान का उन्हें आंदोलन जीवी कहकर उपहासस उड़ाती है और खुद छोटे से छोटे कार्यकर्म को उत्सव का स्वरूप देकर विज्ञापन और प्रचार के दम पर जन समस्याओं को भुनाती रही है । इस उत्सवजीवी सरकार से संवेदना की अपेक्षा व्यर्थ है । मणिपुर की घटनाओं पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा झेल रही सरकार ने महिलाओं के निर्वस्त्र करने की शर्मनाक घटना को दबाने के लिए महिला आरक्षण बिल पूर्व विचार करके आनन फानन में विशेष सत्र बुलाया था, लेकिन माननीय राष्ट्रपति के भाषण में इस महत्वपूर्ण मुद्दे का जिक्र तक नहीं है । छात्रों

की रोजगार की उम्मीदें धूल में मिल चुकी है सरकार के कार्यकाल में देश भर में 40 से ज्यादा पर्चा लीक की घटना से लगता है यह सरकार की मनसा रोजगार देने की है ही नहीं । नौकरी भर्ती के विज्ञापनों में युवाओं में उम्मीद जगाना और फिर उन्हें पकोड़े तलने में भी सम्मान ढूंढना एक शातिर अंदाज रहा है| रोजगार की समस्या को हासिये पर डालने की आज कोई भी परीक्षा पारदर्शी नहीं रही । परीक्षा माफिया का जन्म इस सरकार के कार्यकाल में हुआ है इसी अभिभाषण में परीक्षा लीक होने पर कोई बात नहीं की गई है । हमने समाजवादी विचारों और अखिलेश जी के नेतृत्व में एक सर्व धर्म समभाव और बराबरी पर आधारित समाज की संरचना को बनाना सिखा है । माननीय राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण सामाजिक न्याय सद्भाव और सोहार्द के सरोकारों से कोसों दूर है, मैं इसका विरोध करती हूं ।

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : सर्वप्रथम मैं 18 वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर पुनः निर्वाचित होने पर अपनी ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ । साथ ही साथ मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को भी बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता का विश्वास जीतकर उनका प्रतिनिधित्व करने का अवसर पाया है । माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों एवं आने वाले वर्षों में किए जाने वाले कार्यों का एक दस्तावेज होता है, उसकी रूप रेखा होती हैं । राष्ट्रपति जी के भाषण से यह परिलक्षित होता है कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए सरकार के साथ-साथ इस देश की जनता संकल्पित है । हाल ही में सम्पन्न हुए वर्ष 2024 का लोकसभा कई मायने में विशिष्ट रहा हैः- देशवासियों ने लगातार तीसरी बार स्पष्ट बहुमत से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (एन०डी०ए०) की स्थिर सरकार बनायी है । 2024 का यह चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णय पर विश्वास का चुनाव रहा है । यह चुनाव 64 करोड़ रिकार्ड मतदान का रहा है ।

राष्ट्रपति जी ने सुधार (Reform) प्रदर्शन (Perform) और परिवर्तन (Transform) पर जोर देते हुए भारत की आर्थिक उपलब्धियों का उल्लेख किया जिसमें इसे विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में बदलने का श्रेय दिया । उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में, भारत 11 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से उपर उठकर 5 वीं अर्थव्यवस्था बन गया है एवं तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कृत संकल्पित है । भारत अकेले वैश्विक आर्थिक वृद्धि में 15 प्रतिशत का योगदान दे रहा है ।

माननीय राष्ट्रपति जी ने यह भी बताया कि सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों विनिर्माण, सेवाएँ, और कृषि को समान महत्व दे रही है । PLI schemes और कारोबार में सुगमता (Ease of Doing Business) उपायों ने बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसरों की वृद्धि में योगदान दिया है । किसानों को उनकी छोटी-मोटी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 3,20,000 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई है । अपने नए कार्यकाल के प्रारंभिक दिनों में ही, सरकार ने किसानों को ₹20,000 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की है । सरकार ने खरीफ फसलों के लिए न्यनूतम समर्थन मूल्य (MSP) में रिकॉर्ड वृद्धि भी की है । इसके साथ ही, सरकार एक बड़े पैमाने पर किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और PACS जैसी सहकारी संगठनों का नेटवर्क बना रही है । राष्ट्रपति जी ने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य हरित युग का होगा और सरकार हरित उद्योगों में अग्रणी भूमिका निभा रही है, जिससे हरित रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही है ।

राष्ट्रपति जी ने सरकार द्वारा किए गए कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों और पहलों को उजागर किया । भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनकर उभरा है, जो अप्रैल 2014 में 209 एयरलाइन रूट्स से

बढ़कर अप्रैल 2024 तक 605 रूट्स तक पहुँच गया है । इस विस्तार से देश के टियर-2 और टियर-3 शहरों को विशेष रूप से लाभ हुआ है । पिछले 10 वर्षों में मेट्रो सेवा भी 21 शहरों तक पहुंच चुकी है । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, सरकार ने पिछले दशक में 3,80,000 किलोमीटर से अधिक गांवों की सड़कों का सफलता पूर्वक निर्माण किया है, जिससे ग्रामीण संपर्क में उल्लखेनीय सुधार हुआ है । इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे के विकास में भी उल्लखेनीय प्रगति हुई है, और निर्माण की गति दोगुनी से अधिक हो गई है ।

एक महत्वपूर्ण आर्थिक पहल के अंतर्गत, असम में 27,000 करोड़ के निवेश से एक सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जा रहा है । इस पहल का उद्देश्य उत्तर-पूर्व को देश में निर्मित सेमीकंडक्टर्स के हब के रूप में स्थापित करना है, जो 'मेक इन इंडिया' उत्पादों को बढ़ावा देने की दृष्टि से मेल खाता है ।

माननीय राष्ट्रपति जी नें भारत सरकार के स्त्री-नेतृत्वित विकास और सशक्तिकरण (Women led development & empowerment) के प्रति स्थिर प्रतिबद्धता को उजागर किया, जो राष्ट्र की प्रगति में एक नये युग की निशानी है । लंबे समय से बढ़ती मांग को पहचानते हुए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रावधान से लोक सभा और विधान सभा में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करके महिलाओं को सशक्त किया गया है ।

एक व्यापक अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है 3 करोड़ महिलाओं को "लाखपति दीदी" बनाना, स्व-सहायता समूहों को अधिक वित्तीय सहायता के साथ समर्थन देकर । इस पहल का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक कौशल और अवसरों में सुधार करने के लिए नहीं, बल्कि समाज में महिलाओं के स्थान और सम्मान को भी बढ़ाने के लिए भी डिजाइन किया गया है । नमो ड्रोन दीदी योजना इस उद्देश्य में एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें कई स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन दिया जा रहा है और उन्हें ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है । इस नवाचारी पहल से न केवल उनकी क्षमताओं में सुधार हो रहा है, बल्कि उन्हें तकनीकी प्रगति में शामिल किया जा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को भी बढ़ाया जा रहा है । पिछले 10 वर्षों में, 4 करोड़ पीएम आवास घरों में अधिकांश महिला लाभार्थियों को आवंटित किए गए है । इसके अतिरिक्त, सरकार ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कृषि सखी पहल शुरू की है अब तक, स्व-सहायता समूहों से 30 हजार महिलाओं को कृषि सखी प्रमाण पत्र प्रदान किए गए है, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण कृषि कौशल और संसाधनों से सशक्त किया गया है ।

राष्ट्रपति जी ने समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन स्तर और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के लिए कई परिवर्तनकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला । इनमें से एक प्रमुख योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है जिसका लक्ष्य बिजली के बिलों को शून्य करना और शेष बिजली को बेचकर आय प्राप्त करना है । इस पहल में घरों के छतों पर सोलर पनैल लगाना शामिल है । जिससे प्रत्येक परिवार को सरकार से 78,000 तक की सहायता मिलेगी ।

राष्ट्रपति जी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार की योजनाओं को सही दृष्टिकोण से लागू करने के कारण 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर लाया गया है । कोरोना महामारी के कठिन समय में सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन प्रदान करने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की ।

राष्ट्रपति जी ने कहा कि 24,000 करोड़ से अधिक के आवंटन के साथ पीएम जनमन योजना सबसे वंचित जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए समर्पित है । यह उनकी उन्नति और सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है । वंचित समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने पीएम-सूरूज

पोर्टल लॉन्च किया है, जो सॉफ्ट लोन तक पहुंच को आसान बनाता है । इस पहल का उद्देश्य कमजोर समुदायों के बीच रोजगार के अवसर पैदा करना और आर्थिक स्वतंत्रता में सुधार करना है । समावेशिता की दिशा में एक सराहनीय प्रयास करते हुए, सरकार दिव्यांगों के लिए सस्ती स्वदेशी सहायक उपकरण विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित करर रही है । इस पहल का उद्येश्य देश भर में दिव्यांग व्यक्तियों की पहुँच और समर्थन को बढ़ाता है । इसके अतिरिक्त, पीएम स्वनिधि का दायरा ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित किया जाएगा, जो कि स्ट्रीट वेंडरों को सहायता के अलावा इन क्षत्रों में आर्थिक अवसरों को और मजबूती प्रदान करेगा ।

सरकार की स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए, राष्ट्रपति जी ने कहा कि सरकार, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 55 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है । इस योजना के अंतर्गत अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बजुर्गों को कवर किया जाएगा । देश में 25,000 जन औषधि केंद्रों की स्थापना भी प्रगति पर है ।

राष्ट्रपति जी ने रेखांकित किया कि भारत अब वैश्विक रूप से तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है । राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने 'मेरा युवा भारत (MY भारत)' अभियान की शुरुआत की है जिसमें 1.5 करोड़ से अधिक युवा रजिस्ट्रेशन कर चुके है । इस पहल का उद्दश्य युवाओं में नेतृत्व कौशल विकसित करना और सेवा की भावना को प्रोत्साहित करना है । राष्ट्रपति जी ने केन्द्र सरकार के प्रयासों की सराहना की । इसके साथ ही युवा भारतीय खिलाड़ियों द्वारा वैश्विक मंचों पर जीते गए रिकॉर्ड संख्या मेडल्स का भी जिक्र किया । इसके अतिरिक्त, भारतीय ओलंपिक संघ ने 2036 ओलंपिक खेलों को आयोजित करने की तैयारी कर रहा है ।

सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के अंतर्गत शरणार्थियों को नागरिकता देने की भी शुरुआत की है, जिससे विभाजन से प्रभावित कई परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित हो रहा है ।

राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा कि भविष्य का निर्माण करते हुए सरकार भारतीय संस्कृति के वैभव और विरासत को पुनःस्थापित कर रही है । हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय के भव्य परिसर के रूप में इसमें एक नया अध्याय जोड़ा गया है । नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में भारत के गौरवशाली अतीत का प्रमाण था । राष्ट्रपति जी को विश्वास है कि नया नालंदा विश्वविद्यालय भारत को वैश्विक ज्ञान केंद्र बनाने में मदद करेगा । उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि केन्द्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना शुरू किया । इसके अलावा, 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना से काशी तमिल संगम और सौराष्ट्र तमिल संगम जैसे त्योहारों को मनाने की परंपरा भी सरकार ने शुरू की है ।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र प्रगति को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति जी ने इसके दुरुपयोग की संभावना को स्वीकार किया, तथा ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए रूप रेखाएँ स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्वपूर्ण महत्व पर बल दिया । भारत ने वैश्विक मंचों पर इन चिताओं को सक्रिय रूप से व्यक्त किया है, तथा इन चुनौतयों का मुकाबला करने और नए समाधान खोजने के लिए सामूहिक प्रयासों की सराहना की है ।

राष्ट्रपति जी ने वैश्विक मित्र (विश्व-बंधु) के रूप में भारत की उभरती भूमिका को रेखांकित किया, और इसका श्रेय मानव-केंद्रित दृष्टिकोण को दिया । भारत ने अपनी जी-20 अध्यक्षता के दौरान कई मुद्दो पर दुनिया को एकजुट किया । इसी दौरान अफ्रीकी संघ को जी-20 का स्थायी सदस्य बनाया गया ।

केन्द्र सरकार मोटे अनाज 'श्री अन्न' को सुपर फूड के रूप में दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने का अभियान भी चला रही है । भारत की पहल पर, वर्ष 2023 को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया गया ।

भारत ने संकट के समय सक्रिय प्रतिक्रिया देनेवाले राष्ट्र के रूप में अंतरराष्ट्रीय विश्वास हासिल किया है और ग्लोबल साउथ के लिए एक मजबूत आवाज बनकर उभरा है । चाहे COVID-19 महामारी का प्रबंधन हो, प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना हो, या संघर्षों के दौरान शांति के लिए आवाज उठानी हो, भारत ने मानवता की सुरक्षा और वैश्विक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयासों में लगातार नेतृत्व किया है ।

माननीय राष्ट्रपति जी ने भारत के संविधान के प्रति अपनी सरकार के गहन सम्मान पर जोर देते हुए कहा कि यह केवल शासन संबंधी दस्तावेज नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना की आधारशिला है । जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की पहल की, जिसका उद्देश्य संविधान को जन चेतना में गहराई से समाहित करना है । इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति जी ने जम्मू और कश्मीर में संविधान के पूर्ण एकीकरण का उल्लेख किया, जो पहले अनुच्छेद 370 के कारण अलग-अलग परिस्थितियों में शासित था ।

पिछले दशक के परिवर्तनकारी सुधार और नए आत्मविश्वास पर विचार करते हुए, राष्ट्रपति जी ने एक विकसित राष्ट्र बनने के भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक नई गति की बात की । उन्होंने दोहराया कि यह आकांक्षा हर नागरिक की है और इस मार्ग पर आने वाली बाधाओं को दूर करने में सामूहिक जिम्मदारी पर जोर दिया ।

राष्ट्रपति जी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि 21 वीं सदी भारत की है, उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव आने वाली सदियों तक रहगो । उन्होंने सभी नागरिकों से अपने कर्तर्तयों के प्रति पूरी तरह समर्पित होने का आग्रह करते हुए राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत के भाग्य को पूरा करने में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया ।

विगत 10 वर्षों में देश में 7 नए IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 नए एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं । सरकार इन संस्थानों को और मजबूत बनाकर आवश्यकता के अनुसार इनकी संख्या को भी बढ़ाएगी । सरकार एक डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में भी काम कर रही है । सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले । सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है । इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है । हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है । इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही हैं । इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है । संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है । सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया, सभी में बड़े सुधार करने की दिशा में काम कर रही है ।

दूसरे, पारदर्शिता और ठोस सुधार सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने ISRO के पूर्व अध्यक्ष और IIT कानपुर के BoG के अध्यक्ष, डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की है । यह समिति परीक्षा प्रक्रिया को सुधारने, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को बढ़ाने और NTA का पुनर्गठन करने के लिए व्यापक सिफारिशें करने का कार्य करेगी । तीसरे, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को NEET (UG) परीक्षा 2024 में कथित अनियमितताओं की जांच सौंपी गई है, जिसने बिहार में NTA टीम की कमियों की पहचान की है ।

माननीय शिक्षा मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि NEET की घटना एक संस्थागत विफलता को उजागर करती है, न कि सरकार की विफलता को । यह एक अलग-थलग घटना है, और परीक्षा रद्द करने की विपक्ष की मांग हजारों छात्रों के करियर को खतरे में डालती है । ऐसी मांग अनुचित और बेबुनियाद है ।

केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि परीक्षाएं सुरक्षित रूप से आयोजित की जाएं और योग्य छात्र इससे लाभान्वित हों । हमारा दृष्टिकोण सक्रिय और सतत सुधार पर केंद्रित है । यूपीए युग के दौरान, जब ऐसी घटनाओं के प्रति प्रतिक्रियाएं सीमित सुधारों और सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ होती थीं, हमने 2014 से इन घटनाओं की आवृत्ति को कम करने के लिए निरंतर काम किया है । हालांकि, विपक्ष NEET पेपर लीक जैसे संवेदनशील मुद्दों का राजनीतिकरण कर रहा है, छात्रों का उपयोग करके सरकार पर हमले कर रहा है । वे आसानी से भूल जाते हैं कि कांग्रेस शासन के दौरान राजस्थान में 14 पेपर लीक की घटनाएं हुईं, जिससे 40 लाख छात्रों के करियर प्रभावित हुए । राजस्थान पेपर लीक की राजधानी के रूप में बदनाम था । पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों में भी इसी तरह की समस्याएं थीं, जहां कई पेपर लीक की घटनाएं हुईं, लेकिन राज्य सरकारों ने इन्हें संबोधित करने के लिए सक्रिय कदम नहीं उठाए ।

इसके विपरीत, भाजपा शासित राज्य ऐसी घटनाओं का शीघ्र और प्रभावी ढंग से छात्रों के कल्याण के लिए जवाब देते हैं । एक प्रमुख उदाहरण उत्तर प्रदेश है, जहां योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा और आरओ-एआरओ परीक्षा के दौरान पेपर लीक के बाद उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 पेश करने जा रही है । नए कानून में पेपर लीक और संबंधित गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सबसे सख्त कार्यवाही शामिल होगी, जिसमें भारी जुर्माना, बुलडोजर कार्रवाई और यहां तक कि जेल की सजा भी शामिल होगी ।

छात्रों के लिए हमारी प्रतिबद्धताएं इतनी अधिक हैं कि हमारी सरकार ने इस साल फरवरी में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 लाया, जिसका उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC) रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं और NTA द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना है । इसमें नकल रोकने के लिए तीन से पांच साल की न्यूनतम कैद का प्रावधान है और संगठित अपराधों में शामिल व्यक्तियों को पांच से 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना होगा । केवल हमारी सरकार इतना दूर तक सोच सकती है, कोई और इतना साहस और इच्छा नहीं रखता था कि वह आगे आए और ऐसे कदम उठाए । वे बस पीछे बैठकर हमारी आलोचना करते रहे । यह परीक्षाओं की अखंडता को सुरक्षित करने और हमारे छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि हमारे सक्रिय शासन और विपक्ष के प्रतिक्रियावादी रुख के बीच का अंतर । हम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर काम करते रहेंगे कि कोई भी छात्र के करियर को ऐसे कदाचारों से खतरे में न डालें । केन्द्र सरकार, जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को सबसे सहज तरीके से लागू किया है, देश में अंतिम मील शैक्षिक सुधार और पूरी तरह से स्वच्छ परीक्षा तंत्र लाने के लिए प्रतिबद्ध है ।

आने वाले वर्षों में केन्द्र की NDA सरकार और संसद क्या निर्णय लेती हैं, क्या नीतियां बनाती हैं, इस पर पूरे विश्व की नजर है । इस अनुकूल समय का अधिक से अधिक लाभ देश को मिले, ये दायित्व सरकार के साथ-साथ हम सभी संसद सदस्यों का भी है । जब संसद सुचारू रूप से चलती है, जब यहां स्वस्थ चर्चा परिचर्चा होती है, जब दूरगामी निर्णय होते हैं, तब लोगों का विश्वास सिर्फ सरकार ही नहीं पूरी व्यवस्था पर बनता है ।

अंत में मै माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा अपने अभिभाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक विकसित भारत के संकल्पों एवं स्वर्णिम भारत के सपने को साकार करने के लिए लायी गयी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का स्वागत और पुरजोर समर्थन करता हूं ।

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह **(**अकबरपुर**) :** राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए आभार । मैं लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर माननीय अध्यक्ष को बधाई देते हूए उनका अभिनंदन करता हूं ।

सर्वप्रथम मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में देश ने एक बार फिर एनडीए को जनादेश दिया है और तीसरी बार हमारी सरकार बनी है । हमारे प्रधानमंत्री जी ने सरकार बनाने के बाद सबसे पहला कार्य देश के किसानों के हित में किया है, आते ही उन्होंने सर्वप्रथम किसान के सम्मान में किसान सम्मान निधि को भेजने का कार्य किया है ।

पिछले 10 वर्षों से देश में हमारी सरकार ने इसके चहुमुखी विकास का कार्य करने के पूरे लगन से कोशिश की है । इन्हीं कोशिशों के परिणाम स्वरूप आज हम विकास के पथ पर अग्रसर हैं । आज देश में सड़को का जाल बिछाया जा चुका है तथा यहां पर आज विश्वस्तरीय सड़कों पर आवागमन से देश की परिवहन व्यवस्था मजबूत हुई है । हमारी लोकसभा क्षेत्र में रिंग रोड़ का निर्माण हो रहा है । आज हमारी देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की और अग्रसर है । वैश्विक विकास में आज हमारे देश के योगदान 15% से अधिक तथा इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है । हमारे देश में आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको का मुनाफा सर्वकालिक सर्वाधिक है तथा साथ ही बैंको का नान परफॉर्मिंग असेंट अब बहुत कम हो गई है । आज हमारा जीएसटी कलेक्शन बड़ी मजबूती से प्रतिमाह बढ़ रहा है । यह हमारी मजबूत होती अर्थव्यवस्था का प्रमाण है ।

हमारी सरकार देश के गरीब व कमजोर लोगों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है आज हम 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम मुक्त राशन प्रदान कर रहे हैं ।

किसानो की बढ़ोतरी के लिए सरकार किसान उत्पादक (F.P.O) संगठनों और सहकारी संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क बना रही है इससे बिचौलियों की समस्या से निजात मिलेगी । सरकार ने खरीफ की फसलों को एम. एस.पी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है । दलहन और तिलहन पर आयात निर्भरता कम करने के लिए सरकार किसानों की सहायता करने को प्रतिबद्ध है ।

आज भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मजबूत कदम उठा चुका है तथा हम फाइटर एयरक्राफ्ट का स्वदेशी निर्माण शुरू कर चुके हैं । मेरा सोभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से डिफेंस कारिडोर का निर्माण हो रहा है । देश में सहकारी क्षेत्र में दुनिया कि सबसे बड़ी भण्डारण क्षमता बनाने पर काम शुरू हो गया है । भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन बाजार है इसका सीधा फायदा हमारे देश मे छोटे और मंजुले शहरों को प्राप्त हो रहा है । पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 10 वर्षों में 3.8 लाख किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़को का निर्माण किया गया है । पिछले 10 वर्षों में 21 शहरों में मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू हुआ है तथा वहां पर मेट्रो का परिचालन भी शुरू हो गया है । पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों के निर्माण को स्वीकृत प्रदान की गई है । शिक्षा स्वास्थ्य ऊर्जा खेल तथा उन महत्वचपूर्ण क्षेत्रों में हमारी सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किया है तथा इन क्षेत्रों के विकास उन्नयन के लिए हम कटिबद हैं ।

श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद (संत कबीर नगर) **:** मैं उत्तर प्रदेश के 62 संत कबीर नगर से 18 वीं लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के मौके पर बोलने का समय चाहता था और सर्वप्रथम अध्यक्ष जी को लोक सभा मे अध्यक्ष बनने पर ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे जैसे अति पिछड़ी जाति को टिकट देकर भारत के सबसे बड़ी पंचायत में जाने का अवसर दिया जिसके बाद में लोकसभा 62 संत कबीर नगर की जनता के हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि भारत भारी मतों से अपना कीमती बहुमूल्य वोट देकर अपने बेटे भाई

को जितवा कर भेजने का काम किया । मैं जिस समाज से आता हूं मैं निषाद समाज से आता हूं जो हमारा समाज का पुस्तैनी धंधा नदियों पर नाव चलाना, मत्स्य पालन से अपनी जीविका चलाना था । नदियों पर पुल बन गए । मत्स्य पालन को भी मेरे अधिकार से छीन लिया गया छीनकर बिचौलियों को दे दिया गया तथा है लगान को राज्य सरकार ने इतना बढ़ा दिया कि मेरे निषाद समुदाय का व्यक्ति मत्स्य पालन नहीं कर सकता । मेरे निषाद समुदाय के लोग देश में तमाम प्रदेशों में अनुसूचित जाति में है जैसे कि दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, अनुसूचित जाति में है । मेरे उत्तर प्रदेश में जब-जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तब-तब अनुसूचित जाति में करने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा लेकिन केंद्र की सरकारों ने अनुसूचित जाति में शामिल नहीं करने का काम किया ऐसी दशा में आपके माध्यम से सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर निषाद समाज को अनुसुचित जाति का दर्जा नहीं दिया तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा में आधे से ज्यादा सीटें हारे हैं आने वाले 2027 के चुनाव में निषाद समाज उत्तर प्रदेश की सरकार खत्म करके ही चैन की सांस लेगा । मेरी लोकसभा बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है सड़कों का अभाव है जो सड़कों के खस्ता हाल है सड़क की जगह सिर्फ गड्ढे हैं । मेरा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, नदियों का बांधों का मरम्मत नहीं हुआ है यह जर्जर हो गई है । मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तत्काल बांधों को मरम्मत करने हेतु राज्य सरकार व केंद्र सरकार को तिस्तारण निर्देशित करें कि बाढ़ को देखते हुए जन सामान्य की समस्या को फिर निस्तारण करने का कार्य करें । मेरे लोकसभा में मेडिकल कॉलेज नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, इसलिए सरकार से आग्रह है कि यहां पर आईआईटी कॉलेज व नर्सिंग कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करने का कष्ट करेंगे जिससे संत कबीर नगर क्षेत्र के बच्चों का भविष्य में सुधार होगा ।

धन्यवाद ।

श्री आलोक शर्मा **(**भोपाल**) :** 18 वीं लोक सभा में राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण का मैं समर्थन करता हूँ । साथ ही इस अभिभाषण से यह स्पष्ट होता है कि देश एक नवीन दिशा की तरफ अग्रसर हो रहा है । भारत, दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत लोकतंत्र है । हमें लोकतंत्र की जननी कहा जाता है । पिछले 10 वर्षों में सरकार ने हर क्षेत्र में प्रगति और सुशासन के संकल्प के साथ कदम आगे बढ़ाए है । इन 10 वर्षों के सीमित कार्यकाल में अनेकों उपलब्धियां हासिल करते हुए कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं ।

मैं कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस की सरकार द्वारा लागू किया गया आपातकाल भारत के संविधान पर सीधा हमला था । यह भारत के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है । इस दौरान जनता और प्रेस की आजादी को भी कुचल दिया गया था । देश की सुरक्षा और प्रगति के लिए हमें इन असंवैधानिक निर्णयों से सबक लेते हुए आगे बढ़ना होगा । पिछले दस वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था पहले से काफी सुदृढ हुई है । रिफॉर्म, परफार्म और ट्रांसफार्म के हमारे संकल्प से हुई अभूतपूर्व वृद्धि से भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था बन गया हैं । महिला सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम बड़ा माध्यम बन गया है । महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए आत्मनिर्भर बन रही हैं । सरकारी योजनाओं के लाभ से आज करोड़ों बहनों के जीवन स्तर में बदलाव आया है । माननीय महोदय, आज का भारत चुनौतियों का सामना करने के लिए नहीं बल्कि चुनौतियों का समाधान करने के लिए तत्पर है । और यही वजह है कि आज दुनिया भर की निगाहें हमारी ओर लगी हैं । मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल और सर्विसेज के क्षेत्र में देश भर में बृद्धि हुई है । यही वजह है कि दूसरे देश हमारे यहां निवेश करने के लिए लालायित हैं । जो काम पिछले 60 वर्षों में देश में नहीं हुए वे पिछले 10 वर्षों में सरकार ने कर दिखाए । सरकार ने 7 नए आईआईटी, 16 ट्रिपल आईटी, 7 आईआईएम, 15 नए एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज और 390

विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं । अब आगे इन संस्थाओं को और मजबूत बनाया जाएगा । जिससे जनता को सीधा लाभ मिले ।

पिछले 10 वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती से काम किया गया है । गांव को में कृषि आधारित उद्योग, डेयरी, फिशरीज आधारित उद्योगों का विस्तार किया गया है । सहकारिता को प्राथमिकता देकर इसे जुड़े कार्यों को विस्तार दिया गया है । अनाजों के भंडारण की व्यवस्था पहले से काफी मजबूत हुई है । पिछले दस वर्षों में देश के 21 शहरों में मेट्रो की सुविधा पहुंची है । मेरे संसदीय क्षेत्र भोपाल को मेट्रो की सुविधा भाजपा की सरकार में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में मिली है । मैं भोपाल लोकसभा की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ । इसी प्रकार हमारे देश में हवाई यात्राओं का विस्तार हुआ है । ट्रेनों की कनेक्टिविटी बड़ी है । यही नहीं नॉर्थ ईस्ट में भी सरकार ने अभूतपूर्व विकास के काम किए हैं ।

विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जबकि देश के गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसान सशक्त बनेंगे । सरकार इसी संकल्प को लेकर निरंतर आगे बढ़ रही है । हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है । उनके हितार्थ अनेकों योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिसमें हर गरीब को फ्री खाद्यान्न योजना भी शामिल है । बड़ी और खास बात है कि देश के जनमानस ने हमारी नीति, नीयत और निष्ठा पर भरोसा जताते हुए लगातार तीसरी बार सरकार चलाने का अवसर दिया है ।

विपक्ष यदि अनावश्यक विघ्न पैदा न करे, सहयोग की भावना रखे तो आने वाले पांच वर्षों में सरकार गरीब कल्याण और विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी । मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी एनडीए की सरकार भारत को विश्व के तीसरे नम्बर की इकॉनोमी बनाएगी । इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि जनता की भलाई और लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी पार्टियों और सदस्यों का विकसित भारत की नींव को मजबूत करने में सहयोग जरूरी होगा । सादर ।

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर) **:** मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए हृदय से आभार । मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी का भी दिल से आभार व्यक्त करने के साथ संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं । महामहिम राष्ट्रपति जी ने सरकार की योजनाओं का अपने अभिभाषण में विस्तार से उल्लेख किया है । देश को शीध्र ही एक विकसित देश की श्रेणी में लाने के लिए नीति और योजनाओं का अपने भाषण में उल्लेख किया है ।

माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज देश का चहुमुखी विकास हो रहा है । और देश विकसित देश की श्रेणी की ओर अग्रसर हो रहा है । पहली बार हमारे प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व कौशल के फलस्वरूप विदेश के कई देशों के साथ मधुर संबंध बनने के साथ साथ कई देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से हमारे प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है । माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के फलस्वरूप आज दुनिया के किसी लोकतांत्रिक देश में विगत लगभग 6 दशक के बाद पहली बार किसी देश में लगातार तीसरी बार एक ही दल की सरकार का गठन हुआ है । इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और अपने एनडीए के सभी सहयोगी दलों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं ।

भारत कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था**,** वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है । राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा था**,** जिन मूल भूत सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दशकों तक इंतजार किया**,** वे इन वर्षों में उसे मिली है । बड़े-बड़े घोटालों**,**

सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, वह मुक्ति अब देश को मिल रही है ।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने सरकार की नीतियों और योजनाओं के संबंध में उल्लेख किया कि देश मे वर्ष 2014 में मात्र 6 एम्स थे, अब 19 है और 2025 तक 5 और पूरे हो जाएंगे । हमारे देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 में 387 से बढ़कर वर्तमान में 706 हो गई है और इसी अवधि में MBBS सीटें 51,348 से बढ़कर 1,08,940 हो गईं, जबकि PG सीटें 31,185 से बढ़कर 70,674 हो गईं । अतिरिक्त, 157 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की मंजूरी दी गई है । पीएम उज्ज्वला गैस सिलेंडर के अंतर्गत 75 लाख एलपीजी गैस कनेक्शन महिलाओं को मुफ्त देने के फैसले लिए गए हैं । लागत कम करके और मुनाफा बढ़ाकर खेती को अधिक लाभदायक बनाने पर सरकार ने काम किया है । कृषि क्षेत्र में प्रमुख पहल और उपलब्धियां शामिल हैं । देश की कृषि नीतियों और योजनाओं में 11 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों को प्राथमिकता दी गई है । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 2 लाख 80 हजार करोड़ रुपए से अधिक का वितरण किया गया है । पिछले 10 वर्षों में किसानों के लिए बैंक से आसान ऋण में तीन गुना वृद्धि हुई हुई है । प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने 30 हजार करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा, बदले में उन्हें 1.5 लाख करोड़ रुपए का क्लेम मिला । पिछले दशक में किसानों को धान और गेहूं की फसल क्लेम लिए एम.एस.पी. (न्यूनतम मूल्य) के रूप में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए मिले जो 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में 2.5 गुना अधिक है । पिछले दशक में तिलहन और दलहन उत्पादक किसानों को एमएसपी के रूप में 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक प्रदान किए गए । कृषि निर्यात नीति का निर्माण, जिससे कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचेगा । किसानों को सस्ती कीमत पर खाद उपलब्ध कराई गई है

पहली बार सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक आरक्षण का लाभ बढ़ाया गया । स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में ओबीसी के लिए केंद्रीय कोटा के तहत 27 प्रतिशत आरक्षण की शुरूआत । राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना । बाबा साहब अंबेडकर से जुड़े पांच स्थानों का पंचतीर्थ के रूप में विकास । देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियो को समर्पित दस संग्रहालयों का निर्माण । राष्ट्रपति जी ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार चार मजबूत स्तंभों युवा शक्ति, महिला शक्ति, किसान और गरीबों पर 'विकसित भारत' के निर्माण में विश्वास करती है ।

प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो प्रबंधन क्षमता को दोगुना करना । ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता की संख्या में 14 गुना वृद्धि, लगभग 2 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना हमारी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां हैं । गांवों में 4 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना, रोजगार का अहम जरिया बन रहा है । 10,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाना. गैस आधारित अर्थ व्यवस्था को बढ़ावा देते हुए वन नेशन वन गैस ग्रिड का शुभारंभ । वन नेशन वन पावरग्रिड का कार्य, देश में विधुत पोषण को बढ़ाना । 5 शहरों से 20 शहरों तक मेट्रो सुविधा का विस्तार 125 हजार किलो मीटर से अधिक रेलवे ट्रैक बिछाया गया, जो कई विकसित देशों में ट्रैक की कुल लंबाई से अधिक है । रेलवे 100% विद्युतिकरण हासिल करने के करीब । भारत में सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनों की शुरूआत । 39 से ज्यादा रूटों पर वंदेभारत ट्रेनों का संचालन । अमृत भारत स्टेशन योजना । गांवों में लगभग 3.75 लाख किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 90 हजार किलोमीटर से बढ़ाकर 1 लाख 46 हजार किलो मीटर । चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में 2.5 गुना वृद्धि ।हाई-स्पीड कॉरिडोर का 500 किलोमीटर से 4 हजार किलोमीटर तक विस्तार । हवाई अड्डों की संख्या 74 से दोगुना कर 149 करना । ये हमारी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो पिछले 10 वर्षों से गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान के साथ भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन को खुशहाल बनाकर भारत को दुनिया के अग्रणी राष्ट्र के रूप में

स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है । मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । धन्यवाद । भारत माता की जय । जय श्री राम ।।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर): मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार रखता हूँ । माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में भारतीय विकास यात्रा की मजबूती और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा अन्य अनेक विषयों के साथ वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती साख का उल्लेख किया । इतना ही नहीं राष्ट्रपति जी ने इस बार आने वाले महीनों में देश की आर्थिक नीति की आकृति कैसी होगी इसका भी उल्लेख किया ।

इससे बिल्कुल साफ है कि यह सरकार पहले की तरह ही काम करेंगी और उन सभी कार्यों को पूरा करने पर ध्यान देगी । जिनका उल्लेख यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पिछले कुछ समय से लगातार करते आ रहे है अर्थात् रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफार्म प्रधानमंत्री के चमत्कारिक संकल्प ने भारत को दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया हैं । सबसे उल्लेखनीय यह है कि राष्ट्रपति महोदया ने नई सरकार के पहले बजट से अपेक्षा की कि उसमें अनेक ऐतिहासिक कदम उठायें जायेंगे और वह निश्चित ही दूरगामी दृष्टिकोण लिये होगा जिसमें सरकार की दूरगामी नीतियों प्रभावी ढंग से दिखाई देंगी । महोदय, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले समय में नीति, नीयत और निर्णयों से देश के हर वर्ग को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है । इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्टार्टअप योजना का क्रियान्वयन । निश्चित ही यह गौरव का विषय 675 में से 600 जिलों में यह काम कर रहा है । हमारा खिलौना का निर्यात 1844 करोड़ों रूपये का हो गया है । हमारा डिफेन्स एक्सपोर्ट एक दशक में 21 हजार करोड़ तक पहुँच गया है । यानि इसमें 18 गुना की वृद्धि हुई है । इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेन्स कोरिडोर्स विकसित हो रहे है ।

इतना ही नहीं मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि गुलामी के दौर की दण्ड व्यवस्था एक जुलाई से खत्म हो रही है । अब देश में भारतीय न्याय संहिता लागू की जा रही है । यह श्री नरेन्द्र मोदी जी के साहस और संकल्प का परिचायक है । विदेशी मकबरों से हिन्दुस्तान की रवायत ढूंढने वालों को मानना पड़ेगा कि "संस्कृत इज है मदर ऑफ ऑल यूरोपियन लेग्वेजेस" और इसलिये भी मानना पड़ेगा कि यह मैं नहीं विलियम जॉन्स कह रहा है भारतीय संस्कृति का वैभव और विरासत हमारी थाती है और इसी को लेकर विश्व की अगुवाई कर सकते हैं और निश्चित ही करेंगे ।

नालन्दा विश्वविधालय अपने अतीत में भी वैश्विक ज्ञान केन्द्र रहा है । और नई सरकार की संकल्पना है कि अपने भव्य संकुल के साथ फिर से यह वैश्विक ज्ञान का केन्द्र होगा अपनी विरासत से आधुनिक भारत यानि नई पीढ़ी को जोड़ना आवश्यक हैं ताकि वह परम्परा को अंधी लाठी से ना पीटे । यही वह बात है कि भगवान बिरसा मुण्डा के जन्म दिवस को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाना शुरू किया । रानी दुर्गावती या माता आहिल्या बाई इनकी जन्म जयन्ती को व्यापक रूप से मनाने का कार्य इस सरकार ने किया । इसके साथ ही गुरूनानक देव जी के350 वें प्रकाश पर्व की अन्त्रराष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई दी ।

दूरदृष्टा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी समकालीन समाज की हर नब्ज पर बराबर दृष्टि रखते है इसीलिये भी टेक्नॉलोजी पर भी जोर देते रहे है और यही कारण है कि आज 82 करोड़ इन्टरनेट यूजर्स है । चन्द्रमों के दक्षिण ध्रुव पर भारत की सफलता सबके लिये गर्व का विषय होनी चाहिये । इस महान देश की राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में कहा "आज हमारे युवाओं में जो सामर्थ्य है आज हमारे संकल्पों मे जो निष्ठा है, हमारी असम्भव लगने वाली उपलब्धियाँ, ये इस बात का प्रमाण है कि आने वाला दौर भारत का दौर है ।" मैं कहना चाहूँगा, कि ऐग्रीकल्चर, मैनुफैक्चरिंग सर्विसेज और इन्फ्रास्ट्रक्चर मैं अनेक उपलब्धियों के बावजूद क्या दुर्भाग्य कि बांग्लादेश

के एक अखबार में शशि थरूर जैसे नेता ने लेख लिखा कि "मोदी हेज टू गो" में पूछना चाहता हूँ कि भारत के बाहर लेख लिखने की क्या जरूरत थी इसी तरह सेम पित्रौदा ने पश्चिम में रहने वालों की तुलना अरब उत्तर भारत की तुलना गौरो और दक्षिण भारत में रहने वालों की तुलना अफ्रीका में रहने वाले लोगों से की थी । फिर वे उत्तराधिकार कानून की बात ले आये । अभिप्राय यह है कि यह पहचानने की जरूरत है कि वस्तुतः लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकते कहाँ है । और कौन सी है? विघटनकारी, जिनका उल्लेख राष्ट्रपति जी ने किया चिन्ता का विषय है । इसी तरह जहाँ दुनिया 2024 के चुनावों की चर्चा कर रही है, जो साठ सालों में लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार देख रही है वहीं कुछ लोग लोकतंत्र को खतरे में बता रहे है । संविधान विपक्षी लोगों की तरह सिर्फ लहराने का विषय नहीं है यह मोदी जी के लिये महज राजकाज की पुस्तक भी नहीं है । यह उनके लिये लोकतांत्रिक आराधना है और इसीलिये वे इसे भारतीय जन चेतना का हिस्सा बनाने के लिये कटिबद्ध है ।

मैं देश के छत्तीसगढ़ राज्य से आता हूँ । पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका निर्माण कराया था । और नरेन्द्र मोदी जी अब इसे संवारने में लगे है । भाजपा की सरकार बनने के बाद से छत्तीसगढ़ में जनता का भरोसा जगा है । और लोग मानने लगे है कि उनकी सरकार जल्दी ही उनकी अपेक्षाओं को पूरा करेगी । महोदय, मैं राज्य में पाँच बार का मंत्री रहा हूँ और में पहली बार लोकसभा के लिये रायपुर से निर्वाचित होकर आया हूँ । मैं यह देखकर दंग था कि आपातकाल के उल्लेख करने मात्र से कांग्रेसी साथी भभकने लगे । आपातकाल इस देश के लोकतंत्र का काला अध्याय था । जिन्होंने इसे झेला है उनमें से कुछ राजनीतिक लाचारी के चलते आज इनके साथ गलबाहें कर रहे है । फिर भी मैं नहीं समझता कि आपातकाल के छालों से उपजी जलन ठण्डी पड़ गई हैं । जिन्होंने संविधान का चुप करा दिया, लोकतंत्री दलों को लहुलुहान कर दिया वह किस मुँह से संविधान की बात करते है यह चिन्ता की बात है कि कांग्रेस को आपातकाल के दुर्दिनों कि याद पर भी आपत्ति है । जहाँ तक नीट या अन्यान्य परीक्षाओं के उठे सवाल पर नई पीढ़ी का प्रश्न है मुझे यकीन है कि हमारी सरकार इसका सर्वमान्य हल खोजने में जुटी है । इसमें शिरकत करने की आवश्यकता है । यह मसला विधार्थियों के जीवन का है । दलगत राजनीति में चेहरे चमकाने का नहीं ।

मैं उम्मीद करता हूँ कि विरोध, वैमनस्य की राह ना पकड़े आशा है कि बदलते दौर में यह समय संकल्प से सिद्धि का है । कहते है कि हमराह चलो मेरे या राह से हट जाओ दीवार के रोके से दरिया कहीं रूकता है । धन्यवाद ।

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर) **:** मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के संसद में दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार रखता हूं । अपने भाषण में राष्ट्रपति जी ने हम सबके साथ देशावासियों का मार्गदर्शन किया है । आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने आदिवासी समाज का गौरव बढ़ाया ही है साथ ही देश की कोटि कोटि बहन-बेटियों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का अवसर भी है ।

आज दुनिया की हर विश्वसनीय संस्था, सारे एक्सपर्ट्स जो वैश्विक प्रभावों को बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं । जो भविष्य का अच्छे से अनुमान भी लगा सकते हैं । उन सबको आज भारत के प्रति बहुत आशा है, विश्वास है और उमंग भी है । आज पूरी दुनिया भारत की तरफ बड़ी आशा की नजरों से देख रही है । इसके कारण यह हैं कि भारत में आई स्थिरता, भारत की वैश्विक साख, भारत के बढ़ते सामर्थ्य और भारत में बन रही नई संभावनाओं में है ।

पिछले नौ वर्ष में भारत में नब्बे हजार स्टार्ट-अप्स और आज स्टार्टअप्स की दुनिया में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं । एक बहुत बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज देश के टीयर-दो, टीयर- तीन सिटीज में भी पहुंच चुका है । हिन्दुस्तान के हर कोने-कोने में पहुंचा है । भारत के युवा सामर्थ्य की पहचान बनता जा रहा है ।

हमारी सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से देशभर में कहीं पर भी गरीब से गरीब जनता को भी राशन उपलब्ध करने में सक्षम है । साथ ही किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसान के खाते में साल में तीन बार ग्यारह करोड़ किसानों के खाते में पैसे जमा होते हैं ।

हमारी सरकार ने बेघर के लिए या जो कल फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करते थे. ऐसे तीन करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर देने का काम किया है ।

हमारी सरकार ने महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया हैं और उनके उज्ज्वला जैसे योजनाओं का लाभ देकर नौ करोड़ को मुफ्त गैस के कनेक्शन देने का काम किया है । हर घर जल नल योजना के लाभ देते हुए आठ करोड़ परिवारों को लाभान्वित करने का काम किया है ।

मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में दूरगामी नीतियों और भविष्य की दूरदर्शिता के साथ संकल्प से सिद्धि तक यात्रा का खींचा गया खाका का अभिनंदन करता हूं । राष्ट्रपति जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं । देश आज यहां से एक नई उमंग- ए विश्वास-नए संकल्प के साथ चल पड़ा है ।

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): On behalf of the people of Sangli and my state of Maharashtra I would like to express my views on the motion of thanks to Madam President's address to the Parliament.

While it was expected that the President's speech would try to over glorify the achievements of the Government over the past ten years, but being the first address of the 18th Lok Sabha, we were expecting more emphasis on current happenings in our country. For Instance, the speech fails to mention the agitation for caste reservations ongoing in Maharashtra for Maratha Aarakshan. Simultaneously, the Dhangar and other OBC communities and their leaders are also agitating for their demands and concerns about reservation. While opinions may vary on the specific demands and methods of agitation, we cannot deny the authenticity and grassroots nature of these movements. The Government at the State and their office bearers have only used these agitations for their own political advantage, dividing the state on caste lines and making communities fight among each other. This is the current situation of the country speaker sir, which should have been talked about in the President's address. The Government has FAILED to ease tensions, FAILED to understand demands, and FAILED to find solutions for these agitators. This is reflected in the NDA's electoral performance in Maharashtra, declining from 41 to 17 seats, with the BJP losing 70% of the seats they contested.' The Reservation Agitations are nationwide and not limited to

Maharashtra. Across India, from Gujarat to Assam, we've seen communities demanding reservations. We need to go to the core of this problem.

अब खेती में कोई आना नहीं चाहता । सरकार कहती है उन्होंने हजारों करोड़ रुपये किसानों के लिए दिये हैं फिर भी 24000 से ज्यादा किसानों ने पिछले दस साल में आत्महत्या क्यों की है? Because farming is not affordable anymore. Sugarcane, Milk, Cotton, Grapes, Onions, Oranges there is stress everywhere. GST on seeds and fertilisers I could go on however my esteemed colleagues have already spoken on this topic. These Farmer children now want to study and move to jobs. लेकिन वहाँ NEET जैसे पेपर लीक्स, सरकारी शिक्षा की कमी, महँगी निजी शिक्षा । इसीलिए तो बच्चे आरक्षण की माँग कर रहे हैं ।

Point 19 of the President's speech talks about the Government having added educational institutions. Despite this, I wonder why thousands of students are still migrating to war-affected countries like Ukraine and Russia to Study. Is the Government spending enough on education? The overall allocation of funds to education has been only 2.8% since 2015. When we compare this to countries like the US (6.2%), UK (5.5%), Germany (5%), and even Namibia in Africa spends 9.64% of its GDP on education, Are we spending enough? In spite of all these hurdles, if a person does get education and tries to enter the workforce, we see the sorry state of government jobs. क्योंकि आज भी माँ उम्मीद करती है कि मेरे बेटा/बेटी को अच्छी सरकारी नौकरी मिले । क्या हाल है सरकारी नौकरियों का । आज महाराष्ट्र में 75000 सरकारी पद रिक्त पड़े हैं । और जब भर्ती होती है तो पेपर लीक हो जाते हैं । 45 instances in the last five years.

Let's talk about Maharashtra. Mahapariksha Portal Scam (18) Mumbai Police Paper Leak (22) Talathi Paper Leak (23) Mahanirmiti Paper Leak (23) Forest Department Paper Leak (23) Soil and Water Conservation Department Paper Leak (23) Municipal Council & ZP (some positions) Paper Leak (23) This is why more and more communities are asking for reservations. खेती करे तो दम नहीं, पढ़ना चाहे तो बिना लीक एग्जाम नहीं, करना चाहे तो सरकारी काम नहीं । The reservation demand would never have cropped up if the Government would have ensured that farming is lucrative and had getting admissions and Government jobs been easier.

2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी सांगली आए थे और घोषणा की थी कि सांगली को चांगली करेंगे यानी सांगली को अच्छा बनाएंगे । उनके इस बात पे विश्वास करके सांगली ने दस साल भाजपा का सांसद दिल्ली पहुंचाया । Kya mila sangli ko. Does the President's speech then mention anything about the development of Sangli? Does it mention an airport in Sangli or the dry port which is much needed for a high agricultural produce exporting district like Sangli? Does the speech talk about the inclusion of Sangli-Miraj-Kupwad city in the smart city project? Does the President's speech mention the allocation of funds for the

incomplete farm irrigation projects of Sangli district? It does not and it hasn't for the last ten years.

I would very happily thank the President if these points were included. Hoping they will be part of the next address. I thanks again for providing me this opportunity. Jai Hind, Jai Maharashtra.

श्री संजय उत्तमराव देशमुख (यवतमाल-वाशिम) : मैं, यवतमाल लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करता हूं । जबकि अभिभाषण भारत की प्रगति और भविष्य का एक सुनहरा चित्र प्रस्तुत करता है, यह महत्वपूर्ण चुनौतियों को नजरअंदाज करता है और हमारे देश, विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के सामने आने वाले गंभीर मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहता है ।

यवतमाल और विदर्भ क्षेत्र में कृषि संकट गंभीर है । सितंबर 2023 में एक ही महीने में यवतमाल जिले में 43 से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली थी । कपास और सोयाबीन की फसलों के नुकसान, अनिश्चित मौसम, और कर्ज के बोझ ने किसानों को गंभीर संकट में डाल दिया है । सरकार की नीतियां इस समस्या को हल करने में पूरी तरह असफल रही हैं । महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के मामले पूरे देश में एक नंबर पर यवतमाल है । हालांकि दोनों जिलों यवतमाल वाशीम में किसानों की आत्महत्या के आंकड़ों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है । मई 2024 तक 132 आत्महत्याएं दर्ज की गई हैं । जून के आंकड़े अभी संकलित किए जाने बाकी हैं ।

मैं उगाता हूँ कपास, तो सारी दुनियाँ कपडे पहनती है.....

फिर मेरी ही लाश क्यों आखिर एक कफन के लिए तरसती है

किसानों ने सोयाबीन की खेती की और उपज में उल्लेखनीय गिरावट देखी । 2 साल पहले 6000 रु क्विंटल से 4,000 रुपये प्रति क्विंटल हो गईं । पर्याप्त बैंकिंग ऋण की कमी के कारण, कई लोग छोटी वित्त कंपनियों या साहूकारों पर निर्भर हैं, और उन्हें कठोर वसूली का सामना करना पड़ता है । 2001 से राज्य सरकार विदर्भ के छह जिलों अमरावती, अकोला, यवतमाल, वाशिम, बुलढाणा और वर्धा में किसानों की आत्महत्याओं का डेटा रख रही है । दो दशकों में इन जिलों में 22,000 से ज़्यादा आत्महत्याएं हुई हैं । सर कपास उगाने वाले यवतमाल का किसान बहुत संकट में हैं । 2 साल पहले 10000 प्रति क्विंटल कपास बिका मगर पिछले साल 7000 क्विंटल कपास लेने को कोई तैयार नहीं था । एक इधर खेती के उत्पादन अनाज के कम कम होते हैं मगर व्यापारी उद्योगपति के काम बढ़ते जाते हैं । यही किसान का दुख है किसानों को देखना है हमारा दुख जानने वाला कोई सरकार है कि नहीं । भारत में यवतमाल के किसान कीटनाशक विषाक्तता से जूझ रहे हैं, जिससे व्यापक नुकसान और मौतें हुई हैं । किसान सरकार द्वारा सुझाए गए कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये हानिकारक साबित हुए हैं । कई किसानों को कैंसर सहित स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो गई हैं और कुछ की मृत्यु हो गई है । किसान अपनी पीड़ा के लिए न्याय और मुआवजे की मांग कर रहे हैं । ? - एक स्विस अदालत उनके मामले की सुनवाई कर रही है, क्योंकि कीटनाशकों का निर्माण एक स्विस कंपनी द्वारा किया गया था । किसानों को उम्मीद है कि अदालत कंपनी को जवाबदेह ठहराएगी और उन्हें वह मुआवजा देगी जिसकी उन्हें आवश्यकता है । यह मामला भारत में किसानों के लिए सुरक्षित खेती के तरीकों और बेहतर समर्थन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है । किसान का मानना है कि kapas ki कीमत कम से कम 10,000 रुपये प्रति क्विंटल होनी

चाहिए । किसानों के बीज और औषधि पर जीएसटी न लगाए । जीएसटी से किसानों को राहत मिले । सरकारी योजनाएं नुकसान की भरपाई करने के लिए अपर्याप्त हैं ।

महाराष्ट्र में यवतमाल में क्राइम रेट बहुत बढ़ा है हर दो दिन में एक कत्ल हो रहा है महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है ।

भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताने का दावा बढ़ती बेरोजगारी की वास्तविकता को छिपाता है, विशेष रूप से युवाओं के बीच । महाराष्ट्र में, जहां कपड़ा और कृषि क्षेत्र प्रमुख रोजगार स्रोत हैं**,** इन क्षेत्रों में संकट ने बेरोजगारी को और बढ़ा दिया है । यवतमाल जैसे क्षेत्रों में रोजगार की कमी विशेष रूप से चिंताजनक है, जहां युवा बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं । कल रात दो सौ नौजवानो ने आत्महत्या कर ली, बात बहुत चौकाने वाली थी, बाद में पता चला. जन्नत में कलर्क की एक जगह खाली थी ।

विदर्भ क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं की कमी एक बड़ी समस्या है । गोसीखुर्द परियोजना, देमद्धा अमरावती प्रोजेक्ट में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है किसानों को खेत तक पानी नहीं मिल रहा है कुछ किसानों को जमीन का मुआवजा बहुत कम मिल रहा है । सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ।

महाराष्ट्र में जल संकट और वन क्षेत्रों का संरक्षण महत्वपूर्ण मुद्दे हैं । यवतमाल के आसपास के जंगलों में मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है, लेकिन इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

निष्कर्ष में, जबकि हम सभी एक विकसित महाराष्ट्र और भारत की आकांक्षा साझा करते हैं, हम अपनी कमियों को नजरअंदाज करके या एक चयनात्मक कथा प्रस्तुत करके इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते । सच्ची प्रगति के लिए ईमानदार आत्मनिरीक्षण, समावेशी नीतियों और समाज के सभी वर्गों की चिंताओं को संबोधित करने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है ।

मैं इस सरकार से आग्रह करता हूं कि वह नारों से आगे बढ़े और हमारे राज्य और राष्ट्र के भविष्य के लिए एक अधिक संतुलित और व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करे । इन कारणों से, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं । धन्यवाद

प्रधानमंत्री **(**श्री नरेन्द्र मोदी**) :** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं ।?(व्यवधान) आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने विकसित भारत के संकल्प को अपने प्रवचन में विस्तार दिया है ।?(व्यवधान) आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने अहम विषय उठाएं हैं ।?(व्यवधान) आदरणीय राष्ट्रपति जी ने हम सबका और देश का मार्गदर्शन किया है ।?(व्यवधान) इसके लिए मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं ।?(व्यवधान) आदरणीय अध्यक्ष जी, कल और आज कई माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किए हैं ।?(व्यवधान)

मैं विशेषकर जो पहली बार सांसद बनकर हमारे बीच आए हैं और उनमें सें कुछ आदरणीय साथियों ने अपने जो विचार व्यक्त किए, संसद के सभी नियमों का पालन करते हुए किए, उनका व्यवहार ऐसा था, जैसे एक अनुभवी सांसद का होता है । ? (व्यवधान) इसलिए प्रथम बार आने के बावजूद भी उन्होंने सदन की गरिमा को बढ़ाया है ।? (व्यवधान) उन्होंने अपने विचारों से इस डिबेट को और अधिक मूल्यवान बनाया है । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, देश ने एक सफल चुनाव अभियान को पार करते हुए विश्व को दिखा दिया है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव अभियान था ।? (व्यवधान) देश की जनता ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव अभियान में हमें चुना है ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं कि लगातार झूठ चलाने के बावजूद भी उनकी घोर पराजय हुई । लोकतंत्र के ? (व्यवधान)

16.18 hrs

At this stage, Shri Alfred Kanngam S. Arthur, Shri B. Manickam Tagore,

Shri Gaurav Gogoi and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

-

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय प्रतिपक्ष के नेता, यह आपको शोभा नहीं देता है । आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है । आपको यह शोभा नहीं देता है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप सदन में डायरेक्शन दो, माननीय नेता जब बोल रहे हों, तब आप खड़े हो जाएं, यह आपको शोभा नहीं देता है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** संसदीय परंपराओं के अनुसार यह उचित नहीं है । आपका यह तरीका ठीक नहीं है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** नो, आपका यह गलत तरीका है । सदन इस तरीके से नहीं चलेगा ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** नो, यह गलत तरीका है । आप संसद के अंदर गरिमा बना कर रखें । आप गरिमा को तोड़ना चाहते हैं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप पीठ पीछे बात नहीं करें । आपको सदन की गरिमा का नहीं पता है । आप वेल में आने के लिए लोगों को डायरेक्शन देते हैं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप प्रतिपक्ष के नेता हैं । आपका यह गलत तरीका है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय प्रधान मंत्री जी ।

? (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी **:** आदरणीय अध्यक्ष जी, यह विश्व का सबसे बड़ा चुनाव अभियान था और उसमें भारत की जनता ने हमें तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया है ।? (व्यवधान) यह अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, बहुत ही गौरवपूर्ण घटना है ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें हर कसौटी पर कसने के बाद देश की जनता ने यह जनादेश दिया है ।? (व्यवधान) जनता ने हमारे 10 साल के ट्रेक रिकॉर्ड को देखा है ।? (व्यवधान) जनता ने देखा है कि गरीबों के कल्याण के लिए हमने जिस समर्पण भाव से, जन-सेवा ही प्रभु सेवा के मंत्र को चरितार्थ करते हुए, हमने जो कार्य किया है, उसके कारण 10 साल में 25 करोड़ गरीब लोग गरीबी से बाहर निकले हैं ।? (व्यवधान) देश की आज़ादी के कालखण्ड में, इतने कम समय में इतने लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का सफल प्रयास इस चुनाव में हमारे लिए आशीर्वाद का कारण बना है ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, जब पहली बार वर्ष 2014 में हम जीतकर आये थे, तो चुनाव के अभियान में भी हमने कहा था कि हमारा करप्शन के प्रति ज़ीरो टॉलरेन्स रहेगा ।? (व्यवधान) आज मुझे गर्व है कि हमारी सरकार में, देश का सामान्य मानवी, जो करप्शन के कारण पीड़ित है, देश को करप्शन ने दीमक की तरह खोखला कर दिया है, ऐसे में भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जो ज़ीरो टॉलरेन्स की नीति है, आज देश ने हमें उसके लिए आशीर्वाद दिया है ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, आज दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है । आज विश्व में भारत का गौरव हो रहा है । भारत की तरफ देखने का नज़रिया भी, एक गौरवपूर्ण नज़रिया हर भारतवासी अनुभव करता है ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, देश की जनता ने देखा है कि हमारा एक मात्र लक्ष्य ?नेशन फर्स्ट? है, ?भारत सर्वप्रथम? है । हमारी हर नीति, हमारे हर निर्णय, हमारे हर कार्य का एक ही तराजू रहा है- ?भारत प्रथम ।?? (व्यवधान) ? भारत प्रथम? की भावना के साथ देश के जो आवश्यक रिफॉर्म्स थे, उन रिफॉर्म्स को भी हमने लगातार जारी रखा है । 10 वर्षों में हमारी सरकार ?सबका साथ, सबका विकास? के मंत्र को लेकर लगातार देश के सभी लोगों का कल्याण करने का प्रयास करती रही है ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, हम उन सिद्धांतों के प्रति समर्पित हैं, जिनमें भारत के संविधान की स्पिरिट के अनुसार, ? सर्व पंत सम्भाव? के विचार को सर्वोपरि रखते हुए, हमने देश की सेवा करने का प्रयास किया है ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, इस देश ने लम्बे अरसे तक तुष्टिकरण की राजनीति भी देखी, इस देश ने लम्बे अर्से तक तुष्टिकरण की गवर्नेंस का मॉडल भी देखा ।? (व्यवधान) देश ने पहली बार सेक्युलरिज्म का एक पूरा, हमने जो प्रयास किया और वह हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण किया । ? (व्यवधान) उस संतुष्टीकरण के विचार को लेकर हम चले हैं । ? (व्यवधान) जब हम संतुष्टीकरण की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हर योजना का

सैचुरेशन, गवर्नेंस की, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की हमारी जो संकल्पना है, इसको परिपूर्ण करना । ? (व्यवधान) जब हम सैचुरेशन के सिद्धांत को लेकर चलते हैं, तब सैचुरेशन सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय होता है । ? (व्यवधान) सैचुरेशन सच्चे अर्थ में सेक्युलरिज्म होता है और उसी को देश की जनता ने हमें तीसरी बार बैठाकर के मोहर लगा दी है । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, अपीज़मेंट ने इस देश को तबाह करके रखा है । ? (व्यवधान) इसलिए, हम ?Justice to all, appeasement to none? के सिद्धांत को लेकर चले हैं । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, दस साल के हमारे कार्यकाल को देखने-परखने के बाद भारत की जनता ने हमारा समर्थन किया है । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें फिर एक बार 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने का मौका मिला है । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, इस चुनाव ने इस बात को सिद्ध किया है कि भारत की जनता कितनी परिपक्व है, भारत की जनता कितने विवेकपूर्ण रूप से और कितने उच्च आदर्शों को लेकर अपने विवेक का सदबुद्धि से उपयोग करती है । ? (व्यवधान) उसी का नतीजा है कि आज तीसरी बार हम आपके सामने, देश की जनता के सामने नम्रतापूर्वक सेवा करने के लिए उपस्थित हुए हैं । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, देश की जनता ने हमारी नीतियों को देखा है, हमारी नीयत, हमारी निष्ठा, उस पर देश की जनता ने भरोसा किया है । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, इस चुनाव में हम जनता के बीच एक बड़े संकल्प के साथ, देश की जनता के पास आशीर्वाद मांगने के लिए गए थे । ? (व्यवधान) हमने ?विकसित भारत? के हमारे संकल्प के लिए आशीर्वाद मांगा था । ? (व्यवधान) हमने ?विकसित भारत? के निर्माण के लिए एक प्रतिबद्धता के साथ, एक शुभनिष्ठा के साथ, जन-सामान्य का कल्याण करने के इरादे से हम गए थे । ? (व्यवधान) जनता ने ?विकसित भारत? के संकल्प को चार-चांद लगाकर, हमें फिर से एक बार विजयी बनाकर देश की जनता की सेवा करने का मौका दिया है । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, जब देश विकसित होता है, तब कोटि-कोटि जनों के सपने पूरे होते हैं । ? (व्यवधान) देश जब विकसित होता है, तब कोटि-कोटि जनों के संकल्प सिद्ध होते हैं । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, जब देश विकसित होता है तब आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत नींव उनके सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, विकसित भारत का सीधा-सीधा लाभ हमारे देश के नागरिकों की गरिमा, हमारे देश के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार, यह स्वाभाविक सुधार विकसित भारत होने से देश के कोटि-कोटि जनों के भाग्य में आता है ।? (व्यवधान) आजादी के बाद मेरे देश का सामान्य नागरिक इन चीजों के लिए तरसता रहा है ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, जब विकसित भारत होता है, तब हमारे गाँव की स्थिति, हमारे शहरों की स्थिति, उनमें भी बहुत बड़ा सुधार होता है ।? (व्यवधान) गाँव के जीवन में गौरव भी होता है, गरिमा भी होती है और विकास के

नए-नए अवसर भी होते हैं ।? (व्यवधान) हमारे शहरों का विकास भी एक अवसर के रूप में विकसित भारत में तब उभरता है, ? (व्यवधान) जब दुनिया की विकास यात्रा में भारत के शहर भी बराबरी करेंगे ।? (व्यवधान) यह हमारा सपना है ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, विकसित भारत का मतलब होता है कोटि-कोटि नागरिकों को, कोटि-कोटि अवसर उपलब्ध होते हैं, अनेक-अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं और वे अपने कौशल, अपनी क्षमता और संसाधनों के अनुसार विकास की नई सीमाओं को प्राप्त कर सकता है ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज आपके माध्यम से देशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि विकसित भारत के जिस संकल्प को लेकर हम चले हैं, उस संकल्प की पूर्ति के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे, पूरी निष्ठा से करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे और हमारे समय का पल-पल और हमारे शरीर का कण-कण हम देशवासियों के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में लगाएंगे ।? (व्यवधान) हमने देश की जनता को कहा था 24 बाई 7 फॉर 2047? (व्यवधान) आज मैं इस सदन में भी दोहराता हूँ कि हम इस काम को अवश्य पूरा करेंगे ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014 के उन दिनों को याद कीजिए ।? (व्यवधान) वर्ष 2014 के उन दिनों को याद करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि हमारे देश के लोगों का आत्मविश्वास खो चुका था ।? (व्यवधान) देश निराशा की गर्त में डूब चुका था ।? (व्यवधान) ऐसे समय, वर्ष 2014 के पहले देश ने जो सबसे बड़ा नुकसान भुगता था, जो सबसे बड़ी अमानत खोयी थी, वह था देशवासियों का आत्मविश्वास ।? (व्यवधान) जब विश्वास और आत्मविश्वास खो जाता है, तब उस व्यक्ति का, समाज का, देश का खड़ा हो जाना मुश्किल हो जाता है ।? (व्यवधान) उस समय सामान्य मानव के मुँह से यही निकलता था कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता है । उस समय हर जगह ये सात शब्द सुनाई देते थे कि ?इस देश का कुछ नहीं हो सकता? । यही शब्द वर्ष 2014 के पहले सुनाई देते थे ।? (व्यवधान) भारतीयों की हताशा के ये सात शब्द एक प्रकार से पहचान बन गए थे । उस समय आए दिन जब अखबार खोलते थे, तो घोटालों की खबरें ही पढ़ने को मिलती थीं और सैकड़ों करोड़ रुपये के घोटाले होते थे, रोज नए घोटाले । घोटालों की घोटालों से स्पर्धा थी । ये घोटालेबाज लोगों के घोटाले, इसी का यह काल खंड था ।? (व्यवधान) बेशर्मी के साथ सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर लिया जाता था कि दिल्ली से एक रुपया निकलता है तो पन्द्रह पैसे पहुंचते हैं । एक रुपये में 85 पैसे का घोटाला । इन घोटालों की दुनिया ने देश को निराशा की गर्त में डूबो दिया था । पालिसी पैरालिसिस था, फ्रैजाइल फाइव में पहुंच चुके थे । भाई भतीजावाद इतना फैला हुआ था, जिसके लिए सामान्य नौजवान तो आशा छोड़ चुका था कि यदि कोई सिफारिश करने वाला नहीं है तो जिंदगी अटक जाएगी, यह स्थिति पैदा हुई थी । गरीब को घर लेना हो तो हजारों रुपये की रिश्वत देनी पड़ती थी ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, गैस के कनेक्शन के लिए मैम्बर पार्लियामेंट के यहां अच्छों-अच्छों को चक्कर काटने पड़ते थे और वह भी बिना कट लिए गैस के कनेक्शन नहीं मिलते थे । मुफ्त राशन के लिए भी पता नहीं होता था कि कब बाजार में दुकान पर बोर्ड लटक जाए । हक का राशन नहीं मिलता था और उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़ती थी ।? (व्यवधान) हमारे ज्यादातर भारतीय भाई-बहन इतने निराश हो चुके थे कि वे अपने भाग्य को दोष देकर, अपने नसीब को दोष देकर जिंदगी काटने के लिए मजबूर हो जाते थे । वर्ष 2014 के पहले वह एक वक्त था जब वे सात शब्द हिंदुस्तान के जन-मन में स्थिर हो चुके थे । निराशा की गर्त में डूबा हुआ समाज था, तब देश की जनता ने हमें सेवा करने के लिए चुना और उस पल देश के परिवर्तित युग का प्रारम्भ हो चुका था ।?

(व्यवधान) पिछले दस सालों में, मैं कहूंगा मेरी सरकार की अनेक सफलताएं हैं, अनेक सिद्धियां हैं जिनकी ताकत से देश निराशा की गर्त में से निकल कर आशा और विश्वास के साथ खड़ा हो गया । देश में आत्मविश्वास बुलंदी पर पहुंचा और जो सात शब्द थे, देश की युवा पीढ़ी उनसे बाहर आने लगी ।? (व्यवधान) धीरे-धीरे देश के मन में स्थिर हो गया, जो वर्ष 2014 से पहले कहते थे कि ?कुछ नहीं हो सकता? वे कहने लगे कि इस देश में सब कुछ हो सकता है । इस देश में सब कुछ संभव है । यह विश्वास जताने का हमने काम किया है ।? (व्यवधान) हमने सबसे पहले तेजी से 5G का रोलआउट करके दिखाया ।? (व्यवधान) तीव्र गति से 5G का रोलआउट होने के बाद देश गौरव से कहने लगा कि भारत कुछ भी कर सकता है ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, वह एक जमाना था, जब कोयला घोटाले में बड़े-बड़ों के हाथ काले हो चुके थे, आज कोयले का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है ।? (व्यवधान) इसी के कारण, देश अब कहने लगा है कि अब भारत कुछ भी कर सकता है ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014 के पहले वह एक समय था, जब फोन बैंकिंग करके बड़े-बड़े घोटाले किए जा रहे थे ।? (व्यवधान) अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह बैंक का खजाना लूट लिया गया था ।? (व्यवधान) वर्ष 2014 के बाद नीतियों में परिवर्तन, निर्णयों में गति, निष्ठा और प्रामाणिकता की गयी और उसी का परिणाम है कि आज दुनिया के अच्छे बैंकों में भारत के बैंकों का एक स्थान बन गया है ।? (व्यवधान) आज भारत के बैंक सर्वाधिक मुनाफा करने वाले बैंक बन गए हैं और लोगों की सेवा करने की जगह बन गए हैं ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014 के पहले भी एक वक्त था, जब आतंकी आकर, जहां चाहे, जब चाहे, हमला कर सकते थे ।? (व्यवधान) वर्ष 2014 के पहले निर्दोष लोग मारे जाते थे, हिन्दुस्तान के कोने-कोने को टारगेट किया जाता था और सरकारें चुपचाप बैठी रहती थीं, मुँह तक खोलने को तैयार नहीं थीं ।? (व्यवधान) आज वर्ष 2014 के बाद का हिन्दुस्तान घर में घुस कर मारता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और उसने आतंकवाद के आकाओं को भी सबक सिखाने का सामर्थ्य दिखा दिया है ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, देश का एक-एक नागरिक जानता है कि अपनी सुरक्षा के लिए भारत कुछ भी कर सकता है ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, आर्टिकल-370 की पूजा करने वाले लोगों ने, वोट बैंक को राजनीति का हथियार बनाने वाले लोगों ने जिस तरह से जम्मू-कश्मीर के जो हालात कर दिये थे, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए गए थे, उस समय भारत का संविधान जम्मू-कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था और यहां संविधान को सिर पर रख कर नाचने वाले लोग तब संविधान को जम्मू-कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते थे ।? (व्यवधान) वे बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया करते थे ।? (व्यवधान) आर्टिकल-370 का वह ज़माना था, जब सेनाओं पर पत्थर चलते थे और लोग निराशा में डूब कर कहते थे कि अब तो जम्मू-कश्मीर में कुछ हो नहीं सकता ।? (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, आर्टिकल-370 की दीवार गिरी, पत्थरबाज़ी बंद है, लोकतंत्र मज़बूत है और जम्मू-कश्मीर के लोग बढ़-चढ़ कर भारत के संविधान में भरोसा करते हुए, भारत के तिरंगे झंडे पर भरोसा करते हुए, भारत के लोकतंत्र में भरोसा करते हुए, बढ़-चढ़ कर मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं, यह साफ-साफ दिखाई देता है । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, 140 करोड़ देशवासियों में यह विश्वास पैदा होना, यह उम्मीद पैदा होना बड़ी बात है और जब विश्वास जागता है, तब वह विकास का ड्राइविंग फोर्स बन जाता है । ? (व्यवधान) इस विश्वास ने विकास के ड्राइविंग फोर्स का काम किया है । ? (व्यवधान) आदरणीय अध्यक्ष जी, यह विश्वास विकसित भारत संकल्प से सिद्धि का विश्वास है । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, जब आज़ादी की जंग चल रही थी और जो भाव देश में था, जो जोश था, उत्साह था, उमंग था, जो विश्वास था कि आज़ादी ले कर रहेंगे, आज देश के कोटि-कोटि जनों में वह विश्वास पैदा हुआ है, जिस विश्वास के कारण आज विकसित भारत होना, एक प्रकार से उसकी मज़बूत नींव का इस चुनाव में शिलान्यास हो चुका है । ? (व्यवधान) जो ललक आज़ादी के आंदोलन में थी, वही ललक विकसित भारत के इस सपने को साकार करने में है । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, आज भारत के लक्ष्य बहुत विराट हैं । ? (व्यवधान) आज भारत दस सालों में एक ऐसी स्थिति में पहुंचा है कि हमें खुद से ही प्रतिस्पर्धा करनी है । ? (व्यवधान) हमें ही अपने पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं और नेक्स्ट लैवल पर हमें अपनी विकास यात्रा को ले जाना है । ? (व्यवधान) दस वर्षों में भारत विकास की जिस ऊंचाई पर पहुंचा है, वह हमारी प्रतिस्पर्धा का एक मार्क बन चुका है, एक बेंचमार्क बन चुका है । ? (व्यवधान) पिछले दस सालों में हमने जो स्पीड पकड़ी है, अब हमारा मुकाबला, उसी स्पीड को और ज्यादा स्पीड में ले जाने का है और मेरा विश्वास है कि देश की इच्छा को हम उसी गति से पूरा करेंगे । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, हम हर सफलता को, हर सैक्टर को नेक्स्ट लैवल तक ले जाएंगे । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत की इकोनॉमी को दस साल के अल्पकाल में हम दसवें नंबर की इकोनॉमी से 5 वें नंबर पर ले गए हैं । ? (व्यवधान) अब हम नेक्स्ट लैवल पर जाने के लिए जिस गति से निकले हैं, हम देश की इकोनॉमी को विश्व में तीसरे नंबर पर ले जाएंगे । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, दस सालों में हमने भारत को मोबाइल फोन का बड़ा मैन्युफक्चरर बना दिया है । ? (व्यवधान) भारत को मोबाइल फोन का बड़ा एक्सपोर्टर बना दिया । अब यही काम हमारे इस टेन्योर में सेमी कंडक्टर और अन्य सेक्टर्स में हम करने जा रहे हैं । दुनिया के महत्वपूर्ण कामों में जो चिप्स काम में आएंगी, वह चिप्स मेरे भारत की मिट्टी में तैयार हुई होंगी । मेरे भारत के नौजवानों की बुद्धि का परिणाम होगा, मेरे भारत के नौजवानों के परिश्रम का परिणाम होगा, यह विश्वास हमारे बीच में है ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, हम आधुनिक भारत की तरफ भी जाएंगे । हम विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे, लेकिन हमारी जड़ें जमीन से जुड़ी रहेंगी ।? (व्यवधान) हमारे पैर देश के जन सामान्य की जिंदगी से जुड़े रहेंगे । हम चार करोड़ गरीबों के घर बना चुके हैं । आने वाले इस टेन्योर में तेज गति से तीन करोड़ और घर बना कर, इस देश में किसी को भी घर के बिना रहना नहीं पड़े, यह हम देखेंगे ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 साल में वुमन सेल्फ ग्रुप में देश की कोटि-कोटि बहनों को एंटरप्रिन्योर के क्षेत्र में हम बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं । अब हम उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं ।? (व्यवधान) हमारे वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो बहनें काम कर रही हैं, उनकी आर्थिक गतिविधि इतनी बढ़ाना चाहते हैं, उसका इतना विस्तार करना चाहते हैं कि हम बहुत कम समय में तीन करोड़ ऐसी बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लेकर चलने वाले हैं ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी कहा है, आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं । हमारी तीसरी टर्म में, इसका मतलब है ? हम तीन गुना स्पीड से काम करेंगे । हमारी तीसरी टर्म का मतलब है ? हम तीन गुना शक्ति लगाएंगे । हमारी तीसरी टर्म का मतलब है ? हम देशवासियों को तीन गुना परिणाम लाकर देंगे ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** सदस्यगण, मैंने नेता प्रतिपक्ष सहित सबको मौका दिया । आपने 90 मिनट बोला ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** संसद में यह तरीका ठीक नहीं है । मैं आपसे आग्रह करूंगा । आप इस तरीके से संसद की मर्यादा का पालन कर रहे हैं, यह उचित नहीं है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** आप वेल में से जाइए और अपनी सीट पर बैठिए । आपको मैंने पर्याप्त समय और अवसर दिया ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** आपको मैंने 90 मिनट बोलने दिया और पूरा समय दिया । आपके सभी सदस्यों को बोलने का अवसर दिया, लेकिन जब सदन के नेता बोलते हैं और आप जिस तरीके का व्यवहार करते हैं, यह संसदीय परंपराओं के अनुरुप नहीं है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** आपकी इतनी बड़ी पार्टी है, जिसको आप लेकर चल रहे हैं, उसकी परंपराओं के अनुरुप भी नहीं है । ये पाँच साल ऐसे चलने वाला नहीं है ।

माननीय प्रधानमंत्री जी ।

? (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी **:** आदरणीय अध्यक्ष जी, एनडीए का तीसरी बार सरकार में आना एक ऐतिहासिक घटना है ।? (व्यवधान) आज़ादी के बाद यह सौभाग्य दूसरी बार इस देश में आया है और 60 साल के बाद आया है । इसका मतलब है कि यह सिद्धि पाना कितना कठोर परिश्रम के बाद होता है, कितना अभूतपूर्व विश्वास संपन्न होने के बाद होता है ।? (व्यवधान) यह ऐसे ही राजनीति के खेल से नहीं होता है, जनता जनार्दन की सेवा से प्राप्त आशीर्वाद से होता है ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, जनता ने हमें स्थिरता और निरन्तरता के लिए जनादेश दिया है । ?(व्यवधान) लोक सभा चुनाव के साथ ही लोगों की नजर से चीजें जरा ओझल हो गईं । लोक सभा चुनाव के साथ-साथ हमारे देश में चार राज्यों के भी चुनाव हुए ।? (व्यवधान) इन चारों ही राज्यों में एनडीए ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है । ? (व्यवधान) हमने शानदार विजय प्राप्त की है ।? (व्यवधान) महाप्रभु जगन्नाथ जी की धरती ओडिशा ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है ।?(व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, आंध्र प्रदेश में एनडीए ने क्लीन स्वीप किया है । ?(व्यवधान) सूक्ष्मदर्शी यंत्र में भी ये नजर नहीं आते हैं । ?(व्यवधान) अरुणाचल प्रदेश में हम फिर एक बार सरकार बनाएंगे । ?(व्यवधान) सिक्किम में एनडीए ने फिर एक बार सरकार बनाई है ।?(व्यवधान) अभी 6 महीने पहले ही आपका होम स्टेट राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमने प्रचंड विजय पाई है । ? (व्यवधान) हमें नए-नए क्षेत्रों में जनता का प्यार मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, बीजेपी ने केरल में इस बार खाता खोला है और बड़े गर्व के साथ केरल के सांसद हमारे साथ बैठते हैं । ? (व्यवधान) तमिलनाडु में कई सीटों पर बीजेपी ने दमदार उपस्थिति दर्ज की है । ?(व्यवधान) कर्नाटक, यू.पी. और राजस्थान में पिछली बार की तुलना में बीजेपी का वोट पर्सेंट बढ़ा है ।?(व्यवधान) आने वाले समय में तीन राज्यों में चुनाव हैं । जिन राज्यों में चुनाव हैं, उनमें से तीन की मैं बात करता हूं । ? (व्यवधान) महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, यहां चुनाव आ रहे हैं । ? (व्यवधान) पिछली विधान सभा में इन तीन राज्यों में हमें जितने वोट मिले थे, इस लोक सभा चुनाव में इन तीन राज्यों में हमें उससे भी ज्यादा वोट मिले हैं ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, पंजाब में भी हमारा अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा है और हमें बढ़त मिली है । ?(व्यवधान) जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद हमारे साथ है । ? (व्यवधान) 2024 के चुनाव में कांग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है । ? (व्यवधान) इस देश का जनादेश है कि आप वहीं बैठिए । ? (व्यवधान)

17.00 hrs

विपक्ष में ही बैठो, तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो, ? (व्यवधान) कांग्रेस के इतिहास का यह पहला मौका है, जब लगातार तीन बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पायी है। कांग्रेस के इतिहास में यह तीसरी सबसे बड़ी हार है । तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है । अच्छा होता, कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता जनार्दन के आदेश को सर आंखों पर चढ़ाती, आत्ममंथन करती, लेकिन ये तो शीर्षासन करने में लगे हुए हैं । ? (व्यवधान) कांग्रेस और उसका इको सिस्टम दिन-रात बिजली जलाकर हिन्दुस्तान के नागरिकों के मन में यह प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बता रहा हूं, कोई छोटा बच्चा साइकिल लेकर निकला है, अगर वह बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, कोई बड़ा व्यक्ति उसके पास पहुंच जाता है, उसको कहता है कि चीटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, तुम गिरे नहीं हो, ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटकाकर उस बच्चे का मन बहला देते हैं । आजकल बच्चे का मन बहाने का काम चल रहा है । ? (व्यवधान) कांग्रेस के लोग और उनका इको सिस्टम आजकल मन बहलाने का काम कर रहा है ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, 1984 के चुनाव को याद कीजिए, उसके बाद इस देश में 10 लोक सभा के चुनाव हुए, 1984 के बाद 10-10 लोक सभा के चुनाव होने के बावजूद भी कांग्रेस 250 के आंकड़े को छू नहीं पायी है । इस बार किसी तरह 99 के चक्कर में फंस गए हैं । ? (व्यवधान) इस बार किसी तरह 99 के चक्कर में फंस गए हैं । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे किस्सा याद आता है, 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और सबको दिखा रहा था कि देखो, कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं । लोग भी 99 मार्क्स सुनते थे तो शाबाशी देते थे और उसका बहुत हौसला बुलंद करते थे । उनके टीचर आए और बोले कि किस बात की मिठाई बांट रहे हो, 100 में से 99 मार्क्स नहीं लाए हैं, 543 में से लाए हैं । ? (व्यवधान) अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के नेताओं के बयानों में बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है । ? (व्यवधान) आप सबको शोले फिल्म की मौसीजी याद होंगी । यह बात तो सही है कि तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी, मोरल विक्टरी तो है न । ? (व्यवधान) 13 राज्यों में जीरो सीट आई है, अरे मौसी, पर हीरो तो हैं न । ? (व्यवधान) पार्टी की लुटिया तो डुबोई है, अरे मौसी, लेकिन पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है । ? (व्यवधान) मैं कांग्रेस के लोगों को कहूंगा कि जनादेश को फर्जी जीत के जश्न में मत दबाओ । ? (व्यवधान) जनादेश को फर्जी जीत के नशे में मत डुबाओ । ? (व्यवधान) उस जश्न में मत दबाओ ।? (व्यवधान) ईमानदारी से देशवासियों के जनादेश को ज़रा समझने की कोशिश करो, उसे स्वीकार करो । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस के जो साथी दल हैं, उन्होंने इस चुनाव का विश्लेषण किया है या नहीं किया है । ये चुनाव इन साथियों के लिए भी एक संदेश हैं । ? (व्यवधान) अब कांग्रेस पार्टी वर्ष 2024 से एक परजीवी कांग्रेस के रूप में जानी जाएगी । वर्ष 2024 से जो कांग्रेस है, वह परजीवी कांग्रेस है और परजीवी वह होता है, जो जिस शरीर के साथ रहता है, उसी को खाता है । ? (व्यवधान) कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है, उसी के वोट खा जाती है और अपनी सहयोगी पार्टी की कीमत पर वह फलती-फूलती है । इसीलिए कांग्रेस परजीवी कांग्रेस बन चुकी है । ? (व्यवधान) मैं जब परजीवी कह रहा हूं, तो तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ आंकड़े आपके माध्यम से सदन को और इस सदन के माध्यम से देश के सामने रखना चाहता हूं । ? (व्यवधान) जहां-जहां भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था या जहां कांग्रेस मेजर पार्टी थी और साथियों के पास एक-दो सीटें थीं, वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ और सिर्फ 26 परसेंट है, लेकिन जहां कांग्रेस किसी का पल्लू पकड़कर चलती थी, जहां वह जूनियर पार्टनर थी, किसी दल ने इनको मौका दे दिया, ऐसे राज्यों में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 50 परसेंट है । ? (व्यवधान) कांग्रेस की 99 सीटों में से ज्यादातर सीटें उनके सहयोगियों ने जिताई हैं । इसीलिए मैं कहता हूं कि यह परजीवी कांग्रेस है । 16 राज्यों में जहां कांग्रेस अकेले लड़ी, वहां उसका वोट शेयर इस चुनाव में गिर चुका है । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने दम पर लड़ी और 64 में से केवल 2 सीटें ही जीत पाई है । ? (व्यवधान) इसका साफ मतलब है कि इस चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से परजीवी बन चुकी है और अपने सहयोगी दलों के कंधे पर चढ़कर सीटों का आंकड़ा बढ़ाया है । अगर कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के वोट न खाए होते, तो लोक सभा में उनके लिए इतनी सीटें जीत पाना भी बहुत मुश्किल था । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, ऐसे समय में एक अवसर आया है । देश ने विकास के रास्ते को चुना है । देश ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का मन बना लिया है । भारत को एकजुट होकर समृद्धि का नया सफर तय करना है । ऐसे समय में यह देश का दुर्भाग्य है कि हिन्दुस्तान में 6-6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी अराजकता फैलाने में जुटी हुई है ।? (व्यवधान) ये दक्षिण में जाकर उत्तर के लोगों के खिलाफ बोलते

हैं । ये उत्तर में जाकर पश्चिम के खिलाफ जहर उगलते हैं । पश्चिम के लोगों के खिलाफ बोलते हैं । महापुरूषों के खिलाफ बोलते हैं । इन्होंने भाषा के आधार पर बांटने की हर कोशिश की है । ? (व्यवधान) जिन नेताओं ने देश के हिस्से को भारत से अलग करने की वकालत की थी, उनको संसद की टिकट देने का दुर्भाग्य हमें देखना पड़ा । जो कांग्रेस पार्टी ने पाप किया है, कांग्रेस पार्टी खुलेआम एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ लड़ाने के लिए रोज नई-नई नरेटिव गढ़ रही है । नई तय अफवाहें फैला रही है । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के एक हिस्से के लोगों को हीन बताने की प्रवृत्ति को भी कांग्रेस के लोग बढ़ावा दे रहे हैं । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की दिशा में भी सोची-समझी चाल चल रही है । ? (व्यवधान) चुनाव के दौरान जो बातें की गईं राज्यों में, उनके राज्यों में जिस प्रकार से ये आर्थिक कदम उठा रहे हैं, वह रास्ता आर्थिक अराजकता की तरफ देश को घसीटने वाला है ।? (व्यवधान) उनके राज्य देश पर आर्थिक बोझ बन जाएं, यह खेल जान-बूझकर के खेला जा रहा है । मंचों से साफ-साफ घोषणा की गई । अगर इनके मन का परिणाम नहीं आया तो 4 जून को देश में आग लगा दी जाएगी । लोग इकट्ठे होंगे, अराजकता फैलाएंगे, ये अधिकृत रूप से आह्वान किए गए । यह अराजकता फैलाना इनका मकसद है । भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सवालों के घेरे में लाकर अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया है । सीएए को लेकर जो अराजकता फैलाई गई, देश के लोगों में गुमराह करने का जो खेल खेला गया, पूरी इको सिस्टम इस बात को बल देती रही, ताकि उनके राजनीतिक मकसद पूरे हों ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, देश को दंगों में झोंकने के भी कुत्सित प्रयास पूरे देश ने देखे हैं । ?(व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, आजकल सिम्पथी गेन करने के लिए एक नई ड्रामेबाजी शुरू की गई है । नया खेल खेला जा रहा है । मैं एक किस्सा सुनाता हूं । एक बच्चा स्कूल से आया और जोर-जोर से रोने लगा । उसकी मां भी डर गई कि क्या हो गया । वह बहुत रोने लगा, फिर कहने लगा कि मां मुझे आज स्कूल में मारा गया । आज स्कूल में मुझे उसने मारा, आज स्कूल में मुझे इसने मारा और वह जोर-जोर से रोने लगा । मां परेशान हो गई, उसने उससे पूछा कि बेटा बात क्या थी, लेकिन वह बता नहीं रहा था, बस रो रहा था कि मुझे मारा, मुझे मारा ।? (व्यवधान)

बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उस बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे को मां की गाली दी थी । उसने ये नहीं बताया कि उसने किसी बच्चे की किताबें फाड़ दी थीं । उसने ये नहीं बताया कि उसने टीचर को चोर कहा था । उसने ये नहीं बताया कि वह किसी का टिफिन चुराकर खा गया था । हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है । कल यहां बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था । मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा । ये चल रहा था । ?(व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, सिम्पथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है, लेकिन देशवासी ये सच्चाई जानते हैं कि ये हजारों-करोड़ रुपयों की हेराफेरी के मामले में जमानत पर बाहर हैं ।?(व्यवधान) ये ओबीसी वर्ग के लोगों को चोर बताने के मामले में सजा पा चुके हैं । इनको देश की सर्वोच्च अदालत में गैर-जिम्मेदाराना बयान देने के बाद माफी मांगनी पड़ी है । इन पर महान स्वातंत्र्य सेनानी वीर सवारकर जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान करने का मुकदमा है । इन पर देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को हत्यारा कहने का मुकदमा चल रहा है । इन पर अनेक नेताओं, अधिकारियों, संस्थानों पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप हैं और वे केस चल रहे हैं ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, बालक बुद्धि में न तो बोलने का ठिकाना होता है और न ही व्यवहार का कोई ठिकाना होता है । ? (व्यवधान) जब यह बालक बुद्धि पूरी तरह से सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं । ? (व्यवधान) यह बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठकर के आंखें मारते हैं ।? (व्यवधान) इनकी सच्चाई को अब पूरा देश समझ गया है ।? (व्यवधान) इसलिए, आज देश इनसे कह रहा है- ? तुमसे नहीं हो पाएगा ।? ? (व्यवधान) ?तुमसे ना हो पाएगा ।? ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी **:** आदरणीय अध्यक्ष जी, तुलसीदास जी कह गए हैं ।? (व्यवधान) अखिलेश जी, तुलसीदास जी कह गए हैं- ?झुठइ लेना, झुठइ देना, झुठइ भोजन, झुठइ चबेना ।?? (व्यवधान) तुलसीदास जी ने कहा है- ?झुठइ लेना, झुठइ देना, झुठइ भोजन, झुठइ चबेना ।? ? (व्यवधान) कांग्रेस ने झूठ को राजनीति का हथियार बनाया ।? (व्यवधान) कांग्रेस के मुंह झूठ लग गया है ।? (व्यवधान) जैसे आदमखोर एनिमल होता है, जिसको लहु मुंह पर लग जाता है ।? (व्यवधान) वैसे ही, कांग्रेस के मुंह झूठ का खून लग गया है ।? (व्यवधान) देश ने कल यानी 1 जुलाई को खटाखट दिवस भी मनाया है ।? (व्यवधान) 1 जुलाई को लोग अपने बैंक अकाउंट चेक कर रहे थे कि 8500 रुपये आए या नहीं आए!? (व्यवधान) इस झूठे नरेटिव का परिणाम देखिए, इसी चुनाव में कांग्रेस ने देशवासियों को गुमराह किया ।? (व्यवधान) माताओं-बहनों को हर महीने 8500 रुपये देने का झूठ? (व्यवधान) इन माताओं-बहनों के दिलों को जो चोट लगी है न! ? (व्यवधान) वह सर्प बनकर के कांग्रेस को तबाह करने वाली है ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, ईवीएम को लेकर झूठ, संविधान को लेकर झूठ, आरक्षण को लेकर झूठ? (व्यवधान) उससे पहले राफेल को लेकर झूठ, एच.ए.एल. को लेकर के झूठ, एल.आई.सी. को लेकर के झूठ, बैंकों को लेकर झूठ तथा कर्मचारियों को भी भड़काने के प्रयास हुए । हौसला तो इतना बढ़ गया कि कल सदन को भी गुमराह करने का प्रयास हुआ । कल अग्निवीर को लेकर सदन में झूठ बोला गया । कल यहां भरपूर असत्य बोला गया कि एम.एस.पी. नहीं दी जा रही है ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, संविधान की गरिमा से खिलवाड़, यह सदन का दुर्भाग्य है । अनेक बार लोक सभा में जीतकर के आए लोग सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ करें, यह शोभा नहीं देता है । यहां पर जो दल 60-60 सालों तक बैठा है, जो सरकार के कामों को जानता है, जिसके पास अनुभवी नेताओं की श्रृंखला है, वे जब अराजकता के इस रास्ते पर चले जाएं, झूठ के रास्ते को चुन लें, तब देश गंभीर संकट की तरफ जा रहा है और इसका सबूत भी मिल रहा है ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, सदन की गरिमा से खिलवाड़ हमारे संविधान निर्माताओं का अपमान है, इस देश के महापुरुषों का अपमान है । देश के लिए, आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों का अपमान है । आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूँ कि आप बहुत सर्वोदयी हैं । आप उदार मन के मालिक हैं । आप संकट के समय भी हल्की-फुल्की मीठी मुस्कान के साथ चीजों को झेल लेते हैं, लेकिन अब जो हो रहा है और कल जो हुआ है, उसे गंभीरता से लिए बिना संसदीय लोकतंत्र को हम रक्षित नहीं कर पाएंगे ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इन हरकतों को बालक बुद्धि कहकर, बालक बुद्धि मानकर के अब नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए । मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे इरादे नेक नहीं

हैं । इरादे गंभीर खतरे के हैं । मैं देशवासियों को भी जगाना चाहता हूँ । इन लोगों का झूठ हमारे देश के नागरिकों की विवेक बुद्धि पर आशंका व्यक्त करता है । उनका झूठ देश के सामान्य विवेक बुद्धि पर एक तमाचा मारने की निर्लज्ज हरकत है ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, ये हरकतें देश की महान परंपराओं पर तमाचा है । इस सदन की गरिमा बचाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है । हम सदन में शुरू हुई झूठ की परंपरा पर कठोर कार्रवाई करेंगे । यह देशवासियों की भी और इस सदन की भी अपेक्षा है ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण पर भी हमेशा झूठ बोला है । ?(व्यवधान) आज मैं 140 करोड़ देशवासियों के सामने सच्चाई रखना चाहता हूं, बड़ी नम्रतापूर्वक रखना चाहता हूं ।?(व्यवधान) देशवासियों ने भी इस सत्य को जानना बहुत जरूरी है ।?(व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपातकाल, इमरजेंसी का यह 50 वां वर्ष है । इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लोभ की खातिर, तानाशाही मानसिकता के कारण देश पर थोपा गया तानाशाही शासन था और कांग्रेस क्रूरता की सभी हदें पार कर चुकी है ।?(व्यवधान) उसने अपने ही देशवासियों पर क्रूरता का पंजा फैलाया था और देश के ताने-बाने को छिन्न-विच्छिन्न करने का पाप किया था । ?(व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, सरकारों को गिराना, मीडिया को दबाना, हर कारनामे, संविधान की भावना के खिलाफ, संविधान की धाराओं के खिलाफ, संविधान के एक-एक शब्द के खिलाफ है ।?(व्यवधान) ये वे लोग हैं, जिन्होंने प्रारंभ से देश के दलितों के साथ, देश के पिछड़ों के साथ घोर अन्याय किया है ।?(व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी कारण से बाबा साहेब अम्बेडकर ने कांग्रेस की दलित विरोधी, पिछड़े विरोधी मानसिकता के कारण नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था ।?(व्यवधान) उन्होंने पर्दाफाश किया था कि कैसे नेहरू जी ने दलितों, पिछड़ों के साथ अन्याय किया और बाबा साहेब अम्बेडकर ने कैबिनट से इस्तीफा देते समय जो कारण बताए थे, वे कारण इनके चरित्र को दर्शाते हैं ।?(व्यवधान) बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था, मैं सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों की उपेक्षा पर अपने अंदर उत्पन्न आक्रोश को रोक नहीं सका । ये बाबा साहेब अम्बेडकर के शब्द हैं । ?(व्यवधान) अनुसूचित जातियों की उपेक्षा, इसने बाबा साहेब अम्बेडकर को आक्रोशित कर दिया । ?(व्यवधान) बाबा साहेब के सीधे हमले के बाद नेहरू जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर का राजनीतिक जीवन खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा दी ।?(व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, पहले षड़यंत्रपूर्वक बाबा साहेब अम्बेडकर को चुनाव में हरवाया गया । ?(व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की इस पराजय का जश्न मनाया, खुशी मनाई ।? (व्यवधान) उन्होंने खुशी व्यक्त की । एक पत्र में यह लिखित है ।? (व्यवधान) इस खुशी का? (व्यवधान) बाबा साहेब की तरह ही दलित नेता बाबू जगजीवन राम जी को भी उनका हक नहीं दिया गया ।? (व्यवधान) इमर्जेंसी के बाद जगजीवन राम जी की पीएम बनने की सम्भावना थी ।? (व्यवधान) इंदिरा गांधी जी ने पक्का किया कि जगजीवन राम जी किसी भी हालत में पीएम न बनें ।? (व्यवधान) एक किताब में लिखा गया है कि किसी भी कीमत पर जगजीवन राम जी प्रधान मंत्री नहीं बनने चाहिए । अगर बन गए तो वे जिंदगी भर हटेंगे नहीं ।? (व्यवधान) यह इंदिरा गांधी जी का क्वोट उस किताब में है ।? (व्यवधान) कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह जी के साथ भी यही व्यवहार किया । उनको भी नहीं छोड़ा था ।? (व्यवधान) पिछड़ों के नेता, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष,

बिहार के सपूत सीताराम केसरी के साथ भी अपमानित व्यवहार करने का पाप इसी कांग्रेस ने किया था ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी प्रारम्भ से ही आरक्षण की घोर विरोधी रही है ।? (व्यवधान) नेहरू जी ने तो मुख्य मंत्रियों को चिट्ठी लिखकर साफ-साफ शब्दों में आरक्षण का विरोध किया था ।? (व्यवधान) कांग्रेस के एक प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट ठंडे बक्से में सालों तक दबाए रखा था ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी के तीसरे प्रधान मंत्री श्रीमान राजीव गांधी जब विपक्ष में थे, तो उनका सबसे लम्बा भाषण आरक्षण के खिलाफ था ।? (व्यवधान) वह आज भी संसद के रिकॉर्ड में उपलब्ध है । इसलिए? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज एक गम्भीर विषय पर आपका और देशवासियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।? (व्यवधान) कल जो हुआ, इस देश के कोटि-कोटि देशवासी आने वाली सदियों तक माफ नहीं करेंगे ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, 131 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था? मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से आता हूं, जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और वैश्विक स्वीकृति सिखाई है ।? (व्यवधान) 131 साल पहले हिन्दू धर्म के लिए विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में दुनिया के दिग्गजों के सामने कहा था ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, हिन्दू सहनशील है, हिन्दू अपनत्व को लेकर चलने वाला समूह है । इसी कारण से, भारत का लोकतंत्र भारत की इतनी विविधताएं, उसकी वैविध्यता की विराटता के कारण ही पनपी है और पनप रही है ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, यह एक गंभीर बात है कि आज हिन्दुओं पर झूठा आरोप लगाने की साज़िश हो रही है, गंभीर षड़यंत्र हो रहा है ।? (व्यवधान) यह कहा गया कि हिन्दू हिंसक होते हैं । यह है आपका संस्कार, यह है आपका चरित्र, यह है आपकी सोच, यह है आपकी नफरत? इस देश के हिन्दुओं के साथ ये कारनामे? ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, यह देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है ।? (व्यवधान) कुछ दिन पहले हिन्दुओं में जो शक्ति की कल्पना है, उसके विनाश की घोषणा की गई थी ।? (व्यवधान) आप किस शक्ति के विनाश की बात करते हैं? ? (व्यवधान) यह देश सदियों से शक्ति का उपासक है । ? (व्यवधान) यह मेरा बंगाल माँ दुर्गा की पूजा करता है, शक्ति की उपासना करता है ।? (व्यवधान) यह बंगाल माँ काली की उपासना करता है, समर्पित भाव से करता है ।? (व्यवधान) आप उस शक्ति के विनाश की बातें करते हो? ? (व्यवधान) ये वे लोग हैं, जिन्होंने ?हिन्दू आतंकवाद? शब्द गढ़ने की कोशिश की थी ।? (व्यवधान) इनके साथी हिन्दू धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया जैसे शब्दों से करें और ये लोग तालियाँ बजाएं, यह देश कभी माफ नहीं करेगा ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, एक सोची-समझी रणनीति के तहत इनका पूरा इको-सिस्टम हिन्दू परम्परा, हिन्दू समाज, इस देश की संस्कृति, देश की विरासत को नीचा दिखाना, उसे गाली देना, उसे अपमानित करना, हिन्दुओं का मजाक उड़ाने को फैशन बना दिया है और उसे संरक्षण देने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे तत्त्व कर रहे हैं ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, हम बचपन से सीखते हुए आये हैं, गांव का हो, शहर का हो, गरीब हो, अमीर हो, इस देश का हर बच्चा-बच्चा जानता है कि ईश्वर का हर रूप दर्शन के लिए होता है । ईश्वर का कोई भी रूप निजी स्वार्थ के लिए प्रदर्शन के लिए नहीं होता है ।? (व्यवधान) जिसके दर्शन होते हैं, उसके प्रदर्शन नहीं होते हैं । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे देवी-देवताओं का अपमान 140 करोड़ देशवासियों के दिलों को गहरी चोट पहुंचा रहा है । ? (व्यवधान) निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ईश्वर के रूपों का इस प्रकार से खेल? ? (व्यवधान) आदरणीय अध्यक्ष जी, यह देश कैसे माफ कर सकता है? ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, सदन के कल के दृश्यों को देखकर अब हिंदू समाज को भी सोचना होगा कि क्या यह अपमानजनक बयान कोई संयोग है या कोई प्रयोग की तैयारी है? ? (व्यवधान) यह हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सेनाएं देश का अभिमान हैं । ? (व्यवधान) सारे देश को उनके साहस और हमारी सेना की वीरता पर गर्व है । ? (व्यवधान) आज सारा देश देख रहा है । ? (व्यवधान) हमारी सेनाएं, हमारा डिफेंस सेक्टर आज़ादी के बाद इतने सालों में जितना नहीं हुआ, इतने रिफॉर्म्स हो रहे हैं, हमारी सेना को आधुनिक बनाया जा रहा है । ? (व्यवधान) हर चुनौती को हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे सके, इसलिए युद्ध के सामर्थ वाली सेना बनाने के लिए, देश की सुरक्षा का मकसद लेकर हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं, रिफॉर्म्स कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, बीते कुछ सालों में बहुत सारी चीजें बदली हैं । ? (व्यवधान) सीडीएस का पद बनने के बाद इंटीग्रेशन और सशक्त हुआ है । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सशस्त्र सेनाओं के बीच उनके सहयोग से, लंबे समय से युद्धशास्त्र के निष्णातों का मत था कि भारत में थिएटर कमांड जरूरी है । ? (व्यवधान) आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि सीडीएस व्यवस्था बनने के बाद देश में सुरक्षा के लिए जरूरी थिएटर कमांड की दिशा में प्रगति हो रही है । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, ?आत्मनिर्भर भारत? में हमारी सेना को आत्मनिर्भर बनाना, उसकी भी बहुत बड़ी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है । ? (व्यवधान) हमारे देश की सेना युवा होनी चाहिए । ? (व्यवधान) सेना दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए होती है । ? (व्यवधान) हमें हमारे युवाओं पर भरोसा होना चाहिए । ? (व्यवधान) सेना में युवाओं की ताकत बढ़ानी चाहिए । ? (व्यवधान) इसलिए, हम लगातार युद्ध-योग्य सेना बनाने के लिए रिफॉर्म्स कर रहे हैं । ? (व्यवधान) समय पर रिफॉर्म्स न करने के कारण हमारी सेना का बहुत नुकसान हुआ है । ? (व्यवधान) लेकिन ये बातें सार्वजनिक कहने योग्य नहीं होने के कारण मैं अपने मुंह को ताला लगाकर बैठा हूं । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, देश की सुरक्षा एक गंभीर मसला होता है । ? (व्यवधान) आदरणीय अध्यक्ष जी, ऐसे रिफॉर्म्स का उद्देश्य किसी भी परिस्थिति में, अब युद्ध के रूप बदल रहे हैं, संसाधन बदल रहे हैं, शस्त्र बदल रहे हैं, तकनीक बदल रही है । ? (व्यवधान) ऐसे में हमें हमारी सेनाओं को उन्हीं चुनौतियों के अनुरूप तैयार करना, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसको निभाने के लिए गालियाँ खाकर के भी, झूठे आरोप सहकर के भी मुँह पर ताला लगाकर हम काम कर रहे हैं ।? (व्यवधान) ऐसे समय में देश की सेना को आधुनिक बनाने, सशक्त बनाने

के लिए,?(व्यवधान) ऐसे समय कांग्रेस क्या कर रही है?? (व्यवधान) ये झूठ फैला रहे हैं ।? (व्यवधान) डिफेंस रिफॉर्म्स के प्रयासों को कमजोर करने की शरारत? (व्यवधान) कर रहे हैं ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, दरअसल कांग्रेस के लोग कभी भी भारतीय सेनाओं को ताकतवर होते नहीं देख सकते ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, कौन नहीं जानता कि नेहरू जी के समय देश की सेनाएं कितनी कमजोर होती थीं?? (व्यवधान) हमारी सेनाओं में कांग्रेस ने जो लाखों, करोड़ों रुपये के घोटाले किए, वही एक तरीका था, जिस तरीके से देश की सेनाओं को कमजोर किया है ।? (व्यवधान) इस देश की सेनाओं को कमजोर किया ।? (व्यवधान) जल हो, थल हो, नभ हो, सेना की हर आवश्यकता में इन्होंने देश आज़ाद हुआ तब से भ्रष्टाचार की परम्परा बनाई ।? (व्यवधान) जीप घोटाला हो, पनडुब्बी घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, इन सारे घोटालों ने देश की सेना की ताकत को बढ़ने से रोका है ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, वह भी एक वक्त था, कांग्रेस के जमाने में हमारी सेनाओं के पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं हुआ करती थीं ।? (व्यवधान) सत्ता में रहते हुए देश की सेना को तो बर्बाद किया ही किया, उसे कमजोर किया ही किया, लेकिन ये कारनामे विपक्ष में जाने के बाद भी चलते रहे ।? (व्यवधान) विपक्ष में जाने के बाद भी सेना को कमजोर करने के लगातार प्रयास होते रहे हैं ।? (व्यवधान) जब यह कांग्रेस सरकार में थी तो फाइटर जेट नहीं लिए और जब हमने कोशिश की तो कांग्रेस हर तरह की साजिश पर उतर आई ।? (व्यवधान) फाइटर जेट एयरफोर्स तक न पहुँच पाए, इसके लिए साजिशें की गईं ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, यह बालक बुद्धि देखिए कि राफेल के छोटे-छोटे खिलौने बनाकर के उड़ाने में मजा लेते थे ।? (व्यवधान) देश की सेना का मजाक उड़ाते थे ।? (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, कांग्रेस ऐसे हर कदम का और रिफॉर्म का विरोध करती है, जो भारत की सेना को मजबूती दे, भारत की सेना को मजबूत बनाए ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्यों, सभा की कार्यवाही माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण तक के लिए बढ़ाई जाती है और सभा की कार्यवाही सारी कार्यवाही पूर्ण होने तक बढ़ाई जाती है ।

? (व्यवधान)

18.00 hrs

श्री नरेन्द्र मोदी **:** आदरणीय सभापति जी, समय देने के लिए और समय का विस्तार करने के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के लोगों को यह पता चल गया है कि हमारे नौजवानों की ऊर्जा हमारे सैनिकों का आत्मबल ही हमारे सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी शक्ति है और अब इस पर हमला करके एक नया तरीका सेना में भर्ती को लेकर सरासर झूठ फैलाया जा रहा है, ताकि मेरे देश के नौजवान मेरे देश की रक्षा करने के लिए सेना में न जाएं । उन्हें रोकने के लिए षड्यंत्र हो रहा है ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के माध्यम से जानना चाहता हूं कि आखिर किसके लिए कांग्रेस हमारी सेनाओं को कमजोर करना चाहती है । किसके फायदे के लिए कांग्रेस वाले सेना के संबंध में इतना झूठ फैला रहे हैं । ?वन रैंक वन पेंशन? को लेकर देश के वीर जवानों की आंखों में झूल झोंकने का प्रयास किया गया ।? (व्यवधान) हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ?वन रैंक वन पेंशन? की व्यवस्था को खत्म किया था । दशकों तक कांग्रेस ने ?वन रैंक वन पेंशन? को लागू नहीं होने दिया और जब चुनाव आए तो 500 करोड़ रुपया दिखा कर सेवानिवृत्त सेना के नायकों को मूर्ख बनाने की कोशिशें भी की गईं । उनका इरादा था कि जितना हो सके ? वन रैंक वन पेंशन? को टालते रहें । एनडीए सरकार ने ?वन रैंक वन पेंशन? लागू की । भारत के पास संसाधन कितने ही सीमित क्यों न हों, लेकिन उसके बावजूद भी, कोरोना की कठिन लड़ाई के बावजूद भी 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये हमारे पूर्व सैनिकों को ?वन रैंक वन पेंशन? के रूप में दिए गए ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्यों, यह तरीका ठीक नहीं है । आप संसदीय परम्पराओं का पालन करें ।

? (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी **:** आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने अपने उद्बोषण में पेपर लीक पर भी चिंता जताई है । मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवान को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं ।? (व्यवधान) युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा । नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं । केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है ।? (व्यवधान) परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, एनडीए सरकार ने बीते दस वर्षों में विकास को अपना सबसे बड़ा संकल्प बनाया है ।? (व्यवधान) आज हमारे सामने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का संकल्प है ।? (व्यवधान) आज हमारे सामने आज़ादी के इतने सालों के बाद पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए हर घर जल पहुंचाने का हमारा संकल्प है ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, हर गरीब को आवास देना, यह हमारा संकल्प है ।? (व्यवधान) विश्व में भारत की जैसे-जैसे ताकत बढ़ रही है, हमारी सेनाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का हमारा दृढ़ संकल्प है ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, यह युग हरित युग है, यह युग ?ग्रीन एरा? है ।? (व्यवधान) इसलिए, दुनिया, जो ग्लोबल वार्मिंग से लड़ाई लड़ रही है, उसको एक बहुत बड़ी ताकत देने का बीड़ा भारत ने उठाया है ।? (व्यवधान) भारत रिन्यूएबल एनर्जी का पावरहाउस बने, उस दिशा में हमने एक के बाद एक कदम उठाया है और उसको अचीव करने का हमारा संकल्प है ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, भविष्य ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ा है, ई-व्हीकल से जुड़ा हुआ है ।? (व्यवधान) भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाने के लिए भी हम पूरी तरह संकल्पबद्ध हैं ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, इक्कीसवीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए जिन संकल्पों को लेकर हम चले हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत बड़ी भूमिका है ।? (व्यवधान) हमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमें विश्व के सारे बेंचमार्क्स की बराबरी पर जाना है ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितना निवेश हुआ है, उतना निवेश पहले कभी नहीं हुआ है, जिसका लाभ आज देशवासी देख रहे हैं ।? (व्यवधान) देश में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बन रहे हैं ।? (व्यवधान) अब उसका विस्तार हो, उसको एक नया रूप-रंग मिले, आधुनिक भारत की आवश्यकताओं के अनुसार स्किल डेवलपमेंट हो और उसके आधार पर ?इंडस्ट्री 4.0? में भी भारत लीडर के रूप में उभरे और हमारे नौजवानों का भविष्य भी संवरे, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, एक स्टडी है, यह स्टडी बड़ी महत्वपूर्ण है ।? (व्यवधान) यह अध्ययन कहता है कि पिछले 18 सालों में प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएशन में आज सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है, 18 सालों में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है ।? (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, आज भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम पूरी दुनिया में एक उदाहरण बना है । ? (व्यवधान) मैं जब भी जी-20 समूह की बैठक में गया, तब भारत के डिजिटल इंडिया मूवमेंट को ले कर, डिजिटल पेमेंट को ले कर, विश्व के समृद्ध देशों को भी अचरज होता है और वे बड़ी जिज्ञासा के साथ हमसे सवाल पूछते हैं । ? (व्यवधान) यह भारत की सफलता की बहुत बड़ी कहानी है । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, प्लीज़ । यह तरीका ठीक नहीं है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप सब अपनी-अपनी सीटों पर जाइए ।

? (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी **:** आदरणीय अध्यक्ष जी, जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, स्वाभाविक है कि प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है और चुनौतियां भी बढ़ रही हैं । ? (व्यवधान) जिन्हें भारत की प्रगति से दिक्कत है, जो भारत की प्रगति को चुनौती के रूप में देखते हैं, वे गलत हथकंडे भी अपना रहे हैं । ये ताकतें भारत की डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डायवर्सिटी पर हमला कर रही है । ? (व्यवधान) यह चिंता सिर्फ मेरी नहीं है । ? (व्यवधान) यह चिंता सिर्फ सरकार की नहीं है । ? (व्यवधान) यह चिंता सिर्फ ट्रेज़री बेंच की नहीं है । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, देश की जनता और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक सब कोई इन बातों से चिंतित है । ? (व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, वह कोट मैं आज सदन के सामने रखना चाहता हूँ । ? (व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट का यह कोट, देश के करोड़ों-करोड़ लोगों के लिए भी कैसे-कैसे संकट आने की संभावनाएं दिख रही हैं, इसकी तरफ इशारा करता है । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में बड़ी गंभीरतापूर्वक कहा है और मैं वह कोट पढ़ता हूँ - ?ऐसा लगता है कि इस महान देश की प्रगति पर संदेह प्रकट करने, उसे कम करने और हर संभव मोर्चे पर उसे कमज़ोर करने का एक ठोस प्रयास किया जा रहा है ।? यह मैं सुप्रीम कोर्ट की बात पढ़ रहा हूँ । सुप्रीम कोर्ट आगे कह रहा है ? ?इस तरह के किसी भी प्रयत्न या प्रयास को आरंभ में ही रोक दिया जाना चाहिए ।? देश की सुप्रीम कोर्ट का यह कोट है ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह जो भावना व्यक्त की है, इस पर हम यहां वाले या वहां वाले, जो सदन में हैं उन्होंने और जो बाहर हैं उन्होंने, सबको गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत में भी कुछ लोग हैं, जो ऐसी ताकतों की मदद कर रहे हैं । ? (व्यवधान) देशवासियों को ऐसी ताकतों से सतर्क रहने की ज़रूरत है । ? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014 में सरकार में आने के बाद देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस का इको सिस्टम भी रहा है ।? (व्यवधान) इस इको सिस्टम से मिली खाद-पानी, इसके दम पर कांग्रेस की मदद से यह इको सिस्टम 70 साल तक फला-फुला है ।? (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं आज इस इको सिस्टम को चेताना चाहता हूं । इस इको सिस्टम की जो हरकतें हैं, जिस तरह से इस इको सिस्टम ने ठान लिया है कि विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डीरेल कर देंगे ।? (व्यवधान) मैं आज इस इको सिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा । यह देश, देश विरोधी साजिशों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, यह ऐसा काल खंड है, जब दुनिया भारत की प्रगति को बहुत गंभीरता से ले रही है, हर बारीकी को नोटिस कर रही है ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, अब चुनाव हो चुके हैं । 140 करोड़ देशवासियों ने अपना निर्णय व जनादेश दे दिया है, आवश्यक है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए इस संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए, इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का योगदान होना चाहिए ।? (व्यवधान) मैं उन सब को निमंत्रित करता हूं कि विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए आप भी जिम्मेवारी के साथ आगे आइए ।? (व्यवधान) देश हित के विषय पर हम साथ चलें, मिल कर के चलें और देशवासियों की आशा-आकांक्षाओं को पूरा करने में हम कोई कमी न रहने दें ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, पॉजिटिव राजनीति भारत के इस काल खंड में बहुत आवश्यक है और मैं अपने साथी पक्षों से भी कहना चाहूंगा, इंडी गठबंधन पक्ष के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप मैदान में आइए । आप गुड गवर्नेंस पर स्पर्धा करें । जहां-जहां आपकी सरकारें हैं, वहां आप एनडीए की सरकारों के साथ गुड गवर्नेंस पर स्पर्धा करें, डिलिवरी पर स्पर्धा करें, लोगों की आकांक्षा पूरी करने पर स्पर्धा करें, इससे देश का भला होगा और आपका भी भला होगा ।? (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, आप अच्छे कामों के लिए एनडीए के साथ स्पर्धा करें । आप रिफॉर्म्स के मामले में हिम्मत करें । जहां-जहां आपकी सरकारें हैं, वहां आप रिफॉर्म्स से कदम बढाएं और वहां विदेशी निवेश को आकर्षित करें ।? (व्यवधान) अपने-अपने राज्यों में विदेशी निवेश ज्यादा आए, इसके लिए प्रयास करें । ? (व्यवधान) उनको यह अवसर है, उनके पास राज्यों में कुछ सरकारें हैं । ? (व्यवधान) इसके लिए वह भाजपा की सरकारों से स्पर्धा करें, एनडीए की सरकारों से स्पर्धा करें, सकारात्मक स्पर्धा करें ।? (व्यवधान) जिन लोगों को जहां सेवा करने का मौका मिला है, वहां पर वे रोजगार के लिए स्पर्धा करें ।? (व्यवधान) कौन सरकार ज्यादा रोजगार देती है, स्पर्धा के लिए मैदान में आएं, एक तंदुरुस्त स्पर्धा हो ।?(व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां भी कहा है कि गहना कर्मणो गतिः, यानी कर्म की गति गहन है ।?(व्यवधान) इसलिए आक्षेप, झूठ, फरेब, डिबेट ऐसे जीतने के बजाए, कर्म से, कुशलता से, समर्पण भाव से, सेवा भाव से जरा लोगों के दिल जीतने के लिए कोशिश होनी चाहिए ।?(व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी इस समय चर्चा के बीच मुझे एक दु:खद खबर भी दी गई है । यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई, उसमें अनेक लोगों की दु:खद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है । जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं । मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं । राज्य सरकार की देख-रेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है । केंद्र सरकार के वरिष्ठ, उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार सम्पर्क में हैं । मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आज एक लम्बी चर्चा हुई ।? (व्यवधान) मुझे पहली बार लोक सभा में प्रधान मंत्री के रूप में यहां पर सेवा के लिए आप लोगों ने अवसर दिया, तब भी मुझे ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा था । ?(व्यवधान) वर्ष 2019 में भी मुझे ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा ।?(व्यवधान) मुझे राज्य सभा में भी ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा ?(व्यवधान) और इसलिए अब तो हौसला भी बड़ा मजबूत हो गया है ।?(व्यवधान) मेरा हौसला भी मजबूत है, मेरी आवाज भी मजबूत है और मेरे संकल्प भी मजबूत हैं ।?(व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, ये कितनी ही संख्या का दावा क्यों न करते हों, 2014 में जब हम आए, राज्य सभा में हमारी ताकत बहुत कम थी और चेयर का भी जरा झुकाव दूसरी तरफ था ।?(व्यवधान) लेकिन सीना तान करके देश की सेवा करने के संकल्प से हम डिगे नहीं ।?(व्यवधान) मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आपने जो फैसला सुनाया है, आपने हमें सेवा करने का जो आदेश दिया है, ऐसी किसी रुकावटों से न मोदी डरने वाला है और न यह सरकार डरने वाली है ।?(व्यवधान) जिन संकल्पों को लेकर हम चले हैं, उन संकल्पों को पूरा करके रहेंगे ।?(व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, जो नए सांसद चुनकर आए हैं, उनको मैं विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं ।?(व्यवधान) मैं मानता हूं ? (व्यवधान) कि वे बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे । ? (व्यवधान) देश के लोगों की नजरों से गिरते हुए बचने का प्रयास भी करेंगे, इसलिए उनको भी परमात्मा कुछ सदबुद्धि दें, बालक बुद्धि को भी सदबुद्धि दे, इस अपेक्षा के साथ आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी के उदबोधन के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं ।

अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, विस्तार से बात बताने का मौका दिया, किसी का कोलाहल सत्य की आवाज को दबा नहीं सकता, ? (व्यवधान) सत्य ऐसे प्रयासों से नहीं दबता है और झूठ की कोई जड़ नहीं होती है ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जिन लोगों को बोलने का अवसर नहीं दिया, यह उनकी पार्टी की जिम्मेवारी है, वह आगे अपने सांसदों का ध्यान रखेंगे, यह मैं अपेक्षा करता हूं । मैं इस सदन का भी धन्यवाद करते हुए ? (व्यवधान) आज मुझे बहुत आनंद आया, ? (व्यवधान) बहुत आनंद आया ? (व्यवधान) सत्य की ताकत क्या होती है, वह आज मैंने जी कर देखा, सत्य का सामर्थ्य क्या होता है, ? (व्यवधान) उसका मैंने आज साक्षात्कार किया ? (व्यवधान) इसलिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों ने अनेक संशोधन प्रस्तुत किए हैं, अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

(संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।)

माननीय अध्यक्ष **:** अब मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है:

?कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :-

?कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 27 जून, 2024 को एक साथ समेवत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं ।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।)

_____

14.09 hrs